

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 103]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 10, 2013/वैशाख 20, 1935

No. 103]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 10, 2013/VAISAKHA 20, 1935

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मई, 2013

अंतिम जांच परिणाम

विषयः— चीन जन.गण., इण्डोनेशिया, मलेशिया और श्रीलंका मूल के अथवा वहां से निर्यातित रेजिन या किसी अन्य जैव पदार्थ द्वारा बांडेड न किए गए इन्सुलेशन बोर्डों, लैमिनेटिड फाइबर बोर्डों और बोर्डों को छोड़कर, 6 मिमी से कम की मोटाई के रेजिन या अन्य जैव पदार्थ बाण्डेड लकड़ी या लकड़ी जैसे फाइबर बोर्डों, के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच ।

संख्या 14/29/2010—डीजीएडी: समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे एतदपश्चात अधिनियम कहा गया है) और उसके अंतर्गत बने समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली (जिसे एतदपश्चात पाटनरोधी नियमावली कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

2. निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें एतदपश्चात प्राधिकारी कहा गया है) को पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत, चीन जन.गण. इण्डोनेशिया, मलेशिया और श्रीलंका (जिन्हें एतदपश्चात सम्बद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “रेजिन या किसी अन्य जैव पदार्थ द्वारा अनाबद्ध इन्सुलेशन बोर्डों, लैमिनेटिड फाइबर बोर्डों और बोर्डों को छोड़कर 6 मिमी से कम की मोटाई के रेजिन या किसी अन्य जैव पदार्थ द्वारा बाण्डेड लकड़ी या लकड़ी जैसे फाइबर बोर्डों (जिन्हें एतदपश्चात “विचाराधीन उत्पाद, पतला फाइबर बोर्ड और “सम्बद्ध वस्तु” कहा गया है) के पाटन का आरोप लगाते हुए मै. बालाजी एक्शन बिल्डवेल (जिसे एतदपश्चात आवेदक कहा गया है) ने अधिनियम तथा पाटनरोधी नियमावली के अनुसार एक आवेदन; प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने पाटनरोधी जांच की शुरुआत करने और पाटनरोधी उपाय अधिरोपित करने का अनुरोध किया है।

3. आवेदन की प्रारंभिक संवीक्षा करने पर कुछ त्रुटियां प्राप्त हुई जिनमें आवेदक ने बाद में सुधार कर दिया। अतः, उनके आवेदन को समुचित प्रलेखित आवेदन के रूप में माना गया। प्राधिकारी ने, जांच प्रारंभ करने को आवेदक द्वारा न्यायोचित ठहराने के लिए प्रस्तुत पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर सम्बद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सम्बद्ध वस्तु के आयातों के सम्बंध में जांच प्रारंभ करने का निश्चय किया।

1928 GI/2013

(1)

4. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(5) के अनुसार जांच प्रारंभ करने की प्रक्रिया से पहले अन्य बातों के साथ-साथ पाटन तथा उसके परिणाम स्वरूप घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति के आरोप युक्त आवेदन की प्राप्ति के बारे में भारत में सम्बद्ध देशों के उच्चायोगों/राजदूतावासों को अधिसूचना भेजी गई।

5. तदनुसार प्राधिकारी ने, कथित पाटन और उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति की पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 में दी गई शर्तों के अनुसार जांच प्रारंभ की ताकि कथित पाटन की मौजूदगी उसकी मात्रा तथा उसके प्रभाव का निर्धारण और पाटनरोधी शुल्क की मात्रा की सिफारिश की जा सके जो, यदि अधिरोपित की जाती तो वह घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति से बचाने के लिए पर्याप्त होगी।

क. **प्रक्रिया**

6. इसमें निम्नलिखित वर्णित प्रक्रिया का अनुसरण किया गया है :

i. प्राधिकारी ने, पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 (1) के अनुसार कथित पाटन की मौजूदगी, उसकी मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने तथा पाटनरोधी शुल्क की राशि की सिफारिश करने, जो यदि यदि अधिरोपित की गई होती तो घरेलू उद्योग की क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होती, के लिए सम्बद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सम्बद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच प्रारंभ करने के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण में दिनांक 11 नवम्बर, 2011 को प्रकाशित एक सार्वजनिक सूचना जारी की।

ii. प्राधिकारी ने 11 नवम्बर, 2011 की जांच शुरुआत अधिसूचना की एक प्रति भारत में सम्बद्ध देशों के उच्चायोगों/राजदूतावासों, सम्बद्ध देशों के ज्ञात निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं और आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए पत्रों पर घरेलू उद्योग को भेजी तथा उनसे अनुरोध किया कि वे इस अधिसूचना के प्रारंभ से 40 दिनों के अंदर अपने विचारों से लिखित रूप में अवगत कराए।

iii. प्राधिकारी ने नियम 6 (3) तथा उसके अंतर्गत बने नियमों के अनुसार आवेदनपत्र के अगोपनीय पाठ की एक प्रति ज्ञात निर्यातकों और भारत में संबद्ध देशों के उच्चायोगों/राजदूतावासों को प्रदान की।

iv. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 (2) के अनुसार इस जांच शुरुआत के बारे में सम्बद्ध देशों के भारत स्थित उच्चायोगों/राजदूतावासों को इस अनुरोध के साथ सूचित किया गया कि वे अपने देश के निर्यातकों/उत्पादकों को निर्धारण समयसीमा के अंदर प्रश्नावलियों का उत्तर देने का सुझाव दें। निर्यातकों/उत्पादकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावलियों की ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों के नाम और पत्तों सहित प्रति उन्हें भी भेजी गई।

v. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 (4) के अनुसार सम्बद्ध देशों के ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों को संगत सूचना प्रदान करने के लिए प्रश्नावलियां भेजी:

क्रम सं.	उत्पादक/निर्यातक का नाम
1	मै. टोमरिच इंटरनेशनल ट्रेडिंग लिमिटेड, पुडान्ग, शंघाई, चीन
2	मै. नानजिंग ई टी ए आई ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड जिन्झाजिंग नान्जिंग चीन जन.गण.
3	मै. लिन्थी होंगफू टिम्बर कम्पनी लिमिटेड, यितांग टाउन, लिनयी, शान्दांग, चीन जन.गण.
4	मै. शौगुआन्ग गुइही इकमोनमिक एवं व्यापार कम्पनी लिमिटेड, शान्दांग चीन जन.गण.
5	मै. जिन्थी बैडेली इंटरनेशनल ट्रेड कम्पनी लिमिटेड, नैन लोऊ जोन यितांग टाउन, लैनशान जिला, लिनयी सिटी शान्दांग, चीन जन.गण.
6	मै. झान्जियांग किंगस्टार बिल्डिंग मैटीरियल कम्पनी लिमिटेड, झान्जियांग गौगडांग, चीन जन.गण.
7	मै. वैन्झोऊ टिम्बर ग्रुप कम्पनी लिमिटेड, झेजियांग, चीन जन.गण.
8	मै. डाइकेन मीरी एस डी एन. बीएचडी, मीरी सारावाक, मलेशिया
9	मै. मेरबाक एम डी एफ लंका प्रा. लिमिटेड, होराना, श्रीलंका
10	मै. राबिन रिसोर्सेस (मलेशिया) एस डी एन. बीएचडी, पहांग, मलेशिया
11	मै. एवरग्रीन फाइबर बेरहाद (जेबी)एसडीएम, बीएचडी, जोहोर, मलेशिया
12	मै. पीटी अण्डालान कार्या बेरसामा; काकारटा राया.इण्डोनेशिया
13	मै. ला. मोबिला पन्नेल्ली पीटी, रूकान एकक्लेव बुकिट गोल्फ पन्टाई इन्डाह कापुक इण्डोनेशिया

vi. उपर्युक्त अधिसूचना के प्रत्युत्तर में निर्यातकों/आयातकों/एसोसिएशनों आदि सहित निम्नलिखित हितबद्ध पक्षकारों ने प्रत्युत्तर दिया:

क्रम सं.	उत्पादक/निर्यातक का नाम
1	मै. मैग्ना-फोरमोस्ट एसडीएन, बीएचडी, मलेशिया
2	मै. मैशोनाइट काम्पोनेन्ट्स, आयरलैंड
3	मै. मेरबाक एमडीएफ लंका (प्राइवेट) लिमिटेड, श्रीलंका
4	मै. सेगामट पैनल बोर्ड्स एस डी एन, बीएचडी, मलेशिया
5	मै. पीटी मसारी द्विसेपाकट इण्डोनेशिया
6	मै. पी.टी. सुमाटेरा प्राइमा फाइबर बोर्ड, इण्डोनेशिया
7	मै. एवरग्रीन फाइबर बोर्ड बेरहाद (ईएफबी), मलेशिया
8	मै. एवरग्रीन फाइबर बोर्ड (जे बी) एसडीएन, बीएचडी, मलेशिया
9	मै. एवरग्रीन फाइबर बोर्ड (निलाई) एस डी एन बीएचडी (ईएफएन) मलेशिया
10	मै. डाइकेन मिरि. एसडीएन. बीएचडी, मिरि सारावाक, मलेशिया
11	मै. पी.टी.हिजाऊ लेस्टारी राया फाइबर बोर्ड, इण्डोनेशिया
12	मिनिस्ट्री आफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इण्डस्ट्री, मलेशिया
13	इण्डोनेशिया गणराज्य का राजदूतावास, नई दिल्ली
14	महानिदेशक, केजरा सामा इंडस्ट्री इंटरनेशनल, जकार्ता, इंडोनेशिया
15	मै. डॉंगवाहा फाइबर बोर्ड एस डी एन बीएचडी, मलेशिया

vii. भारत में सम्बन्धित वस्तु के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं/एसोसिएशनों को पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 (4) के अनुसार आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए प्रश्नावलियां भेजी:

क्रम सं.	कंपनी का नाम
1	मै. सी एल गुप्ता एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, गांव जीवल, जेपीनगर, उ.प्र.
2	मै. वेणुगोपाल स्लेट इंडस्ट्रीज, मारकापुर, आंध्र प्रदेश
3	मै. मुरादाबाद हैण्डिकाफ्ट्स एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन, मुरादाबाद, उ.प्र.
4	मै. थामाराप्पल्ली ब्रदर्स, एम जी रोड, एर्नाकुलम, कोचीन
5	मै. स्पेशलुड फर्निशर्स, प्रा. लिमिटेड, टी-48, एम आई डी सी रोड, नागपुर: 440016
6	मै. फेरोक बोर्ड्स लिमिटेड, कारद फेरोक कालेज, मालाप्पुरम होकर, केरल
7	मै. आर जे मेटल्स, एक्सएल/4039 फाबा काम्प्लेक्स, ज्यूस स्ट्रीट, एर्नाकुलम, कोचीन, केरल
8	मै. कलिंगा एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स प्रा. लिमिटेड, 18/777, कल्लाई रोड, कालीकट, केरल
9	मै. विक्ट्री प्लाईवुड डिस्ट्री ब्यूटर्स, स्टेडियम काम्प्लेक्स, कन्नूर, केरल
10	मै. मैथ्यूस् एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स प्रा. लिमिटेड, कलूर, कोचीन, केरल
11	मै. प्लाई प्वाइंट, कोडामुञ्जा रोड, पेट्टा फेरोक, कोझीकोड, केरल
12	मै. लेबल सेल्स कारपोरेशन, इन्द्रधनुष अपार्टमेंट्स, शाप सं. 7,8 एवं 9 टी डी रोड, कोचीन, केरल

13	मै. श्रीवारी ट्रेडर्स, ओडान्थुराई, मिटुपलायम, तमिलनाडु
14	मै. कृष्णा प्लाईवुड, कामराज रोड, करूर, तमिलनाडु
15	मै. ताम्रपल्ली ब्रदर्स, एर्नाकुलम, कोची, केरल
16	मै. जैकसन्स वनीर्स एंड पैनल्स प्रा. लिमिटेड, एर्नाकुल, कोच्ची, केरल
17	मै. कुट्टी फ्लशडोर्स एंड फर्नीचर कम्पनी प्रा. लिमि. कोयाम्बेड, चेन्नई
18	एसोसिएशन आफ फर्नीचर मैन्यूफैक्चरर्स आफ इंडिया (एएफएमआई) मुम्बई

viii. उपर्युक्त अधिसूचना के प्रत्युत्तर में निम्नलिखित आयातकों/प्रयोक्ताओं, एसोसिएशनों ने प्रत्युत्तर दिया:

क्रम सं.	आयातक का नाम
1	मै. वेणुगोपाल स्लेट इंडस्ट्रीज, मारकापुर, आंध्र प्रदेश
2	इंडिया मोल्डेड पैनल शटर्स मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन
3	मै. मुरादाबाद हैण्डीक्राफ्ट्स एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन, मुरादाबाद, उ.प्र.
4	मै. सी एल गुप्ता एक्सपोर्टर्स लिमि. उत्तर प्रदेश (उ.प्र.) भारत
5	इंडियन मोल्डेड पैनल शटर्स मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन
6	बालाजी इम्पेक्स
7	कोटेश्वरी स्लेट वर्क्स
8	साई कृपा स्लेट वर्क्स
9	विश्वामित्र स्लेट वर्क्स
10	आल इंडिया फाइबर बोर्ड मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन, हरियाणा
11	सार्थक ओवरसीज दिल्ली

ix. सभी ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों तथा चीन जन.गण. के नई दिल्ली स्थित राजदूतावास को गैर बाजार अर्थव्यवस्था निरूपण (एम ई टी) प्रश्नावली भेजी गयी। जांच शुरुआत के लए चीन जन.गण. में सामान्य मूल्य का विचार चीन जन.गण. में सम्बद्ध वस्तु की निर्मित उत्पादन लागत के आधार पर की गई क्योंकि आवेदकों ने अभिवचन किया कि तृतीय देश बाजार अर्थव्यवस्था के लिए सूचना उनके पास उपलब्ध नहीं है। प्राधिकारी ने सभी ज्ञात निर्यातकों को सूचित किया कि उनका पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 और 8 के आलोक में आवेदक के दावे की जांच करने का प्रस्ताव है। अतः, चीन जन.गण. से सम्बद्ध वस्तु के निर्यातकों/उत्पादकों से अनुरोध किया गया कि वे पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध के पैराग्राफ 8 के उप पैरा (3) में यथा उल्लिखित आवश्यक सूचना/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करें जिससे कि प्राधिकारी यह विचार कर सके कि क्या चीन जन.गण. के सहयोगकर्ता निर्यातकों/उत्पादकों को बाजार अर्थव्यवस्था निरूपण किया जाए या नहीं।

x. प्राधिकारी ने विभिन्न हित बद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय पाठ को हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण के लिए खुली रखी गई सार्वजनिक फाहल के रूप में उपलब्ध कराया।

xi. वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकीय महानिदेशालय (डीजीसीआई एंड एस) से अनुरोध किया गया कि वह सम्बद्ध वस्तु के पिछले तीन वर्षों, जांच की अवधि सहित, के लिए किए गए आयातों का विवरण उपलब्ध कराए।

xii. आवेदक द्वारा सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों (जीएपी) के आधार पर प्रस्तुत सूचना के आधार पर भारत में सम्बद्ध वस्तु की इष्टतम उत्पादन लागत और उसे बनाने एवं बिक्री की लागत का निर्धारण किया गया ताकि यह निश्चित किया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से न्यूनतम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग की क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

xiii. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने दिनांक 23.07.2012 की अधिसूचना सं. 14/29/2010: डीजीएडी के तहत प्रारंभिक जांच परिणाम अधिसूचित किए और सम्बद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सम्बद्ध वस्तु के आयातों पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित करने की सिफारिश की थी। प्राधिकारी ने दिनांक 1 अक्टूबर, 2012 की शुद्धि पत्र अधिसूचना सं. 14/29/2010: डीजीएडी के तहत मोल्डेड डोर-स्कन का अपवर्जन करके सम्बद्ध वस्तु के दायरे में संशोधन किया। निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा की गई अंतरिम सिफारिशों को केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया और दिनांक 21 सितम्बर, 2012 की अधिसूचना सं. 43/2012-सीमा शुल्क (एडीडी) के तहत अंतरिम शुल्क लगाया गया। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार ने यह जांच पूरी करने के लिए 10 मई, 2013 तक का समय बढ़ा दिया गया।

xiv. प्राधिकारी ने, पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार 22 नवम्बर, 2012 को आयोजित एक सार्वजनिक सुनवाई में सभी हितबद्ध पक्षकारों को अपने विचार मौखिक रूप से व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया। जिन पक्षकारों ने इस सार्वजनिक सुनवाई में अपने विचार मौखिक रूप से व्यक्त किए उनसे कहा गया कि वे मौखिक रूप अभिव्यक्त अपने विचार लिखित रूप में भी प्रस्तुत करें। हितबद्ध पक्षकारों को विपक्षी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तुतिकरणों का प्रतिवादी उत्तर प्रदान करने का अवसर भी दिया गया। हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त लिखित [प्रस्तुतिकरणों/प्रतिवादी](#) प्रत्युत्तरों में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्कों पर इस अधिसूचना में, जहां संगत पाया गया, विचार किया गया।

xv. यह जांच 1 अप्रैल, 2010 से 30 जून, 2011 (पी ओ आई) तक की अवधि के लिए की गई थी। तथापि, क्षति विश्लेषण के संबंध में प्रवृत्तियों की जांच करने के लिए अप्रैल, 2007, मार्च, 2008, अप्रैल, 2008-मार्च, 2009, अप्रैल, 2009-मार्च, 2010 और जांच की अवधि अर्थात् 1 अप्रैल, 2010 से 30 जून, 2011 को कवर किया गया है।

xvi. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान कराई गई सूचना की गोपनीयता दावे की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने, जहां कहीं आवश्यक हुआ गोपनीयता के दावे को स्वीकार कर लिया और ऐसी जानकारी को गोपनीय के रूप में माना गया और इसका अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकटन नहीं किया गया। गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान कराने वाले पक्षकारों को, जहां कहीं संभव हुआ, निदेश दिया गया कि वे गोपनीय आधार पर प्रदान कराई गई जानकारी का पर्याप्त अगोपनीय पाठ भी प्रदान कराएं।

xvii. यदि किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच के दौरान आवश्यक सूचना तक पहुंच की मनाही कर दी अथवा अन्यथा उपलब्ध नहीं कराई अथवा जांच में पर्याप्त रूप से अवरोध उत्पन्न किया वहां प्राधिकारी ने यह जांच परिणाम 'उपलब्ध तथ्यों' के आधार पर दर्ज किए हैं।

xviii. नियम 16 और उसके अंतर्गत बने नियमों के अनुसार इन जांच परिणामों के लिए जरूरी समझे गए तथ्य/आधार का ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को प्रकटन विवरण के तहत खुलासा कर दिया और उन पर प्राधिकारी द्वारा संगत समझी गई प्राप्त टिप्पणियों का इस अधिसूचना में समाधान कर दिया गया है।

xix यह सिफारिश केन्द्रीय सरकार द्वारा बढ़ाई गई समय-सीमा के अंतर्गत, विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए की जा रही है।

xx. ***इस अधिसूचना में एक हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना का प्रतिनिधित्व है और इसलिए पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा उन पर विचार किया गया।

ख. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए विविध मुद्दे
अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण

7. हितबद्ध पक्षकारों किए गए प्रस्तुतिकरण संक्षेप में निम्नलिखित हैं—

मै. वेणुगोपाल स्लेट इण्डस्ट्रीज, मै. सेगामैट पैनल बोर्ड्स एस डीएन, बीएचडी और मैसर्स मेरबाक एम डीएफ लंका (प्राइवेट) लिमिटेड, श्रीलंका द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण

- आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन त्रुटिपूर्ण है, जांच शुरुआत को न्यायोचित ठहराने के लिए अपर्याप्त है और याचिकाकर्ता ने अत्यधिक गोपनीयता का आश्रय लिया है।
- आंकड़ों की गोपनीयता की जांच नहीं की जा सकती है क्योंकि असंशोधित आंकड़े प्रदान नहीं कराए गए हैं। एच डी एफ की एक प्रविष्टि को, जिसका उच्च कीमतों पर आयात किया गया था, शामिल नहीं किया गया है। तथापि, न्यूनतर कीमत की प्रविष्टि को शामिल कर लिया गया।
- याचिका का अगोपनीय पाठ अन्य पक्षकारों को अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने में सक्षम बनाने के लिए पूरी तरह से अपर्याप्त और अनुचित है।
- जांच शुरुआत अधिसूचना के अनुसार, जांच की अवधि अप्रैल, 2010 से जून, 2011 है परंतु घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान कराई गई आवेदन पत्र के अगोपनीय पाठ की प्रति में ऐसी प्रतीत होता है कि जांच की अवधि के रूप में अप्रैल, 2010 से मार्च, 2011 तक को लिया गया है।
- ग्रीन प्लाई इण्डस्ट्रीज लिमिटेड ने मौखिक सुनवाई में कोई मौखिक प्रस्तुतिकरण नहीं किया था। इसके बावजूद भी उन्होंने लिखित प्रस्तुतिकरण दर्ज किए। ग्रीन प्लाई द्वारा किए गए दावे, यदि वह अपनी सूचना तक पहुंच की माना ही करते हैं तो, अनुचित माने जाने चाहिए।

- यह प्रस्तुत किया गया कि घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के दौरान 2.5 मिमी और उससे कम मोटाई की सम्बद्ध वस्तु का निर्माण नहीं किया है और इसलिए उन्हें विचाराधीन उत्पाद की परिधि से अपवर्जित करने देना चाहिए।

मैसर्स मेग्ना-फोरमोस्ट एमडीएन एवं मै. मैसोइट कम्पोनेट्स, आयरलैण्ड की ओर से किया गया प्रस्तुतिकरण

- प्राधिकारी ने, इस तथ्य के बावजूद कि जांच शुरूआत करने को न्यायोचित ठहराने के लिए साक्ष्य पर्याप्त नहीं है, अनुच्छेद 5.3 का उल्लंघन करते हुए यह जांच प्रारंभ कर दी। प्राधिकारी ने स्वतः स्फूर्त अपने विवेक से आवेदक द्वारा फाइल की गई जांच अवधि तथा क्षति जांच अवधि में परिवर्तन कर दिया।
- प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा मूल रूप से प्रस्तावित जांच की अवधि अर्थात् अप्रैल, 2010 मार्च, 2011 (12 माह) में 3 माह तक का समय बढ़ा दिया। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने इस तथ्य के बावजूद कि कम से कम फरवरी, 2010 तक एम डी एफ मौजूद नहीं था फिर भी क्षति जांच अवधि 2007 और 2010 की अवधि के बीच निश्चित की। याचिका में किए गए उल्लेख के अनुसार आवेदक ने फरवरी, 2010 तक एम डी एफ का वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ नहीं किया था, जबकि उसके सहयोगी ने अपना उत्पादन काफी समय पश्चात् दिसम्बर, 2010 में शुरू किया था। प्राधिकारी ने उक्त अवधि में संशोधन करने का कोई औचित्य प्रदान नहीं कराया है। तथापि, अधिक महत्वपूर्ण यह है कि परिवर्तित अवधि भी आवेदक द्वारा प्रदान कराए गए साक्ष्य यह हांच शुरू करने को न्यायोचित ठहराने के लिए अपर्याप्त है।

एवरग्रीन फाइबर बोर्ड बेरहाद (ई एफ बी), मलेशिया; एवरग्रीन फाइबर बोर्ड (जे बी) एसडीएन, बी एच डी (ईजेबी) मलेशिया और एवरग्रीन फाइबर बोर्ड (निलाई) एसडीएन बीएचडी (ईएफएन) मलेशिया की ओर से किए गए प्रस्तुतिकरण

- याचिका का प्रदान कराया गया अगोपनीय पाठ त्रुटिपूर्ण है क्योंकि इसमें सम्पूर्ण जांच अवधि अर्थात् अप्रैल, 2010 से जून, 2011 (15 माह) की जानकारी नहीं दी गई है। इसमें जांच अवधि के केवल एक भाग अर्थात् अप्रैल, 2010 से मार्च, 2011 (12 माह) तक की ही जानकारी दी गई है। इसके अतिरिक्त, आवेदक ने उसे आई बी आई एस से प्राप्त अपरिष्कृत आयात आंकड़े याचिका के साथ उपलब्ध नहीं कराए हैं और न ही इसने इस तथ्य का संकेत दिया है कि वे आंकड़े प्राधिकारी को प्रदान करा दिए गए हैं।
- यह कि घरेलू उद्योग ने अधिक गोपनीयता का दावा किया है और आवेदक द्वारा गोपनीयता के लिए जा रहे दावे का विवरण याचिका के अगोपनीय पाठ के साथ संलग्न नहीं है।

मै. पी टी मसारी द्विसेपाकर फाइबर, इण्डोनेशिया और मै. पीटी सुमाटेरा प्राइमा फाइबर बोर्ड (एसपीएफ) इण्डोनेशिया की ओर से किए गए प्रस्तुतिकरण

- घरेलू उद्योग द्वारा दायर किए गए और उन्हें प्रदान किए गए आवेदन का अगोपनीय पाठ निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा सभी मौजूदा मामलों में अनुकरण किए जा रहे नए दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं है। आवेदन में ऐसी कोई अनुक्रमणिका नहीं है जिससे वे यह जान सकें कि गोपनीय पाठ में कौन से दस्तावेज फाइल किए गए हैं, इसके अलावा लगातार (क्रमबद्ध) पेजीकरण भी नहीं है, गोपनीयता के लिए कारणों का उल्लेख तालिका फार्म में किए जाने का भी कोई कारण प्रदान नहीं कराया गया है।
- आवेदक उद्योग ने वैध एवं पूर्ण प्रलेखित आवेदन पत्र सिद्ध होने के लिए यथा-अपेक्षित आवेदन प्रपत्र नहीं दिया है। अत्यधिक गोपनीयता के आवरण के अंतर्गत की गई अपेक्षा के अनुरूप प्रपत्र में यथानिर्धारित आवश्यक साक्ष्य भी प्रदान नहीं कराए गए हैं। फारमट आवेदनपत्र में प्रश्ना का बदल दिया गया है जिससे व उनकी अपक्षाओं के अनुरूप बन सकें। आपरेटर द्वारा अथवा समर्थक द्वारा स्वयं अपनी ओर से किए गए आयातों और संबंधों के बारे में दिया गया प्रमाणन जांच की अवधि के लिए नहीं है।
- गोपनीयता: घरेलू उद्योग द्वारा दायर किया गया और निर्यातकों को भेजा गया निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा सभी मौजूदा मामलों में अनुपालन किए जा रहे नए दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं है। निम्नलिखित जानकारी को बिना किसी संगत कारणों के गोपनीय रखा गया:

क. पूर्ण प्रकाश्यात्मक उत्पादन फ्लो-चार्ट आवेदक की वेबसाइट पर है। अंतः, इसकी गोपनीयता का दावा करने का कोई औचित्य ही नहीं है।
 ख. आयात आंकड़ों से अपवर्जित उत्पादों का परिकलन के लिए अपवर्जन करने हेतु कियापद्धति अपनाई गई क्योंकि चौड़ाई और मोटाई के आधार पर सम्बद्ध वस्तु के सभी गुणधर्म कवर नहीं होते हैं।
 ग. क्या बालाजी द्वारा किए गए आयातों को आयात आंकड़ों से अपवर्जित किया गया है अथवा नहीं और उनके द्वारा वास्तव में आयात की गई मात्रा क्या है।

घ. अगोपनीय सार तथा परियोजना रिपोर्ट की अनुकूर्माणकाबद्ध संख्यायें जिनपर आवेदक ने भरोसा किया है।

ड. सामान्य मूल्य के निर्माण का आधार। यह भी स्पष्ट नहीं है कि आवेदक ने विद्युत दरों तथा अन्य उसी सूचना का प्रयोग किया है जो सम्बद्ध देशों के सार्वजनिक क्षेत्रों में उपलब्ध है अथवा उन्होंने अपनी निजी दरों का प्रयोग किया है। इसके अतिरिक्त, अगोपनीय पाठ में संलग्न विद्युत संबंधी जानकारी किसी काम की नहीं है क्योंकि यह जांच की अवधि से संबंधित नहीं है और विभिन्न प्रयोगों के लिए विभिन्न दरें हैं।

च. आवेदक ने आवेदन में विनिर्मित सामान्य मूल्य के बारे में तथा निर्यात कीमतों का परिकलन करने के लिए प्रदान कराई गई सूचना के किसी स्रोत का उल्लेख प्रदान नहीं किया है। स्रोत के संबंध में कुछ स्थानों पर दी गई जानकारी पुरानी है तथा कार्यशील नहीं है। क्षति जांच अवधि के लिए लेखा परीक्षित तुलनपत्र प्रदान नहीं कराए गए हैं।

छ. आवेदक के निर्यात या आयात संबंधी गोपनीयता के विवरण से इसके संबंध का कोई उचित प्रमाणन नहीं दिया गया है।

- त्रुटिपूर्ण जांच अवधि एवं क्षति अवधि: प्राधिकारी द्वारा निर्धारित जांच अवधि तथा क्षति जांच अवधि त्रुटिपूर्ण एवं अनुचित है। वर्तमान मामले में जांच की अवधि अप्रैल, 2010—जून, 2011 तक अर्थात् 15 माह है। आवेदक ने बाजार में अभी हाल ही में अपने पैर जमाए हैं और उसने अप्रैल, 2010 में केवल 2 महीने ही पूरे किए थे। अतः, पाटन एवं क्षति का निर्धारण पक्षपात पूर्ण प्रतीत होता है क्योंकि आवेदक के लिए परिवर्ती लागत और निश्चित लागत बहुत अधिक उच्च होनी चाहिए और कोई भी उचित अथवा व्यापक विश्लेषण नहीं किया जा सकता है। प्राधिकारी ने वित्त वर्ष वर्ष 2010:11 पर विचार ही नहीं किया जो वह ही ऐसा एकमात्र पूर्ण वित्त वर्ष था जिसका विश्लेषण किया जा सकता था। यद्यपि अभी हाल ही में समाप्त हुए वित्त वर्ष को जांच की अवधि में जोड़ दिया गया है और इसलिए उसके आंकड़ों को भी विशेष रूप से एक क्षति अवधि के रूप में लिया जाना चाहिए था।

- पर्याप्तता एवं परिशुद्धता: यह जांच पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 जिसमें विशेष रूप से जांच शुरुआत का ही उल्लेख है, की अपेक्षाओं का पालन किए बिना प्रारंभ कर दी गई। वर्तमान जांच की शुरुआत करने के लिए दृढ़ निश्चय करने से पहले अधिदेशित प्राचलों की जांच नहीं की गई थी। निम्नलिखित के अभाव में यह कंपनी पर्याप्तता एवं परिशुद्धता के संबंध में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने में अक्षम है:

क. आवेदन की तारीख तथा जांच शुरुआत करने से पहले आवेदक के साथ किया गया पत्राचार।

ख. भारत में संबंधित मंत्रालय तथा अन्य उत्पादकों को भेजे गए पत्र।

ग. आवेदक और समर्थक उत्पादक की विगत तीन वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट।

घ. सामान्य मूल्य/निर्यात कीमत के लिए किए गए परिकलन तथा गई क्रियापद्धति का अगोपनीय पाठ से यह देखा जा सकता है कि आवेदनकर्ता उद्योग ने विनिर्मित सामान्य मूल्य तथा निर्यात कीमत का परिकलन करने संबंधी कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसे अतिरिक्त, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुरूप यह जानकारी विपक्षी हितबद्ध पक्षकार को उपलब्ध कराई जानी चाहिए जिससे वे अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने में सक्षम हो सकें।

ड. आवेदक उद्योग द्वारा यह दावा किया गया है कि सम्बद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा अपनाई गई विनिर्माण प्रक्रिया तथा आवेदक उद्योग द्वारा अपनाई गई विनिर्माण प्रक्रिया में कोई खास अंतर नहीं है। ऐसी स्थिति में आवेदक द्वारा विनिर्माण प्रक्रिया के लिए गोपनीयता का दावा नहीं किया जा सकता है।

- आवेदन पत्र, जो वर्तमान मामले में जांच शुरुआत करने के आधार बना है, उपलब्ध कराने में काफी विकल्ब हुआ है।
- अपरिपक्व आयात आंकड़े आईबीआई एस द्वारा प्रदान कराए गए आंकड़े होने चाहिए थे तथा इसके साथ में अपवर्जित प्रविष्टियों युक्त सूची का ऐसे अपवर्जन के लिए स्पष्टीकरण देते हुए, उल्लेख होना चाहिए था।
- प्राधिकारी को वर्तमान मामले में मोटे एम डी एफ मामले के अनुरूप ही केवल संदर्भ कीमत शुल्कों की ही सिफारिश करनी चाहिए थी। यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि पतले तथा मोटे दोनों तरह के एम डी एफ के लिए उत्पादन प्रक्रिया, कच्चा माल, विपणन सरणियां, वितरण नेटवर्क एक समान ही है। इन हालातों के अंतर्गत प्राधिकारी के लिए एक ही उत्पादन श्रृंखला के एक भाग के लिए संदर्भ कीमत आधारित शुल्क की सिफारिश करने तथा दूसरे के लिए निश्चित शुल्क की सिफारिश करने का कोई कारण नहीं है।
- अनंतिम शुल्क का अधिरोपण करने के लिए धारा 9ख तथा नियम 12 की आधार भूत जरूरतों का भी पालन नहीं किया गया है। इस आशय का कोई तर्क, विश्लेषण अथवा निर्धारण नहीं है कि जांच के दौरान अनंतिम शुल्क अधिरोपित करना अपेक्षित होगा।

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण

8. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण, संक्षेप में, निम्नलिखित हैं:

- जहां तक इस तर्क का संबंध है कि एनसीबी याचिका पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण तथा अन्य पक्षकारों द्वारा अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने में सक्षम बनाने के लिए अपर्याप्त है; संगत नियमों और विनियमों का उल्लेख करते हुए आवेदक ने अभिव्यक्त किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा दायर की गई याचिका में बहुत कुछ ऐसी बातों का उल्लेख किया गया है जिनका घरेलू उद्योग पर दायित्व है।
- इस तर्क के संबंध में कि जांच शुरुआत अधिसूचना के अनुसार जांच की अवधि अप्रैल, 2010 से जून, 2011 है जबकि एनसीबी के पास केवल मार्च, 2011 तक के आंकड़े हैं और इस कारण प्राधिकारी द्वारा जिस जानकारी पर भरोसा किया है वह अधूरी है, आवेदक ने उल्लेख किया है कि ऐसी कोई विधिक अपेक्षा नहीं है कि जांच की शुरुआत के समय घरेलू आवेदन के पास संपूर्ण जांच अवधि की जानकारी रिकार्ड में हो। “याचिका की अवधि” जिसके लिए याचिका दायर की गई है तथा विस्तृत जांच के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा चुनी गई “जांच की अवधि” दोनों ही अलग-अलग कारक हैं। याचिका में एक अवधि को अभिज्ञात किया जाना चाहिए और इसमें उक्त अवधि से संबंधित सभी संगत जानकारी होनी चाहिए। परंतु निर्दिष्ट प्राधिकारी को विस्तृत जांच के लिए आवेदक द्वारा सुझायी गई अवधि सहित किसी भी अन्य अवधि पर विचार करने की पूर्ण उन्मुक्तता हाती है।
- यह वास्तव में आश्चर्यजनक है कि एक हितबद्ध पक्षकार वर्तमान मामले में जांच की अवधि के रूप में वर्ष 2010-11 की जांच अवधि का आशय वर्तमान उद्देश्य के लिए एक निरर्थक अवधि होगी। द्वितीयतः, उस अवधि से लम्बी अवधि जिस पर विचार किया जा सकता है निश्चय तौर पर किसी भी हितबद्ध पक्षकार की पूर्वावधारण नहीं होनी चाहिए। यदि वर्तमान उद्देश्य के लिए वर्ष 2010:11 की अवधि उपयुक्त रहती तो उत्तरवर्ती तिमाही इसमें जोड़ना कोई कम अनुपयुक्त नहीं होता।
- जहां तक इस तर्क का संबंध है कि जांच की अवधि त्रुटिपूर्ण हैं तथा निर्धारित की गई क्षति अवधि भी त्रुटिपूर्ण एवं अनुचित है, यह उल्लेख किया जाता है कि पिछले पैराग्राफ में हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया था कि आवेदक एक मौजूदा कम्पनी है। इस पैराग्राफ में आवेदक ने कहा है कि आवेदक ने अभी बाजार में नया-नया ही प्रवेश किया है। यदि आवेदक नवागन्तुक है तो स्पष्ट रूप से यह मामला निश्चय ही किसी उद्योग की स्थापना के लिए भौतिक दुर्बलता के अंतर्गत आता, जब तक कि विरोधी पक्षकारों ने यह न स्पष्ट कर दिया होता कि देश में विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन तथा उसकी सदैव ही होती रही है। सड़ संबंध में यह उल्लेख करना संगत होगा कि माध्यम धनत्व वाले फाइबर बोर्डों के संबंध में दायर की गई पिछली अपील में सभी तरह की मोटाई वाले फाइबर बोर्डों को शामिल किया गया है। तथापि, हितबद्ध पक्षकार ने पतले बोर्डों का अपवर्जन इस आधार पर करने का तर्क दिया है कि भारत में पहले बोर्ड का उत्पादन करने वाली कोई कंपनी नहीं है। उपयुक्त विचार-विमर्श के बाद प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि 6 मिमी से कम की मोटाई वाले फाइबर बोर्ड का उत्पादन देश में नहीं किया जा रहा था और तदनुसार, विचाराधीन उत्पादन का दायरा 6 मिमी तथा उससे अधिक के फाइबर बोर्ड तक सीमित किया है।
- जहां तक इस तर्क का संबंध है कि वर्तमान जांच शुरुआत के लिए एक निश्चय पर पहुंचने से पहले अधिदेशित प्राचलकों की जांच नहीं की गई थी, उल्लेख किया जाता है कि ऐसी कोई अधिदेशित अपेक्षा नहीं है। इसके अतिरिक्त, चूंकि आवेदक ने अद्यतन याचिका दायर की है और चूंकि यह अद्यतनीकृत याचिका जांच शुरुआत का आधार बनी है, इसलिए इस जांच शुरुआत से पहले आवेदक के साथ किया गया पत्राचार निरर्थक सिद्ध हो जाता है। भारत में संबंधित मंत्रालय तथा अन्य उत्पादकों को भेजे गए पत्रों के संबंध में उल्लेख किया जाता है कि कानून के अंतर्गत ऐसी कोई अधिदेशित व्यवस्था नहीं है। जहां तक आवेदक और उसके समर्थनकर्ता उत्पादक की पिछले तीन वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट का संबंध है, यह उल्लेख किया जाता है कि समर्थनकर्ता उत्पादक के वार्षिक रिपोर्ट की को अधिदेशित आवश्यकता नहीं है। जहां तक आवेदनकर्ता की वार्षिक रिपोर्ट का संबंध है, यह उल्लेख किया जाता है कि समर्थनकर्ता उत्पादक के वार्षिक रिपोर्ट की को अधिदेशित आवश्यकता नहीं है। जहां तक आवेदनकर्ता की वार्षिक रिपोर्ट का संबंध है, यह मुद्दा पहले ही डीजीएडी द्वारा उठाया गया था और आवेदक ने इसका समाधान कर दिया था। आवेदक द्वारा लिखे गए पत्रों की प्रतियां इन प्रस्तुतिकरणों के साथ संलग्न हैं। जहां तक किए गए परिकलनों तथा निर्यात कीमत/सामान्य मूल्य के लिए अपनाई गई क्रियापद्धति के एन सी वी रूपान्तर का संबंध है, केवल उसी याचिका पर भरोसा किया जाता है जिसमें संगत जानकारी मौजूद हो।
- उत्पादन फ्लों चार्ट के संबंध में, आवेदक ने उत्पादन प्रक्रिया के संबंध में पर्याप्त जानकारी प्रदान की है। आवेदक द्वारा प्रदान कराई गई जानकारी प्रदान की है। आवेदक द्वारा प्रदान कराई गई जानकारी फ्लो चार्ट के संबंध में भी पर्याप्त जानकारी उपलब्ध कराती है। याचिका के साथ संलग्न किया गया फ्लों चार्ट आवेदक का वास्तविक उत्पादन फ्लो चार्ट है और इसलिए उसका प्रकटन नहीं किया गया है।

- जहां तक इस तर्क का संबंध है कि हितबद्ध पक्षकारों को जानकारी उपलब्ध कराने में पर्याप्त विलम्ब हुआ, यह उल्लेख किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकारों को पर्याप्त समय प्रदान किया गया। यह वह मामला नहीं है जहां हितबद्ध पक्षकारों को जांच शुरुआत किए जाने की तारीख से 40 दिनों का समय प्रदान किया गया हो। प्राधिकारी ने वास्तव में हितबद्ध पक्षकारों को 40 दिन का समय हितबद्ध पक्षकारों को भेजे गए/सम्प्रेषित पत्रों की तारीख से दिया है। अतः, विपक्षी पक्षकारों के हितों की किसी भी हाल में कोई क्षतिकारक पूर्वाग्रह नहीं था।

प्राधिकारी द्वारा जांच

9. इस तर्क के संबंध में कि प्रदान कराई गई याचिका के अगोपनीय पाठ त्रुटिपूर्ण है क्योंकि इसमें संपूर्णक्षति अवधि अर्थात् अप्रैल, 2010 से जून, 2011 (15 माह) की जानकारी नहीं दी गई है; प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि वर्तमान मामले में आवेदक से जांच की अवधि के संशोधित आंकड़ों/जानकारी विधिवत मांगी गई और उसे सार्वजनिक फाइल में रखा गया जो सभी हितबद्ध पक्षकारों के निरीक्षणार्थ उपलब्ध कराई गई थी। ऐसी कोई कानूनी बाधयता नहीं है कि विस्तृत जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा प्रस्तावित जांच की अवधि तथा जांच की वह अवधि जिसके लिए प्राधिकारी के समक्ष याचिका दायर की गई है, समान होनी चाहिए। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने भारी संख्या में मामलों में याचिका में प्रस्तावित जांच की अवधि से भिन्न जांच की अवधि पर विचार किया है।

10. प्राधिकारी ने गोपनीयता के संबंध में किए गए प्रस्तुतिकरणों पर विचार किया है और यह नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान कराई गई सूचना की गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई। प्राधिकारी ने संतुष्ट होने पर यथावश्यक गोपनीयता के दावे को स्वीकार कर लिया है तथा ऐसी जानकारी को गोपनीय के रूप में माना गया है तथा उसका अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकटन नहीं किया गया। जहां तक संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को निदेश दिया गया कि वे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई जानकारी का पर्याप्त अगोपनीय पाठ भी प्रदान करें। जहां किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच की अवधि के दौरान अन्यथा जरूरी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई अथवा जांच में पर्याप्त रूप से अवरोध उत्पन्न किया वहां प्राधिकारी ने इन जांच परिणामों को "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर दर्ज किया है।

11. जहां तक जांच की अवधि की उपयुक्तता के संबंध में दिए गए तर्क का संबंध है, यह उल्लेख किया जाता है कि उसका चयन वर्तमान मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए किया गया और विषय से संबंधित अद्यतन आंकड़ों को कवर करने के लिए उसका चयन उपयुक्त ढंग से किया गया। इसके अतिरिक्त, यह कहना सही नहीं है कि यद्यपि जांच अधिसूचना के अनुसार जांच की अवधि अप्रैल, 2010 से जून, 2011 है परंतु एन सी बी में केवल मार्च, 2011 तक के आंकड़े ही हैं क्योंकि जांच की अवधि से संबंधित जानकारी घरेलू उद्योग से विधिवत प्राप्त कर ली गई थी और उसे पाटनरोधी नियमावली के अनुरूप सार्वजनिक फाइल में उपलब्ध करा दिया गया था। इसके अतिरिक्त, यह उल्लेख किया जाता है कि वर्तमान मामले में पाटनरोधी जांच प्रारंभ करने को न्यायोचित ठहराते हुए आवेदन में पर्याप्त साक्ष्य मौजूद थे। प्राधिकारी पुनः नोट करते हैं कि अधिदेशित पैरामीटरों की विधिवत जांच की गयी और वर्तमान मामले में जांच शुरुआत को न्यायोचित ठहराने के लिए रिकार्ड में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध कराया गया।

12. जहां तक हितबद्ध पक्षकारों को जानकारी उपलब्ध कराने में किए गए विलम्ब के संबंध में दिए गए तर्क का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों को वास्तव में लाभ पहुंचाया गया क्योंकि हितबद्ध पक्षकारों को पत्र प्रेषित किए जाने की तारीख से सभी ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को विधिवत 40 दिनों का समय प्रदान किया गया था। अतः, उनके हितों को स्पष्टतः को विपर्यय प्रभाव से प्रभावित नहीं किया गया।

13. शुल्क के स्वरूप के संबंध में किए गए प्रस्तुतिकरण के बारे में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि शुल्क की प्रमात्रा और उसका स्वरूप, अन्य बातों के साथ-साथ, पाटन के विस्तार जो मामले के तथ्यों द्वारा स्थापित होता है, पर निर्भर होती है। नियमों में प्राधिकारी को पाटन मार्जिन के बराबर अथवा उससे कम पाटनरोधी शुल्क की राशि की सिफारिश करने का अधिकार प्रदान किया गया है जो अधिरोपित किए जाने पर घरेलू उद्योग की क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त हो। इसके अतिरिक्त, वर्तमान मामले में, प्राधिकारी ने एन सभी संगत कारकों की जांच कर ली है जिनका जांच के विषय से संबंध है और वर्तमान जांच के तथ्यपरक सांचे पर विचार करते हुए प्राधिकारी ने शुल्क के स्वरूप का निर्धारण मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए किया है।

14. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि अनंतिम शुल्क का अधिरोपण करने के लिए आधारभूत जरूरतों का अनुपालन नहीं किया गया है, प्राधिकारी ने, पाटनरोधी नियमावली के नियम 12 के अंतर्गत यथा अधिदेशित तथा प्रारंभिक जांच का आयोजन करने के पश्चात् निर्यात कीमत, सामान्य मूल्य, और पाटन मार्जिन तथा घरेलू उद्योग को क्षति के संबंध में प्रारंभिक निष्कर्ष रिकार्ड किए और इस प्रकार, पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश करने के लिए सभी जरूरी अपेक्षाओं को पूरा किया है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने प्रारंभिक निष्कर्षों में यह उल्लेख किया कि आगे की जांच लम्बित रहने तक अंतरिम शुल्क का अधिरोपण करने की सिफारिश करना जरूरी एवं उपयुक्त समझा गया। तब से, प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरणों की पुनः जांच की और विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी का स्थल पर जाकर सत्यापन किया गया। वर्तमान प्रकटन विवरण जारी किया जा रहा है जिसमें प्रारंभिक जांच परिणाम के पश्चात् हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों को ध्यान में रखा गया है।

ग. **विचाराधीन उत्पाद तथा घरेलू समान वस्तु**

अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण

15. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण संक्षेप में निम्नलिखित हैं:

इंडियन मोल्डेड पैनेल शटर्स मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण

16. इंडियन मोल्डेड पैनेल शटर्स मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण, संक्षेप में, निम्नलिखित हैं:

- यह स्पष्ट नहीं है कि डोरस्किन्स विचाराधीन उत्पाद के अंतर्गत आते हैं या नहीं क्योंकि जांच शुरूआत अधिसूचना में यथापरिभाषित विचाराधीन उत्पाद बहुत व्यापक एवं अस्पष्ट है। घरेलू उद्योग ने मात्रा और कीमत के प्रयोजन के लिए अपनी याचिका से संबंध देशों से एच डी एफ तथा डोर स्किन्स के आयातों का अपवर्जन कर दिया परंतु वाद में किए गए कुछ प्रस्तुतिकरण दर्शाते हैं कि यह मुद्दा प्राधिकारी द्वारा निर्णय किए जाने के लिए खुला रखा गया। डोर स्किन्स और विचाराधीन उत्पाद की आयात कीमत में भारी विभिन्नता स्वयं यह दर्शाती है कि डोर स्किन्स विचाराधीन उत्पाद से अलग होने चाहिए। एम डी एफ या एच डी एफ की तुलना में डोर स्किन की कीमते काफी अधिक हैं और डोर स्किन्स अलग-अलग उत्पाद हैं। एच डी एफ डोर स्किन्स के लिए कच्चा माल एम डी एफ और एच डी एफ डोर स्किन्स के लिए कच्चा माल एमडीएफ और एचडीएफ बोर्ड होता है जबकि एमडीएफ एवं एच डी एफ के लिए कच्चा माल लकड़ी, रेजिन तथा कुछ अन्य सामग्री होती है जो यह दर्शाती है कि डोर स्किन्स मूल्यवर्धित तथा पृथक उत्पाद होते हैं। डोर स्किन्स का दरवाजों के अलावा अन्य अनुप्रयोगों के लिए वाणिज्यिक रूप से अंतर्निमेय नहीं किए जा सकते हैं। अतः, एचडीएफ और एमडीएफ वाणिज्यिक रूप से अंतर्निमेय नहीं होते हैं क्योंकि एमडीएफ की तुलना में डोर स्किन की कीमत 200 प्रतिशत अधिक होती है। फाइबर बोर्ड मोल्डेड डोर स्किन्स का उत्पादन 800 किग्रा/एम³ से अधिक के घनत्व युक्त 3 मिमी की मोटाई के फाइबर बोर्ड से ही किया जा सकता है। आवेदक उद्योग हो सकता है कि मोल्डेड डोर स्किन का उत्पादन केवल एमडीएफ बोर्ड से ही करता हो। अतः मोल्डेड डोर स्किन आवेदक के लिए साधारण फाइबर बोर्ड एम डीएफ/एचडीएफ की तुलना में एक मूल्यवर्धित उत्पाद हो सकता है। दूसरे शब्दों में संबंधित घरेलू उद्योग के लिए डोरस्किन बनाने की प्रक्रिया में एमडीएफ/एचडीएफ एक इनपुट सामग्री हो सकती है। मोल्डेड डोर स्किन की औसत कीमत पतले एमडीएफ की तुलना में (औसतन 150–200 प्रतिशत) अधिक है। इसके अतिरिक्त, पतले एचडीएफ की कीमतें भी पतले एमडीएफ की तुलना में काफी अधिक हैं। इस प्रकार, एमडीएफ, एचडीएफ और मोल्डेड डोर स्किन की कीमतों के बीच एक दूसरे से तुलना नहीं की जा सकती है।
- आवेदक ने विचाराधीन उत्पाद के दायरे को परिभाषित करने के लिए घनत्व एवं मोटाई के पैरामीटर को जानबूझकर अपवंचन किया है। इसके परिणाम होते हैं क्योंकि प्रति सी बी एम कच्चे माल की खपत बोर्ड के घनत्व को शासित करती है। एचडीएफ कच्चे माल की तुलना में इसका घनत्व ज्यादा होता है। यहां तक कि घरेलू उद्योग का सूचीपत्र स्वयं भी यह दर्शाता है कि डोर स्किन एमडीएफ या एचडीएफ से पृथक है। यह दावा कि उच्च घनत्व वाले बोर्ड की आयात कीमत औसत आयात कीमत से भी कम है निराधार है। एचडीएफ का सही-सही मूल्यांकन विचाराधीन उत्पाद के दायरे के बाहर ही किया जा सकता है।

मैसर्स वेणुगोपाल स्लेट उद्योग द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण

17. मैसर्स वेणुगोपाल स्लेट इंडस्ट्रीज द्वारा किया गया प्रस्तुतिकरण संक्षेप में निम्नलिखित हैं:

- आवेदक द्वारा भरोसा किये गये संपूर्ण अपरिष्कृत आयात आंकड़ों को यह आकलन करने के लिए प्रदान कराने की जरूरत है कि क्या आवेदक द्वारा विचाराधीन उत्पाद के आयात आंकड़ों का संग्रह करने के लिए अपनाई गई क्रियापद्धति सही है या नहीं क्योंकि प्रदान कराये गये परिवर्तित आंकड़े ऐसा करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।
- 2.5 मिमी और उससे कम के उत्पाद का उत्पादन नहीं हुआ जिसका जांच अवधि के दौरान स्लेट उद्योग द्वारा प्रमुख रूप से प्रयोग किया गया चूंकि 2.5 मिमी तथा उससे कम पतले फाइबर बोर्डों का वाणिज्यिक उत्पादन नहीं हुआ इसलिए, घरेलू उद्योग द्वारा किये गये किसी ऐसे उत्पाद के उत्पादन की गुणवत्ता की संपुष्टि को छोड़कर, स्लेट उद्योग के पास सम्बद्ध देशों से उत्पाद का आयात करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं रह गया।

इंडोनेशिया गणराज्य के व्यापार निदेश द्वारा किया गया प्रस्तुतिकरण

18. एचएस कोड 4411 के अंतर्गत आने वाले उत्पादों की व्यापक श्रृंखला पर पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण किया गया। 2.1 मिमी की मोटाई वाले फाइबर बोर्डों का अपवर्जन कर दिया जाना चाहिए। यह जांच की जानी चाहिए कि क्या घरेलू उद्योग के पास वाणिज्यिक रूप से विनिर्माण करने और 2.1 मिमी से कम के विचाराधीन उत्पाद के लिए बाजार मांग को पूरा करने के लिए संस्थापित मशीनें हैं।

मैसर्स मैगना-फोरमोस्ट एसडीएन और मैसर्स मैसोनाइट कम्पोनेंट्स, आयरलैंड की ओर से किया गया प्रस्तुतिकरण

19. जांच शुरूआत अधिसूचना में प्रदान कराई गई परिभाषा से यह स्पष्ट है कि मोल्डेड डोर फेसिंग्स जिन्हें डोर स्किन के रूप में भी जाना जाता है, को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से अलग कर दिया गया और इसकी संपुष्टि अपने उत्पाद शीर्षकों और आयात आंकड़ों से डोर स्किन के संबंध में आंकड़ों का अपवर्जन कर देने की आवेदक की अभिव्यक्ति से होती है। उत्पादन प्रक्रिया में अंतर है और इसके अनुप्रयोगों में अंतर है। डोर स्किन का प्रयोग अनन्य रूप से डोर स्किन के रूप में— अर्थात् दरवाजे बनाने के लिए दरवाजों के बाहरी पैनेल के रूप में प्रयोग किया

जाता है। अपने रसायनिक गुण धर्मों और सतही कन्दुरों के कारण उन्हें फाइबर बोर्ड के अन्य उत्पादों में नया रूप अथवा नया आकार नहीं दिया जा सकता है और इस कारण वे आवेदक के एमडीएफ उत्पादों के प्रतिस्थानी या प्रतिस्पर्धी नहीं बन सकते हैं।

मै. सेगामैट पैनल बोर्ड्स एसडीएन.बीएचडी एवं मैक्र मेरबाक एमडीएफ लंका (प्राइवेट) लिमिटेड, श्रीलंका की ओर से की गई प्रस्तुति

20. मै. सेगामैट पैनल बोर्ड्स एसडीएन.बीएचडी एवं मैक्र मेरबाक एमडीएफ लंका (प्राइवेट) लिमिटेड, श्रीलंका की ओर से की गई प्रस्तुति संक्षेप में निम्नलिखित है:-

- यह कि घरेलू उद्योग ने उल्लेख किया कि इसने आई बी आई एस द्वारा प्रदान कराए गए संव्यवहार-वार आयात आंकड़े अपनाए हैं क्योंकि विचाराधीन उत्पाद का समर्पित सीमा शुल्क कोड नहीं है। इस तरह के आई बीआई एस द्वारा प्रदान कराए गए अपरिष्कृत आयात आंकड़े जो अध्याय उप-शीर्षक संख्या 4411 के अंतर्गत आते हैं में आयातों का विवरण विभिन्न वर्णनों एवं यूनिटों में होना चाहिए। तथापि, घरेलू उद्योग ने अपने आवेदन में केवल सम्बद्ध उत्पाद के आयात आंकड़ों को संग्रहित करने के लिए कियापद्धति युक्त केवल परिवर्तित आयात आंकड़े ही प्रदान कराए हैं। अतः, हम यह समझ नहीं पा रहे हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा सम्बद्ध वस्तु के लिए संग्रहित आयात आंकड़े सही हैं या नहीं क्योंकि आवेदन पत्र में संपूर्ण अपरिष्कृत आयात आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए गए हैं।

एवरग्रीन फाइबर बोर्ड बेरहाद (ई एफ बी), मलेशिया; एवरग्रीन फाइबर बोर्ड (जेबी) एसडीएन, बीएचडी (ईजेबी) मलेशिया और एवरग्रीन फाइबर बोर्ड (निलाई) एसडीएन.बीएचडी की ओर से किए गए प्रस्तुतिकरण

21. एवरग्रीन फाइबर बोर्ड बेरहाद (ई एफ बी), मलेशिया; एवरग्रीन फाइबर बोर्ड (जेबी) एसडीएन, बीएचडी (ईजेबी) मलेशिया और एवरग्रीन फाइबर बोर्ड (निलाई) एसडीएन.बीएचडी (ईएफएन) मलेशिया की ओर से किए गए प्रस्तुतिकरण संक्षेप में निम्नलिखित हैं:

- वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद बहुत व्यापक है। घरेलू उद्योग ने उत्पादों के ऐसे प्रकारों को शामिल कर लिया है जिनका विनिर्माण भी आवेदक द्वारा नहीं किया जाता है। वे आयातित उत्पादों द्वारा तकनीकी रूप से एवं वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय नहीं हैं। घरेलू उद्योग ने 6 मिमी से कम के सभी तरह के बोर्डों को शामिल कर लिया है फिर चाहे वह मध्यम घनत्व वाले बोर्ड हो अथवा उच्च घनत्व वाले बोर्ड हो। घरेलू उद्योग 2.5 मिमी से कम चौड़ाई के बोर्ड को उत्पादित करने में सक्षम नहीं है और उन्हें इस जांच के दायरे से अपवर्जित कर दिया जाना अपेक्षित है।

मै.पी टी मसारी द्विसेपाकर फाइबर, इंडोनेशिया और मै. पी टी समुमाटेरा प्राइमा फाइबर बोर्ड (एसपीएफ) इंडोनेशिया की ओर से किया गया प्रस्तुतिकरण

22. मै.पी टी मसारी द्विसेपाकर फाइबर, इंडोनेशिया और मै. पी टी समुमाटेरा प्राइमा फाइबर बोर्ड (एसपीएफ) इंडोनेशिया की ओर से किया गया प्रस्तुतिकरण संक्षेप में निम्नलिखित है:

- आयात आंकड़ों में गैर-विचाराधीन उत्पाद को गलती से शामिल करना: संव्यवहार-वार जांच यह व्यक्त करती है कि उच्च घनत्व वाले बोर्डों से संबंधित संव्यवहार के आंकड़ों को शामिल किया गया है। संव्यवहार वार विवरण से यह स्पष्ट नहीं है कि किस तरह इन्सुलेशन बोर्डों तथा गैर-विचाराधीन उत्पादों का अपवर्जन किया गया। वे यह समझने की स्थिति में नहीं हैं कि क्या अपरिष्कृत आंकड़ों का फिल्टरेशन अपवर्जित श्रेणियों के लिए खासकर जब प्रत्येक संव्यवहार का अभिकथन विशेष तत्वों, जैसे लैमिनेटिड फाइबर बोर्ड का कोई विवरण प्रदान नहीं करता है। हर हाल में, प्रशुल्क शीर्ष 4411 में न केवल उन बोर्डों को शामिल किया जाता है जो रेजिन अथवा सिकी अन्य जैव पदार्थ द्वारा आबद्ध हैं। प्राधिकारी आयात आंकड़ों की भी समीक्षा कर सकते हैं और उन प्रविष्टियों का अपवर्जन कर सकते हैं जो विचाराधीन उत्पाद के अंतर्गत नहीं आते हैं। यह कार्य करते वक्त आवेदकों को बुलाकर उनके द्वारा अपनाई गई कियापद्धति का प्रकटन किया जा सकता है जब उन्हें अपने अपरिष्कृत आंकड़ों तथा ऐसे सभी अपवर्जनों से उत्पाद का अपवर्जन कर दिया हो।
- विचाराधीन उत्पाद का दायरा: वर्तमान जांच को 3 मिमी. से कम की मोटाई के पतले फाइबर बोर्ड विचाराधीन उत्पाद के कार्यक्षेत्र से अलग कर देना चाहिए क्योंकि उनका घरेलू उद्योग द्वारा न तो उत्पादन किया जाता है और न ही उनकी बिक्री की जाती है। किसी बोर्ड की मोटाई एक किसी खास अनुप्रयोग के लिए एक महत्वपूर्ण पैरामीटर होता है और विभिन्न मोटाई के बोर्डों को तकनीकी रूप से और वाणिज्यिक रूप से एक दूसरे से प्रतिस्थानीय नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी डिजाइन में 3 मिमी मोटे बोर्ड का उपयोग करने की जरूरत है तो किसी भी प्रयोक्ता के लिए तकनीकी रूप से यह संभव नहीं होगा कि वह उसके स्थान पर किसी अन्य मोटाई के बोर्ड का उपयोग कर ले। पतले फाइबर बोर्ड का अंतिम उपयोग मोटे साइज के प्रयोग की तुलना में पूर्णता भिन्न है। आवेदक द्वारा चयन किया गया उत्पाद दायरा अस्पष्ट है और उसको उपयुक्त रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। इस विवरण में एक महत्वपूर्ण तथा अर्थात घनत्व का विवरण नहीं किया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि विचाराधीन उत्पाद को घनत्व के जरिए परिभाषित न करने के लिए अपनाया गा अभिगम इसे कार्यनीतिक रूप से ऐसे उत्पाद घनत्व दायरे के अंतर्गत शामिल करना है जिसका आवेदक द्वारा उत्पादन नहीं किया जा रहा है। उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद की ग्राही खपत के संबंध में सूचना को अपने पास रोके रखा।
- आवेदक मुख्यतः उच्च कीमत वाले सम्बद्ध वस्तु के व्यवसाय में है जिसके लिए कच्चे माल के रूप में सादा फाइबर बोर्ड की जरूरत होती है। उपर्युक्त के मद्देनजर प्राधिकारी को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से निम्नलिखित को अलग कर देना चाहिए:

- 2.5 प्रतिशत 3 मिमी की मोटाई से कम की मोटाई वाले फाइबर बोर्ड इस बात पर निर्भर करते हुए कि घरेलू उद्योग द्वारा जांच के दौरान क्या उत्पादित किया गया है और वास्तव में किसी आपूर्ति की जा रही है।
- ई2, ई3 उत्सर्जन मानक और कोई अन्य मानदंड जो ई1 उत्सर्जन मानदंड के समकक्ष हो के सभी माध्यम घनत्व वाले बोर्ड
- अग्नि अवरोधक पार्टिकल बोर्ड
- काष्ठपरत युक्त एमडीएफ एवं पार्टिकल बोर्ड
- उपर्युक्त प्रस्तुतिकरणों के मद्देनजर प्राधिकारी आयात आंकड़ों की समीक्षा भी कर सकते हैं और उन सभी प्रविष्टियों का अपवर्जन कर सकते हैं जो विचाराधीन उत्पाद में शामिल नहीं हैं। यह कार्य करते समय आवेदक को इस तथ्य का प्रकटन करने के लिए बुलाया जा सकता है कि अपरिष्कृत आंकड़ों से उत्पाद का अपवर्जन करते समय और इन सब अपवर्जनों का सूचीकरण करते समय उसने कौन सी क्रियापद्धति अपनाई है। हम इस समय यह समझने की स्थिति में नहीं हैं कि अपवर्जित श्रेणियों के लिए अपरिष्कृत आंकड़ों का फिल्टरेशन किया गया खासकर तब, जब प्रत्येक संव्यवहार के विवरण में लैमिनेटेड फाइबर बोर्ड आदि जैसे विशेष तत्वों का वर्णन नहीं दिया गया। हर हाल में, प्रशुल्क शीर्षक 4411 में न केवल उन बोर्डों को शामिल किया गया है जो रेजिन या किसी अन्य जैव पदार्थ द्वारा जुड़े हैं बल्कि यह अपने दायरे के अंतर्गत उन बोर्डों को भी शामिल करता है जो रेजिन अथवा किसी अन्य जैव पदार्थ द्वारा जुड़े हुए नहीं होते हैं।
- प्रतिस्थापनीयता के बारे में असत्य घोषणा: आवेदन ने अपने आवेदनपत्र में उल्लेख किया है कि सम्बद्ध वस्तुओं का कोई तकनीकी एवं वाणिज्यिक रूप से अर्थक्षम ज्ञात स्थानापन्न नहीं है। इस संदर्भ में, निर्यातकों ने गंभीर आपत्तियां उठाई हैं कि इसके बाजार में कई अर्थक्षम स्थानापन्न उपलब्ध हैं। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक ने स्वयं अपनी वेबसाइट पर सम्बद्ध वस्तु तथा उसके सीनापन्नों के बीच अंतर का उल्लेख किया है। अतः आवेदक द्वारा किया गया प्रस्तुतिकरण गलत है और उसे नकार दिए जाने की जरूरत है।

मै. बालाजी इम्पेक्स मै. कोटेश्वरी स्लेट वर्क्स एवं मैसर्स विश्वमित्र स्लेट वर्क्स की ओर से किया गया प्रस्तुतिकरण

23. मै. बालाजी इम्पेक्स मै. कोटेश्वरी स्लेट वर्क्स एवं मैसर्स विश्वमित्र स्लेट वर्क्स की ओर से किया गया प्रस्तुतिकरण संक्षेप में निम्नलिखित है

- घरेलू उद्योग लिखने वाली स्लेट के उत्पादन के लिए अपेक्षित समान मोटाई के बोर्ड की तुलना में घरेलू उद्योग विभिन्न मोटाई वाली सम्बद्ध वस्तु का उत्पादन करता है। आवेदक उत्पाद की गुणवत्ता घटिया होती है और इसका घनत्व कम होता है तथा वे 2.5 मिमी से 6.0 मिमी की मोटाई का ही उत्पादन करते हैं।
- 2.5 मिमी से कम और 2.5 मिमी से 4.00 मिमी तक की राइटिंग स्लेट इण्डस्ट्री के लिए प्रयुक्त सम्बद्ध वस्तु से शुल्क अवमुक्त कर दिया जाना चाहिए।

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण

24. घरेलू उद्योग की ओर से संक्षेप में निम्नलिखित प्रस्तुतिकरण किए गए:

- जहां तक इस तक का सम्बंध है कि परिभाषित विचाराधीन उत्पाद अस्पष्ट है और उसे सही ढंग से परिभाषित नहीं किया गया है, और यह कि उसके विवरण में घनत्व का उल्लेख नहीं है, जो एक महत्वपूर्ण कारक है, यह उल्लेख किया जाता है कि विवरण में किसी तरह की संदिग्धता अथवा अस्पष्टता नहीं है। इस आरोप का आधार ही समझ में नहीं आता है क्योंकि हितबद्ध पक्षकार ने यह प्रदर्शित नहीं किया कि किस तरह घनत्व एक प्राचल के रूप में उसकी कीमत/प्रभाव को शासित करता है। आवेदक ने आयात प्रविष्टियों की समीक्षा की और पाया कि घनत्व और कीमत के संबंध में कोई एक रूप प्रणाली नहीं है। न्यून घनत्व वाले उत्पाद की कीमत कभी-कभार उच्च घनत्व वाले उत्पाद की तुलना में अधिक होती है और कभी यह कम होती है। जब तक किसी पैरामीटर के आधार पर उत्पाद कीमत निर्धारण की एक समान प्रणाली नहीं हो तब तक यह निष्कर्ष निकाल ला जाना चाहिए कि इस पैरामीटर का अनुपालन संबंधित पक्षकारों द्वारा नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, हितबद्ध पक्षकारों ने इस संबंध में कोई एकरूप प्रणाली का प्रदर्शन नहीं किया है।
- जहां तक इस तर्क का संबंध है कि आवेदक केवल 2.5 से 5 मिमी तक की मोटाई का ही उत्पादन करता है, यह उल्लेख किया जाता है कि मौजूदा आवेदन घरेलू उद्योग की सामग्री दुर्बलता को स्थापित करने के संबंध में है। अतः, इस मामले में क्षति अवधि के दौरान उत्पादन न करने का तथ्य असंगत हो जाता है। घरेलू उद्योग अभी भी पूरी तरह से स्थापित नहीं है। यह स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग इस उत्पाद के सभी विवरणों का उत्पादन एवं बिक्री नहीं करता है। यह नोट किया जा सकता है कि घरेलू उद्योग 2.1 मिमी के फाइबर बोर्ड का उत्पादन करता है और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित 2.1 मिमी के फाइबर बोर्ड की प्रयोगशाला परीक्षण रिपोर्टों को अलग से दार किया गया है। आवेदक ने ई1 मानक के पार्टिकल बोर्ड का उत्पादन किया है। यदि आवेदक ई1 मानक के पार्टिकल बोर्ड का उत्पादन का निश्चित रूप से उत्पादन कर सकता है। यह याचिका ऐसे पाटन के संबंध में है जो घरेलू उद्योग की स्थापना की सामग्री दुर्बलता स्थापित करता है। जहां तक अग्नि

अवरोधक पार्टिकल बोर्डों का संबंध है, इस दावे के उत्पाद की केवल कुछ चुनिंदा श्रेणियों का ही उत्पादन किया है और यह याचिका घरेलू उद्योग की अवस्थापना में सामग्री दुर्बलता से संबंधित है। आवेदक स्पष्टतः उत्पादन की सभी श्रेणियों एवं प्रकारों की आपूर्ति नहीं कर सकता है। जैसे ही उसके उत्पादन का वाणिज्यीकरण होता है, आवेदक उन सभी उत्पादों का प्रस्ताव करेगा जिनकी बाजार में जरूरत है। तथापि, आवेदक द्वारा उत्पादित सर्वाधिक लोकप्रिय उत्पाद प्रकार की बिक्री उसके उत्पादन की सीमा तक नहीं की जा सकी और आवेदक को अवनवी मालसूची का भंडार करने को मजबूर होना पड़ा। इसके अतिरिक्त, आवेदक को उत्पाद के पाटन मद्देनजर अत्यधिक कम कीमतों पर अपने उत्पादित माल की बिक्री करनी पड़ी।

- जहां तक इस तथ्य का संबंध है कि प्रशुल्क शीर्षक 4411 में न केवल उन बोर्डों को शामिल किया गया है जो रेजिन द्वारा जुड़े होते हैं बल्कि इसमें वे बोर्ड भी शामिल हैं जो रेजिन द्वारा जुड़े नहीं होते हैं; आवेदक इसके प्रति जागरूक है और बोर्डों के संबंध में उसके आवेदन में ना केवल ऐसे बोर्डों को शामिल किया गया है जो रेजिन द्वारा जुड़े होते हैं बल्कि इसमें उन बोर्डों को भी शामिल किया गया है जो रेजिन द्वारा जुड़े नहीं होते हैं। यह तथ्य कि बोर्ड किसी अन्य जैव पदार्थ द्वारा भी जुड़े हो सकते हैं, उनसे कोई भिन्न स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। आवेदक यह प्रस्तुत करता है कि वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद “रेजिन या किसी अन्य जैव पदार्थ द्वारा जुड़ी हुई 6मिमी से कम की मोटाई वाले लकड़ी अथवा लकड़ी जैसे फाइबर बोर्ड हैं” जिन्हें याचिका में एतदृष्ट्यात् ‘फाइबर बोर्ड’ कहा गया है। फाइबर बोर्ड एक कस्टम लकड़ी अथवा काफ्ट लकड़ी युक्त इंजीनियर्ड उत्पाद होता है और इसका उत्पादन ताप दावित रेजिन से जुड़े कास्ट फाइबर से किया जाता है। फाइबर बोर्डों को इसके उपरान्त भी यांत्रिक रूप से प्रशंसकृत किया जा सकता है जैसे लैमिनेटेड, सरफेस कोटेड, कार्बड, मोल्टेड, आदि। वर्तमान याचिका में विचाराधीन उत्पाद के दायरे में सीमा शुल्क शीर्षक 4411 के अंतर्गत वर्गीकरण योग्य सभी उत्पाद शामिल हैं परंतु इसमें (क) 6 मिमी अथवा उससे अधिक की मोटाई वाले फाइबर बोर्ड, (ख) इन्सुलेशन बोर्ड (ग) लेमिनेटेड फाइबर बोर्ड और (घ) वे बोर्ड शामिल नहीं हैं जो रेजिन अथवा किसी अन्य जैविक पदार्थ द्वारा जुड़े नहीं होते इसके अतिरिक्त, विनिर्माता सी ए आर बी (केलीफोर्निया एयर रिसोर्स बोर्ड) जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा निर्धारित दिशा निदेशों के अनुरूप उत्सर्जन मानकों के आधार पर उत्पाद का वर्गीकरण भी कर सकते हैं। उत्सर्जन मानक उपयुक्त रेजिन का प्रयोग करके प्राप्त किये जा सकते हैं। संबद्ध देशों में फाइबर बोर्डों के सभी उत्पादक और भारतीय उत्पादक विभिन्न उत्सर्जन मानकों युक्त विचाराधीन उत्पाद का उत्पाद एवं उसकी आपूर्ति करने की स्थिति में हैं। ई-1 फाइबर बोर्डों को बनाने के लिए संपूर्ण विश्व में प्रयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकी यह है कि ई-2 के गोंद में कुछ संयोजों को जोड़ा जाता है और फार्मेलडी हाइड उत्सर्जन को कम कर दिया जाता है आवेदक ने ई-1 मानक के बोर्डों का उत्पादन किया है।
- दोनों घरेलू उत्पादक अर्थात् बालाजी एक्शन ग्रीन प्लाई जांच की अवधि के दौरान स्थापित होने की प्रक्रिया में थे इसलिए आपूर्ति ना की गई वस्तुओं का विचाराधीन उत्पाद के दायरे से अपवर्जन करने का प्रश्न ही नहीं उठाता है।
- घरेलू उद्योग स्लेट विनिर्माताओं को विचाराधीन उत्पाद की आपूर्ति करता है स्लेट विनिर्माताओं से उनके अधिप्रापण और संतोष की संपुष्टि करने वाले पत्र प्रस्तुत किये गये हैं।
- घरेलू उद्योग द्वारा 2.3 मिमी और 2.0 मिमी के बोर्ड का उत्पादन की प्रयोग शाला परीक्षण रिपोर्ट की गई तथा उसे प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जो यह दर्शाता है कि उद्योग 2.5 मि.मी से कम की चौड़ाई वाली सम्बद्ध वस्तु का उत्पादन करने में सक्षम।
- जहां तक घनत्व एवं मोटाई का सम्बन्ध है घनत्व एवं मोटाई दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। सामान्यतः पहले एमडीएफ का घनत्व 750 से 850 किग्रा/सीबीएम होता है। बीआईएस मानदंड 10प्रतिशत घनत्व अंतर की अनुमति प्रदान करता है। वास्तव में, यदि कोई विनिर्माता घनत्व को बढ़ा देता है तो कच्चे माल उर्जा की अधिक खपत के कारण कच्चे माल की लागत बढ़ जाएगी क्योंकि जैसे ही उत्पादकता कम होगी क्योंकि घनत्व जितना अधिक होगा क्योरिंग टाइम भी उतना ही अधिक होगा। यह भी देखा जा सकता है मोटाई कम होने से उत्पादन में गिरावट आ जाती है। तथापि, यह देखा जाता है कि घनत्व विभिन्न मोटाइयों का अधिच्छादन करता है परंतु विभिन्नता महत्वपूर्ण नहीं है। अतः, उत्पाद कीमतों पर घनत्व एवं मोटाई का कोई प्रभाव नहीं होता है। इससे पहले कि प्राधिकारी कीमत तुलना के लिए किसी प्राचल पर विचार करता है, हितबद्ध पक्षकारों को पहले यह स्थापित कर देना चाहिए कि कीमतों में अत्यधिक एवं प्राचल के संगत उतार-चढ़ाव आता रहता है। यदि कीमत में संगत अंतर नहीं आता है तो प्राचल की किसी भी मामले में अनदेखी करना अपेक्षित होता है। हितबद्ध पक्षकारों ने मोटाई एवं घनत्व के आधार पर कीमतों में कोई एकरूप अंतर नहीं रखा है। ऐसा मामला होने पर प्राधिकारी इस अंतर की अनदेखी कर सकते हैं। केवल एक तथ्य की अवस्थिति के परिणामस्वरूप अंतर अपर्याप्त होगा। वाणिज्य में इस कारक को एक ऐसे कारक के रूप में मानना चाहिए जो कीमतों को प्रभावित करता है। इस कारक को उत्पादक द्वारा एक रूप ढंग से लागू किया जाना चाहिए।
- जहां तक इस तर्क का संबंध है कि आवेदक द्वारा उल्लेख किए गए की तुलना में बाजार में कई व्यवहार्य स्थानापन्न उपलब्ध हैं; याचिका में उत्पादन के लिए “अर्थक्षम स्थानापन्न” संबंधी सूचना अपेक्षित होती है। व्यवहार्य स्थानापन्न पर विचार उत्पाद की तकनीकी एवं वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीयता पर आधारित होना चाहिए। यह स्पष्ट स्थिति है कि विचाराधीन उत्पादों के लिए कोई तकनीकी अथवा वाणिज्यिक रूप से कोई प्रतिस्थापन नहीं है। किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने इस उत्पाद के तकनीकी और वाणिज्यिक स्थानापन्न को अभिज्ञात नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, यदि इस उत्पाद को तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से कोई स्थानापन्न वास्तव में मौजूद है तापे हितबद्ध पक्षकारों को इस जांच के बारे में परेशान नहीं होना चाहिए। वे इस व्यवहार्य स्थानापन्न का आश्रय ले सकते हैं।

- जहां तक इस तर्क का संबंध है कि घरेलू उद्योग द्वारा ऐसी टी/टी आंकड़े अपनाए गए हैं जिनमें आयातों की रिपोर्टिंग विभिन्न तरीकों और यूनिटों में की गई तथा केवल परिवर्तित आयात आंकड़े और अपनाई गयी क्रियाविधियां ही प्रदान की गई है और यह कि सम्पूर्ण अपरिष्कृत आंकड़े प्रस्तुत किए जाने चाहिए जिसे कि आयात आंकड़ों के संग्रहण की विशुद्धता का आकलन किया जा सके; अपरिष्कृत आंकड़े प्रदान करने के संबंध में ऐसी कोई विधिक अपेक्षा नहीं है। विनिर्धारित आवेदनपत्र प्रोफार्मा के इसके संगत भाग में याचिका में (क) आयातों की मात्रा और मूल्य (देशवार); और (ख) सूचना के स्रोत का उल्लेख होना चाहिए। स्पष्टतः स्वयं टी/टी सूचना को याचिका में अनुबंधित करने की जरूरत नहीं है। आवेदक की प्रतिबद्धता केवल यह है कि वह आयातों के स्रोत तथा उनकी मात्रा एवं मूल्य की प्रमात्रा को अभिज्ञात करे।
- समान वस्तु: आवेदक कम्पनी द्वारा उत्पादित उत्पाद तथा सम्बद्ध देश से निर्यातित उत्पाद में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। दोनों ही उत्पादों का भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्यो एवं प्रयोगों उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन और प्रशुल्क वर्गीकरण आदि जैसे प्राचलों के रूप में तुलनीय विशेषताएं हैं। घरेलू उत्पाद तथा आयातित उत्पाद के बीच अनिवार्य उत्पाद गुणधर्मों की तुलना दर्शाती है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु अनिवार्य उत्पाद गुणधर्मों के रूप में आयातित वस्तुओं के तुलनीय हैं। सम्बद्ध वस्तुओं का उत्पादन एवं उनकी बिक्री विभिन्न भेदरूपों में की जाती है जिससे कि वे विशिष्ट अनुप्रयोगों को पूरा कर सके। समान अथवा एक जैसे कच्चे माल का प्रयोग करके, समान तथा एक जैसी उत्पादन प्रक्रिया अपनाकर, प्रौद्योगिकी एवं कर्मचारियों का प्रयोग करके विभिन्न उत्पाद प्रकारों का उत्पादन किया जाता है। आवेदक के मामले में किसी विशिष्ट उत्पाद प्रकार के उत्पादन अथवा अनुत्पादन का तथ्य बाजार की जरूरतों पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त, चूंकि आवेदक अभी स्वयं को भारतीय बाजारों में स्थापित करने की प्रक्रिया में है, इसलिए आवेदक भी विभिन्न वैरिएन्ट प्रस्तुत कर रहा है।
- यदि सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत से संबंधित आंकड़े निर्यातकों के लिए व्यवसाय संवेदी है तो घरेलू उद्योग से संबंधित आंकड़े भी समान रूप से व्यवसाय संवेदी है। वास्तव में, निर्यातकों ने अपने निर्यातों की एकल मात्रा का भी प्रकटन नहीं किया है। संगत अवधि के दौरान निर्यातक द्वारा किए गए निर्यात की एकल मात्रा के संबंध में कुछ भी गोपनीय नहीं हो सकता है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

- वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "रेजिन या किसी अन्य जैव पदार्थ द्वारा जुड़ा हुआ 6 मिमी से कम की मोटाई का लकड़ी और लकड़ी जैसा फाइबर बोर्ड है जिसे एतदप्रसंगत "फाइबर बोर्ड" कहा गया है, परंतु इसमें इन्सुलेशन बोर्ड, लैमिनेटेड फाइबर बोर्ड और वे बोर्ड शामिल नहीं हैं जो रेजिन या किसी अन्य जैव पदार्थ द्वारा जोड़े न गए हो।"
- उत्पाद विवरण से यह पर्याप्ततः स्पष्ट होता है कि यह 6 मिमी से कम की मोटाई वाले काष्ठ अथवा काष्ठ जैसे फाइबर बोर्डों को कवर करता है जिन्हें रेजिन द्वारा जोड़ा गया हो परंतु इसमें उन बोर्डों को भी शामिल किया गया है जो रेजिन द्वारा जुड़े न हो, लेकिन इन्सुलेशन बोर्ड, लैमिनेटेड फाइबर बोर्ड और वे बोर्ड शामिल नहीं हैं जो रेजिन अथवा किसी अन्य पदार्थ द्वारा जुड़े न हो।
- फाइबर बोर्डों को इसके उपरान्त भी यांत्रिक रूप से प्रशंसकृत किया जा सकता है जैसे लैमिनेटेड, सरफेस कोटेड, कार्बड, मोल्टेड, आदि। वर्तमान याचिका में विचाराधीन उत्पाद के दायरे में सीमा शुल्क शीर्षक 4411 के अंतर्गत वर्गीकरण योग्य सभी उत्पाद शामिल हैं परंतु इसमें (क) 6 मिमी अथवा उससे अधिक की मोटाई वाले फाइबर बोर्ड, (ख) इन्सुलेशन बोर्ड (ग) लैमिनेटेड फाइबर बोर्ड और (घ) वे बोर्ड शामिल नहीं हैं जो रेजिन अथवा किसी अन्य जैविक पदार्थ द्वारा जुड़े नहीं होते।
- फाइबर बोर्ड काष्ठ आधारित बोर्ड होते हैं जो विभिन्न आकार एवं मोटाई में उपलब्ध हैं। तथापि, एक लकड़ी के टोस टुकड़े की तुलना में वे उच्च शक्ति वाले अभियांत्रिक उत्पाद होते हैं—जिन्हें लकड़ी अथवा लिंगों सेल्युलोजिक सामग्री से बनाया जाता है—रेशों में रिफाइन किया जाता है तथा उन्हें उच्च ताप पर रेजिन बाइण्डर से पुनर्गठित करके बोर्ड का रूप दिया जाता है।
- चूंकि फाइबर बोर्ड एक इंजीनियर्ड उत्पाद होता है जिसके टोस लकड़ी की तुलना में (लकड़ी के एक टोस टुकड़े से बने) कुछ निश्चित फायदे होते हैं। फाइबर बोर्डों की टोस लकड़ी की तुलना में नमी परिवर्तन को सहन करने की अधिक सहन शक्ति होती है क्योंकि यह अतिव्याप्ति प्रणाली में व्यवस्थित काष्ठ फाइबर से बना होता है। इसमें पर्यावरणीय परिवर्तनों के लिए बेहतर अनुकूलनता होती है तथा अत्यधिक विविधतापूर्ण होता है। फाइबर बोर्ड के विभिन्न अनुप्रयोग होते हैं जैसे फर्नीचर हस्तशिल्प, उपभोक्ता वस्तुएं आदि।
- विचाराधीन उत्पाद को सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम के अध्याय 44 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। विचाराधीन उत्पाद का कोई समर्पित सीमा शुल्क वर्गीकरण कोड नहीं होता है। तथापि, यह वर्गीकरण केवल संकेतक है और किसी भी तरह से यह वर्तमान जांच के दायरे में बाध्यकारी नहीं है।
- इसके वर्णन में को विसंगति नहीं है। पुनः यह नोट किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकारों ने अपने प्रस्तुतिकरण उपयुक्त तर्क के बिना विचाराधीन उत्पाद से विभिन्न प्रकार के अपवर्जनों की मांग करते हुए प्रस्तुत किए हैं। यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने अनिवार्यतः मौजूदा आवेदन में क्षति का दावा किया है। इसके अतिरिक्त, यह उम्मीद नहीं की जा सकती है कि जहां तक विचाराधीन उत्पाद का सम्बंध है, घरेलू उद्योग को भारतीय बाजार में पाटित आयातों की उपस्थिति के कारण अनिवार्य रूप से क्षति के दावे के लिए सम्बद्ध वस्तु का इसके सभी रूपों में उत्पादन और बिक्री करनी चाहिए।

32. जहां तक घनत्व और कीमतों का संबंध है, हितबद्ध पक्षकारों के प्रत्युत्तरों की जांच करने के पश्चात कोई एक रूप प्रणाली नोट नहीं की गई है। यह भी नोट किया जाता है कि सहयोगकर्ता निर्यातकों/उत्पादकों ने इस संबंध में अपने परिशिष्ट 8 आंकड़ों में कोई विभेद नहीं किया है।

33. कुछ हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक केवल 2.5 से 5 मि.मी की मोटाई वाले बोर्डों का ही उत्पादन करता है और स्लेट विनिर्माता आवेदक द्वारा आपूर्ति किए गए सामान का उपयोग नहीं कर सकते हैं। इस मामले की जांच की गई है और यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने 2.1 मिमी तक की मोटाई वाली सम्बद्ध वस्तु का उत्पादन किया है। सभी हितबद्ध पक्षकारों के प्रस्तुतिकरणों पर विचार करने तथा उनके प्रस्तुतिकरणों का विश्लेषण करने के पश्चात 2 मिमी तथा उसके कम की मोटाई वाले सम्बद्ध वस्तु को विचाराधीन उत्पाद की परिधि से ओलग रखने का निश्चय किया गया है क्योंकि घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के दौरान 2 मिमी और उससे कम की मोटाई वाले सम्बद्ध वस्तु का विनिर्माण नहीं किया है।

34. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि बाजार में कई व्यवहार्य स्थानापन्न उपलब्ध हैं परंतु इसके लिए साक्षात्कृत प्रमाण नहीं दिया गया है। यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग ने दावे का विरोध किया है कि प्राधिकारी ने जांच के सिलसिले में यह पाया कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई व्यवहार्य स्थानापन्न स्थापित नहीं किया गया।

35. प्राधिकारी इस विचार से सहमत है कि डोर स्किन्स मूल्य वर्धित एवं पृथक उत्पाद है। इसके अतिरिक्त डोरस्किन की कीमतें सामान्य फाइबर बोर्ड की कीमतों की तुलना में अत्यधिक ज्यादा हैं। पुनः यह नोट लिया जाता है कि फाइबर बोर्ड मोल्डेड डोरस्किन का उत्पादन आठ सौ 800 कि.ग्रा./एम³ से अधिक के घनत्व वाले 3 मि.मी. की मोटाई के फाइबर बोर्ड से किया जाता है। चूंकि मोल्डेड डोरस्किन एक मूल्यवर्धित उत्पाद है इसलिए इसे इस जांच के दायरे और विस्तार के अंतर्गत नहीं आता है अतः विचाराधीन उत्पाद को निम्नवत परिभाषित किया जाता है:

इसमें रेजिन या अन्य जैव पदार्थ द्वारा नहीं जुड़े इनसुलेशन बोर्डों, लेमिनेटेड फाइबर बोर्डों, मोल्डेड डोर स्किन्स और बोर्डों को छोड़कर, 2 मि.मी से अधिक और 6 मि.मी से कम की मोटाई वाले बांडेड लकड़ी के अथवा लकड़ी जैसे फाइबर बोर्ड।

36. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान पी यू सी में प्रयोग किए गए आंकड़े विचाराधीन उत्पाद से संबंधित हैं। इन आंकड़ों का निर्धारण जांच शुरूआत अधिसूचना में यथापरिभाषित विचाराधीन उत्पाद के दायरे और विस्तार के आधार पर की गई है।

37. आवेदक ने दावा किया है कि आवेदक कम्पनी द्वारा उत्पादित उत्पाद तथा सम्बद्ध देश से निर्यातित उत्पाद में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। दोनों ही उत्पादों का भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य एवं प्रयोगों उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन और प्रशुल्क वर्गीकरण आदि जैसे प्राचलों के रूप में तुलनीय विशेषताएं हैं। घरेलू उत्पाद तथा आयातित उत्पाद के बीच अनिवार्य उत्पाद गुणधर्मों की तुलना दर्शाती है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु अनिवार्य उत्पाद गुणधर्मों के रूप में आयातित वस्तुओं के तुलनीय हैं। सम्बद्ध वस्तुओं का उत्पादन एवं उनकी बिक्री विभिन्न भेदरूपों में की जाती है जिससे कि वे विशिष्ट अनुप्रयोगों को पूरा कर सकें। समान अथवा एक जैसे कच्चे माल का प्रयोग करके, समान तथा एक जैसी उत्पादन प्रक्रिया अपनाकर, प्रौद्योगिकी एवं कर्मचारियों का प्रयोग करके विभिन्न उत्पाद प्रकारों का उत्पादन किया जाता है।

38. इस प्रकार, आवेदक द्वारा उत्पादित सम्बद्ध वस्तु तथा संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद को इस जांच के प्रयोजन के लिए पाटनरोधी नियमावली के आशय के अंतर्गत समान वस्तु के रूप में माना जा रहा है।

घ. “घरेलू उद्योग” का दायरा एवं आधार

39. इस जांच के प्रारंभ के समय, पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के तहत निम्नवत परिभाषित किया गया है:—

“घरेलू उद्योग” का आशय समान वस्तु के विनिर्माण या उससे संबंधित किसी अन्य क्रियाकलाप में समग्र रूप से लगे उन सभी घरेलू उत्पादकों अथवा उन उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उस वस्तु के समस्त घरेलू उत्पादन का एक बड़ा अनुपात बनाता हो, सिवाय इसके कि यदि ये उत्पादक कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों अथवा आयातकों से संबंधित हो पाटित वस्तु के निर्यातकों अथवा आयातकों से संबंधित हों अथवा उसके स्वयं आयातक हो तो ऐसे मामलों में वाक्यांश “घरेलू उद्योग” को केवल शेष उत्पादकों के रूप में माना जाएगा।

40. तथापि, इस नियम में बाद में संशोधन करके निम्नवत पढ़ा जायेगा:

“घरेलू उद्योग” का आशय समान वस्तु के विनिर्माण या उससे संबंधित किसी अन्य क्रियाकलाप में समग्र रूप से लगे उन सभी घरेलू उत्पादकों अथवा उन उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उस वस्तु के समस्त घरेलू उत्पादन का एक बड़ा अनुपात बनाता हो, सिवाय इसके कि यदि ये उत्पादक कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों अथवा आयातकों से संबंधित हो पाटित वस्तु के निर्यातकों अथवा आयातकों से संबंधित हों अथवा उसके स्वयं आयातक हो तो ऐसे मामलों में वाक्यांश “घरेलू उद्योग” को शेष उत्पादकों के रूप में माना जाएगा।

अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतिकरण

41. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतिकरण संक्षेप में निम्नलिखित हैं:

मैसर्स वेनुगोपाल स्लेट इंडस्ट्रीज द्वारा किया गया प्रस्तुतिकरण

- आवेदक 'घरेलू उद्योग' के रूप में माने जाने के लिए उसकी कोई सामाजिक स्थिति नहीं है और यह जांच तुरंत समाप्त कर देनी चाहिए क्योंकि आवेदक ने पहले ही यह स्वीकार कर लिया है कि इसने संबंध वस्तु का आयात जांच की अवधि के दौरान किया है और उसकी लाभ अर्जित करके बाजार में बिक्री की है।

मैसर्स सेगामेट पैनल बोर्ड एसडीएन.बीएचडी.और मैसर्स मेरवाक एमडीएफ लंका (प्राइवेट) लिमिटेड, श्रीलंका की ओर से प्रस्तुत किये गये प्रस्तुतिकरण

- आवेदक ने स्वीकार किया है कि उसने जांच की अवधि के दौरान संबंध वस्तु का आयात किया है तथा उसकी लाभ अर्जित करके बाजार में बिक्री की है। अतः, संबंध वस्तु का एक आयातक होने के नाते आवेदक संविधि में यथा परिभाषित "घरेलू उद्योग" के विस्तार के बाहर आता है।

एवरग्रीन फाइबर बोर्ड बेरहाद (ई एफ बी), मलेशिया; एवरग्रीन फाइबर बोर्ड (जेबी) एसडीएन, बीएचडी (ईजेबी) मलेशिया और एवरग्रीन फाइबर बोर्ड (निलाई) एसडीएन.बीएचडी (ईएफएन) मलेशिया की ओर से किए गए प्रस्तुतिकरण

- आवेदक को घरेलू उद्योग के रूप में निर्धारित करने का कानून के अनुसार कोई आधार नहीं बनता है क्योंकि आवेदक इस तथ्य को स्वीकार किया है कि जांच अवधि के दौरान उसने आयात किये और इसलिए आवेदक को उपर्युक्त के मद्देनजर घरेलू उद्योग के रूप में विचार किये जाने का कोई आधार नहीं बनता है। घरेलू उद्योग ने आयातों के संबंध में परस्पर विरोधी विचार व्यक्त किये हैं यह प्रस्तुत किया गया है कि जांच शुरूआत अधिसूचना में, यह खुलासा किया गया कि यह आयात कंपनी द्वारा उत्पादित किये जा रहे उत्पाद का अनुसंधान एवं विकास के जरिए बेंच मार्क करने के लिए किये गये थे न कि व्यापार करने के लिए और यह कि आयातों की मात्रा आवेदक द्वारा किये गये उत्पादन की तुलना में बहुत कम है। इसके विपरीत, उनकी याचिका में, उन्होंने उल्लेख किया कि उन्होंने आयातित सामग्री की बिक्री घरेलू बाजार में की और वह भी पर्याप्त लाभ के साथ की।
- आवेदक द्वारा कुल आयातों की तुलना में अपने आयात का विश्लेषण करने अथवा उस उद्देश्य के लिए बिक्री/क्षमता का विश्लेषण करने का कोई परिणाम नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ता के आधार का निर्धारण इसके उत्पादन के स्तर से किया जाता है न कि कुल आयातों/बिक्री/क्षमता की मात्रा के आधार पर। याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादन की तुलना में आयातों के विश्लेषण से विलग होने के लिए प्रारंभिक जांच परिणाम में कोई कारण नहीं दिया गया है।

मैसर्स मैगना-फोरमोस्ट एडीएन तथा मैसर्स मैसोनाइट कंपोनेंट्स, आयरलैंड की ओर से किया गया प्रस्तुतिकरण

- आवेदक के पास पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) और पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 4.1 और 5.4 के अंतर्गत "घरेलू उद्योग" के रूप में बनने का कोई आधार नहीं है क्योंकि आवेदक संबंध उत्पाद का स्वयं एक आयातक है।

मैसर्स पीटी.मसारी द्विसेपार्कट फाइबर, इंडोनेशिया तथा मैसर्स पीटी.सुमाटेरा प्राइमा फाइबर बोर्ड (एसपीएफ), इंडोनेशिया की ओर से किया गया प्रस्तुतिकरण

- बेंच मार्क के लिए संबंध वस्तु का स्वयं आयात: घरेलू उद्योग ने नियम 2(ख) की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अपनी रक्षा हेतु घृष्टतापूर्वक यह उल्लेख किया है कि स्वयं किये गये आयात बेंचमार्क उद्देश्यों के लिए है। इस प्रयोजन की पूर्ति स्थानीय बाजार से आयातित वस्तु की खरीद करके भी की जा सकती है और न कि संबंध वस्तु का कंटेनर भरके आयात करके। रुचिकर बात यह है कि, आवेदक ने याचिका में उल्लेख किया है कि उसने संबंध वस्तु का आयात अनुसंधान एवं विकास के लिए किया है न कि व्यापार करने के लिए। इसके विपरीत, याचिका के ही एक अन्य पृष्ठ पर उन्होंने सुस्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि उन्होंने आयातित माल की बिक्री भारी लाभ पर की है, इसका आशय यह है कि उन्होंने संबंध वस्तु का व्यापार किया है और उससे लाभ भी अर्जित किया है। जांच की अवधि से पहले और जांच की अवधि के दौरान आवेदक के स्वयं आयातों के कारण आयातों की प्रवृत्ति का विश्लेषण त्रुटिपूर्ण है। आवेदक की वेबसाइट में यह स्वीकार किया गया है कि जांच की अवधि से पहले वे केवल आयातों पर ही आश्रित थे। यह कि इस मामले को एक अन्य कारण से भी समाप्त कर दिये जाने की जरूरत है क्योंकि नियम 5 की पूर्व शर्तों और आधार का निर्धारण नियम 17 अथवा नियम 12 के अंतर्गत नहीं किया जा सकता है।

घरेलू उद्योग द्वारा किया गया प्रस्तुतिकरण

- आवेदक कंपनी ने संबंध वस्तु का आयात नहीं किया है, उसने वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने के पश्चात अल्प मात्रा में आयात अवश्य किया था। विभिन्न कम्पनीयों से विभिन्न मोटाई के उत्पाद का अल्प मात्रा में आयात उसके उद्योग में उत्पादित उत्पाद की तुलना करने के लिए किया गया था। उत्पाद तुलना केवल तभी कारगर होती है जब उत्पाद के संपूर्ण बेंच का आयात किया जाता है ताकि उनके नमी संघटक, ग्ल्यू संघटक तथा विभिन्न अन्य उत्पाद विनिर्देशनों की तुलना आवेदक द्वारा उत्पादित उसी उत्पाद श्रृंखला से की जा सके। ये आयात कंपनी द्वारा उत्पादित किये जा रहे उत्पाद का अनुसंधान एवं विकास के जरिए बेंच मार्क करने के उद्देश्य से किये गये थे न कि व्यापार करने के उद्देश्य से। वास्तव में आयातों की यह मात्रा आवेदक के उत्पादन के साथ तुलना करने पर बहुत अल्प मात्रा है। इस

आयातों के संबंध में प्रविष्टि के बिल प्राधिकारी को प्रदान कराये गये हैं। आवेदक संबद्ध देश में विचाराधीन उत्पाद के किसी भी निर्यातक या आयातक से संबंधित (प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः) नहीं है।

- आवेदक द्वारा किये आयातों के संबद्ध में आयातों के कारणों का उल्लेख उपर्युक्त पैरा में किया गया है। यह वह मामला नहीं है जहां आवेदक ने आयातित माल की बिक्री पर्याप्त लाभ पर की हो। यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदन में की गई अभिव्यक्ति को इस आशय से नहीं पढ़ा जाना चाहिए कि आवेदक ने उत्पाद की बिक्री की है। वास्तव में, आवेदक ने उत्पाद की बिक्री नहीं की है। इसने इस उत्पाद की खपत अपने उत्पादन में की है और इन डाउन स्ट्रीम उत्पादन की बिक्री की है (डाउन स्ट्रीम उत्पादों में भी आवेदक को वित्तीय घाटा हुआ था)। आवेदक ने पाटन से लाभ उठाने के लिए आयातों का आश्रय नहीं लिया था। आवेदक का मुख्य उद्देश्य आयात करना नहीं था, उसका मुख्य उद्देश्य था अपना उत्पादन करना। अतः आवेदक को पाटन रोधी नियमावली के आशय के अंतर्गत पात्र घरेलू उद्योग के रूप में माना जाए।
- इस तर्क के संबंध में कि आवेदक की जांच की अवधि के दौरान आयातित वस्तुओं के कारण कोई आधिकारिक स्थिति नहीं है; यह तर्क बिना किसी कानूनी और तथ्य परक आधार पर आधारित है। किये गये दावे के विपरीत, घरेलू उद्योग की परिभाषा में प्रावधान है कि प्राधिकारी "घरेलू उत्पादकों को समग्र रूप से" विचार करेंगे। इसके अतिरिक्त, यदि किसी घरेलू उत्पादक ने संबद्ध देशों से उत्पाद का आयात किया है तो नियमावली में प्रावधान है कि प्राधिकारी ऐसे घरेलू उत्पादक का "निर्वचन" पात्र घरेलू उद्योग के रूप में कर "सकता" है। यह नोट किया जा सकता है कि प्रथमतः, नियम यह उल्लेख नहीं किया गया है कि प्राधिकारी ऐसी कंपनी को अपात्र घरेलू उत्पाद के रूप में मानेंगे। दूसरे, "सकता है" शब्द का प्रयोग करने के कारण कोई भी हितबद्ध पक्षकार प्राधिकारी के समक्ष यह स्थापित कर सकता है कि उक्त उत्पादक अपात्र घरेलू उत्पादक है। यह घरेलू उद्योग के सामान अर्था के अंतर्गत और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरे शब्दों में यद्यपि समावेशन पर विचार किया जाना चाहिए फिर भी अपवर्जन करने की जरूरत ही स्थापित की जा सकती है।
- बैचमार्क उद्देश्य के लिए किये गये आयातों के बारे में और यह कि विरोधाभासी अभिकथन किया गया है के संबंध में यह प्रस्तुत किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने अपने आयातों की वास्तविक रक्षा करने और इन आरोपों को निराधार साबित करने के लिए ऐसा किया है। आवेदक द्वारा उत्पादन प्रारंभ किये जाने से पहले भारत में पतले बोर्डों का उत्पादन नहीं हो रहा था। अतः बैचमार्किंग के उद्देश्य से उनकी स्थानीय बाजारों से खरीदारी करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। इसके अतिरिक्त बैच मार्क उद्देश्यों के लिए आयातित उत्पाद का भंडारण अनिश्चित काल तक के लिए नहीं किया जा सकता है। व्यवसाय विवेक यह मांग करता है कि उसकी बिक्री उद्देश्य प्राप्त होने के तुरंत पश्चात कर दी जानी चाहिए। आवेदक ने आयातित उत्पाद की बिक्री बाजारों में नहीं की बल्कि उसने आयातित उत्पाद की खपत अपने डाउन स्ट्रीम उत्पाद का उत्पादन करने के लिए की और तत्पश्चात उस उत्पाद की बिक्री कर दी। वास्तव में इस सूचना से यह देखा जा सकता है कि आवेदक को डाउन स्ट्रीम उत्पाद में घाटा हुआ।
- इसके अतिरिक्त, हितबद्ध पक्षकारों को घरेलू उत्पादक का, उसके द्वारा किये गये आयातों के कारण घरेलू उद्योग के दायरे से अपवर्जित करने की जरूरत स्थापित करनी चाहिए। नियम यह नहीं है कि घरेलू उत्पादक ने आयात किया है, इसे स्वयं ही अपवर्जित कर दिया जाए। सामान्य नियम यह है कि घरेलू उद्योग का आशय समग्र रूप से घरेलू उत्पादकों से है; और यदि किसी घरेलू उत्पादक ने उत्पाद का आयात किया है तो उसे न्यायोचित पाये जाने पर अपवर्जित किया जा सकता है।
- आवेदन में विभिन्न उत्पादकों द्वारा उत्पाद को दर्शाये जाने और आवेदक तथा उसकी सहायक कंपनी द्वारा उसमें भागीदारी किये जाने के विवरण का उल्लेख किया गया है। उल्लिखित आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि भारत में बालाजी एक्शन बिल्डवेल (आवेदक) तथा ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज नामक केवल दो ही कंपनियां हैं जिन्होंने अभी हाल ही में विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन प्रारंभ किया है। ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज ने विचाराधीन उत्पाद का वाणिज्यिक उत्पादन अभी हाल ही में दिसम्बर, 2010 से शुरू किया है। ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने वर्तमान आवेदन का समर्थन किया है। अतः आवेदक का उत्पादन कुल भारतीय उत्पादन में "एक बहुत बड़ा अनुपात" बनता है। आवेदक का उत्पादन कुल भारतीय उत्पादन (लगभग 87 प्रतिशत) का 50 प्रतिशत से अधिक बनता है और इसलिए उसे विचाराधीन उत्पाद के एक बड़े उत्पादक के रूप में माना जाना चाहिए। यह आवेदन घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उनकी ओर से किया गया है और इसलिए यह पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 (1) के अंतर्गत आधार की जरूरतों को पूरा करती है।
- जहां तक फाइबर बोर्डों के बीच प्रतिस्थापनीयता से संबंधित तर्क का संबंध है, यह प्रस्तुत किया जाता है कि विभिन्न मोटाईयों के फाइबर बोर्डों का उत्पादन समान उत्पादन प्रक्रिया से किया जाता है। उत्पादकगण प्रक्रिया नियंत्रण पैरामीटरों का समायोजन करके और कच्चे माल की रेसीपी में संशोधन करके एक उत्पाद से दूसरे उत्पाद का उत्पादन आसानी से कर सकते हैं।

प्राधिकारी द्वारा जांच

42. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिये गये तर्कों को नोट किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियमावली प्राधिकारी को, अन्य बातों के साथ-साथ किसी घरेलू उत्पादक को जिसने संबद्ध वस्तु का आयात किया है घरेलू उद्योग के दायरे और विस्तार से, प्रत्येक मामले के तथ्यों और गुण-अवगुण के आधार पर अपवर्जित या शामिल कर सकते हैं। पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (ख) में 1 दिसम्बर, 2011 को संशोधन किया गया था परंतु इससे हालात में कोई परिवर्तन नहीं हुआ बल्कि उसका स्पष्टीकरण दिया गया है। पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (ख) में यह उल्लेख किया गया है कि कोई घरेलू उत्पादक जिसका संबंध निर्यातकों अथवा आयातकों से है या जो स्वयं पाटित वस्तुओं के आयातक है, को कतिपय परिस्थियों में घरेलू

उद्योग का निर्धारण करते समय अपवर्जन किया जा सकता है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उत्पादक विचाराधीन उत्पाद का एक अथवा उससे अधिक सदाशतापूर्ण कारणों से, जिसमें परीक्षण, अनुसंधान एवं विकास, बीज-विपणन उद्देश्य शामिल है (गुणवत्ता का परीक्षण करने के लिए उत्पाद का आयात) कर सकते हैं।

43. यह नोट किया जाता है कि आवेदक कंपनी ने विभिन्न मोटाई वाले संबद्ध वस्तु का आयात वर्ष 2010-11 के दौरान *** सीबीएम की सीमा तक अपने उत्पाद की तुलना करने के लिए अल्प मात्रा में किया था, जो कुल आयातों का लगभग 0.46 प्रतिशत बनता है। यह नोट किया जाता है कि आवेदक द्वारा यह आयात उसकी कंपनी द्वारा उत्पादित उत्पाद की अनुसंधान एवं विकास के जरिए बेंचमार्क करने के लिए किये गये थे न कि व्यापार करने के लिए। आयातों की मात्रा आवेदक के उत्पादन की तुलना में बहुत कम है। यह भी नोट किया जाता है कि आयात करना कंपनी के मुख्य क्रियाकलाप में शामिल नहीं था और इसने घरेलू उत्पादक की अपनी भूमिका का अबत्याग नहीं किया।

44. आवेदन पत्र के अनुसार भारत में इस उत्पाद के दो उत्पादक हैं अर्थात् मैसर्स बालाजी एक्शन बिल्डवेल (आवेदक) तथा ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज लिमिटेड केवल दो ही कंपनियां हैं। मैसर्स ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने वर्तमान आवेदन का समर्थन किया है। अतः, आवेदक तथा उसका समर्थक भारत में संबद्ध वस्तु का 100 प्रतिशत उत्पादन करते हैं।

45. आवेदक ने दावा किया है कि उसकी कंपनी का मुख्य उद्देश्य आयात करने के बजाय अपना उत्पादन जारी रखना है और अतः आवेदक को पाटनरोधी नियमावली के आशय के अंतर्गत पात्र घरेलू उद्योग के रूप में माना जाना चाहिए।

46. उपर्युक्त के मद्देनजर, ऐसे घरेलू उत्पादक को घरेलू उद्योग के रूप में मानने से अपवर्जित कर देना अनूचित होगा। प्राधिकारी आवेदक के दावे में गुण देखते हैं कि इसे भारत में संबद्ध वस्तु के घरेलू उत्पादक के रूप में अपवर्जित नहीं किया जाना चाहिए और उसे इस आवेदन पत्र के प्रयोजन के लिए घरेलू उद्योग के रूप में माना जाना चाहिए।

47. आवेदक का उत्पादन कुल भारतीय उत्पादन (लगभग 87 प्रतिशत) का 50 प्रतिशत से अधिक बनता है और इसलिए उसे विचाराधीन उत्पाद के एक बड़े उत्पादक के रूप में माना जाना चाहिए। यह आवेदन घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उनकी ओर से किया गया है और इसलिए यह पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के अंतर्गत 'आधार' की जरूरतों को पूरा करती है। इसके अतिरिक्त, आवेदक पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (ख) में दी गई शर्तों के अनुरूप 'घरेलू उद्योग' बनता है।

प्रकटन विवरण जारी करने के पश्चात हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दे तथा प्राधिकारी द्वारा जांच

48. प्रकटन विवरण जारी होने के पश्चात निम्नलिखित हितबद्ध पक्षकारों ने मुद्दे उठाए हैं:

- क) मै. वेणुगोपाल स्लेट इंडस्ट्रीज, मरकापुर, आंध्र प्रदेश (प्रयोक्ता एवं आयातक)
- ख) मै. सेगामट पैनल बोर्ड्स एस डी एन, बी एच डी, मलेशिया (निर्यातक)
- ग) मै. पीटीसुमाटेरा प्राइमा फाइबर बोर्ड, इण्डोनेशिया (निर्यातक)
- घ) मै. एवरग्रीन फाइबर बोर्ड बेरहाद (ईएफबी) मलेशिया (निर्यातक)
- ड.) मै. एवरग्रीन फाइबर बोर्ड (जे बी) एस डी एन बी ए डी मलेशिया (निर्यातक)
- च) मै. मेरबाक एम डी एफ लंका (प्राइवेट) लिमिटेड श्रीलंका (निर्यातक)
- छ) मै बालाजी एक्शन बिल्डवेल, दिल्ली (याचिकाकर्ता एवं घरेलू उद्योग)

49. यह नोट किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए कुछ मुद्दे उनके द्वारा किए गए पिछले प्रस्तुतिकरणों की ही पुनरावृत्ति हैं। यह नोट किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए कई मुद्दे बिल्कुल सामान्य हैं और उन्हें दोहराया नहीं गया है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दे तथा प्राधिकारी द्वारा उनकी जांच निम्नलिखित हैं:-

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण और प्राधिकारी द्वारा उनकी जांच

50. घरेलू उद्योग ने निर्दिष्ट प्राधिकारी से अनुरोध किया कि वह इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि निर्यातक विचाराधीन उत्पाद का तृतीय देशों के निर्यात भारत को निर्यात की जाने वाली कीमत से अधिक कीमत पर कर रहे हैं, पाटन मार्जिन का निर्धारण करने के लिए पुनःविचार करें। उन्होंने प्रस्तुत किया कि मेरबाक श्रीलंका द्वारा विचाराधीन उत्पाद का पाकिस्तान को निर्यात भारत को किये जाने वाले निर्यात से अधिक कीमतों पर कर रहा है जिससे स्पष्टता स्थापित होता है कि वे भारत में अपने माल का बहुत कम कीमत पर पाटन कर रहे हैं और भारतीय घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हैं। ऐसी ही स्थिति अन्य सम्बद्ध देशों के संबंध में भी है।

51. मैसर्स ईएफबी और ईजेबी को पाटन मार्जिन देने के मुद्दे पर यह प्रस्तुत किया जाता है कि कंपनी द्वारा कच्चे माल और इनपुटों की खरीद की गई है। तथापि सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी तथा पहले प्रस्तुत किये गये अभिलेखों के अनुसार यह स्पष्ट है कि उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण ग्राही

कच्चे माल का उत्पादन किया है। पुनः यह प्रस्तुत किया गया कि निर्यात से संबंधित कंपनियां संबद्ध वस्तु का विनिर्माण करने के लिए अपेक्षित गोंद का विनिर्माण करने तथा पौध रोपण, विद्युत उत्पादन सहित संबद्ध वस्तु का उत्पादन करने और/या उसकी बिक्री करने से जुड़े क्रियाकलापों में संलिप्त है। चूंकि एमडीएफ का निर्माण करने में मुख्य कच्चा माल लकड़ी, पावर और गोंद होता है, इसलिए निर्यात द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर के आधार पर उसके लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण करने से पहले परिशुद्ध अवस्थापन लागत अनिवार्य है। अतः, उत्पादन लागत के संबंध में दावा करना अपर्याप्त है। यह दर्शाया जाना चाहिए कि यह उत्पादन लागत तर्क संगत रूप से उस लागत को प्रदर्शित करती है जो विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करने और उसकी बिक्री करने से जुड़ी हुई है। मैसर्स सेगामट पैनल बोर्ड्स एसडीएन बीएचडी के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के संबंध में यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह स्पष्ट नहीं है कि क्या ब्याज लागत को वास्तविक उत्पादन लागत में समायोजित किया गया है। यदि ऐसा नहीं किया गया है तो यह स्पष्ट है कि कंपनी द्वारा अनुरक्षित रिकार्ड तर्क संगत रूप से विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और उसकी बिक्री करने से जुड़ी लागत को प्रदर्शित नहीं करती है। मैसर्स पीटी सुमाटेरा प्राइमा फाइबर बोर्ड के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के संबंध में यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्राधिकारी ने अपूर्ण जानकारी पर विचार कैसे किया। मेरबाक एमडीएफ लंका (प्राइवेट) लिमिटेड के संबंध में प्रस्तुत किया जाता है कि निर्यातक की निर्यात कीमत और घरेलू बिक्री लागत से कम है और केवल यह तथ्य पर्याप्त नहीं है कि यह लागत कंपनी द्वारा रखे गये रिकार्ड पर आधारित है। पुनः यह प्रस्तुत किया गया है कि लागत में विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करने और उसकी बिक्री करने से जुड़ी लागत प्रदर्शित होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त यह प्रस्तुत किया गया कि इस उद्देश्य के लिए लाभ पर उत्पादन लागत के 10 प्रतिशत की दर से विचार किया जाना चाहिए। इस मामले की जांच की गई और नोट किया जाता है कि सभी प्रस्तुतिकरणों की जांच संबद्ध निष्कर्षों में उपयुक्त शीर्षकों के अंतर्गत कर ली गई है। यह पुनः नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने निर्यातक के आंकड़ों का सत्यापन कर लिया है और पाटनरोधी नियमावली के अनुसार पाटिन मार्जिन का निर्धारण कर लिया गया है।

52. क्षति और कारणात्मक संबंध के मुद्दे पर घरेलू उद्योग ने अपने प्रस्तुतिकरणों को ही दोहराया है। पुनः यह प्रस्तुत किया गया है कि उन्होंने अपने वाणिज्यिक उत्पादन के 17 महीनों, वह अवधि जिसके लिए याचिकाकर्ता ने उत्पाद का उत्पादन और उसकी बिक्री की है, के लिए क्षति संबंधी जानकारी प्रदान कराई है तथा निर्दिष्ट प्राधिकारी ने उसकी जांच भी कर ली है। वाणिज्यिक उत्पादन की घोषणा करने के बाद याचिकाकर्ता ने अपना उत्पादन अनवरत जारी रखा। यह वह मामला नहीं है जहां याचिकाकर्ता ने आन्तरायिक उत्पादन किया हो। तथापि, याचिकाकर्ता अपना उत्पादन निरंतर बढ़ाये जाने में सक्षम हुआ है, तथापि इसे अपना उत्पाद लाभदायक कीमतों पर बेचने से रोका गया। याचिकाकर्ता अपने उत्पाद की बिक्री गैरक्षतिकारी कीमत से वास्तव में कम कीमत पर बेच रहा है। आयातों से घरेलू कीमतों का भारी अधोरदन हो रहा है। घरेलू उद्योग टूटने के कगार पर पहुंच चुका है, इसके बावजूद भी घरेलू उद्योग को भारी वित्तीय घाटे, निवेश पर नकारात्मक अर्जन और ऋणात्मक नकद लाभ का सामना करना पड़ रहा है। पुनः यह उल्लेख किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने यद्यपि उत्पादन का अच्छा खासा स्तर पहले ही प्राप्त कर लिया है तथापि इसके प्रत्याशित/परिकल्पित निष्पादन से इसके निष्पादन की तुलना करने पर तथा इसकी अवस्थिति यह दर्शाती है कि घरेलू उद्योग ने उसी सीमा तक क्षति का सामना किया है जिस सीमा तक इसने वस्तु का उत्पादन किया है। आंकड़ा संग्रहण के संबंध में यह प्रस्तुत किया गया कि डब्लू टी ओ ने भी केवल उन्ही व्यापार स्थितियों को मान्यता दी है जहां क्षति की अवधि कम है। समिति के शब्दों में, “क्षति संबंधी जांच करने के लिए आंकड़ा संग्रहण की अवधि कम से कम 3 वर्ष होनी चाहिए जब तक कि वह पक्षकार जिससे आंकड़े एकत्र किये जा रहे हैं कम अवधि के लिए अवस्थित न रहा हो.....” इसके अतिरिक्त, डब्ल्यूटीओ, एडीए के प्रस्तावित संशोधन के फुटनोट 15 के अनुसार जांचकर्ता प्राधिकारी को सभी आर्थिक कारकों एवं देशनाकों के संबंध उपलब्ध जानकारी, उस सीमा तक जिस तक आंकड़े मौजूद हो, का मूल्यांकन करना चाहिए। अतः, ऐसी स्थिति में जहां घरेलू उद्योग अल्पतर अवधि के लिए मौजूद रहा हो, जैसाकि वर्तमान मामले में है, वहां क्षति का विश्लेषण घरेलू उद्योग की ऐसी मौजूदगी अल्पतर अवधि के लिए ही करने की जरूरत होती है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले में क्षति के सभी अधिदेशित 14 पैरामीटरों की जांच की गई है और चूंकि क्षति पैरा मीटर के अंतर्गत जरूरत स्वयं ही विस्तृत नहीं है इसलिए इस मामले में निष्पादन का मूल्यांकन उत्पाद की संकल्पना और उसका उत्पादन करने के समय के परिकल्पित निष्पादन के रूप में मूल्यांकन करना चाहिए। इस मामले की जांच की गई है और घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किये गये मुद्दों की जांच इस जांच परिणाम में उपयुक्त शीर्षकों में की गई।

53. याचिकाकर्ता ने यह प्रस्तुत किया कि घरेलू उद्योग को क्षति इसी तथ्य से सिद्ध हो जाती कि संबद्ध देशों से आयात में भारी बढ़ोतरी हुई जबकि घरेलू उद्योग द्वारा अपना उत्पादन शुरू कर दिये जाने की स्थिति में आयातों में भारी गिरावट आनी चाहिए थी। कीमत अधोरदन का स्तर बहुत अधिक है। न्यून कीमतें प्रस्तुत किये जाने के बावजूद घरेलू उद्योग अपने उत्पाद की बिक्री करने में अक्षम रहा और इस कारण उसे अपनी कीमतों में और अधिक कटौती करनी पड़ी। इनपुट कीमतों में वृद्धि को देखते हुए उत्पादन लागत में प्रत्येक उत्पादक की वैश्विक रूप से बढ़ोतरी हुई, फिर भी विदेशी उत्पादकों ने अपनी कीमतों में बढ़ोतरी उस अनुपात में नहीं की जिसमें इनपुट कीमतों में वृद्धि के कारण लागत में बढ़ोतरी हुई। वास्तव में, इनपुट कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद कीमते लगभग वही बनी रही।

54. याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी से अनुरोध किया है कि वह निर्यातकों की तृतीय देश कीमतों के विश्लेषण का प्रकटन करें और यह देखें कि क्या तृतीय देश की कीमतें भी संपूर्ण अवधि में उसी स्तर पर बनी रही। यदि नहीं तो, इससे भारतीय बाजार में चयनित पाटन का स्पष्ट प्रदर्शन होता है। क्षति के मुद्दे के संबंध में यह प्रस्तुत किया जाता है कि घरेलू उद्योग को अपना उत्पाद अत्यधिक वित्तीय घाटे पर बेचने को मजबूर किया गया जिसके परिणाम स्वरूप उसे निवेश और नकद प्रवाह पर ऋणात्मक अर्जन हुआ। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग का निष्पादन प्रक्षेपित स्तर से बहुत कम था, यद्यपि देश में उत्पाद की मांग बहुत अधिक थी। घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत का समायोजन किये जाने के पश्चात यह देखा जा सकता है कि घरेलू उद्योग अपनी उत्पादन लागत उगाहने और तर्क संगत लाभ अर्जित करने में अक्षम रहा है। यह प्रस्तुत किया गया कि जांच की अवधि के पश्चात की अवधि में भी उन्हें क्षति होती रही और वे जांच की अवधि के पश्चात की अवधि में भी घाटा सहन करते रहे। पुनः यह प्रस्तुत किया गया है कि यद्यपि कुछ पैरामीटरों के रूप में उनके कार्यनिष्पादन में सुधार हुआ परंतु समग्र रूप से वे घाटा सहन करते रहे और उन्हें यह घाटा संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के कारण होता रहा। इसलिए, याचिकाकर्ता ने निर्दिष्ट प्राधिकारी से यह धारित करने का अनुरोध किया है कि इस मामले में

याचिकाकर्ता को वास्तविक क्षति हुई है। इस मामले की जांच की गई है और इस मुद्दे पर घरेलू उद्योग द्वारा किये गये प्रस्तुतिकरणों पर इस जांच परिणाम के उपयुक्त शीर्षकों के अंतर्गत जांच की गई।

55. यह प्रस्तुत किया गया है कि पाटन रोधी शुल्क अमेरिकी डालर के रूप में और यह शुल्क निश्चित रूप-विधान में निर्धारित की जानी चाहिए। इस संबंध में यह उल्लेख किया गया कि चूंकि लगाया गया अनंतिम शुल्क अमेरिकी डालर के रूप में अभिव्यक्त पाटनरोधी शुल्क की निश्चित प्रमात्रा के रूप में अभिरोपित किया गया है। इसलिए शुल्क के रूप-विधान में परिवर्तन करने का कोई औचित्य नहीं है। यह प्रस्तुत किया गया है कि सीमा शुल्क पत्तन प्राधिकारियों के पास आयातक द्वारा रिपोर्ट की गई आयात कीमत की परिशुद्धता सुनिश्चित करने का कोई तंत्र नहीं होता है और इसलिए पत्तन प्राधिकारियों के लिए आयात कीमतों का सत्यापन करना न तो व्यवहार्य है न ही अर्थक्षम। इस मामले की जांच की गई है और पाटन रोधी शुल्क का अधिरोपण इस मामले के तथ्यपरक आधारों, कार्यवाही के दौरान सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये प्रस्तुतिकरणों और इन प्रस्तुतिकरणों के विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए किया गया है।

56. कीमत अधोरदन के संबंध में यह प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान मामले में कीमत प्रतिबद्धता को इसकी मॉनीटरिंग करने में आने वाली कठिनाईयों के मद्देनजर स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। इस मामले की जांच की गई है और यह उल्लेख किया जाता है कि कीमत प्रतिबद्धताओं को मॉनीटर करने में आने वाली व्यवहारिक दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए कीमत प्रतिबद्धता को स्वीकार नहीं किया गया है।

उत्पादकों, निर्यातकों, आयातकों और प्रयोक्ताओं द्वारा किये गए प्रस्तुतिकरण तथा प्राधिकारी द्वारा जांच

57. आयातकों और प्रयोक्ताओं द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि क्षति के सभी कारकों का आकलन तिमाही आंकड़ों के आधार पर किया जाना चाहिए न कि वार्षिक आंकड़ों अथवा प्रक्षेपित निष्पादन के आधार पर। इसमें लाभप्रदायकता तथा इस उद्देश्य के लिए आकलित 15 पैरामीटरों में से किसी अन्य पैरामीटर जैसी मद को शामिल किया जाना चाहिए। इस संबंध में यह नोट किया जाता है कि क्षति के सभी कारकों का विश्लेषण तिमाही आंकड़ों के रूप में उस सीमा तक किया गया है जिस सीमा तक वे अपने रिकार्डों में उपलब्ध हो।

58. आयातकों और प्रयोक्ताओं द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि क्षति विश्लेषण और गैर क्षतिकारी कीमत का निर्धारण करने के प्रयोजन के लिए घरेलू उद्योग द्वारा प्रभारित उत्पादन लागत में शुरुआती लागत का विश्लेषण नहीं किया गया है। यह भी उल्लेख किया गया है कि उत्पादन की प्रति इकाई लागत पर पहुंचने के लिए उन सभी लागतों पर विचार किया जाना चाहिए जो नये उद्योग के लिए अपरिवर्तनीय रूप से उच्च होगी। इस मामले की जांच की गई है और यह नोट किया जाता है कि क्षति मार्जिन और गैर क्षतिकारी कीमत का निर्धारण करने के प्रयोजन के लिए घरेलू उद्योग द्वारा अपनी उत्पादन लागत में प्रभारित शुरुआती लागत का संपूर्ण समायोजन किया गया है। इसके अतिरिक्त गैर क्षतिकारी कीमत का निर्धारण यथासंशोधित पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III के अनुरूप किया गया है जिसमें घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग के न्यून स्तर का पूरा ध्यान रखा गया है।

59. आयातकों और उपयोक्ताओं द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि इस जांच में जांच की अवधि के पश्चात की अवधि के निष्पादन की कोई संगतता नहीं है। यह भी उल्लेख किया गया है कि घरेलू उद्योग को क्षति कारित करने वाली प्रवृत्ति का विश्लेषण करने के लिए कोई आंकड़ों उपलब्ध नहीं है। इस मामले की जांच की गई है और यह उल्लेख किया जाता है कि पाटनरोधी नियमावली में जांच की अवधि के पश्चात की अवधि के लिए क्षति आंकड़ों की जांच करने की प्राधिकारी को कहीं मनाही नहीं है। तथापि पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का निर्धारण करने के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि के पश्चात की अवधि के आंकड़ों पर प्राधिकारी के सुसंगत व्यवहार के रूप में विचार नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, जांच की अवधि के पश्चात की अवधि के आंकड़ों को लेने का कारण यह है कि इससे यह आकलन करने एवं सुनिश्चित करने का एक साधन प्रदान करता है कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कंपनी थोड़े समय के लिए प्रचालनरत रही थी और इसमें आंकड़ों की विश्वसनीयता बनाई रखी थी यह भी उल्लेख किया जाता है कि घरेलू उद्योग का निष्पादन करने के लिए विश्लेषण की अल्प अवधि होने के कारण विभिन्न क्षति पैरा मीटरों के रूप में घरेलू उद्योग की प्रवृत्तियों का निर्धारण करने के लिए तिमाही वार विश्लेषण किया गया है।

60. आयातकों और प्रयोक्ताओं द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक केवल 2.5 से 5 मिमी तक की मोटाई के बोर्डों का ही उत्पादन करता है और आवेदकों द्वारा आपूर्ति किये गये माल का प्रयोग स्लेट विनिर्माताओं द्वारा नहीं किया जा सकता है। कुछ हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया है कि 2.1 मिमी और उससे से कम मोटाई के बोर्डों को विचाराधीन उत्पाद के विस्तार से अपवर्जित कर दिया जाना चाहिए। इस मामले की जांच की गई है और यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने केवल 2.1 मिमी तक की मोटाई युक्त संबद्ध वस्तु का उत्पादन किया है। सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्तुतिकरणों पर विचार करने और उनके प्रस्तुतिकरणों का विश्लेषण करने के पश्चात यह मानना उपयुक्त है कि 2 मिमी और उससे कम की मोटाई की संबद्ध वस्तु को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से अपवर्जित कर दिया जाना चाहिए क्योंकि घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के दौरान 2 मिमी और उससे कम की मोटाई के संबद्ध वस्तु का विनिर्माण नहीं किया है।

61. श्रीलंका के सहयोगकर्ता उत्पादकों और निर्यातकों के उत्पादन लागत में ब्याज लागत को जोड़ने के मुद्दे के संबंध में मैसर्स मेरबाक एमडीएफ लंका प्राइवेट लिमिटेड के प्रत्युत्तर के संबंध में उत्पादक निर्यातक मैसर्स मेरबाक द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि श्रीलंका के विनिमय नियंत्रण अधिनियम में यह प्रावधान है कि ऋण एलआईबीओआर+ 6 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि प्रत्युत्तर का पैरा ग यह दर्शाता है कि बैंक ऑफ सीलोन की वेबसाइट में निर्यातकों को अमेरिकी डालर के रूप में 5 से 7 प्रतिशत के बीच ऋण की शर्त है। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि मालिक की निधि पर अनुप्रयोगमूलक ब्याज या कोई अन्य अनुप्रयोगमूलक ब्याज का विचार करना लागत लेखाकरण में स्वीकार्य प्रक्रिया नहीं है इसके अतिरिक्त, यह भी तर्क दिया गया है कि डीजीएडी ने अपनी एक पिछली जांच में 9.5 मिलियन अमेरिकी डालर के ऋण पर 5.7 प्रतिशत

के ब्याज दर पर विचार किया था। एक अलग से प्राप्त ई-मेल में यह उल्लेख किया गया है कि प्राधिकारी ब्याज की दर को बैंक ऑफ श्रीलंका या अमेरिकी डालर ऋण के रूप में लागू करें। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेख किया गया है कि विनिर्मित सामान्य मूल्य के लिए उत्पादन लागत का अधिकतम 5 प्रतिशत ब्याज की दर पर विचार किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, उन्होंने प्राधिकारी का ध्यान इस ओर भी आकृष्ट किया कि धारक कंपनी ने मलेशिया में 1.5 प्रतिशत की दर से ऋण लिया है परंतु यह कंपनी श्रीलंका के वाणिज्यिक बैंक से 4.57 प्रतिशत पर ऋण प्राप्त करने में सक्षम थी। यह भी उल्लेख किया गया है कि बैंक ऑफ श्रीलंका निर्यातकों को अमेरिकी डालर के रूप में 5 से 7 प्रतिशत की दर पर ऋण प्रदान करती है।

62. यह भी नोट किया जाता है कि वर्तमान जांच श्रीलंका में कम्पनी के प्रचालनों के लिए विशिष्ट होने के कारण यह प्रशासिक है कि श्रीलंका में अमेरिकी डालर के रूप में वित्त पोषण की लागत पर विचार किया जाए न कि किसी अन्य ब्याज दर पर जिस पर मूल कंपनी पूंजी ऋण ले सकती है। प्राधिकारी के उपलब्ध कराये गये प्रकाशित आंकड़ों के आधार पर अमेरिकी डालर के ऋण पर प्रचलित ब्याज दरों पर विचार किया गया और ब्याज लागत में 7 प्रतिशत का समुचित समायोजन किया गया है जो मैसर्स मोरबाक के दोनों तर्कों अर्थात् एलआईबीओआर + 6 प्रतिशत संगत है अथवा अमेरिकी डालर ऋण के 5 से 7 प्रतिशत प्रकाशित सेंट्रल बैंक ऑफ सीलोन का प्रयोग किया जा सकता है, को कवर किया गया है।

63. मैसर्स मेरबाक द्वारा किये गये इस प्रस्तुतिकरण के संबंध में कि विचाराधीन उत्पाद और गैर विचाराधीन उत्पाद के बीच आबंटन संबंधित संयंत्र और मशीनरी के मूल्य के आधार पर करना चाहिए न कि उत्पादन मात्रा के आधार पर, यह नोट किया जाता है कि निर्यातक द्वारा स्थल पर किये गये सत्यापन के दौरान विचाराधीन उत्पाद और गैर विचाराधीन उत्पाद के बीच संयंत्र और मशीनरी के संबंध में संशोधित आंकड़े प्रस्तुत करने में कुछ त्रुटियां हुई हैं। इसलिए प्राधिकारी ने मूल्यह्रास प्रभारित करने के लिए, जैसा कि निर्यातक द्वारा शुरू में दावा किया गया था, उत्पादित मात्रा को आधार के रूप में माना है। चूंकि प्राधिकारी ने निर्यातक द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधित आंकड़ों की समीक्षा स्थल पर सत्यापन के समय कर ली है और स्वीकृत लागतकरण सिद्धांतों के रूप में त्रुटि सुधार करके संबंधित संयंत्र और मशीनरी के मूल्य के आधार पर विचाराधीन उत्पाद और गैर विचाराधीन के बीच परिसंपत्तियों के आबंटन पर पुनः विचार किया है। तदनुसार, विचाराधीन उत्पाद पर प्रभारित मूल्यह्रास दर अब निर्यातक द्वारा मूल रूप से दावाकृत 35 प्रतिशत के बजाय 28 प्रतिशत बनती है।

64. जांच की अवधि के पश्चात की अवधि के आंकड़ों पर विचार किये जाने के संबंध में इंडोनेशिया के सहयोगकर्ता उत्पादक और निर्यातक मैसर्स एसपीएफ द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी को यह प्रकटन करना चाहिए कि किस पत्र में पीओआई डाटा दायर किया गया है और वह जांच के किस स्तर पर है। इस मामले की जांच की गई है और यह नोट किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकारों के लिखित प्रस्तुतिकरणों और प्रत्युत्तर प्रस्तुतिकरणों के उपरांत घरेलू उद्योग से प्राधिकारी ने कुछ अतिरिक्त जानकारी मंगाई थी। जैसाकि इस अंतिम जांच परिणाम में अन्यत्र उल्लेख किया गया है, जांच की अवधि के पश्चात की अवधि के आंकड़ों को लेने का कारण यह है कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कंपनी अभी थोड़े समय से ही कार्यरत थी, इसलिए इससे उसके द्वारा अनुरक्षित आंकड़ों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने और आकलन करने का एक साधन उपलब्ध होता था। तथापि यह उल्लेख किया जाता है कि पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का निर्धारण करने के लिए पीओआई पश्चात आंकड़ों को प्राधिकारी की संगत प्रक्रिया के अनुसार विचार में नहीं लिया गया है।

65. एक उत्पादक निर्यातक मैसर्स एवरग्रीन (ईजेबी और ईएफबी) में प्रस्तुत किया है कि पाटन मार्जिन का निर्धारण करने और उसकी जांच करने के लिए पीसीएन अभिज्ञान का प्रयोग किया जाना चाहिए। उसी निर्यातक ने न्यून उत्सर्जन बोर्ड और मानक बोर्ड के बारे में भी बात की है। उसी उत्पादक निर्यातक ने न्यून उत्सर्जन बोर्ड बनाम मानक बोर्ड का निर्धारण करने के लिए ग्ल्यू टाइफ के बारे में भी चर्चा की है इसके अतिरिक्त उन्होंने सामान्य मूल्य की तुलना में निर्यात कीमत की सीमित भूमिका का उल्लेख किया यह भी कहा की निर्यातकों से पीसीएन बार लागत विवरण प्रदान करने को कहना अपेक्षित नहीं है। इस मामले पर सावधानी पूर्व विचार किया गया और यह उल्लेख किया जाता है कि इस मामले की सहयोगकर्ता उत्पादक निर्यातक की पाटन मार्जिन निर्धारण की जांच करने में प्रयोग किया गया है। जैसा कि प्राधिकारी ने अन्यत्र उल्लेख किया है, यह उल्लेख किया जाता है कि उक्त कंपनी उत्पाद कोडिंग प्रणाली का प्रयोग नहीं करती है और उत्पाद टाइप की पहचान बीजक/बिक्री संविदा पर किये गये विवरण के आधार पर की जाती है जहां ऐसे विवरण को नोट नहीं किया गया है। प्रत्युत्तर की जांच करने और आंकड़ों का स्थल पर जाकर सत्यापन करने के दौरान यह नोट किया गया कि घरेलू बाजार में उत्पादित या बेची गई वस्तुओं या भारत को निर्यातित वस्तुओं के बीच वास्तविक/तकनीकी/रसायनिक गुण धर्मों के अनुरूप कोई अंतर नहीं है। प्राधिकारी पुनः नोट करते हैं कि निर्यातक द्वारा दावा की गई प्रक्रिया के अनुसार संबद्ध वस्तु (न्यून उत्सर्जन बोर्ड सहित) संबद्ध वस्तु की बिक्री कीमत या उत्पादन लागत में कोई प्रवृत्ति नहीं दिखी। प्रत्येक प्रकार या पीसीएन के लिए लागत, बिक्री कीमत और लाभ प्रदायकता ने विभिन्नता के लिए कंपनी द्वारा साक्ष्य सहित कुछ भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। इसके अतिरिक्त, संबद्ध देशों के अन्य उत्पादक निर्यातकों तथा घरेलू उद्योग सहित किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने पाटन मार्जिन का निर्धारण पीसीएन के आधार पर करने की वांछनीयता के बारे में कोई टिप्पणी अथवा जानकारी नहीं दी गई है। इस तर्क में संबंध में की सामान्य मूल्य का परिकलन करने में लागत की निर्यात कीमत की तुलना में कम भूमिका होती है यह उल्लेख किया जाता है कि सामान्य मूल्य का निर्धारण करने में उसकी जरूरत होती है क्योंकि व्यापार जांच का सामान्य अनुक्रम बिक्री की तुलना उत्पादन लागत के साथ करके की जाती है। दोनों समूह की कंपनियों अर्थात् ईएफबी और ईजेबी के लिए एक शुल्क के संबंध में यह उल्लेख किया जाता है कि प्राधिकारी ने एक शुल्क का निर्धारण प्राधिकारी की संगत परम्परा के अनुरूप किया गया है क्योंकि दोनों कंपनियां संबद्ध कंपनियां हैं।

66. मैसर्स एवरग्रीन (ईजेबी और ईएफबी) ने प्रस्तुत किया है कि संबद्ध वस्तु के उपभोक्ताओं की संख्या कम है और इन उपभोक्ताओं के हितों का समाधान करने के लिए संदर्भ कीमत आधार पर शुल्क उपयुक्त होगा। मामले की जांच की गई और मामले के तथ्यों तथा सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये प्रस्तुतिकरणों को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी संदर्भ कीमत आधार पर पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित करने की सिफारिश करना उपयुक्त समझते हैं।

67. मैसर्स एवरग्रीन (ईजेबी और ईएफबी) ने प्रस्तुत किया है कि प्राधिकारी को एक उद्देश्य परक जांच करनी चाहिए और निर्दिष्ट प्राधिकारी इस मामले की जांच पक्षपात रहित ढंग से, किसी भी हितबद्ध पक्षकार या समूह के हित का समर्थन किये बिना करें। पुनः यह प्रस्तुत किया गया है कि सभी पैरा 15 पैरामीटरों में क्षति नहीं है। इस मामले की जांच की गई है और घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना की जांच के आधार पर यह उल्लेख किया जाता है कि घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से भारत में आयातों का पाटन होने के कारण कीमत अधोरदन तथा कीमत अधोबिक्रयन का सामना करना पड़ा इसके अतिरिक्त, सम्बद्ध देशों के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग पर पड़ने वाले कीमत प्रभाव की जांच की गई जिससे यह व्यक्त होता है कि घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि की सभी तिमाहियों के दौरान नुकसान सहन किया है। इसके अतिरिक्त घरेलू उद्योग ने क्षति अवधि के दौरान नकदी प्रवाह और निवेश पर नकारात्मक अर्जन सहन किया है।

68. मैसर्स एवरग्रीन (ईजेबी और ईएफबी) ने प्रस्तुत किया है कि घरेलू कीमत और आयात कीमत के बीच प्रतिलोम संबंध है और यह कि क्षति स्वयं सृजित की गई स्वयं अंशदायी है, यह क्षति कथित पाटन प्रक्रियाओं के कारण नहीं हुई है। इस संबंध में यह नोट किया जाता है कि सभी सहयोगकर्ता उत्पादकों और निर्यातकों के आंकड़ों के सत्यापन के आधार पर यह पाया गया है कि पाटन की प्रमात्रा बहुत अधिक रही है। इसके अतिरिक्त, कीमत अधोरदन और कीमत अधोबिक्रयन भी बहुत अधिक रहा जिसके कारण घरेलू उद्योग को वित्तीय क्षति हुई।

69. कारणात्मक संबंधों के संबंध में मामले की जांच की गई है और यद्यपि पिछले वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान आयात कीमत में मामूली सी वृद्धि हुई थी तथापि तथ्यों के आलोक में यह देखा गया कि उसी समय के दौरान सम्बद्ध वस्तु के लिए कच्चे माल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई और सम्बद्ध देशों से संबद्ध वस्तु की निर्यात कीमत कच्चे माल की कीमतों में इस वृद्धि को नहीं देखा गया जिससे प्रतीत होता है कि निर्यातकों द्वारा इस कीमत का अवशोषण कर लिया गया। इस तथ्य के संबंध में कि घरेलू उद्योग की कीमतें उसी अवधि के दौरान गिरावट की प्रवृत्ति प्रदर्शित करती हैं, इससे यह संकेत मिलता है कि घरेलू उद्योग को संबद्ध वस्तु की बिक्री उसी कीमत पर या उससे अधिक कीमत पर करना मुश्किल पड़ रहा था और इसलिए उसने अपनी बिक्री और बाजार हिस्से को बढ़ाने के लिए अपनी बिक्री कीमत कम कर दी। कुछ क्षति पैरा मीटरों में सुधार के संबंध में यह उल्लेख किया जाता है कि यह तथ्य कि एक या उससे अधिक पैरामीटरों में घरेलू उद्योग के निष्पादन से सुधार होने का आशय यह नहीं है कि घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई। यह तथ्य की घरेलू उद्योग ने सतत वित्तीय घाटा, निवेश पर और नकदी प्रवाह पर प्रतिलोम अर्जन, कीमत अधोरदन, कीमत अधोबिक्रयन सहन किया और यह तथ्य की घरेलू उद्योग के समक्ष भारी कीमत अधोबिक्रयन की स्थिति उत्पन्न हो गई, यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। इसके अतिरिक्त, यह उल्लेख किया जाता है कि प्राधिकारी को घरेलू उद्योग के समस्त निष्पादन के समग्र आकलन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचना अपेक्षित होता है कि क्या घरेलू उद्योग को क्षति हुई और यह क्षति केवल कुछ एक पैरामीटरों पर ही नहीं हुई थी।

ड. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन

अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये प्रस्तुतिकरण

70. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये प्रस्तुतिकरण संक्षेप में निम्नलिखित हैं:-

श्रीलंका उच्चायोग की ओर से किया गया प्रस्तुतिकरण

- उत्पादन लागत का परिकलन करने का तरीका एमडीएफ के विगत मामलों से असंगत है। इस मामले में संबंध में पक्षपात रहित युक्तिसंगतता के लिए परिकलन तरिके में एकरूपता बनाये रखना जरूरी है।

एवरग्रीन फाइबर बोर्ड बेरहाद (ई एफ बी), मलेशिया; एवरग्रीन फाइबर बोर्ड (जेबी) एसडीएन, बीएचडी (ईजेबी) मलेशिया और एवरग्रीन फाइबर बोर्ड (निलाई) एसडीएन.बीएचडी (ईएफएन) मलेशिया की ओर से किए गए प्रस्तुतिकरण

- सामान्य मूल्य का निर्धारण घरेलू उद्योग द्वारा कच्चे माल की उच्च खपत मानकों और उपयोगिता के आधार पर करना अनुचित है जबकि कच्चे माल के लिए खपत मानक और उपयोगिता निर्यातकों के लिए बहुत कम है।
- दो पृथक विधिक निकायों के लिए एकल पाटन मार्जिन का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। प्राधिकारी को चाहिए कि वह अलग-अलग निर्यातकों के लिए अलग-अलग पाटन मार्जिन का निर्धारण करें।
- ईजेबी के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण किया गया है तथापि सामान्य मूल्य का निर्धारण निर्यातक द्वारा प्रदान कराई गई जानकारी के आधार पर, यदि यह जानकारी उपलब्ध है तो, किया जाना चाहिए। निर्यातक ने सभी जानकारी प्रदान करा दी है।

मैसर्स पीटी.मसारी द्विसेपार्कट फाइबर, इंडोनेशिया तथा मैसर्स पीटी.सुमाटेरा प्राइमा फाइबर बोर्ड (एसपीएफ), इंडोनेशिया की ओर से किया गया प्रस्तुतिकरण

- स्थानापन्न देश का चयन: प्राधिकारी बाजार अर्थव्यवस्था तृतीय देश का चयन करने में अनुबंध-1 के पैराग्राफ 7 के अंतर्गत यथानिर्धारित समूचित प्रक्रिया का अनुपालन करने में अक्षम रहे हैं। इस प्रक्रिया के अंतर्गत घरेलू उद्योग से यह अपेक्षा की जाती है कि वह प्राधिकारी को जांच शुरुआत अधिसूचना में ऐसा चयन करने के प्रयोजन से उत्पादकों के नाम और पर्याप्त साक्ष्य प्रदान करायेगा। प्रस्तावित तीन देशों में से

समुचित बाजार अर्थव्यवस्था तृतीय देश का चयन करने के लिये न तो घरेलू उद्योग ने कोई सामग्री अथवा साक्ष्य उपलब्ध कराया न ही प्राधिकारी ने कोई प्रयास किया। समुचित जानकारी प्राप्त करने के लिए प्राधिकारी ने कोई भी प्रयास नहीं किया। इसके अतिरिक्त प्राधिकारी यह निर्धारित करने में असफल रहे कि, पैराग्राफ 7 के अंतर्गत कानूनी प्रतिबद्धताओं के बावजूद, वह पक्षकारों को तृतीय देश बाजार अर्थव्यवस्था अथवा स्थानापन्न देश का चयन करने के बारे में बिना किसी तर्क संगत कारण के हुए विलम्ब की जानकारी जांच के पक्षकारों को प्रदान नहीं करा सके। आवेदक संबद्ध वस्तु के उत्पादन में अंतर्गस्त कई सामान अर्थव्यवस्थाओं का पूर्ण ज्ञान होने के बावजूद भी यह निर्धारित नहीं कर पाया कि स्थानापन्न देश के रूप में किस देश का प्रस्ताव किया जाए और उनकी वर्तमान जांच में प्रतिभागिता की जाए।

- निर्यात कीमत का समायोजन: जांच शुरुआत अधिसूचना में प्राधिकारी ने निर्यातों की फैक्टरी बाह्य कीमत का परिकलन करने के लिए समुंद्री भाड़ा, सामुद्रिक बीमा, प्रलेखन प्रभार, स्वच्छता प्रभार और प्रकटीकरण प्रभार पर विचार किया है परंतु याचिका में आवेदनकर्ता ने इसके कमीशन पर भी विचार किया है। इस संबंध में प्राधिकारी को जांच शुरुआत प्रयोजन के लिए प्रयोग की गई अंतिम निर्यात कीमत प्रदान करानी चाहिए। इसके अतिरिक्त आवेदक द्वारा प्रभारित कमीशन बहुत अधिक है। अधिकांश मामलों में एफओबी कीमत के एक प्रतिशत के रूप में कमीशन पर विचार किया जाता है।

घरेलू उद्योग की ओर से किये गये प्रस्तुतिकरण

- जहां तक इस तर्क का संबंध है कि प्राधिकारी समुचित बाजार अर्थव्यवस्था तृतीय देश का चयन करने में अनुबंध-1 के पैरा 7 के अंतर्गत उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करने में असफल रहे हैं, यह उल्लेख किया जाता है कि प्राधिकारी द्वारा आवेदन के पैरा 7 के स्तर तक अभी पहुंचा भी नहीं गया है। आवेदनकर्ता प्रस्तुत करते हैं कि चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था तृतीय देश में निर्मित मूल्य अथवा कीमत के आधार पर इस कारण से नहीं किया जा सकता है कि संगत जानकारी आवेदक के पास उपलब्ध नहीं है। यह नोट किया जाता है कि यह सामान्य मूल्य "समान वस्तु के लिए व्यापार के सामान्य अनुक्रम में जब यह ऐसी बाजार अर्थव्यवस्था तृतीय देश में खपत के लिए हो, तुलनीय कीमत होना चाहिए"। इस आधार पर सामान्य मूल्य पर पहुंचने के लिए प्राधिकारी को ऐसे तृतीय देश में किसी सहयोगकर्ता उत्पादक द्वारा की गई समस्त घरेलू बिक्री के संबंध में व्यापक सत्यापन योग्य एवं संपूर्ण जानकारी तथा इसकी उत्पादन लागत एवं इससे संबंधित अन्य सभी सूचनाओं एवं साक्ष्यों (व्यापार के सामान्य अनुक्रम में समस्त जानकारी सहित) की जानकारी होना अपेक्षित है। करार के अनुच्छेद 2.4 के अंतर्गत निर्धारित निष्पक्ष तुलना के सिद्धांत भी इस बारे में संगत हैं। आवेदनकर्ता बाजार अर्थव्यवस्था तृतीय देश में किसी उत्पादक से ऐसी जानकारी प्राप्त करने में सक्षम नहीं हुए हैं।
- आवेदन कर्ता प्रस्तुत करते हैं कि चीन जन.गण. के लिए भारत एक समुचित स्थानापन्न देश है। भारत को स्थानापन्न देश के रूप में मानने के परिणामस्वरूप न केवल परिशुद्ध एवं यथार्थ जानकारी प्राप्त होगी बल्कि यह विचार करने के लिए तथ्यपरक कोई आधार नहीं है कि भारत एक समुचित स्थानापन्न देश नहीं हो सकता है। अन्य जांच कर्ता प्राधिकारियों द्वारा भी भारत को एक समुचित स्थानापन्न देश के रूप में माना गया है। चीन में सामान्य मूल्य का निर्धारण उपरोक्त किसी एक आधार पर किया जा सकता है। इस प्रकार चीन में सामान्य मूल्य का निर्धारण (क) भारत में कीमत, और (ख) भारत में उत्पादन लागत का विधिवत समायोजन करके, जिसमें बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय तथा लाभ भी शामिल है, किया जा सकता है। तदनुसार सामान्य मूल्य का निर्धारण भारत में, इस तथ्य के मद्देनजर की बिक्री कीमत घाटा कराने वाली कीमत है, का विधिवत समायोजन करके, उत्पादन लागत के आधार पर किया जा सकता है।
- इसके अतिरिक्त, आवेदन कर्ता ने नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8 का उल्लेख किया है जिसमें प्रावधान है कि प्राधिकारी यह जांच करेंगे कि क्या चीन में बाजार अर्थव्यवस्था माहौल में प्रचालन उत्पाद कर रहा है अथवा उत्पादक कर रहे हैं। प्राधिकारी को इस संबंध में संबंधित पक्षकारों को पर्याप्त अवसर प्रदान करना अपेक्षित होता है। केवल इसके पश्चात ही प्राधिकारी पैरा 7 के अनुप्रयोग पर विचार कर सकते हैं और केवल तभी स्थानापन्न देश का प्रश्न सुजित होगा। इस स्तर पर ऐसे स्थानापन्न देश से सूचना का आशय प्राधिकारी की ओर से यह प्रकल्पना होगी की चीन के निर्यातक, किसी भी हाल में, अपने उत्पाद अथवा कंपनियों के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था दर्जे का दावा नहीं कर सकेंगे।
- जहां तक इस तर्क का संबंध है कि जांच शुरुआत अधिसूचना में निर्यात कीमत के समायोजन में कमीशन को शामिल नहीं किया गया था, जबकि आवेदन कर्ता ने आवेदन में कमीशन के आधार पर समायोजन करने का दावा किया है; निर्दिष्ट प्राधिकारी को आवेदक द्वारा किये गये सभी दावे स्वीकार कर लेने चाहिए; कमीशन के कारण दावे को अस्वीकार करने से पाटन मार्जिन में कोई खास अंतर नहीं आयेगा। आवेदन में पाटन में प्रथमदृष्टया पर्याप्त साक्ष्य होने चाहिए।
- आवेदनकर्ता को ज्ञात सूचना के अनुसार संबद्ध देश में विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करने में कई उत्पादक लगे हुए हैं। किसी प्रत्युत्तर को स्वीकार करने से पहले आवेदनकर्ता प्राधिकारी से अनुरोध करता है कि वह इन हितबद्ध पक्षकारों द्वारा भारतीय सीमा शुल्क आंकड़ों के संबंध में किये गये दावे की दोबारा जांच कर ले। कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि के बावजूद स्थिर आयात कीमत पाटन का स्पष्ट साक्ष्य है। यह देखा जा सकता है कि इनपुट लागतों में भारी वृद्धि हुई है। यदि आयात कीमतों का समायोजन इन इनपुट लागतों में वृद्धि के साथ किया जाता है तो यह देखा जायेगा कि आयात कीमतों में भारी गिरावट आयी है अर्थात् लागत समायोजित आयात कीमतें अवधि के साथ-साथ भारी गिरावट प्रदर्शित करती है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि पाटन में समय के साथ-साथ तीव्र बढ़ोतरी हुई है।

- मैसर्स एवर ग्रीन फायर बोर्ड वेरहाद (ईएफबी)की भारत में मैसर्स एवर ग्रीन फायर बोर्ड (जेबी) एसडीएन.वेरहाद (ईजेबी) नामक एक अनुषंगी कंपनी है जिसने प्रश्नावली का प्रतिउत्तर दायर किया है। तथापि एक अन्य ग्रुप कंपनी, मैसर्स एवर ग्रीन फायर बोर्ड (निलाई) एसडीएन. बीएचडी. है जो घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तु का उत्पादन एवं बिक्री करती है, ने प्रश्नावली का प्रतिउत्तर दायर नहीं किया है इसलिए एवर ग्रीन के प्रतिउत्तर को अस्वीकार कर देना चाहिए।
- प्राधिकारी सामान्य मूल्य का निर्धारण घरेलू कीमतों के आधार पर तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक निर्यातक यह न स्थापित कर दे कि यह निर्यात “व्यापार के सामान्य अनुक्रम” में किये गये हैं। क्योंकि निर्यातकों द्वारा ऐसी किसी जानकारी/साक्ष्य का प्रेषण नहीं किया गया है इसलिए प्रश्नावली के प्रतिउत्तर को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए।

प्राधिकारी द्वारा जांच

71. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि आवेदनकर्ता घरेलू उद्योग को उसके पास तर्कसंगत रूप से उपलब्ध समस्त जानकारी प्रदान कर देना अपेक्षित होता है और वर्तमान मामले में जांच की शुरुआत को न्यायोचित ठहराने के लिए पर्याप्त जानकारी उपलब्ध कराई गई थी।

72. जहां तक इस मुद्दे का सवाल है कि सामान्य मूल्य का निर्धारण घरेलू उद्योग के कच्चे माल के उच्च खपत मानकों और उपयोगिता के आधार पर गलत ढंग से की गई जबकि निर्यातकों के लिए कच्चे माल और उपयोगिता के खपत मानक बहुत न्यून हैं इसलिए ऐसा करना गलत है। जांच शुरुआत अधिसूचना में रिकार्ड किये गये के अनुसार आवेदनकर्ता ने सामान्य मूल्य का आकलन संबद्ध देशों ने विनिर्मित सामान्य मूल्य अभिगम पर विचार करते हुए किया है। इस उद्देश्य के लिए इसने विदेशी उत्पादकों के उत्पादन लागत का आकलन ऐसी जानकारी को अपनाकर किया है जो तर्क संगत रूप से और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। प्राधिकारी ने इस जांच की शुरुआत करने के प्रयोजन के लिए संबद्ध देशों ने संबद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य पर विचार प्रथम दृष्टया विनिर्मित मूल्य के आधार पर किया है। तथापि प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध देशों के संबंधित निर्यातकों/उत्पादकों से यह उम्मीद की जाती है कि वे पाटन मार्जिन का समुचित निर्धारण करना सुलभ बनाने के लिए अपनी-अपनी निर्यातक प्रश्नावली का प्रतिउत्तर भरकर जांच प्रक्रिया में सहयोग करेंगे ताकि संबंधित प्रश्नावली प्रतिउत्तरों के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया जा सके। यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों (चीन जन.गण से छोड़कर) के कुछ गिने चुने निर्यातकों/उत्पादकों ने निर्यातक प्रश्नावलियों के प्रतिउत्तर भेजे हैं। प्राधिकारी द्वारा मांगी गई अतिरिक्त सूचना/आंकड़ों सहित निर्यातक प्रश्नावलियों के प्रतिउत्तरों की जांच करने पर यह स्पष्ट होता है कि पाटन मार्जिन अत्यधिक सकारात्मक है।

73. इस तर्क के संबंध में की प्राधिकारी समुचित बाजार अर्थव्यवस्था तृतीय देश का चयन करने में अनुबंध-1 के पैरा 7 के अंतर्गत निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन करने में अक्षम रहे हैं, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस मुद्दे को इंडोनेशिया के एक ऐसे निर्यातक द्वारा उठाया गया था जिसका संबंध इस मुद्दे से नहीं होना चाहिए था क्योंकि पैरा 7 उनपर किसी भी हाल में लागू नहीं होता है। चीन के किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने इस प्रश्न की मांग नहीं की है। ऐसा होने के बावजूद भी प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि आवेदक ने प्रस्तुत किया है कि चीन जन के लिए उनके द्वारा सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था तृतीय देश में कीमत या विनिर्मित मूल्य के आधार पर नहीं किया जा सका क्योंकि संगत जानकारी उनके पास उपलब्ध नहीं थी। यह नोट करने की जरूरत है कि संबंधित देश के विकास तथा प्रश्नाधीन उत्पाद के विकास के स्तर को ध्यान में रखते हुए समुचित बाजार अर्थव्यवस्था तुलनीय होनी चाहिए। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि उनके पास ऐसी कोई भरोसेमंद जानकारी नहीं है जो उन्हें इस जांच की शुरुआत के समय उपलब्ध कराई गई हो। उसके अतिरिक्त आवेदनकर्ता ने यह प्रस्तुत किया है कि चीन जन.गण के लिए भारत एक उपयुक्त स्थानापन्न देश है क्योंकि भारत को विगत में डबल्यू टी ओ सदस्यों द्वारा चीन जन गण के लिए एक स्थानापन्न देश के रूप में माना गया है बल्कि इसके परिणामस्वरूप विशुद्ध एवं परिशुद्ध जानकारी तक पहुंच उपलब्ध होगी। इस प्रकार सामान्य मूल्य का निर्धारण भारत में उत्पादन लागत का विधिवत समायोजन करने के आधार पर किया गया है। ऐसा करते समय प्राधिकारी ने आवेदनकर्ता के दावों का परिमार्जन कर दिया और इस प्रकार यह निर्धारित किया गया कि इस जांच की शुरुआत को न्यायोचित ठहराने के बारे में रिकार्ड में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है।

74. जहां तक जांच शुरुआत अधिसूचना के समय निर्यात कीमत का समायोजन करने का प्रश्न है, यह स्पष्ट किया जाता है कि प्राधिकारी ने समुद्री भाड़ा, सामुद्री बीमा, प्रलेखन प्रभार, स्वच्छता प्रभार और प्रकटीकरण प्रभार पर विचार किया है तथा संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु की फैक्टी बाह्य कीमत का आकलन करने के उद्देश्य के लिए कमीशन के संबंध में किये गये दावे को अस्वीकार कर दिया। अतः एफओबी कीमत के एक प्रतिशत की दर से कमीशन पर विचार करने, जैसा कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा सुझाव दिया गया था, के बजाय प्राधिकारी ने उसके लिए निर्यात कीमत में कोई समायोजन नहीं किया है।

75. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों को प्रश्नावलियां भेजी और यह सुझाव दिया कि वे संगत जानकारी निर्धारित स्वरूप और ढंग में उपलब्ध करायें। निम्नलिखित से प्रश्नावलियों के प्रतिउत्तर प्राप्त हुए थे:-

क्रम सं.	उत्पादक/निर्यातक का नाम
1	मै. मैग्ना-फोरमोस्ट एसडीएन, बीएचडी, मलेशिया
2	मै. मैशोनाइट काम्पोनेन्ट्स, आयरलैंड
3	मै. मेरबाक एमडीएफ लंका (प्राइवेट) लिमिटेड, श्रीलंका

4	मै. सेगामट पैनेल बोर्ड्स एस डी एन, बीएचडी, मलेशिया
5	मै. पीटी मसारी द्विसेपाकट इण्डोनेशिया
6	मै. पी.टी. सुमाटेरा प्राइमा फाइबर बोर्ड, इण्डोनेशिया
7	मै. एवरग्रीन फाइबर बोर्ड बेरहाद (ईएफबी), मलेशिया
8	मै. एवरग्रीन फाइबर बोर्ड (जे बी) एसडीएन, बीएचडी, मलेशिया
9	मै. एवरग्रीन फाइबर बोर्ड (निलाई) एस डी एन बीएचडी (ईएफएन) मलेशिया
10	मै. डाइकेन मिरि. एसडीएन. बीएचडी, मिरि सारावाक, मलेशिया

76. मैसर्स डाइकेन मिरि. एसडीएन. बीएचडी, मिरि सारावाक, मलेशिया ने उल्लेख किया कि उन्होंने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु का निर्यात नहीं किया है।

प्राधिकारी द्वारा चीन जन.गण के बारे में बाजार अर्थव्यवस्था दावे की जांच

77. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पिछले तीन वर्षों में चीन जन.गण को भारत तथा अन्य डबलू टी ओ सदस्यों द्वारा पाटन रोधी जांच में गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में माना गया है। चीन जन गण को निर्यातक देशों अथवा व्यक्तिगत निर्यातकों द्वारा पाटनरोधी नियमावली में दी गई शर्तों के अनुसार प्रकल्पना का खंडन करने के अध्यक्षीन गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में माना गया है।

78. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैराग्राफ 8 के अनुसार गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में प्रकल्पना का खंडन किया जा सकता है यदि चीन जन.गण से निर्यातक/उत्पादक पैराग्राफ 8 के उप-पैराग्राफ (3) में निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर पर्याप्त साक्ष्य एवं जानकारी प्रदान कराते हैं और इसके विपरीत तथ्य स्थापित करते हैं। चीन जनवादी गणराज्य के सहयोगकर्ता निर्यातकों/उत्पादकों से बाजार अर्थव्यवस्था उपचार प्रश्नावलियों के प्रतिउत्तर में पाटन रोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैराग्राफ 8 के उपपैरा (3) में यथाउल्लेखित आवश्यक साक्ष्य/पर्याप्त जानकारी उपलब्ध कराने की अपेक्षा की जाती है जिससे कि प्राधिकारी निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण कर सके कि क्या:

- चीन जन.गण में संबंधित फार्मों का यह निर्णय कि कीमत, लागत और इनपुट कच्चे माल सहित प्रौद्योगिकी की लागत, श्रम, उत्पादन, बिक्री और किये गये निवेश बाजार संकेतकों के प्रत्युत्तर में किये जाते हैं और उनमें मांग एवं आपूर्ति प्रदर्शित होती है तथा इस संबंध में राज्य का कोई विशेष हस्तक्षेप नहीं होता है और बड़े-बड़े इनपुटों की लागत पर्याप्त रूप से बाजार मूल्यों को प्रदर्शित करती है।
- इन फार्मों की उत्पादन लागत और वित्तीय स्थिति पिछली गैर बाजार अर्थव्यवस्था प्रणाली से प्राप्त, खासकर परिसंपत्तियों के मूल्यहास, अन्य पुनर्मूल्यांकन, विनिमय व्यापार तथा ऋणों की क्षतिपूर्ति के जरिए भुगतान के संबंध में भारी विकृतियों के अध्यक्षीन है।
- ये फर्म दिवालियापन और संपत्ति विधियों के अध्यक्षीन है जो विधिक निश्चितता और फर्मों के प्रचालन के लिए स्थायित्व की गारंटी देती है।
- विनिमय दर परिवर्तन बाजार दरों पर किया जाता है।

79. प्राधिकारी ने जांच शुरुआत अधिसूचना में यह संकेत दिया कि आवेदक ने दावा किया है कि चीन जन गण को गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में माना जाए और इस कारण चीन जन गण के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 और 8 के अनुसार किया जाना चाहिए। आवेदक ने प्रस्तुत किया है कि वे चीन जन गण के बारे में सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के प्रयोजन के लिए बाजार अर्थव्यवस्था तृतीय देश से सूचना तक पहुंच बनाने में सक्षम नहीं हो पाये हैं और उन्होंने तर्क दिया है कि चीन जन गण में सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए भारत को उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तृतीय देश के रूप में माना जा सकता है। प्राधिकारी ने चीन जन गण के सभी ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों को सूचित किया कि वे आवेदक के दावे की जांच पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 और 8 के आलोक में करने का प्रस्ताव करते हैं। अतः चीन जन गण से संबद्ध वस्तु के निर्यातकों/उत्पादकों से अनुरोध किया गया कि वे, अन्य बातों के साथ-साथ, पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8 के उपपैरा (3) में यथाउल्लेखित जरूरी सूचना/पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध कराये जिससे कि प्राधिकारी यह तथ्य पर विचार करने में समर्थ हो सके कि क्या चीन जन के सहयोगी निर्यातकों/उत्पादकों को बाजार अर्थव्यवस्था उपचार का दर्जा दिया जाए या नहीं।

80. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि प्राधिकारी द्वारा जारी जांच शुरुआत नोटिस के परिणाम स्वरूप चीन के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने प्रश्नावलियों, जिसमें बाजार अर्थव्यवस्था प्रश्नावलियों के प्रतिउत्तर भी शामिल थे, का प्रतिउत्तर नहीं दिया और इस प्रकार गैर बाजार अर्थव्यवस्था की प्रकल्पना का खंडन करने का अवसर नहीं प्रदान किया।

चीन के निर्यातकों/उत्पादकों के संबंध में सामान्य मूल्य का निर्धारण

81. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 में प्रावधान है कि:

गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था तृतीय देश में कीमत अथवा विनिर्मित मूल्य, अथवा ऐसे तृतीय देश से भारत सहित किसी अन्य देश को कीमत के आधार पर किया जायेगा अथवा जहां संभव न हो वहां किसी अन्य तर्क संगत आधार पर, भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तविक रूप में संदत्त अथवा प्रदत्त कीमत सहित विधिवत समायोजित कीमत जिसमें तर्क संगत लाभ मार्जिन को शामिल किया जा सके, के आधार पर किया जायेगा। निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा तर्क संगत ढंग से, संबंधित देश और प्रश्नाधीन उत्पाद के विकास के स्तर को ध्यान में रखते हुए एक समुचित बाजार अर्थव्यवस्था तृतीय देश का चयन किया जायेगा और चयन के समय उपलब्ध कराई गई किसी भरोसेमंद सूचना पर समुचित ध्यान दिया जायेगा। निश्चित समयसीमा के अंदर, जहां आवश्यक हो, किसी अन्य बाजार अर्थव्यवस्था तृतीय देश के बारे में किसी समान मामले में की गई जांच को भी ध्यान रखा जायेगा। जांचकर्ता पक्षकारों को बिना किसी अनुचित विलम्ब के बाजार अर्थव्यवस्था तृतीय देश के उपर्युक्त चयन के बारे में सूचना दी जायेगी और उन्हें अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए तर्क संगत समय प्रदान किया जायेगा।

82. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तु के संबंध में विशेष रूप से विचार करते हुए किसी ऐसे बाजार अर्थव्यवस्था तृतीय देश की कीमत अथवा विनिर्मित मूल्य के बारे में पर्याप्त सूचना अथवा साक्ष्य रिकार्ड में उपलब्ध नहीं है जिसका स्तर चीन जन गण के विकास से तुलनीय हो। अतः, उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी चीन जन गण के निर्यातकों/उत्पादकों के बारे में सामान्य मूल्य का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के द्वितीय परंतुक में दी गई शर्तों के अनुरूप तर्क संगत आधार पर करते हैं। तदनुसार विचाराधीन उत्पाद के फैक्ट्री बाह्य सामान का निर्धारण विधिवत समायोजित उत्पाद की विनिर्मित लागत के आधार पर किया गया है। सामान्य मूल्य का निर्माण निम्नलिखित क्रियापद्धति का अनुपालन करके किया गया।

चीन जन गण के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए अपनाई गई क्रियापद्धति

83. तदनुसार, प्राधिकारी ने चीन जन गण में उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण निम्नलिखित के आधार पर किया है:-

- घरेलू उद्योग द्वारा यथाअधिप्राप्त इनपुट लागत
- गैर क्षतिकारी कीमत में विचार किये गये के अनुरूप घरेलू उद्योग के कच्चे माल के खपत के कारगर मानक
- घरेलू उद्योग की उपयोगिता लागत और परिवर्तन लागत जैसा कि एन आईपी लागत में विचार किया गया।
- उपर्युक्त के विचार सीएनवी के लिए कुल उत्पादन लागत पर पहुंचने के पश्चात, 5 प्रतिशत लाभ की अनुमति दी गई है।

84. इस तरह निर्धारित सामान्य मूल्य का उल्लेख पाटन मार्जिन को दर्शाने वाली तालिका में किया गया है:-

इंडोनेशिया, मलेशिया और श्रीलंका के बारे में सामान्य मूल्य –प्रत्युत्तर दाता निर्यातक

85. मलेशिया के निम्नलिखित कंपनियों ने प्रश्नावली के प्रत्युत्तर प्रस्तुत किये थे।

क्रम सं.	उत्पादक/निर्यातक का नाम
1	मै. मैग्ना-फोरमोस्ट एसडीएन, बीएचडी, मलेशिया
2	मै. मैशोनाइट काम्पोनेन्ट्स, आयरलैंड
3	मै. मेरबाक एमडीएफ लंका (प्राइवेट) लिमिटेड, श्रीलंका
4	मै. सेगामट पैनेल बोर्ड्स एस डी एन, बीएचडी, मलेशिया
5	मै. पीटी मसारी द्विसेपाकट इण्डोनेशिया
6	मै. पी.टी. सुमाटेरा प्राइमा फाइबर बोर्ड, इण्डोनेशिया
7	मै. एवरग्रीन फाइबर बोर्ड बेरहाद (ईएफबी), मलेशिया
8	मै. एवरग्रीन फाइबर बोर्ड (जे बी) एसडीएन, बीएचडी, मलेशिया
9	मै. एवरग्रीन फाइबर बोर्ड (निलाई) एस डी एन बीएचडी (ईएफएन) मलेशिया
10	मै. डाइकेन मिरि. एसडीएन. बीएचडी, मिरि सारावाक, मलेशिया

86. मैसर्स मैग्ना-फोरमोस्ट एसडीएन, और मैशोनाइट काम्पोनेन्ट्स, आयरलैंड ने उल्लेख किया है कि उन्होंने संबद्ध वस्तु का भारत को निर्यात नहीं किया है और यह कि उन्होंने केवल डोर स्किन्स का ही निर्यात किया है। चूंकि यह पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है कि डोर स्किन्स विचाराधीन उत्पाद के भाग नहीं हैं इसलिए उनके आंकड़ों की जांच उनके मामले में व्यक्तिगत पाटन मार्जिन का निर्धारण करने के लिए की गई है। प्रारंभिक जांच परिणाम के उपरांत मैसर्स पी टी मसारी द्विसेपाकट इण्डोनेशिया ने जांच शुरूआत के पश्चात उनके द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना का सत्यापन करने की सम्मति नहीं दी गई और उनके द्वारा प्रस्तुत जानकारी असत्यापित ही रह गई।

87. सहयोगकर्ता उत्पादकों और निर्यातकों का सत्यापन करने के पश्चात सभी संबंधित उत्पादकों और निर्यातकों को अपनी टिप्पणी देने के लिए सत्यापन रिपोर्ट जारी की गई। प्राधिकारी अपने प्रकटन विवरण में पाटन मार्जिन का निर्धारण करने के संबंध में उनकी टिप्पणियों पर विचार किया। प्रकटन विवरण जारी करने के पश्चात सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण करने के संबंध में विवरण सभी संबंधित उत्पादकों और निर्यातकों को भेजा गया। इसके अतिरिक्त पाटन मार्जिन का निर्धारण करने संबंधी वर्किंग, जिसमें एक्सेल शीट में वर्किंग भी शामिल थी, सभी संबंधित निर्यातकों को उनकी टिप्पणियों के लिए दी गई। इन वर्किंग्स को उन निर्यातकों के समक्ष भी स्पष्ट किया गया जो इसका स्पष्टीकरण चाहते थे। उन संबंधित निर्यातकों की टिप्पणियों, जिनका प्रकटन विवरण में उल्लेख है, पर पाटन मार्जिन का निर्धारण करते समय ध्यान में रखा गया जिसका विवरण निम्नलिखित है।

सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए प्रत्युत्तरदाता निर्यातकों के लिए अपनाई गई सामान्य क्रियापद्धति

88. प्राधिकारी ने उन सहयोगकर्ता निर्यातकों/उत्पादकों के बारे में व्यक्तिगत पाटन मार्जिन का निर्धारण किया जिन्होंने अपेक्षित सूचना उपलब्ध कराई थी। सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए अपनाई गई सामान्य क्रियापद्धति निम्नलिखित है:

89. पहले यह देखा गया कि क्या प्रत्युत्तरदाता निर्यातक/उत्पादक द्वारा संबद्ध वस्तु की घरेलू बिक्री उनकी घरेलू बाजार में प्रतिनिधित्व करती है या नहीं और क्या यह उनके घरेलू बिक्री कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए अनुमति देने हेतु व्यवहार्य है और क्या व्यापार जांच के सामान्य अनुक्रम में प्राधिकारी द्वारा मांगे गये तथा प्रत्युत्तरदाता द्वारा प्रदान कराये गये आंकड़ों के अनुरूप संतुष्ट होते हैं या नहीं। जहां कहीं प्रतिवादियों ने उनकी गृह बाजारों में सामान्य वस्तु की बिक्री के संयवहार—वार आंकड़े प्रदान कराये हैं वहां व्यापार परीक्षण के सामान्य अनुक्रम तथा पर्याप्तता जांच के पश्चात, अतिरिक्त जांच एवं सत्यापन के अध्वधीन, संबद्ध वस्तु के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण उनके द्वारा प्रदान कराई गई सूचना पर विश्वास करते हुए किया गया है।

90. ओसीटी जांच करने के लिए उत्पादन लागत की जांच निर्यातक/उत्पादक के प्रश्नावली प्रतिउत्तर के संदर्भ में तथा प्राधिकारी द्वारा मांगी गई अतिरिक्त जानकारी के अनुरूप की गई। इस जानकारी का संबद्ध देशों के सहयोगकर्ता उत्पादकों और निर्यातकों का स्थल पर जाकर सत्यापन करके और भी अधिक सत्यापन किया गया। दर्ज की गई सूचना/आंकड़ों में विसंगतियां प्राप्त होने पर प्राधिकारी ने रिकार्ड में उपलब्ध सर्वोत्तम जानकारी के आधार पर वस्तु का निर्माण करने और उनकी बिक्री करने के लिए लागत का निर्माण किया है।

91. यदि कहीं घरेलू बिक्री अथवा पर्याप्त घरेलू बिक्रियां उपलब्ध नहीं होती हैं तो प्राधिकारी द्वारा सामान्य मूल्य का निर्धारण पाटन रोधी नियमावली के नियम 6 (8) के अनुसार 'उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया है।

92. उनके प्रत्युत्तर में यह नोट किया गया कि प्रत्युत्तर दाता उत्पादकों एवं निर्यातकों ने संबद्ध वस्तु की उनकी घरेलू बाजारों में बिक्री का संयवहार—वार विवरण तथा भारत को निर्यात का विवरण प्रदान कराया है। इसके अतिरिक्त, सभी घरेलू बिक्री लेनदेनों की जांच संबंधित वस्तु के उत्पादन की लागत/विनिर्मित लागत के संदर्भ में यह निर्धारित करने के लिए की गई कि क्या घरेलू बिक्रियां व्यापार के सामान्य अनुक्रम में थी। यह भी देखा गया कि क्या क्षति करने वाले लेन—देन कुल बिक्री का 20 प्रतिशत थे या नहीं। जहां कहीं लाभ प्रदायक बिक्री लेन—देने को कुल बिक्रियों से 80 प्रतिशत से अधिक पाया गया वहां सभी घरेलू बिक्री की औसत भारित कीमत पर विचार किया गया। तथापि जहां कहीं लाभदायक बिक्रियों की मात्रा 80 प्रतिशत से कम पायी गई वहां लाभदायक घरेलू बिक्रियों की भारित औसत कीमत पर विचार किया गया।

इंडोनेशिया, मलेशिया और श्रीलंका के सहयोगकर्ता निर्यातकों/उत्पादकों के बारे में सामान्य मूल्य का निर्धारण

मैसर्स एवरग्रीन फाइबरबोर्ड वेरहाद (ईएफबी)

मैसर्स एवरग्रीन फाइबरबोर्ड (जेबी)एसडीएन.वेरहाद (ईजेबी)

93. यह नोट किया गया कि इस कंपनी का मलेशिया की ऐसी विभिन्न कंपनियों में शेयर धारिता है जो डाउन स्ट्रीम तथा अप स्ट्रीम उत्पादों में लगी हुई है। अपने प्रतिउत्तर में तथा सत्यापन के दौरान यह उल्लेख किया गया कि कंपनी अपने कच्चे माल अर्थात् लकड़ी के लट्टों तथा गोंद की खरीद क्रमशः *** और *** नामक संबंधित कंपनियों से करती है। उनके द्वारा बनाये गये पीसीएन के आधार पर उत्पादक और निर्यातक द्वारा दावा किया गया की समान पीसीएन वाली वस्तुओं को घरेलू बाजार में बेचा गया तथा निर्यात बाजारें समरूप हैं। तथापि कंपनी के प्रतिउत्तर की जांच करने पर यह नोट किया गया कि कंपनी उत्पाद कोडिंग प्रणाली का अनुपालन नहीं करती है तथा उत्पाद के प्रकार की समरूपता बीजक/बिक्री संविदा में दिये गये विवरण के आधार पर की जाती है परंतु ऐसा कोई भी विवरण नोट नहीं किया गया। प्रतिउत्तर की जांच करने के दौरान तथा आंकड़ों का स्थल पर सत्यापन के दौरान यह नोट किया गया कि घरेलू बाजार में बेची गई अथवा उत्पादन की गई वस्तुओं अथवा भारत में निर्यातित वस्तुओं के बीच कोई वास्तविक/तकनीकी/रसायनिक गुण धर्म संबंधी अंतर नहीं है। प्राधिकारी ने पुनः यह नोट किया कि निर्यातक द्वारा दावा किये गये प्रक्रिया के अनुसार

किसी भी प्रवृत्ति को, चाहे वह उत्पादन लागत में हो अथवा संबद्ध वस्तु की बिक्री कीमत में, नोट नहीं किया गया। प्रत्येक प्रकार की अथवा पीसीएन की कीमतों, बिक्री कीमत और लाभप्रदायकता में अंतर के कारणों का कंपनी द्वारा कोई विस्तृत साक्ष्य नहीं दिया गया।

94. कंपनी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रश्नावली के प्रत्युत्तर का गहन अध्ययन किया गया। यह पाया गया कि प्रत्युत्तर दाता ने अपने प्रत्युत्तर के संगत परिशिष्टों में संबद्ध वस्तु की बिक्री कीमत और अन्य विवरण प्रदान कराये हैं। यह नोट किया गया कि मैसर्स एवरग्रीन फाइबर बोर्ड वेरहाद (ईएफबी) की मैसर्स एवरग्रीन फायरबोर्ड (जेबी) एसडीएन वेरहाद (ईजेबी) नामक एक अनुषंगी एक कंपनी है जिसने भी अपने प्रश्नावली का उत्तर दायर किया है। इसके अतिरिक्त यह भी नोट किया गया एक अन्य गुप्त कंपनी मैसर्स एवरग्रीन फाइबर बोर्ड है (निलाई) एसडीएन.बीएचडी है जो संबद्ध वस्तु का उत्पादन एवं घरेलू बाजार में बिक्री करती है परंतु इस कंपनी की ओर से प्रारंभ में कोई प्रत्युत्तर दायर नहीं किया गया। प्राधिकारी द्वारा किये गये परिप्रश्न के प्रत्युत्तर में यह स्पष्ट किया गया कि प्रत्युत्तर इस दायर नहीं किया गया क्योंकि कंपनी ने भारत को किसी तरह का निर्यात नहीं किया गया था। बाद में कंपनी ने अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर दिया।

95. कंपनी के वेबसाइट पर उपलब्ध प्रकाशित आंकड़ों से यह नोट किया जाता है कि कंपनी के कई संगत निकाय हैं जो संबद्ध वस्तु के उत्पादन से जुड़ी गतिविधियों जिनमें संबद्ध वस्तु के विनिर्माण के लिए अपेक्षित गोंद विनिर्माण, रोपण, विद्युत उत्पादन सहित, में जुड़ी हैं।

96. यह नोट किया गया कि कंपनी ने जांच की अवधि में संबद्ध वस्तु की *** एम³ घरेलू बिक्री की है। परिशिष्ट 1 के अनुसार कंपनी ने क्रेडिट लागत, बैंक प्रभार, अंतरदेशीय भाड़ा आदि के आधार पर समायोजन का दावा किया है जिसकी सूचना का सत्यापन करने के बाद अनुमति दे दी गई। सूचना के सत्यापन करने के बाद यह नोट किया गया कि कंपनी ने घरेलू बिक्रियों लाभ अर्जित किया है। इन परिस्थितियों ने प्राधिकारी ने घरेलू बिक्री के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है जिसका उल्लेख पाटन मार्जिन को दर्शाने वाली तालिका में किया गया है।

मैसर्स एवरग्रीन फाइबर बोर्ड (जेबी) एसडीएन वेरहाद (ईजेबी)

97. यह नोट किया गया कि इस कंपनी का मलेशिया की ऐसी विभिन्न कंपनियों में शेयर धारिता है जो डाउन स्ट्रीम तथा अप स्ट्रीम उत्पादों में लगी हुई है। सत्यापन के दौरान यह उल्लेख किया गया कि कंपनी अपने कच्चे माल अर्थात् लकड़ी के लट्टों तथा गोंद की खरीद क्रमशः *** और *** नामक संबंधित कंपनियों से करती है। उनके द्वारा बनाये गये पीसीएन के आधार पर उत्पादक और निर्यातक द्वारा दावा किया गया की समान पीसीएन वाली वस्तुओं को घरेलू बाजार में बेचा गया तथा निर्यात बाजारें समरूप हैं। तथापि कंपनी के प्रत्युत्तर की जांच करने पर यह नोट किया गया कि कंपनी उत्पाद कोडिंग प्रणाली का अनुपालन नहीं करती है तथा उत्पाद के प्रकार की समरूपता बीजक/बिक्री संविदा में दिये गये विवरण के आधार पर की जाती है परंतु ऐसा कोई भी विवरण नोट नहीं किया गया। प्रत्युत्तर की जांच करने के दौरान तथा आंकड़ों का स्थल पर सत्यापन के दौरान यह नोट किया गया कि घरेलू बाजार में बेची गई अथवा उत्पादन की गई वस्तुओं अथवा भारत में निर्यातित वस्तुओं के बीच कोई वास्तविक/तकनीकी/रसायनिक गुण धर्म संबंधी अंतर नहीं है। प्राधिकारी ने पुनः यह नोट किया कि निर्यातक द्वारा दावा किये गये प्रक्रिया के अनुसार किसी भी प्रवृत्ति को, चाहे वह उत्पादन लागत में हो अथवा संबद्ध वस्तु की बिक्री कीमत में, नोट नहीं किया गया। प्रत्येक प्रकार की अथवा पीसीएन की कीमतों, बिक्री कीमत और लाभप्रदायकता में अंतर के कारणों का कंपनी द्वारा कोई विस्तृत साक्ष्य नहीं दिया गया।

98. कंपनी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रश्नावली के प्रत्युत्तर का गहन अध्ययन किया गया। यह पाया गया कि प्रत्युत्तर दाता ने अपने प्रत्युत्तर के संगत परिशिष्टों में संबद्ध वस्तु की बिक्री कीमत और अन्य विवरण प्रदान कराये हैं। यह नोट किया गया कि मैसर्स एवरग्रीन फाइबर बोर्ड वेरहाद (ईएफबी) की मैसर्स एवरग्रीन फायरबोर्ड (जेबी) एसडीएन वेरहाद (ईजेबी) नामक एक अनुषंगी एक कंपनी है जिसने भी अपने प्रश्नावली का उत्तर दायर किया है। इसके अतिरिक्त यह भी नोट किया गया एक अन्य गुप्त कंपनी मैसर्स एवरग्रीन फाइबर बोर्ड है (निलाई) एसडीएन.बीएचडी है जो संबद्ध वस्तु का उत्पादन एवं घरेलू बाजार में बिक्री करती है परंतु इस कंपनी की ओर से प्रारंभ में कोई प्रत्युत्तर दायर नहीं किया गया। प्राधिकारी द्वारा किये गये परिप्रश्न के प्रत्युत्तर में यह स्पष्ट किया गया कि प्रत्युत्तर इस दायर नहीं किया गया क्योंकि कंपनी ने भारत को किसी तरह का निर्यात नहीं किया गया था। बाद में कंपनी ने अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर दिया।

99. कंपनी के वेबसाइट पर उपलब्ध प्रकाशित आंकड़ों से यह नोट किया जाता है कि कंपनी के कई संगत निकाय हैं जो संबद्ध वस्तु के उत्पादन से जुड़ी गतिविधियों जिनमें संबद्ध वस्तु के विनिर्माण के लिए अपेक्षित गोंद विनिर्माण, रोपण, विद्युत उत्पादन सहित, में जुड़ी हैं।

100. यह नोट किया गया कि कंपनी ने जांच की अवधि में संबद्ध वस्तु की *** एम³ घरेलू बिक्री की है। परिशिष्ट 1 के अनुसार कंपनी ने क्रेडिट लागत, बैंक प्रभार, अंतरदेशीय भाड़ा आदि के आधार पर समायोजन का दावा किया है जिसकी सूचना का सत्यापन करने के बाद अनुमति दे दी गई। इन परिस्थितियों ने प्राधिकारी ने घरेलू बिक्री के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है जिसका उल्लेख पाटन मार्जिन को दर्शाने वाली तालिका में किया गया है।

101. इस तथ्य के आलोक में की कंपनी एक बार किसी अन्य कंपनी की अनुषंगी कंपनी रही है, इसलिए प्राधिकारी ने दोनों प्रत्युत्तर दाताओं अर्थात् मैसर्स एवरग्रीन फाइबर बोर्ड वेरहाद और मैसर्स एवरग्रीन फाइबर बोर्ड (जेबी) एसडीएन, वेरहाद के लिए एकल पाटन मार्जिन का निर्धारण किया।

मैसर्स सेगामट पैनल बोर्ड्स एसडीएन पीएचडी

102. निर्यातक के प्रत्युत्तर से यह नोट किया गया कि मैसर्स एसपीबी ने अपना उत्पादन मलेशिया में *** की शेयरधारिता निधि से अगस्त, 2002 से प्रारंभ किया था। उनके प्रत्युत्तर से पुनः यह नोट किया गया कि यह कंपनी सिंगापुर आधारित एक कंपनी मैसर्स *** की *** प्रतिशत वाली एक

अनुषंग कंपनी है। पुनः यह सूचित किया गया है कि उनका एमडीएफ संयंत्र के साथ-साथ एक पार्टिकल बोर्ड संयंत्र भी है। कंपनी द्वारा यह प्रस्तुत किया कि पार्टिकल बोर्ड संयंत्र अभी प्रारंभ होना है। कंपनी ने घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तु की *** सीबीएम बिक्री की है। कंपनी के प्रत्युत्तर का अध्ययन करने से यह नोट किया गया कि एसपीबी के 2.2 मिमी मोटाई से 6.00 मिमी मोटाई के पतले एमडीएफ का उत्पादन करती है।

103. कंपनी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रश्नावली प्रत्युत्तर का अध्ययन किया गया है। यह नोट किया गया कि कंपनी ने अपने घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तु की *** सीबीएम बिक्री की है। यह स्पष्ट किया गया कि घरेलू बाजार में उपर्युक्त संबद्ध वस्तु की बिक्री या तो फैक्टरी बाह्य कीमत पर की गई अथवा सुपुर्दगी आधार पर। सुपुर्दगी आधार के मामले में कंपनी को अंतरदेशीय भाड़े का भुगतान करना पड़ा। यह पाया गया कि प्रत्युत्तर दाता ने संबद्ध वस्तु की बिक्री कीमत तथा अन्य विवरण अपने प्रत्युत्तर के संगत परिशिष्टों में उपलब्ध कराया है। कंपनी द्वारा दायर किये गये प्रश्नावली प्रत्युत्तर तथा प्राधिकारी द्वारा मांगी गयी अतिरिक्त जानकारी/आंकड़ों की जांच से यह संकेत मिलता है कि कंपनी को गैर लागत मदों से प्रापण का अपवर्जन करने के पश्चात संबद्ध वस्तु की समग्र बिक्रियों पर वित्तीय घाटा हुआ है। प्राधिकारी द्वारा पूछे एक परिप्रश्न के प्रत्युत्तर में कंपनी ने स्पष्ट किया है कि संबद्ध वस्तु के लिए इसके घरेलू प्रचालनों से लाभ हो रहा है कि जबकि तृतीय देश (भारत के अलावा) को किये गये निर्यात से उच्चतर करभार के कारण नुकसान हुआ है। यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि कंपनी द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी का सत्यापन करने के पश्चात कंपनी को सत्यापन रिपोर्ट जारी की गई। सत्यापन के दौरान प्राधिकारी ने नोट किया कि कंपनी को इसके किसी संबद्ध पक्षकार द्वारा ब्याज रहित ऋण प्राप्त हुआ है। सत्यापन रिपोर्ट पर की गई अपनी टिप्पणी में कंपनी ने यह उल्लेख किया है कि की राष्ट्रीय ब्याज जिसे उनकी लेखा बहियों में प्रभारित नहीं किया गया है को उत्पादन लागत में नहीं गिना जाना चाहिए। कंपनी द्वारा प्रदान कराये गये प्रत्युत्तर की प्राधिकारी द्वारा पुनः जांच की गई और यह नोट किया गया कि उनकी लाभ प्रदायक घरेलू बिक्री मात्रा के रूप में 80 प्रतिशत से कम है। वैध सत्यापन तथा संबंधित कंपनियों से लिये गये उधार पर ब्याज का समायोजन करने के पश्चात कंपनी द्वारा दावा किये गये समायोजन को स्वीकार कर लिया गया। अतः कंपनी का सामान्य मूल्य घरेलू बिक्रियों अर्थात् कंपनी द्वारा यथापरिकलित लाभ प्रदायक घरेलू बिक्रियों को ध्यान में रखकर किया गया तथा उनका उल्लेख पाटन मार्जिन को दर्शाने वाली तालिका में किया गया है।

पीटी सुमाटेरा प्राइमा फाइबरबोर्ड

104. प्रत्युत्तर से यह नोट किया गया कि मैसर्स पीटी सुमाटेरा प्राइमा फाइबरबोर्ड (एसपीएफ) एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसका निगमन इंडोनेशिया के कंपनी कानून के अंतर्गत किया गया। यह कंपनी जे आई जेड सुदिर मान कैब. जकारता, इंडोनेशिया में स्थित है। यह नोट किया गया कि कंपनी ने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु की *** एम³ घरेलू बिक्री की गई। परिशिष्ट 1 के अनुसार कंपनी द्वारा क्रेडिट लागत, बैंक प्रभार, अंतरदेशीय भाड़ा आदि के संबंध में समायोजन का दावा किया गया जिसे सूचना का सत्यापन करने के पश्चात स्वीकार कर लिया गया। कंपनी द्वारा दिये गये प्रत्युत्तर से यह देखा गया कि कंपनी ने दावा किया है कि कंपनी द्वारा घरेलू बाजार में बेची गई वस्तु निर्यात की गई वस्तु के समान है तथा उनका विनिर्देशन एक जैसा है अतः दोनों बाजारों में कीमतों की तुलना प्रत्येक उत्पादन कोर्ड के लिए की जानी चाहिए। कंपनी द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया कि निर्यातक एसपीएफ 1.5 मिमी की मोटाई से कम मोटाई वाले बोर्डों का उत्पादन करने में सक्षम है। तथापि, जांच दल द्वारा उसी मोटाई के बोर्ड की बिक्री के संबंध में पूछे गये एक परिप्रश्न के उत्तर में उन्होंने ने उत्तर दिया कि उन्होंने जांच अवधि के दौरान भारत को 2.3 मिमी मोटाई से कम की मोटाई की किसी वस्तु की बिक्री नहीं की है और न ही इसकी बिक्री घरेलू बाजार में की गई और आज की तारीख के अनुसार इससे कम की मोटाई वाले उत्पाद की बिक्री भारत को अभी भी की जानी है।

105. कंपनी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रश्नावली प्रत्युत्तर का अध्ययन किया गया। यह पाया कि प्रत्युत्तर दाता ने संबद्ध वस्तु की बिक्री कीमत तथा अन्य विवरण अपने प्रत्युत्तर से संगत परिशिष्टों में उपलब्ध कराई है। तथापि कंपनी ने कोड- बार परिशिष्ट 8 ख आंकड़े नहीं दिये हैं। कंपनी के प्रस्तुतिकरणों की जांच करने के पश्चात कुछ विसंगतियां नोट की गईं और कंपनी को सुझाव दिया गया कि वह उन्हें स्पष्ट करें। यद्यपि आंकड़ों में कुछ विसंगतियां अभी मौजूद हैं तथापि कंपनी द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना/आंकड़ों को स्वीकार कर लिया गया है। यह देखा जाता है कि घरेलू बिक्री लेन-देन अत्यधिक घाटा करने वाले हैं और इस कारण सामान्य मूल्य का निर्धारण उनके परिशिष्ट 8ख आंकड़ों के आधार पर किया गया है जो सत्यापन के अधधीन है। तदनुसार निर्यातक के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण किया गया जिसका उल्लेख पाटन को दर्शाने वाली तालिका में किया गया है।

मैसर्स मेरवाक एमडीएफ लंका (प्राइवेट) लिमिटेड

106. यह नोट किया जाता है कि मैसर्स मेरवाक ने श्रीलंका में *** अमेरिकी डालर की शेयरधारिता निधि के साथ वर्ष 2000 में निवेश किया था। *** में मेरवाक ग्रुप ने अपना पहला एमडीएफ (लाइन-1) उत्पादन लाइन होराना, श्रीलंका में प्रतिस्थापित एवं शुरू किया था। अभी हाल ही में *** में मेरवाक ने "पतले" एफडीएफ का उत्पादन करने तथा शार्ट साइकिल लेमीनेटिंग लाइन के लिए अपनी द्वितीय उत्पादन लाइन (लाइन-2) शुरू की है। यह नोट किया गया कि शुरूआती उत्पादन उपकरण तथा भवन एवं भूमि की खरीद इसकी धारक कंपनी और 100 प्रतिशत शेयर धारक *** (मलेशिया) द्वारा *** ("कंपनी") की ओर से की गई थी। परिशिष्ट 1 के अनुसार कंपनी ने ऋण व्ययों के समायोजन का दावा ऋण व्यय पर किया है जिसकी जांच अवधि के दौरान प्रचलित व्याज दर को ध्यान में रखते हुए अनुमति दे दी गई। पुनः यह नोट किया जाता है कि घरेलू बिक्रियां फैक्टरी बाह्य आधार पर की गईं तथा कंपनी ने घरेलू बाजार ने सम्बद्ध वस्तु की *** सीबीएम की बिक्री की है। कंपनी के प्रत्युत्तर का अध्ययन करने से यह देखा गया कि कंपनी ने दावा किया है कि उसके घरेलू देश में बेची गई वस्तु तथा भारत को निर्यात की गई वस्तु के बीच मोटाई और ब्रैंड के अलावा कोई अन्य अंतर नहीं है तथा घरेलू बाजार में बेची गई अथवा उत्पादन की गई अथवा भारत के अलावा अन्य देशों को बेची गई वस्तु में भारत को निर्यात की गई वस्तु की तुलना में मोटाई तथा ब्रैंड के अलावा भौतिक/तकनीकी/रसायनिक गुणधर्म संबंधित कोई अंतर नहीं है।

107. कंपनी द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना का सत्यापन करने के पश्चात कंपनी को सत्यापन रिपोर्ट जारी कर दी गई। सत्यापन रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया कि कंपनी ऋण लागत के लिए ब्याज की दरों का समायोजन करने के दावे के लिए आधार के संबंध में अपने दावे हेतु साक्ष्य उपलब्ध कराने में असफल रही है। इसके अतिरिक्त यह नोट किया गया कि मैसर्स मेरवाक श्रीलंका को अवनबी धारक कंपनी से ब्याज रहित ऋण प्राप्त हुआ था। खातों में उल्लिखित टिप्पणियों के अनुसार इन ऋणों कोई ब्याज नहीं लिया गया। यह ध्यान दिलाया जाता है कि सत्यापन के दौरान कंपनी ने दावा किया कि उसपर *** मिलीयन अमेरिकी डालर का धारक कंपनी द्वारा दिया गया ऋण है जिसपर *** प्रतिशत ब्याज लगता है। तथापि, कार्यशील पूंजी उद्देश्यों के लिए इसे *** में ब्याज रहित ऋण में परिवर्तित कर दिया गया। इस ऋण के संबंध में धारक कंपनी को *** से कोई ब्याज नहीं दिया गया है। उपर्युक्त दावे के समर्थन में कंपनी ने दोनों कंपनियों द्वारा पारित बोर्ड संकल्प प्रस्तुत किया है। मैसर्स मेरवाक द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है। श्रीलंका में कंपनियों को विनिमय नियंत्रण अधिनियम के अनुसार विदेशी राष्ट्रों, मूल कंपनियों से ऋण लेने की अनुमति है और इन ऋणों पर लागू ब्याज दर का निर्धारण लिबरल प्लस मार्जिनों द्वारा किया जाता है। निर्यातक द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया कि एक रूपता सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान मामले में मलेशिया में लागू ब्याज दर पर विचार किया जाना चाहिए जैसा कि डीजीएडी द्वारा अपनी पिछली जांचों में किया गया है।

108. प्राधिकारी द्वारा जारी सत्यापन रिपोर्ट के प्रत्युत्तर में निर्यातक ने ब्याज दरों के संबंध में किये गये अपने उन प्रस्तुतिकरणों को पुनः दोहराया है जिनका उल्लेख ऊपर के पैराग्राफों में पहले ही कर दिया गया है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि श्रीलंका में प्रचलित ब्याज दरों का स्पष्टीकरण श्रीलंका के विनिमय नियंत्रण अधिनियम के आलोक में किये जाने की जरूरत है। निर्यातक ने सत्यापन रिपोर्ट के प्रत्युत्तर में मूल्यद्वांस, कच्चे माल और उपयोगिता के संबंध में भी टिप्पणियां की हैं।

109. निर्यातक द्वारा उठाये गये मुद्दों की जांच की गई और यह नोट किया गया कि उपर्युक्त आदेश में दावा की गई ब्याज दर कई विनिर्देशनों के अध्ययनीय है और यह आदेश के अनुबंध में सूचीबद्ध किये गये उद्योग विशिष्ट है। इसके अतिरिक्त कंपनी ने उपर्युक्त आदेश के अंतर्गत कोई अन्य उधार नहीं लिया है। यह भी नोट किया जाता है कि वर्तमान जांच कंपनी के श्रीलंका में किये गये प्रचालनों से संबंधित है इसलिए श्रीलंका में वित्त पोषण लागत इससे संगत होगी और कोई अन्य ब्याज दर नहीं जिसपर मूल कंपनी ने पूंजी ऋण लिया हो। सत्यापन के दौरान कंपनी ने यह स्वीकार किया कि उधार के लिए प्रचलित ब्याज दरें (पीएलआर) और प्रकाशित स्रोतों में यथा प्रदर्शित औसत उधार लागत जांच की अवधि के दौरान श्रीलंका में बहुत अधिक थी।

110. तब कंपनी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रश्नावली प्रत्युत्तर का अध्ययन किया गया। यह पाया गया कि प्रत्युत्तर दाता ने संबंध वस्तु की बिक्री कीमत तथा अन्य विवरणों का वर्णन अपने प्रत्युत्तर के संगत परिशिष्टों में किया है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया कंपनी द्वारा दर्ज किया गया प्रत्युत्तर देखने पर यह दर्शाता है कि कंपनी ने अपनी धारक कंपनी से ब्याज रहित ऋण के रूप में भारी मात्रा में वित्तीय सहायता प्राप्त की है। कंपनी द्वारा दायर प्रश्नावली प्रत्युत्तर परिशिष्ट 7 और 8 में वित्त लागत के कारण किसी भी तरह के व्यय का उल्लेख नहीं किया गया है। यह नोट किया गया कि इस तरह प्राप्त ऋण पर ब्याज लागत के संबंध में विचार करने के पश्चात कंपनी को घरेलू प्रचालनों में घाटा हुआ। अतः प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य का निर्धारण ब्याज लागत, मूल्यद्वांस, कच्चे माल की लागत और उपयोगिता के लिए समुचित समायोजन करने के पश्चात उनकी उत्पादन लागत के आधार पर किया गया है जिसका उल्लेख पाटन मार्जिन को दर्शाने वाली तालिका में किया गया है।

गैर सहयोगकर्ता निर्यातकों/उत्पादकों के बारे में सामान्य मूल्य का निर्धारण

111. गैर सहयोगकर्ता निर्यातकों/उत्पादकों के बारे में सामान्य मूल्य का निर्धारण 'उपलब्ध तथ्यों' के आधार पर किया गया है।

च. निर्यात कीमत

प्रत्युत्तर दाता निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

मैसर्स एवरग्रीन फाइबर बोर्ड वेरहाद (ईएफबी)

112. प्राधिकारी ने उपर्युक्त प्रत्युत्तर दाता निर्यातक के बारे में निर्यात कीमत की जांच प्रत्युत्तर दाता द्वारा दायर किये गये प्रश्नावली प्रत्युत्तर के आधार पर की है। उनके द्वारा प्रस्तुत सूचना की जांच करने और स्थल पर जाकर सत्यापन करने के पश्चात निर्यात कीमत की अनुमति दे दी गई। यह नोट किया गया कि प्रत्युत्तर दाता ने भारत को किये गये निर्यात, जिसमें समायोजन भी शामिल है, से संबंधित सूचना परिशिष्ट 2 में प्रदान की है। स्थल पर सत्यापन करने के पश्चात समुद्र पारीय भाड़ा, अंतरदेशीय परिवहन पैकिंग, स्थानीय बीमा, सीमा शुल्क हैंडलिंग, निकासी प्रभार तथा बैंक प्रभारों का समायोजन करने के पश्चात स्वीकार कर लिया गया। इस प्रकार निर्धारित फैंक्टरी बाह्य निर्यात कीमत का उल्लेख पाटन मार्जिन को दर्शाने वाली तालिका में किया गया है।

मैसर्स एवरग्रीन फाइबर बोर्ड (जेबी) एसडीएन, वेरहाद (ईजेबी)

113. प्राधिकारी ने उपर्युक्त प्रत्युत्तर दाता निर्यातक के बारे में निर्यात कीमत की जांच प्रत्युत्तर दाता द्वारा दायर किये गये प्रश्नावली प्रत्युत्तर के आधार पर की है। उनके द्वारा प्रस्तुत सूचना की जांच करने और स्थल पर जाकर सत्यापन करने के पश्चात निर्यात कीमत की अनुमति दे दी गई। यह नोट किया गया कि प्रत्युत्तर दाता ने भारत को किये गये निर्यात, जिसमें समायोजन भी शामिल है, से संबंधित सूचना परिशिष्ट 2 में प्रदान की है। स्थल पर सत्यापन करने के पश्चात समुद्र पारीय भाड़ा, अंतरदेशीय परिवहन पैकिंग, स्थानीय बीमा, सीमा शुल्क हैंडलिंग, निकासी प्रभार तथा बैंक प्रभारों का समायोजन करने के पश्चात स्वीकार कर लिया गया। इस प्रकार निर्धारित फैंक्टरी बाह्य निर्यात कीमत का उल्लेख पाटन मार्जिन को दर्शाने वाली तालिका में किया गया है।

मैसर्स सेगामट पैनल बोर्ड्स एसडीएन बीएचडी

114. प्राधिकारी ने उपर्युक्त प्रत्युत्तर दाता निर्यातक के बारे में निर्यात कीमत की जांच प्रत्युत्तर दाता द्वारा दायर किये गये प्रश्नावली प्रत्युत्तर के आधार पर की है। उनके द्वारा प्रस्तुत सूचना की जांच करने और स्थल पर जाकर सत्यापन करने के पश्चात निर्यात कीमत की अनुमति दे दी गई। यह नोट किया गया कि प्रत्युत्तर दाता ने भारत को किये गये निर्यात, जिसमें समायोजन भी शामिल है, से संबंधित सूचना परिशिष्ट 2 में प्रदान की है। स्थल पर सत्यापन करने के पश्चात समुद्र पारीय भाड़ा, अंतरदेशीय परिवहन पैकिंग, स्थानीय बीमा, सीमा शुल्क हैंडलिंग, निकासी प्रभार तथा बैंक प्रभारों का समायोजन करने के पश्चात स्वीकार कर लिया गया। इस प्रकार निर्धारित फैंक्टरी बाह्य निर्यात कीमत का उल्लेख पाटन मार्जिन को दर्शाने वाली तालिका में किया गया है।

पीटी सुमाटेरा प्राइमा फाइबर बोर्ड

115. प्राधिकारी ने उपर्युक्त प्रत्युत्तर दाता निर्यातक के बारे में निर्यात कीमत की जांच प्रत्युत्तर दाता द्वारा दायर किये गये प्रश्नावली प्रत्युत्तर के आधार पर की है। उनके द्वारा प्रस्तुत सूचना की जांच करने और स्थल पर जाकर सत्यापन करने के पश्चात निर्यात कीमत की अनुमति दे दी गई। यह नोट किया गया कि प्रत्युत्तर दाता ने भारत को किये गये निर्यात, जिसमें समायोजन भी शामिल है, से संबंधित सूचना परिशिष्ट 2 में प्रदान की है। स्थल पर सत्यापन करने के पश्चात समुद्र पारीय भाड़ा, अंतरदेशीय परिवहन पैकिंग, स्थानीय बीमा, सीमा शुल्क हैंडलिंग, निकासी प्रभार तथा बैंक प्रभारों का समायोजन करने के पश्चात स्वीकार कर लिया गया। इस प्रकार निर्धारित फैंक्टरी बाह्य निर्यात कीमत का उल्लेख पाटन मार्जिन को दर्शाने वाली तालिका में किया गया है।

पीटी मासारी द्विसेपाकट फाइबर

116. यह नोट किया जाता है कि प्रत्युत्तर दाता उत्पादक और निर्यातक ने उनके द्वारा विगत में प्रस्तुत की जानकारी के सत्यापन पर अपनी सहमति नहीं दी है। इसके मद्देनजर उनकी निर्यात कीमत का सत्यापन नहीं किया जा सके। अतः उनकी निर्यात कीमत उपलब्ध तथ्यों के आधार पर ली गई है।

मैसर्स मेरवाक एमडीएफ लंका (प्राइवेट) लिमिटेड

117. प्राधिकारी ने उपर्युक्त प्रत्युत्तर दाता निर्यातक के बारे में निर्यात कीमत की जांच प्रत्युत्तर दाता द्वारा दायर किये गये प्रश्नावली प्रत्युत्तर के आधार पर की है। उनके द्वारा प्रस्तुत सूचना की जांच करने और स्थल पर जाकर सत्यापन करने के पश्चात निर्यात कीमत की अनुमति दे दी गई। यह नोट किया गया कि प्रत्युत्तर दाता ने भारत को किये गये निर्यात, जिसमें समायोजन भी शामिल है, से संबंधित सूचना परिशिष्ट 2 में प्रदान की है। स्थल पर सत्यापन करने के पश्चात समुद्र पारीय भाड़ा, अंतरदेशीय परिवहन पैकिंग, स्थानीय बीमा, सीमा शुल्क हैंडलिंग, निकासी प्रभार तथा बैंक प्रभारों का समायोजन करने के पश्चात स्वीकार कर लिया गया परंतु इसमें ऋण लागत शामिल नहीं जिसमें प्रचलित ब्याज दर के अनुरूप संशोधन किया गया है। इस प्रकार निर्धारित फैंक्टरी बाह्य निर्यात कीमत का उल्लेख पाटन मार्जिन को दर्शाने वाली तालिका में किया गया है।

सहयोग न करने वाले निर्यातकों/उत्पादकों के संबंध में निर्यात कीमत का निर्धारण

118. चूंकि संबद्ध वस्तु के किसी अन्य उत्पादक/निर्यातक से कोई अन्य प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ है इसलिए प्राधिकारी ने निर्यात कीमत का निर्धारण पाटन रोधी नियमावली के नियम 6 (8) में उल्लिखित शर्तों के अनुरूप 'उपलब्ध तथ्यों' के आधार पर किया है। इन आंकड़ों का सहयोगकर्ता निर्यातकों द्वारा प्रदान कराई गई सूचना तथा आवेदक द्वारा प्रदान कराई गई सूचना के अनुरूप परितुलन किया गया।

छ. पाटन मार्जिन

119. ऊपर निर्यातित निर्यात कीमत तथा सामान्य मूल्य पर विचार करने के पश्चात पाटन मार्जिन का निर्धारण निम्नवत किया गया है:

क.सं.	देश-उत्पादक/निर्यातक	सामान्य मूल्य	निवल निर्यात कीमत	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन %	पाटन मार्जिन रेंज %
	चीन जन गण					
1.	सभी उत्पादक और निर्यातक	***	***	***	***	80-90
	इंडोनेशिया					

2.	पीटी सुमाटेरा प्राइमा फाइबर बोर्ड	***	***	***	***	25 - 35
4.	अन्य सभी उत्पादक और निर्यातक	***	***	***	***	60-65
मलेशिया						
5.	मैसर्स सेगामट पैनल बोर्ड्स एसबीएन बीएचडी	***	***	***	***	15-20
6.	मैसर्स एवरग्रीन फायर बोर्ड बेरहाद(ईएफबी)/	***	***	***	***	15-20
	मैसर्स एवरग्रीन फायर बोर्ड (जेबी) एसडीएन बेरहाद (ईजेबी)	***	***			
7.	अन्य सभी उत्पादक और निर्यातक	***	***	***	***	35-40
श्रीलंका						
8.	मैसर्स मेरबाक एमडीएफ लंका (प्राइवेट) लिमिटेड	***	***	***	***	15-25
9.	अन्य सभी उत्पादक और निर्यातक	***	***	***	***	50-60

120. प्रारंभिक जांच परिणाम जारी करने और सत्यापन रिपोर्ट जारी करने के पश्चात निम्नलिखित उत्पादकों और निर्यातकों ने प्राधिकारी को कीमत प्रतिबद्धता प्रदान की तथा उन्होंने प्राधिकारी से कीमत प्रतिबद्धता प्रपत्र शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया।

- I. पीटी सुमाटेरा प्राइमा फाइबर बोर्ड, इंडोनेशिया
- II. मैसर्स एवरग्रीन फाइबर बोर्ड वेरहाद (ईएफबी)/ मैसर्स एवरग्रीन फाइबर बोर्ड (जेबी) एसडीएन वेरहाद (ईजेबी), मलेशिया
- III. मैसर्स मेरबाक एफडीएफ लंका (प्राइवेट) लिमिटेड, श्रीलंका।

121. इन निर्यातकों और उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत कीमत हलफनामे की जांच की गई और यह प्रस्ताव है कि इन उत्पादकों तथा निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत कीमत हलफनामे को स्वीकार नहीं किया जाए क्योंकि इन हलफनामे को स्वीकार करना व्यवहारिक नहीं पाया गया।

ज. **क्षति एवं कारणात्मक संबंध**

अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये प्रस्तुतीकरण

122. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये प्रस्तुतीकरण संक्षेप में निम्नलिखित हैं:

मैसर्स वेनुगोपाल स्लेट इंडस्ट्रीज और सार्थक ओवरसीज द्वारा किया गया प्रस्तुतिकरण

- आवेदनकर्ता के इस दावे में कोई गुण नहीं है कि बिक्री कीमत परियोजना रिपोर्ट में प्रक्षेपित कीमत से कम है। इन प्रक्षेपणों में तर्क संगतता एवं संगतता का अभाव है जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय कीमतें भारतीय कीमतों की तुलना में क्षति अवधि के दौरान पर्याप्त रूप से कम रही है। उनके निर्णय में हुई किसी तरह की त्रुटि में पाटन रोधी उपाय द्वारा सुधार नहीं करना चाहिए। प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय कीमतों की अवमानना में परियोजना रिपोर्ट में परिकल्पित बिक्री कीमत के साथ-साथ वास्तविक कीमत की तुलना करना उचित नहीं है।

- आवेदनकर्ता ने सामग्री विमन्दन के प्रावधानों की गलत व्याख्या की है क्योंकि नियम 11 (1) में अनन्य रूप से परस्पर प्रावधान किये गये हैं; अतः इस दावे का कोई तथ्यपरक एवं कानूनी आधार नहीं है। आवेदनकर्ता वाणिज्यिक उत्पादन के 17 महीने के बाद प्रारंभिक स्तर का दावा नहीं किया जा सकता है और उन्हें अपनी कच्चे माल की उच्चतर दर, उच्चतर निर्धारित लागत के रूप में निहित अकुशलता द्वारा कारित उच्चतर उत्पादन लागत में सुधार करने के लिए पाटन रोधी तंत्र का दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। याचिका में उल्लिखित आंकड़ों के अनुसार घरेलू उद्योग को कोई वास्तविक क्षति नहीं हुई है। आयातों के स्तर के संबंध में दिये गये तर्कों को बढ़ाचढ़ाकर प्रस्तुत किया गया है; जबकि संबद्ध देशों से आयातों में वास्तविक वृद्धि लगभग एक प्रतिशत के बराबर हुई है जो नगण्य है और इसे स्पष्ट न्यून उत्पादन तथा मांग में वृद्धि के अनुरूप देखा जाना चाहिए। मांग में वृद्धि होने के बावजूद कथित पाटन आयातों के बाजार हिस्से में गिरावट आयी है। विभिन्न अन्य क्षतिपैरा मीटरों में भारी वृद्धि दर्शायी गयी है तथा क्षति का कोई भी चिन्ह देखा जा सकता है। आवेदनकर्ता उत्पादन लागत पूर्व एशियाई देशों के साथ तुलना करने पर असामान्य रूप से बहुत अधिक है जैसाकि सहयोगकर्ता निर्यातकों से इसकी तुलना करने में ज्ञात हुआ है। घरेलू उद्योग की निर्धारित परिवर्तन लागत बहुत अधिक है, पक्षपात रहित विश्लेषण सुनिश्चित करने के लिए क्षति परीक्षण से निर्धारित लागत की उच्चतर राशि को हटा दिया जाना चाहिए।
 - विचाराधीन उत्पाद की कच्चे माल की लागत पर दो परिवर्तनशील तत्वों अर्थात् कच्चे माल की दर और प्रतियुनिट आउटपुट कच्चे माल की वास्तविक खपत से प्रभावित होती है। कच्चे माल की दरें और खपत मानक अंतर्राष्ट्रीय दरों से दोगुने निकट के प्रतीत होते हैं। अन्य कारणों से होने वाले इन घाटों और अकार्यकुशलता की जांच की जानी चाहिए और इनके लिए पाटन के द्वारा होने वाली क्षति को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। आवेदनकर्ता को होने वाला कोई भी नुकसान, यदि कोई हो तो, उसके लिए केवल उत्पादन की उच्चतर लागत को ही जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। वर्तमान मामले में किसी भी पाटन रोधी शुल्क का अधिरोपण करना जनहित के विरुद्ध होगा क्योंकि किसी भी तरह के शुल्क का बोझ आयातों की अक्षमता के कारण उच्चतर लागत के रूप में प्रदर्शित होगा जिससे उपयोग करने वाले उद्योग के हित बुरी तरह से प्रभावित होंगे।
 - संबद्ध देशों से उतराई कीमत में वृद्धि हुई है जबकि उसी अवधि के दौरान आवेदनकर्ता की बिक्री कीमत में गिरावट का रुझान प्रदर्शित हुआ है। इससे विपर्यय संबंध प्रदर्शित होता है तथा घरेलू बिक्री कीमत और उतराई कीमत के बीच कोई अंतः संबंध प्रदर्शित नहीं होता है।
 - आवेदनकर्ता ने अपना उत्पादन अभी हाल ही में शुरू किया है। अतः शुरुआती लागत अस्थापित बिक्री एवं वितरण सरणियों, संवर्धित बाजार में तथा उच्चतर डिस्काउंट, उच्चतर उत्पादन लागत जैसे कारकों के कारण होने वाले क्षति के लिए कथित पाटन को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। यह भी उल्लेख किया गया है कि घरेलू उद्योग द्वारा 2.3 मिमी का उत्पादन नहीं किया जा रहा है इसलिए पाटन रोधी शुल्क का अधिरोपण नहीं किया जा सकता है।
- रबड़ एफडीएफ उत्पादों तथा विशिष्ट आकर की संबद्ध वस्तु का उत्पादन करने में घरेलू उद्योग की अक्षमता के संबंध में भी प्रस्तुतीकरण किये गये हैं और इस संबंध में भी उल्लेख किया गया है कि उन्होंने केवल दो तीन साल पहले ही उत्पादन शुरू किया है और कंपनी की वित्तीय स्थिति के संबंध में निर्णय लेने के लिए यह समय बहुत कम है।

मैसर्स सेगामेट पैनल बोर्ड एडीएन बीएचडी और मैसर्स मैरवाक एमडीएफ लंका (प्राइवेट) लिमिटेड, श्रीलंका प्रजातांत्रिक समाजवादी गणराज्य श्रीलंका के कांसुलेट जनरल की ओर से किये गये प्रस्तुतीकरण ।

- घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति, यदि कोई है तो, क्षति अवधि के दौरान लकड़ी की कीमत और खपत माल को के कारण हुई है।
- परियोजना रिपोर्ट में किये गये प्रक्षेपणों की तर्कसंगतता: आवेदनकर्ता ने क्षति संबंधी अपने दावे के समर्थन में दावा किया है कि वह कीमत जिसपर कंपनी को अपने उत्पाद बाजार में बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा है। परियोजना रिपोर्ट में प्रक्षेपित कीमतों से कम है। इस संबंध में यह प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदनकर्ता की कम से कम बिक्री कीमत वर्ष 2009-10 में 16935 रुपये प्रति सीबीएम थी और जांच की अवधि में यह घटकर 15164 रुपये प्रति सीबीएम रह गई हमने उक्त बिक्री कीमत का अनुमान कीमत अधोदहन के आधार पर किया है। संगत रूप से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में संबद्ध वस्तु की कीमतें क्षति अवधि के दौरान इन भारतीय कीमतों से बहुत अधिक कम रही हैं। यद्यपि यह वित्तीय संस्थान पर निर्भर होता है कि वह लाभप्रदायकता का वास्तविक प्रक्षेपण वित्त पोषण के लिए परियोजना का मूल्यांकन करते व्यक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इस समय प्रचलित कीमतों के संबंध में करें, इस निर्णय में होने वाली किसी भी त्रुटि को पाटन रोधी तंत्र के जरिए सुधारा नहीं जाना चाहिए क्योंकि यह तंत्र अनुचित व्यापार प्रक्रियाओं के प्रभाव को कम करने के लिए बनाया गया है। पाटनरोधी विधियों के अंतर्गत मुक्त व्यापार प्रणाली के तहत कीमत की तुलना करने की एक निर्धारित प्रक्रिया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रचलित कीमत की अवहेलना करते हुए परियोजना रिपोर्ट में प्रकलित बिक्री कीमत तथा वास्तविक बिक्री कीमत की तुलना करना गलत है।
- “भारत में किसी भी उद्योग की स्थापना का वास्तविक रूप में विमंदन” वाक्यांश का शाब्दिक अर्थ यह व्यक्त करता है कि जब पाटन भारत में किसी उद्योग की शुरुआत को निषिद्ध कर देता है परंतु एक संयंत्र अपना वाणिज्यिक उत्पादन करने की घोषणा करता है। वाक्यांश प्रारंभ को घरेलू उद्योग द्वारा विकास एवं विस्तार को दर्शाने के लिए गलत व्याख्या नहीं की जा सकती है और न ही की जानी चाहिए। जैसा की आवेदनकर्ता ने करने का प्रयास किया है। “भारत में ऐसी किसी वस्तु का आयात भारत में स्थापित किसी उद्योग को क्षतिकारित करता है अथवा क्षति पहुंचाने की चुनौती देता है अथवा भारत में किसी उद्योग की स्थापना का विमंदन करता है” जैसे शब्दों का प्रयोग से नियम 11 (1) इसे स्पष्ट कर देता है कि वास्तविक क्षति, वास्तविक क्षति की चुनौती और वास्तविक विमंदन परस्पर अनन्य हैं। तथापि जांच शुरुआत

अधिसूचना यह उल्लेख करती है कि घरेलू उद्योग ने वास्तविक विमंदन को सहन किया है और वास्तविक क्षति हुई है अतः आवेदक द्वारा भरोसा की गई वास्तविक विमंदन की जांच आवेदनकर्ता पर लागू नहीं होती है क्योंकि उसका संयंत्र पहले से ही प्रचालन में था।

- आवेदनकर्ता ने अपना वाणिज्यिक उत्पादन 2 फरवरी, 2010 से शुरू किया है। यह अजीब है कि वाणिज्यिक उत्पादन के 17 माह के पश्चात भी आवेदन उद्योग प्रारंभिक स्तर का दावा करता है। इसके अतिरिक्त यह प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक उद्योग का वास्तविक विमंदन का दावा ऐसी स्थिति में करना जब कि उसने बिक्री कीमत का प्रापण अंतर्राष्ट्रीय कीमतों से अधिक कीमतों पर किया है। उसका यह दावा भरोसेमंद नहीं है। इसके अतिरिक्त यदि घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत उनकी अक्षमता, कच्चे माल की उच्चतर दर और उच्चतर निर्धारित लागत के कारण उच्च रही है तो कोई उद्योग प्रारंभिक उद्योग के रूप में वास्तविक क्षति का दावा कैसे कर सकता है और उसके लिए पाटन को उत्तरदायी कैसे ठहरा सकता है।
- प्राधिकारी ने जांच शुरूआत अधिसूचना में उल्लेख किया है कि संबद्ध देशों से आयातों में पर्याप्त वृद्धि हुई है जिसमें इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए गिरावट आनी चाहिए कि घरेलू उद्योग ने नयी-नयी उत्पादन सुविधाओं की स्थापना की है, और सहायक कंपनी ने भी विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करना प्रारंभ कर दिया है तथापि संबद्ध देशों से आयात जो वर्ष 2009-10 में 44,009 मि.टन था थोड़ा बढ़कर प्रस्तावित जांच अवधि में 44,562 सीबीएम हो गया और इस वृद्धि की दर अनुमानतः केवल एक प्रतिशत थी जो पूरी तरह से नगण्य है।
- घरेलू उद्योग को कोई वास्तविक क्षति नहीं हुई है। याचिका में उल्लिखित आंकड़े पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति की मौजूदगी प्रदर्शित नहीं करते हैं। वास्तव में प्रपत्र IVक दर्शाता है कि घरेलू उद्योग के उत्पादन, क्षमता उपयोग, बाजार हिस्से और बिक्री में जांच की अवधि के दौरान तथा उससे पिछले वर्ष के दौरान काफी सुधार हुआ है। यह एक विचित्र स्थिति है कि जब प्रचालनरत क्षतिपैरा मीटरों में सुधार दिखाया गया है और बाजार हिस्से में सुधार हुआ है यह प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय की तुलना में उच्च बिक्री कीमत प्राप्त कर रहा था फिर भी घरेलू उद्योग ने क्षति का दावा किया है। आवेदनकर्ता का क्षमता उपयोग वर्ष 2009-10 में केवल 27 प्रतिशत था जिसमें जांच अवधि के दौरान सुधार होकर 32 प्रतिशत हो गया, इस प्रकार क्षति प्रदर्शित नहीं होनी चाहिए।
- यह कि घरेलू उद्योग, जब इसकी उत्पादन लागत अंतर्राष्ट्रीय स्तर से 100 प्रतिशत अधिक है तो यह बिलकुल भी प्रतिस्पर्धी नहीं होनी चाहिए। हमने हमारे निर्यातक की वास्तविक उत्पादन लागत और बिक्री कीमत तथा घरेलू उद्योग की वास्तविक उत्पादन लागत और बिक्री कीमत से (हमारे आकलनों के आधार पर) करने का प्रयास किया इससे यह संकेत मिलता है कि आवेदनकर्ता की उत्पादन लागत निर्यातकों की उत्पादन लागत की तुलना में असामान्य रूप से बहुत ज्यादा थी और आवेदनकर्ता की उच्चतर लागत के कारणों का विश्लेषण निम्नवत किया गया है:—

क. आवेदक की उच्चतर निर्धारित परिवर्तन लागत: यह कि आवेदनकर्ता की निर्धारित परिवर्तन लागत 6,372 रुपये प्रति सीबीएम थी जबकि सामान्य उपयोग (90 प्रतिशत) पर यह 2,246 रुपये प्रति सीबीएम होनी चाहिए। अतः घरेलू उद्योग की निर्धारित परिवर्तन लागत जांच की अवधि के दौरान न्यूनतर क्षमता उपयोग के कारण 4126 रुपये प्रति सीबीएम अधिक थी। इसके अतिरिक्त, आवेदनकर्ता उद्योग की वास्तविक निर्धारित लागत निर्यातकों की निर्धारित लागत से दोगुनी अधिक है। अतः, आवेदक द्वारा सहन की गई क्षति का पक्षपात रहित विश्लेषण सुनिश्चित करने के लिए क्षति जांच से निर्धारित लागत की उच्चतर राशि को हटा दिया जाना चाहिए इसके कारण इसे संबद्ध देशों से कथित पाटित आयातों को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।

ख. आवेदनकर्ता के लिए कच्चे माल की दर और खपत मानक: यह प्रस्तुत किया जाता है कि विचाराधीन उत्पाद की कच्चे माल की लागत दो प्रतिमानों अर्थात् कच्चे माल की दर और आउटपुट के प्रतियुनिट के हिसाब से कच्चे माल की वास्तविक खपत से प्रभावित होती है आवेदक उद्योग के कच्चे माल की दर की तुलना निर्यातकों की दरों से करने पर यह देखा जा सकता है कि घरेलू उद्योग की कच्चे माल की दरें सहयोगकर्ता निर्यातकों की दरों से दोगुने के नजदीक हैं। दरों में यह अंतर आवेदक घरेलू उद्योग तथा निर्यातकों की उत्पादन लागत में अंतर के लिए कारणों का आंशिक रूप से उल्लेख करता है। पुनः यह उल्लेख किया जाता है कि जब हम निर्यातकों के आउटपुट की प्रतियुनिट कच्चे माल की वास्तविक खपत की तुलना आवेदक उद्योग से करते हैं तो पाते हैं कि लगभग 28 प्रतिशत अधिक है। यह और कुछ नहीं बल्कि घरेलू उद्योग की प्रचालन अक्षमता है सामग्री की उच्चतर खपत दर्शाकर कीमत बढ़ाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है जिसकी प्राधिकारी द्वारा जांच की जानी चाहिए। कच्चे माल की लागत में अंतर है और कच्चे माल की लागत में इस अंतर के लिए कथित पाटन को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है और न ही ठहराया जाना चाहिए।

ग. अतः, आवेदनकर्ता की लागत न्यून क्षमता उपयोग तथा कच्चे माल की उच्चतर खपत के रूप में अक्षमता के कारण लगभग 9,142 रुपये प्रति सीबीएम अधिक है। अतः ऐसे किसी अन्य कारण से कारित क्षति के लिए पाटन को उत्तरदायी नहीं माना जा सकता है।

- यह कि आवेदनकर्ता को तब भी क्षति हुई जब इसकी निवल बिक्री कीमत 15,164 रुपये प्रति सीबीएम थी और यह कीमत अंतर्राष्ट्रीय कीमतों से अधिक है जो 12 हजार रुपये प्रति सीबीएम थी। हमने इस बिक्री कीमत का आकलन कीमत अधोरदन प्रवृत्ति से किया है। अतः आवेदनकर्ता को क्षति उसकी अक्षमता के कारण उच्च लागत की वजह से हुई। संबद्ध देशों से उतराई कीमत जो पिछले वर्ष 12024 रुपये प्रति मी.टन थी बढ़कर जांच अवधि में 12730 रुपये प्रति मी.टन हो गई जबकि आवेदनकर्ता की बिक्री कीमत में उसी अवधि के दौरान गिरावट की प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई है। इससे एक विपरीत संबंध अभिव्यक्त होता है और उतराई कीमत तथा घरेलू बिक्री कीमत के बीच कोई सह संबंध नहीं दर्शाता है।

- यह कि आवेदनकर्ता ने अपना उत्पादन हाल ही में शुरू किया है। अतः यह स्पष्ट है कि आवेदनकर्ता को विभिन्न कारकों के कारण क्षति हुई होगी जैसे (i) शुरुआती लागत (ii) अस्थापित बिक्री एवं वितरण सरणियां (iii) संवर्धित विपणन व्यय और उच्च डिस्काउंट। कोई कारणात्मक संबंध नहीं है।
- श्रीलंका के काउंसुलेट जनरल ने उत्पादन लागत का निर्धारण करने में ऋण संघटकों के उपचार में असंगतता को ध्यान में लाया और श्रीलंका से संबद्ध वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की मांग की है।

व्यापार निदेशक, इंडोनेशिया गणराज्य द्वारा की गई प्रस्तुति:

- घरेलू उद्योग की स्थापना की वास्तविक विमंदन से होने वाली क्षति तथा घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति दोनों अलग-अलग है और पाटन रोधी करार की पाद टिप्पणी 9।
- वास्तविक विमंदन, उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू उद्योग की बिक्री पर विचार करना तर्क संगत है क्योंकि वे बाजार में संगत रूप से नवागंतुक का प्रतिनिधित्व करते हैं और वास्तविक क्षति के संबंध में भारतीय बाजार से यह उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वह नवागंतुक की शुरुआती लागत को आमेहित कर पायेगी और इस कारण यह एक सामान्य बात है कि एक ऐसी अवधि आती है जिसमें बिक्री कीमत लागत को कवर नहीं करती है।
- घरेलू उद्योग उत्तर भारत में अवस्थित है जबकि इंडोनेशिया के अधिकांश निर्यात दक्षिणी बाजारों में संकेन्द्रित है। बाजार संबंधी चिंताएं भी अलग-अलग है।
- उत्तर से दक्षिण को आंतरिक किराये की लागत घरेलू उद्योग को प्रभावकारी ढंग से अप्रतिस्पर्धी बना देती है।

एवरग्रीन फाइबर बोर्ड बेरहाद (ई एफ बी), मलेशिया; एवरग्रीन फाइबर बोर्ड (जेबी) एसडीएन, बीएचडी (ईजेबी) मलेशिया और एवरग्रीन फाइबर बोर्ड (निलाई) एसडीएन.बीएचडी (ईएफएन) मलेशिया की ओर से किए गए प्रस्तुतिकरण

- नियम यह निर्धारित करता है कि तीन तरह की ऐसी क्षति होती है जो घरेलू उद्योग को कारित की जा सकती है जैसे स्थापित उद्योग को वास्तविक क्षति, स्थापित उद्योग को वास्तविक क्षति की चुनौती अथवा किसी उद्योग की स्थापना में वास्तविक विमंदन की चुनौती। उपर्युक्त नियमों में 'या' शब्द का प्रयोग स्पष्ट करता है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि सभी तीन प्रकार की क्षति अथवा कोई दो प्रकार की क्षति एक साथ मौजूद हो। अतः वास्तविक विमंदन और वास्तविक क्षति के रूप में क्षति एक साथ नहीं रह सकती है। यह उल्लेख करना भी महत्वपूर्ण है कि आवेदनकर्ता ने अपनी याचिका में कहीं भी यह उल्लेख नहीं किया है कि यह मामला वास्तविक क्षति का है। इसमें वास्तविक विमंदन का उल्लेख किया गया है और घरेलू उद्योग को स्थापना का कोई वास्तविक विमंदन नहीं है।
- आयात विश्लेषण पूरी तरह से गलत है। यह स्पष्ट है कि संपूर्ण आयात में वर्ष 2010-11 में पर्याप्त मात्रा में गिरावट आयी है। इसके अतिरिक्त उसी अवधि के दौरान संबद्ध देशों से आयातों में लगभग 1 प्रतिशत की वृद्धि जो बिल्कुल नगण्य को इतनी अधिक वृद्धि के रूप में कल्पना करने के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। यह कि घरेलू उद्योग ने आयात आकड़ों का गलत संकलन किया है।
- क्षति के संबंध में जांच शुरुआत अधिसूचना में यह उल्लेख किया गया है कि घरेलू उद्योग ने अवनबी स्थापना का वास्तविक विमंदन सहन किया है। घरेलू जांच की अवधि सहित 17 माह से संबद्ध वस्तु का सफलता पूर्व उत्पादन करती रही है और इसने जांच की अवधि के परे भी संवद्ध वस्तु का निर्माण जारी रखा।
- आयातों का विश्लेषण वर्ष 2009-10 तथा उसके बाद से किया जाना चाहिए जब घरेलू उद्योग ने अपना उत्पादन प्रारम्भ किया था जो यह दर्शाता है कि आयातों में मामूली सी वृद्धि हुई है।
- रोजगार आंकड़ों का विश्लेषण नहीं किया गया है। सभी क्षति पैरामीटर सुधार प्रदर्शित करते हैं।
- घरेलू उद्योग को कोई वास्तविक क्षति नहीं हुई है जो निम्नलिखित से स्पष्ट है।

- i. क्षमता: आवेदनकर्ता की संस्थापित क्षमता जो पिछले वर्ष 8333 से बढ़कर वर्ष 2010-11 में 50,000 एम³ हो गई।
- ii. उत्पादन: आवेदक का उत्पादन जो वर्ष 2009-10 में 2262एम³ थी बढ़कर वर्ष 2010-11 में 15,860 एम³ हो गई
- iii. क्षमता उपयोग: आवेदक का क्षमता उपयोग वर्ष 2009-10 में 27 प्रतिशत था, यह बढ़कर वर्ष 2010-11 में 32 प्रतिशत हो गया।
- iv. बिक्रियां: आवेदक के बिक्री में एक वर्ष के दौरान 334 एम³ से बढ़ोतरी होकर 15,347 एम³ हो गयी जो 4600 प्रतिशत से अधिक वृद्धि है।

iv. मलसूची: घरेलू उद्योग ने वर्ष 2010-11 में 15,860 एम³ का उत्पादन किया था तथा 15,347 एम³ की बिक्री की थी और इस वर्ष के लिए शेष भंडार 423 एम³ था। यह कि वर्ष 2010-11 में उत्पादन का केवल 2.67 प्रतिशत भंडार रह जाना या 10 दिनों से कम की माल सूची रह जाने को माल सूची के भंडारण के रूप में नहीं माना जा सकता है।

v. बाजार हिस्सा: आवेदक का बाजार हिस्सा वर्ष 2009-10 में 0.63 प्रतिशत से बढ़कर 2010-11 में 25.23 प्रतिशत हो गया।

vii. लाभ प्रदायकता, लगाई गई पूंजी पर अर्जन, नकद लाभ तथा कीमत अधोरदन: इनके संबंध में होने वाले क्षति संबद्ध देशों से कथित पाटित आयातों के कारण नहीं हुई बल्कि शुरुआती लागत के कारण प्रति यूनिट उच्च लागत कच्चे माल की उक्त कीमत, उच्च उपोगिता लागत, उच्च निर्धारित लागत, उच्च श्रम लागत, उच्च ब्याज लागत और उच्च मूल्यहास लागत के कारण हुई है।

viii. वेतन: यह प्रस्तुत किया जाता है कि कर्मचारियों को भुगतान किये गये वेतन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2010-11 में भारी वृद्धि हुई है।

ix. कर्मचारियों की संख्या: आवेदक द्वारा नियोजित कर्मचारियों की संख्या में कोई कमी नहीं आई है।

x. उत्पादकता: आवेदक की उत्पादकता में वृद्धि हुई है।

- घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति, यदि कोई हो, तथा कथित पाटित आयातों के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक द्वारा दो घरेलू उत्पादकों के बीच परस्पर प्रतिस्पर्धा और उनके द्वारा किये गये आयातों के कारण आवेदक को क्षति हुई हो।

मैसर्स पीटी.मसारी द्विसेपाकट फाइबर, इंडोनेशिया और मैसर्स पीटी सुमाटेरा प्राइम फाइबर बोर्ड (एसपीएफ), इंडोनेशिया की ओर किया गया प्रस्तुतीकरण

- आवेदक उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद की ग्राही खपत के संबंध में जानकारी को रोक रखा है। उच्च कीमत वाली संबद्ध वस्तु के व्यवसाय में ही सादा फाइबर बोर्ड नामक कच्चे माल की जरूरत होती है।
- वाणिज्यिक उत्पादन के 15 माह पश्चात कोई उद्योग यह दावा नहीं कर सकता है कि वह अभी शैशव अवस्था में है और वास्तविक विमंदन का दावा भी नहीं कर सकती है।
- आवेदनकर्ताओं ने इस तथ्य के साक्ष्य नहीं दिये हैं कि यह मामला भौतिक विमंदन के दायरे के अंतर्गत कैसे आता है। यह दावा करने का भी कोई आधार नहीं है कि उद्योग अभी शैशव अवस्था में है। आवेदनकर्ता भारत में पहले से ही स्थापित एक उद्योग है। वर्तमान मामला एक ऐसा मामला है जिसमें आवेदनकर्ता की उत्पादन लाइन का अनुपूरण विभिन्न मोटाई के किसी अन्य उद्योग द्वारा किया जाता हो। क्योंकि स्थापित उद्योग इस बाजार में एक प्रमुख उद्योग है इसलिए आवेदनकर्ताओं को वर्तमान ढांचे से पहले ही लाभ हुआ है क्योंकि उसके पास सामान्य उपकरण, कर्मचारी, विशेषज्ञ, मौजूदा वितरण नेटवर्क एवं व्यवस्था, मौजूदा ग्राहक आधार और/ या अन्य संघटक, 6 मिमी के कम की मोटाई वाले फाइबर बोर्डों का उत्पादन करने के लिए कच्चे माल की आपूर्तिकर्ता तथा विक्रेता मौजूद है और वह अपने प्रचालन के अनुरूप अतिरिक्त उत्पादन करने के प्रयोजन के लिए उपयोग करने में सक्षम है। उपर्युक्त के मद्देनजर तथा जांच शुरुआत अधिसूचना में प्रयोग की गई भाषा को देखते हुए हमारी यह सुविचारित राय है कि मौजूदा मामला वह मामला नहीं है कि भारत में पाटित आयातों के कारण सुस्थापित उद्योग ने विमंदन से रक्षा करने की मांग की हो तथा उसके कारण उसे क्षति हुई हो। यह एक विवेकपूर्ण उल्लेख है कि वास्तविक विमंदन का मामला केवल तभी बनता है जब उत्पादन शुरू न हुआ हो या उद्योग ने अपनी वाणिज्यिक मात्रा अभी भी प्राप्त न की हो।
- जांच शुरुआत अधिसूचना एक कारण बताओं नोटिस की तरह है और इसने किसी पक्षकार की जानकारी में यह बात नहीं लाई कि आवेदनकर्ताओं का भौतिक विमंदन का दावा प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। भौतिक विमंदन के लिए जांच शुरुआत के अभाव में हम भौतिक विमंदन के संबंध में कोई अन्य टिप्पणी नहीं कर रहे हैं।
- प्राधिकारी द्वारा निर्धारित जांच की अवधि तथा क्षति परीक्षण की अवधि त्रुटिपूर्ण एवं अनुचित है। वर्तमान मामले में जांच की अवधि अप्रैल, 2010-जून, 2011 अर्थात् 15 माह है। आवेदक इस बाजार में अभी नया-नया ही आया है और अप्रैल, 2010 में उसने केवल दो महीने ही पूरे किये हैं। अतः पाटन एवं क्षति का निर्धारण पक्षपात पूर्ण प्रतीत होता है क्योंकि आवेदक के लिए परिवर्तन शील लागत और निर्धारित लागत बहुत अधिक होगी तथा कोई समुचित या व्यापक विश्लेषण नहीं किया जा सकता है।
- आवेदन पत्र के अनुसार संबद्ध वस्तु का भारत में केवल एक अन्य उत्पादक (ग्रीन प्लाई) है और ऐसे नये उत्पादक ने भी संबद्ध वस्तु का उत्पादन दिसम्बर, 2010 से ही करना प्रारंभ किया है। आवेदनकर्ता ने उत्पादन के आंकड़ों को आवेदन के केवल अगोपनीय पाठ में ही दर्शाया है और क्षति से संबंधित अन्य सभी जानकारी विलुप्त है। निर्दिष्ट प्राधिकारी आवेदक द्वारा किये गये ऐसे तथ्यपरक दावे का निर्धारण अन्य यथार्थ स्रोतों से भी कर सकते हैं।
- क्षति पैरा मीटर: इस संबंध में निम्नलिखित नोट किया जा सकता है:

क. मूल्यहास, व्याज और वेतन के आंकड़े नकारात्मक हैं।

ख. प्रतिकर्मचारी और प्रतिदिन उत्पादकता में भी वृद्धि हुई है।

ग. प्रपत्र IV—क में दर्शाया गया हित आधार वर्ष की तुलना में आकस्मिक वृद्धि प्रदर्शित करता है। यह आकस्मिक वृद्धि आवेदनकर्ता द्वारा सही ढंग से काम न किये जाने का एक आधार हो सकती है।

घ. आवेदक ने प्रपत्र IV—क में ग्राही खपत को नहीं दर्शाया है।

ड. आधार वर्ष की तुलना में औसत माल सूची में गिरावट आयी है जबकि उन्होंने अपना उत्पादन शुरू किया था।

च. जब हम माल सूची की तुलना प्रतिदिन की बिक्री से करते हैं तो यह देखा जा सकता है कि माल सूची में भारी कमी आयी है।

छ. जीएफए, एनएफए, कार्यशील पूंजी तथा कीमत अधोरदन से संबंधित जानकारी नहीं दी गई है।

ज. संशोधित प्रपत्र IV—क के अनुसार आवेदनकर्ता ने आधार वर्ष 2009–10 की तुलना में काफी अच्छा निष्पादन किया है।

झ. आवेदनकर्ता केवल मूल्यवर्धित उत्पादों की ही बिक्री करता है जो सादा एमडीएफ की तुलना में महंगा है। वे डोर स्कीन, एमडीएफ कोटेड बोर्ड, मेलामाइन बोर्ड तथा बाह्य ग्रेड एमडीएफ का विनिर्माण करते हैं। अतः हम प्राधिकारी से यह अनुरोध करेंगे कि वह आवेदक की गैर-क्षतिकारी कीमत तथा लागत का संगणन करते व्यक्त ग्राही खपत पर विचार करें तथा परिकलन पत्र का अगोपनीय पाठ भी प्रदान कराये जिससे कारगर टिप्पणियां की जा सकें।

- इंडोनेशिया से आयात संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान कमोवेश रूप से समान ही बने रहे। जैसा कि तालिका में दर्शाया गया है वर्ष 2010–11 के दौरान मूल्य में 21.70 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि मात्रा के रूप में वृद्धि केवल 20 प्रतिशत ही हुई। वार्षिकीकृत आंकड़ों में इंडोनेशिया के आयातों के मूल्य में वृद्धि लगभग 20 प्रतिशत हुई जबकि इसकी मात्रा में वृद्धि, वर्ष 2009–10 की तुलना में, केवल 12 प्रतिशत ही हुई।
- क्षति के सभी पैरा मीटर यह दर्शाते हैं कि बाजार में नवागन्तुक होने के बादजुद घरेलू उद्योग के निष्पादन में सुधार हुआ है।
- वर्ष 2007–08 से प्रमुख कच्चे माल का विश्लेषण करना गलत एवं भ्रमित करने वाला होगा क्योंकि इस अवधि के दौरान आवेदक संबद्ध वस्तु का उत्पादन ही नहीं कर रहा था। अतः, हम प्राधिकारी से अनुरोध करते हैं कि वह कच्चे माल की कीमतों का विश्लेषण फरवरी, 2010 से करे।

मैसर्स मैगना फोरमोस्ट एजीएन तथा मैसर्स मैसोनाइट कंपोनेंट्स आयरलैंड की ओर से किया गया प्रस्तुतिकरण

- भौतिक विमंदन एवं भौतिक क्षति के दावे परस्पर अपवर्जी हैं: जहां एक घरेलू उद्योग वास्तव में पहले से ही स्थापित हो वहां भौतिक विमंदन का दावा नहीं किया जा सकता है। यह तथ्य की आवेदनकर्ता संबद्ध उत्पाद के कुल भारतीय उत्पादन का लगभग 87 प्रतिशत उत्पादन करता है इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि, इस मामले में, घरेलू उद्योग पूरी तरह से जमा हुआ है। आवेदनकर्ता—जिसने यह स्वीकार किया है कि उसने अपना उत्पादन फरवरी, 2010 में, इस जांच शुरुआत के केवल 21 माह पहले ही शुरू किया है— मुश्किल से यह माना जा सकता है कि वह अच्छी तरह से स्थापित हो गया हो और इस मामले में भौतिक विमंदन का दावा करना उपयुक्त नहीं होगा।

घरेलू उद्योग द्वारा किया गया प्रस्तुतिकरण

123. घरेलू उद्योग द्वारा किये गये प्रस्तुतिकरण संक्षेप में निम्नलिखित हैं:

- इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग को बाजार में अपने उत्पाद की बिक्री परियोजना रिपोर्ट में प्रक्षेपित कीमतों से कम कीमत पर करने के लिए मजबूर किया गया; यह प्रस्तुत किया जाता है कि केवल इस तथ्य के कारण ही निर्यात कीमत किसी अन्य 'अंतर्राष्ट्रीय' कीमत से तुलनीय है, का कोई मतलब नहीं है वास्तव में, "अंतर्राष्ट्रीय कीमत" जैसी कोई कीमत नहीं है। यहां तक कि लेन-देन संबंधी दो कीमतें भी जरूरी नहीं है कि एक जैसी हो। दो ग्राहकों के लिए भी कीमतें अलग-अलग हो सकती हैं। इस आर्थिक वास्तविकता के अंतर्गत निर्यातक एक "अंतर्राष्ट्रीय कीमत" का प्रक्षेपण कर रहा है। वास्तव में, घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत की तुलना लक्षित कीमत से किया जाना अपेक्षित है ताकि कीमत अधोरदन का निर्धारण किया जा सके। यह सार्वभौमिक रूप से स्वीकार एक सिद्धांत है कि कीमत अधोबिक्रयण का निर्धारण लक्षित कीमतों और वास्तविक बिक्री कीमत पर विचार करके किया जा सकता है।
- जहां तक इस तर्क का संबंध है कि वाणिज्यिक उत्पादन के 17 माह के बाद भी घरेलू उद्योग शैशव अवस्था का ही दावा करता है और यह कि इस मामले में भौतिक विमंदन का दावा ऐसी स्थिति में करना जब बिक्री कीमत का प्रापण अंतर्राष्ट्रीय कीमतों से अधिक कीमत पर किया गया हो, असंघार्य हैं; यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्राधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वे घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति का आकलन घरेलू उद्योग के निष्पादन की तुलना जांच की अवधि के दौरान तथा विगत वर्ष के दौरान करके करेंगे। परंपरा यह रही है कि प्राधिकारी पिछले तीन वर्षों पर विचार करते हैं और जांच अवधि में होने वाले निष्पादन की तुलना पिछले तीन वर्षों के निष्पादन से करते हैं। अतः, विशिष्ट रूप से, प्राधिकारी क्षति का आकलन करने के लिए जांच की अवधि तथा पिछले तीन वर्षों की अवधि पर विचार करते हैं। तथापि

वर्तमान मामले में, आवेदनकर्ता का जांच की अवधि के लिए और पिछले तीन वर्षों के लिए कोई वास्तविक प्रचालनात्मक इतिहास नहीं है। यह इस मामले में स्वयं ही यह स्थापित करता है कि आवेदनकर्ता उद्योग एक नया-नया उद्योग है। ऐसा होते हुए भी आवेदनकर्ता ने निम्नलिखित दोनों तरीकों से क्षति की स्थापना की है—

- अपनी अवस्थिति की अवधि के लिए अपने वास्तविक निष्पादन पर विचार करते हुए
- अपने निष्पादन की तुलना प्रक्षेपित/लक्षित निष्पादन से करते हुए

दोनों स्पष्ट रूप से यह स्थापित करते हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति हुई है।

- इस तर्क के संबंध में कि जांच की अवधि से एक वर्ष पहले आयातों में वृद्धि की दर केवल एक प्रतिशत थी, जबकि मांग में वृद्धि की दर 16 प्रतिशत थी, जबकि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन स्तर न्यूनतम था; यह प्रस्तुत किया जाता है कि बाजार में पर्याप्त मांग एवं क्षमता होने के बावजूद घरेलू उद्योग का उत्पादन न्यूनतम ही बना रहा स्वयं ही स्थापित करता है कि घरेलू उद्योग अवनवी क्षमता के अनुरूप उत्पादन करने में सक्षम नहीं हुआ, और इसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति सहन करनी पड़ी। उद्योग, जैसे वर्तमान उद्योग, के तथ्यों एवं परिस्थितियों जहां वाणिज्यिक उत्पादन फरवरी, 2010 में प्रारंभ हुआ और जहां उत्पाद के लिए मांग बहुत अधिक थी तथा घरेलू उद्योग के पास अत्यधिक क्षमताएं थी, इसके बावजूद भी घरेलू उद्योग द्वारा क्षमता उपयोग के लक्षित स्तर तक न पहुंच पाना स्वयं यह स्थापित करता है कि घरेलू उद्योग को अपने उत्पादन का लक्षित सीमा तक वाणिज्यीकरण करने से रोका गया था। किसी उद्योग की स्थापना को उस संदर्भ में देखा जाना चाहिए जिसके लिए इसकी स्थापना की गई है। घरेलू उद्योग ने प्रक्षेपित किया है कि इसका क्षमता उपयोग इसके प्रचालन के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में क्रमशः 60 प्रतिशत, 80 प्रतिशत और 90 प्रतिशत रहेगा। अतः, यह स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग तब तक स्थापित होते रहेगे जब तक कि इसका क्षमता उपयोग 90 प्रतिशत तक न पहुंच जाये। इस लक्षित स्तर के विपरीत घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग न्यून रहना दुखदपूर्ण घटना है। प्राधिकारी को निर्यातक की क्षमता उपयोग पर विचार करना चाहिए और उसकी तुलना घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग से करना चाहिए।
 - इस तर्क के संबंध में की प्रपत्र IV—क यह दर्शाता है कि पिछले वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के उत्पादन, क्षमता उपयोग, बाजार हिस्से तथा बिक्री में वृद्धि हुई है; यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस तर्क में इस विचार का अभाव है कि घरेलू उद्योग का उत्पादन प्रारंभ करने से एक नयी उत्पादन सुविधा का निष्पादन होगा। फरवरी, 2010 में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर देने से यह स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग समय के साथ-साथ अपना उत्पादन और बिक्री बढ़ाने का प्रयास करेगा। यह स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग एक ही दिन में 100 प्रतिशत क्षमता उपयोग प्राप्त कर लेगा। क्षमता उपयोग में धीरे-धीरे सुधार होगा। अतः क्षति अवधि के दौरान उत्पादन और बिक्री में वृद्धि स्पष्टतः यह दर्शाती है कि घरेलू उद्योग बाजार में अपने पैर जमाने का प्रयास कर रहा है। तथापि घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग इसके प्रक्षेपित स्तर से बहुत कम रहा है। यदि पाटन घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहीं है तो घरेलू उद्योग को प्रक्षेपित स्तर की तुलना में इस विपरीत क्षमता उपयोग का सामना क्यों करना पड़ रहा है। यदि हितबद्ध पक्षकारों का यह तर्क है कि आवेदनकर्ता अपना संयंत्र इस स्तर से चलाने में सक्षम नहीं है, यह प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदनकर्ता ने अपना संयंत्र वास्तव में काफी उच्च स्तर से प्रारंभ किया था। तथापि, यह स्तर लम्बे समय तक कायम नहीं रखा जा सका जिसके परिणामस्वरूप मालसूची का भारी संग्रह हुआ और उसके बाद आवेदनकर्ता को अपना उत्पादन कम कर देना पड़ा। क्षति संबंधी सूचना से यह भी देखा जा सकता है कि जब आवेदनकर्ता को यह ज्ञात हुआ कि वह अपने उत्पादन की बाजार में बिक्री करने में असमर्थ है तो उसने बाजार में बिक्री प्रारंभ करने के तत्काल पश्चात बिक्री कीमत में कटौती कर दी। इसके अतिरिक्त कीमत में कटौती करने के पश्चात आवेदनकर्ता को अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए डिस्काउंट आदि में बढ़ोतरी करनी पड़ी घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में उत्पादन और बिक्री शुरू करते ही गिरावट आ गयी। इसके अतिरिक्त, समय के साथ-साथ घरेलू उद्योग के निवल बिक्री प्रापण में भी गिरावट आयी। यह निवल प्रापण में गिरावट और बिक्री कीमत में कटौती घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किये गये न्यून कीमत के बावजूद हुई है। इसके अतिरिक्त यह मानते हुए कि आवेदनकर्ता ने शुरुआती प्रचालन होने के कारण अपनी निर्धारित लागत कुछ अधिक रखी थी परंतु आवेदनकर्ता को अपने लागत ढांचे का निर्धारण इष्टतम क्षमता उपयोग के उच्च स्तर को अपनाकर करना पड़ता है जिसके द्वारा आवेदनकर्ता को अपने प्रचालन की पहली तिमाही में लाभ होना चाहिए परंतु उसे जांच अवधि के समाप्त होने पर वित्तीय घाटा सहन करना पड़ा। दूसरे शब्दों में यदि शुरुआती लागत को हटा दिया जाये तो आवेदनकर्ता ने अपना प्रचालन लाभदायक कीमतों से प्रारंभ किया था परंतु देश में उत्पाद का पाटन होने के कारण उसे नुकसान उठाना पड़ा। घरेलू उद्योग के निवल बिक्री प्रापण की तुलना बिक्री मात्रा से करने पर यह देखा जा सकता है कि घरेलू उद्योग ने जैसे ही अपना प्रापण घटाया वैसे ही उसकी बिक्री में सुधार हुआ। दूसरे शब्दों में घरेलू उद्योग को कुछ मात्रा प्राप्त करने के लिए अपनी बिक्री कीमत के साथ समझौता करना पड़ा। घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत की तुलना संवद्ध देशों से आयातों की भारित औसत उतराई कीमत से करने पर यह देखा जा सकता है कि:
- जब घरेलू उद्योग ने बाजार में अपना उत्पादन शुरू किया तब घरेलू उत्पादन और आयातित उत्पादनों की कीमतों के बीच भारी अंतर था।
 - घरेलू उद्योग ने घरेलू तथा आयातित उत्पाद के इस अंतराल को भरने के लिए अपनी कीमतें कुछ घटा दी। तथापि, घरेलू उत्पाद और आयातित उत्पाद के बीच भारी कीमत भिन्नता होने के कारण आयातों की मात्रा महत्वपूर्ण बनी रही और इसमें कोई गिरावट नहीं आई।

- घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन प्रारंभ कर दिये जाने के पश्चात् आयातों की मात्रा में पर्याप्त गिरावट आनी चाहिए थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि घरेलू उद्योग का उत्पादन “आयात प्रतिस्थापन उत्पाद” था इसलिए घरेलू उद्योग की यह उम्मीद जायज थी कि जैसे ही घरेलू उद्योग का उत्पादन बढ़ेगा वैसे ही इस उत्पाद के आयातों में गिरावट आनी शुरू हो जायेगी और यह बाजार में मांग को कवर कर लेगा।
- भारत में उत्पादन की लागत के संबंध में इस तर्क के बारे में यह उल्लेख किया जाता है कि आवेदनकर्ता ने अपने नवीनतम संयंत्र की स्थापना की थी। और उनके पास ऐसी मशीनें थी जिनकी तुलना विदेशी उत्पादकों के पास उपलब्ध मशीनों से की जा सकती है। तुलनीय प्रौद्योगिकी और संयंत्र तथा उपकरण होने के बावजूद यह असंभव है कि घरेलू उद्योग की परिवर्तन लागत विदेशी उत्पादकों की परिवर्तन लागत की तुलना में पर्याप्त रूप से भिन्न (और अधिक) रहेगी। ऐसे किसी भी दावे का आशय यह होगा कि विदेशी उत्पादकों ने अपने आकड़ों में फेर बदल किया है और वास्तविक परिवर्तन लागत का निग्रहण किया है। इस व्यवसाय में मशीन आपूर्तिकर्ता सीमित ही है और कीमत कारकों में अंतर को ध्यान में रखते हुए एक देश से दूसरे देश में अल्प अंतर के कारण परिवर्तन लागत में भारी अंतर होना संभव है इसका आशय यह है कि तथ्यों का निग्रहण किया जा रहा है या प्राधिकारी को प्रस्तुत तथ्यों का गलत प्रतिनिधित्व किया जा रहा है। आवेदक द्वारा लगाई गई मशीन को कम से कम संबद्ध देशों में अन्य उत्पादकों की तुलना में अधिक कार्य कुशल माना जा सकता है। इस प्रकल्पना का कोई आधार नहीं है कि घरेलू उद्योग की निर्धारित लागत निर्यातकों की निर्धारित लागत से अधिक है। प्रति सीबीएम आधार पर निर्धारित लागत के कुछ तथ्य शुरूआती प्रचालन के कारण अधिक हो सकते हैं परंतु जब क्षमता उपयोग के तर्क संगत स्तर पर लागत पर विचार किया जाता है तो कोई खास अंतर नहीं होना चाहिए। आवेदक यह प्रस्तुत करते हैं कि विदेशी उत्पादक कई उत्पादों का उत्पादन एवं बिक्री कर रहे हैं यह संभव है कि उन्होंने अपने व्यय का समनुदेशन इस ढंग से किया हो कि कीमतों की सुझ विचाराधीन उत्पाद के लिए हो तथा व्यय को अन्य उत्पादों की ओर विपथित किया जा सके। इस संबंध में यह उल्लेख किया जाता है कि लेखाकरण सिद्धांतों में विभिन्न उत्पादों के लिए पृथक् सूचना रखने का कोई अधिदेश नहीं है। अतः, विदेशी उत्पादकों के लिए यह बहुत आसान है कि वह अपने लागत आंकड़ों में फेरबदल कर सकें और न्यूनतर उत्पादन लागत रिपोर्ट कर सकें। अतः यह अक्षमता का प्रश्न नहीं है बल्कि प्राधिकारी को निर्यातकों द्वारा प्रदान कराये जा रहे आंकड़ों में फेर बदल करने/समविचरण करने का प्रश्न है।
 - घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत तथा आयातों की उतराई कीमत के संबंध में दिये गये तर्क के बारे में यह प्रस्तुत किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने अपनी यात्रा की शुरूआत अपने उत्पादों की कीमत का इस तरह निर्धारण करके की थी कि जो इष्टतम उत्पादन लागत से कुछ ही ज्यादा थी जिससे तर्क संगत न्यून स्तर के बजाय कुछ मामूली सा लाभ होता। घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई इतनी यथार्थ परक और तर्क संगत कीमत के बावजूद घरेलू उद्योग की कीमतों तथा आयात कीमतों के बीच अंतर इतना अधिक था कि घरेलू उद्योग को कीमत घटाने के लिए एक तुरंत सुधारात्मक उपाय करना पड़ा इसके बावजूद भी घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा उस स्तर तक नहीं पहुंच पाई जितनी उसकी उत्पादन क्षमता थी अतः घरेलू उद्योग को अपने घरेलू उत्पादों के प्रति ग्राहकों को आकृष्ट करने के लिए डिस्काउंट देना पड़ा। तथापि क्योंकि कीमत अंतर अभी भी बहुत अधिक था इसलिए घरेलू उद्योग उत्पादन का इष्टतम स्तर प्राप्त नहीं कर सका।
 - वारणात्मक संबंध के बारे में यह प्रस्तुत किया जाता है कि घरेलू उद्योग की क्षति पाटित आयातों के कारण हुई है क्योंकि घरेलू उत्पाद और आयातित आयात के बीच भारी कीमत अंतर ने घरेलू उद्योग को अपना उत्पाद उस सीमा तक बेचने से रोक दिया जितनी उसकी उत्पादन क्षमताएं थी जिसके कारण कीमतों में कमी हुई और बिक्री प्रमात्रा में कमी आई, निवल बिक्री प्रापण में कमी हुई, एक ओर आयातों की उतराई कीमत तथा गैर क्षतिकारी कीमत के बीच भारी अंतर तथा दूसरी ओर लक्षित स्तर की सीमा तक अपना उत्पादन बढ़ाने की घरेलू उद्योग की अक्षमता हुई, उत्पादन, मानव शक्ति का भारी नुकसान हुआ, बढ़ते उत्पादन के कारण मालसूची में बढ़ोतरी हुई, मालसूची में बढ़ोतरी के कारण उत्पादन में गिरावट आयी और पाटित आयातों के परिणाम स्वरूप घरेलू उद्योग को सामूहिक रूप से और संचयी रूप से क्षति हुई।
 - इस तर्क के संबंध में कि आवेदनकर्ता ने विचाराधीन उत्पाद की ग्राही खपत से संबंधित जानकारी अपने पास रोक रखी है यह प्रस्तुत किया जाता है कि पर्याप्त जानकारी अभी भी रिकार्ड में उपलब्ध है। यदि प्राधिकारी को कोई अन्य सूचना चाहिए तो आवेदक उसे तुरंत प्रदान करायेगा।
 - इस तर्क में संबंध में की आवेदक और भारत में अन्य सहायक उत्पादकों द्वारा पर्याप्त आयातों की जानकारी दी गई है और संपूर्ण विश्लेषण इन बड़े-बड़े तथ्यों को ध्यान में रखे बिना कर लिया गया है; यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस तर्क में कोई दम नहीं है क्योंकि आवेदक द्वारा किये गये आयात पर्याप्त नहीं है। 68273 सीबीएम के बाजार आकार तथा 50 हजार सीबीएम की क्षमता की तुलना में आवेदक द्वारा *** सीबीएम आयात किया गया।
 - “भारत में किसी भी उद्योग की स्थापना के वास्तविक विमंदन” के बारे में दिये गये तर्क के संबंध में यह प्रस्तुत किया जाता है कि वास्तविक विमंदन के संबंध में डबलू टी ओ सदस्यों के साथ सुझबुझ से वास्तविक विमंदन का आशय पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है। ऐसी स्थिति में भी उत्पाद का पहले से ही उत्पादन किया जा रहा हो प्राधिकारी वहां वास्तविक विमंदन का निर्णय दर्ज कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, वास्तविक विमंदन का आशय यह नहीं है कि कंपनी को अपना वाणिज्यिक उत्पादन शुरू नहीं करना चाहिए। हितबद्ध पक्षकारों के तर्क के विपरीत, वास्तव में इस विषय पर उभरता हुआ क्षेत्राधिकार विल्कुल स्पष्ट है कि अर्थात् प्राधिकारी घरेलू उद्योग की क्षति सूचना की उस सीमा तक जांच करेंगे जहां तक यह मौजूद है। वास्तव में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत विचारों का आशय यह है कि केवल वही कंपनी आवेदन कर सकती है जिसने अपना वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ न किया हो। वस्तुतः इसका आशय यह होगा कि ऐसे उद्योग पर भी पाटन रोधी शुल्क लगाया जा

सकता है जिसने अभी अपना वाणिज्यिक उत्पादन शुरू नहीं किया है। उपर्युक्त के बावजूद आवेदक घरेलू उद्योग द्वारा दायर की गई याचिका स्पष्टतः यह स्थापित करती है कि इसके निष्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ा और समय के साथ-साथ इसके निष्पादन में गिरावट आने लगी। आवेदक ने आवेदन और प्राधिकारी द्वारा किये गये विगत निर्धारणों पर भरोसा किया है। इसने देश में विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करने के लिए विनिर्माण सुविधाएं स्थापित की है। देश में ऐसा कोई अन्य उत्पादक नहीं है जो आवेदक द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किये जाने से पहले विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करता हो। प्राधिकारी द्वारा जांच में शुरूआत में सभी प्रकार की मध्यम घनत्व वाले फाइबर बोर्ड शामिल थे। हितबद्ध पक्षकारों ने पतले बोर्डों का अपवर्जन करने का भारी तर्क इस आधार पर दिया है कि भारत में इसका उत्पादन नहीं किया जा रहा है। प्राधिकारी द्वारा इस बात से स्वयं संतुष्ट होने पर की क्या भारत में विचाराधीन उत्पाद के दायरे को 6 मि.मी और उससे अधिक मोटाई तक सीमित कर रखा है। इसके अतिरिक्त आवेदक ने क्षति अवधि के दौरान उत्पादित और बिक्री किये गये उत्पाद की क्षति के संबंध में जानकारी प्रदान करायी है। प्राधिकारी घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच इसकी मौजूदगी की सीमा तक कर सकते हैं।

- यह तर्क कि आवेदक भारत में पहले से ही एक सुस्थापित उद्योग है और यह कि उसकी उत्पादन लाइन को विभिन्न मोटाई के बोर्डों सहित किसी अन्य उद्योग द्वारा सहायता पहुंचाई जा रही है। परंतु यह आधार निराधार है क्योंकि आवेदक की कोई उत्पादन लाइन नहीं है और मौजूदा ढांचे से पहले फाइबर बोर्ड की बिक्री करने के लिए कोई विशेष ढांचा भी नहीं था। कंपनी का मौजूदा ढांचा भी नहीं था। कंपनी ने तीन उत्पादन लाइनें स्थापित करने का प्रयास किया— (i) पतला फाइबर बोर्ड लाइन (ii) मोटा फाइबर बोर्ड लाइन (इसकी स्थापना की जा रही है) (iii) पार्टिकल बोर्ड लाइन। इसके अतिरिक्त आवेदक ने अन्य डाउन स्ट्रीम उत्पादों जैसे फर्श पर लगाये जाने वाले टाइल्स, डोर रिक्न, लेमिनेटेड फ्लोरिंग, प्रत्यक्ष प्रिंटेड बोर्ड, इंसुलेशन और हार्ड बोर्ड, प्लस बोर्ड, प्लाई बोर्ड, वनिर कोटेड बोर्ड, फर्नीचर और जुड़नार, कंपोजिशन, कंपोजिट बोर्ड, सजावटी लेमिनेटेड बोर्ड, एमडीएफ बोर्ड आदि की उत्पादन सुविधायें भी स्थापित कर ली हैं। यह मानते हुए कि मौजूदा सेटअप उत्पादन की बढ़ती मात्रा को देखते हुए कंपनी पहले से ही “मौजूद थी” और उसके मौजूदा सेटअप को उत्पाद की उत्पादन लाइन का संवर्द्धन करने के लिए एक निश्चित सीमा तक बढ़ाया गया है। यह अभी भी घरेलू उद्योग के अवस्थापन के लिए वास्तविक विमंदन की श्रेणी में आयेगा, जहां तक विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन का सवाल है, अब तक विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन नहीं किया जा रहा था परंतु अब विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करने के लिए नया सेट अप स्थापित कर दिया गया है।
- आंकड़े संग्रहण करने के संबंध में तर्क के बारे में यह आश्चर्यजनक है कि वर्तमान मामले में एक हितबद्ध पक्षकार जांच की अवधि के रूप में 2010-11 पर विचार किये जाने का सुझाव देता है। पहले, यह मामला नवम्बर, 2011 में शुरू किया गया था और इसलिए जांच अवधि 2010-11 वर्तमान उद्देश्यों के लिए काफी पुरानी अवधि होगी। दूसरे विचारीत समय से लम्बी अवधि से किसी भी पक्षकार का हित नहीं होगा। यदि 2010-11 की अवधि वर्तमान उद्देश्य के लिए उपयुक्त होती तो उत्तरवर्ती तिमाही की वृद्धि करना कम अनुचित नहीं होता।
- इस तर्क के संबंध में कि परिवर्तनशील लागत और स्थिर लागत आवेदक के लिए उच्च होगी, आवेदक ने संयंत्र की स्थापना करते समय उनके द्वारा आकलित उत्पादन लागत के संबंध में सूचना प्रदान करायी है यह लागते उत्पादन के न्यून स्तर पर नहीं है। ये लागते क्षमता उपयोग के काफी उच्च स्तर पर हैं। किसी भी हाल में यह तथ्य कि यह आवेदक की उत्पादन लागत अधिक होगी कानून के अंतर्गत आवेदक को राहत प्रदान कराये जाने से वंचित नहीं कर सकती है।
- इस तर्क के संबंध में कि अन्य भारतीय उत्पादक (ग्रीन प्लाई) के उत्पादन आंकड़े ही दिये गये हैं, इसलिए क्षति से संबंधित सभी आंकड़े विलुप्त हो गये हैं, आवेदक ने तर्क दिया है कि “अन्य घरेलू उत्पादकों” के संबंध में क्षति की जानकारी प्रदान कराना कानूनी रूप से अपेक्षित नहीं है। आवेदक ने “घरेलू उद्योग” के बारे में क्षति की जानकारी प्रदान की है। आवेदक ने दावा किया है कि इसमें “घरेलू उद्योग” के आंकड़े शामिल हैं और तदननुसार इसने अपने प्रचालनों के संबंध में भी जानकारी दे दी है। आवेदक ने यह दावा नहीं किया है कि आवेदक तथा ग्रीन प्लाई घरेलू उद्योग बनते हैं। नियमों में घरेलू उद्योग की क्षति का निर्धारण करने की अपेक्षा की जाती है और इस कारण घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति के संबंध में ग्रीन प्लाई से संबंधित जानकारी प्रदान करना पूर्णतः असंगत है। तथापि यह उल्लेख किया गया है कि उत्पाद के पाटन को देखते हुए विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन पूरी तरह से शुरू नहीं किया गया है।
- जहां तक क्षति से संबंधित तर्क का संबंध है, ऐसा कोई नकारात्मक आंकड़ा नहीं है। उत्पादकता में सुधार का आशय यह नहीं है कि घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है वर्तमान याचिका वास्तविक विमंदन के बारे में है। जैसे-जैसे आवेदक अपना उत्पादन प्रारंभ करने के बाद बढ़ता है, यह स्पष्ट हो जाता है कि व्यवसाय संबंधित सभी व्यय पहले किसी कंपनी द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने के रूप में प्रत्याशित वृद्धि प्रदर्शित करेंगे। जहां तक ग्राही खपत का संबंध है संगत जानकारी प्राधिकारी के पास उपलब्ध है। उत्पादन और बिक्री के साथ मालसूची की तुलना स्पष्टतः दर्शाती है कि—
 - i. कंपनी प्रक्षेपित स्तर से कम उत्पादन कर रही थी।
 - ii. उत्पादन के इतने न्यून स्तर के बावजूद मालसूची बढ़ रही थी।
 - iii. कंपनी को अपनी माल सूची बनाये रखने/प्रतिबंधित करने के उद्देश्य से न्यून स्तर के बावजूद अपने उत्पादन में कमी/कटौती करनी पड़ी।

iv. उत्पादन के साथ-साथ मालसूची में वृद्धि उत्पादन पर प्रतिबंध के साथ-साथ मालसूची में गिरावट स्पष्टतः यह स्थापित करती है कि घरेलू उद्योग अपने माल सूची का स्तर बनाये रखने के लिए अपने उत्पादन को नियमित कर रहा है। आवेदक ने प्रस्तुत किया है कि किये गये और उपलब्ध मानव घंटे स्पष्टः यह सिद्ध करते हैं कि घरेलू उद्योग को अपना संयंत्र निष्क्रिय बनाने के लिए बाध्य किया गया है क्योंकि देश में उत्पाद का पाटन हो रहा था।

- जहां तक जीएफए एनएफए और कीमत अधोरदन से संबंधित जानकारी प्रदान न कराये जाने का संबंध है, संगत जानकारी प्राधिकारी के पास उपलब्ध है। नियमों के अंतर्गत प्राधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वह निवेश पर अर्जन पर विचार करते हुए क्षति का निर्धारण करेंगे न कि जीएफए, एनएफए पर विचार करते हुए। इसके अतिरिक्त कीमत अधोबिक्रयण का निर्धारण प्राधिकारी द्वारा किया जाना अपेक्षित है न कि आवेदक द्वारा किया जाना। निर्धारित प्रपत्र में यह अपेक्षा कहीं भी नहीं की गई है कि यह जानकारी आवेदक द्वारा प्रदान करायी जायेगी।
- जहां तक इस तर्क का संबंध है कि इंडोनेशिया से आयात कमोवेश रूप से संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान एक समान बने रहे; किसी एक देश से आयातों की न्यून मात्रा का यह आशय नहीं है कि उससे क्षति नहीं हुई है। यह तर्क किसी ने नहीं दिया है कि इंडोनेशिया से आयात की मात्रा न्यूनतम स्तर पर बनी रही या इंडोनेशिया के बारे में पाटन मार्जिन न्यूनतम है या इंडोनेशिया और किसी अन्य संबद्ध देश के बीच प्रतिस्पर्धा की शर्त वास्तव में अलग थी जिससे कि घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई। जबकि घरेलू उद्योग की क्षति का आकलन समग्र रूप से करने की जरूरत है, यह तथ्य कि किसी एक देश से आयातों की मात्रा संगत रूप से समान बनी रही स्वतः असंगत हो जाती है।
- नियमावली के अनुबंध-1 में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि हर मामले में उन अंतरों पर गुण-अवगुण आधार पर विचार किया जायेगा जो कीमत तुलनात्मकता को प्रभावित करते हो जिसमें बिक्री की शर्तों और निबंधनों में अंतर, कराधान, व्यापार का स्तर, मात्रा, भौतिक गुण धर्म तथा कोई अन्य अंतर शामिल है जो उस स्तर तक प्रदर्शित होता हो जिससे कीमत तुलनात्मकता प्रभावित होती हो। यह देखा जा सकता है कि किसी कारक की केवल मौजूदगी से ही अंतर अपर्याप्त नहीं हो जाता है। ऐसे कारक को वाणिज्य में एक ऐसे कारक के रूप में पहचाना जाए जो कीमतों को प्रभावित करता हो। उत्पादक द्वारा ऐसे कारक का संगत रूप से लगातार प्रयोग किया गया हो। उदाहरण के लिए यदि कोई विदेशी उत्पादक विभिन्न मोटाई के बोर्डों की बिक्री ऐसी कीमत पर कर रहा हो जिसमें मोटाई को एक प्राचल के रूप में न माना गया हो वहां पृथक समान मूल्य, निर्यात कीमत और विभिन्न प्रकार की मोटाई वाले बोर्डों के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण करना जरूरी नहीं होगा। अतः प्राधिकारी पहले प्रश्नावली प्रतिउत्तर तथा आयात आकड़ों की जांच करेंगे और यह निर्धारित करेंगे कि क्या सभी विदेशी उत्पादक कीमतों का निर्धारण करने के लिए उसी प्राचल का अनुसरण कर रहे हैं।
- निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अंतरिम शुल्क की सिफारिश यह निष्कर्ष पर पहुंचने के पश्चात की है कि ऐसी ड्यूटी अधिरोपित करना अनिवार्य हो गया है।
- घरेलू उद्योग उत्पाद के अविवेकपूर्ण पाटन के कारण इस उत्पाद का अपनी क्षमता और सक्षमता के अनुरूप उत्पादन करने के योग्य नहीं रहा है।
- यदि पार्टित आयातों के अलावा किसी अन्य कारक से घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है तो हितपक्ष पक्षकार ऐसे कारक की पहचान करेगा और उसके बाद घरेलू उद्योग पर इसके प्रभाव का प्रदर्शन करेगा। इसके अतिरिक्त जांच की अवधि के दौरान याचिकाकर्ता का उत्पादन कुल भारतीय उत्पादन का 84 प्रतिशत था। अतः यह स्पष्ट है कि आंतरिक प्रतिस्पर्धा के कारण दावाकृत क्षति नहीं हुई है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

124 प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को क्षति के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये विभिन्न प्रस्तुतिकरणों को नोट किया गया है तथा रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों और लागू कानूनों पर विचार करते हुए घरेलू उद्योग की क्षति का विश्लेषण किया है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये प्रस्तुतिकरणों पर संगत समझी गयी सीमा तक विचार किया गया और इन जांच निष्कर्षों की संगत धाराओं में निम्नलिखित रूप से उनकी जांच की गई;

125. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि निर्यात कीमत अंतर्राष्ट्रीय कीमत के तुलनीय थी, इसका आशय यह नहीं है कि संबद्ध वस्तु का पाटन नहीं किया गया है। वास्तव में निर्यातकों की प्रश्नावलियों के प्रत्युत्तर यह दर्शाते हैं कि संबद्ध वस्तु का भारत में पाटन किया गया है।

126 जहां तक इस तर्क का संबंध है कि वाणिज्यिक उत्पादन के 17 महीने बाद भी घरेलू उद्योग ने शैशव स्तर का दावा किया है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने संबद्ध वस्तु का उत्पादन फरवरी, 2010 में शुरू किया था। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग पर विपरीत प्रभाव पड़ा है।

127. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि आयातों में वृद्धि केवल एक प्रतिशत रही है, जबकि मांग में 16 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई; प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि उसका परीक्षण इस पृष्ठ भूमि में किये जाने की जरूरत है कि उस समय तक भारत में संबद्ध वस्तु का कोई भी घरेलू उत्पादक नहीं था और देश की पूरी मांग आयातों से पूरी की जा रही थी। बाजार में घरेलू उत्पादक की मौजूदगी से बाजार हिस्से पर प्रभाव पड़ने की संभावना है क्योंकि अब प्रयोगकर्ता संबद्ध वस्तु का प्रापण स्वदेशी स्रोत के जरिए भी कर सकते थे।

128. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि प्रपत्र ivक यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग के उत्पादन, क्षमता उपयोग, बाजार हिस्से और बिक्री में जांच की अवधि में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है; प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के निष्पादन में यह विचार करते हुए सुधार होने की

संभावना थी कि इसने अभी हाल ही में संबद्ध वस्तु का उत्पादन शुरू किया था। प्रत्येक उत्पादक अपने निष्पादन में उत्पादन और बिक्री के रूप में सुधार करने के लिए आवश्यक कदम उठाता है। उनके परिणामस्वरूप क्षमता उपयोग में धीरे-धीरे सुधार होता है। अतः क्षति अवधि के दौरान उत्पादन और बिक्री में वृद्धि स्पष्टतः घरेलू उद्योग द्वारा बाजार में अपनी स्थिति सुधारने के लिए किए गए प्रयासों को दर्शाती है। तथापि, इसका क्षमता उपयोग प्रक्षेपित स्तर से बहुत कम रहा है।

129. भारत में उत्पादन लागत के संबंध में दिये गये तर्क के बारे में यह नोट किया जाता है कि आवेदक ने अपना संयंत्र अभी हाल ही में स्थापित किया था और उसने ऐसी मशीनें स्थापित करने का दावा किया है जो विदेशी उत्पादकों के पास उपलब्ध मशीनों के अनुरूप थी। उनके द्वारा यह तर्क दिया गया है कि तुलनीय प्रौद्योगिकी, संयंत्र एवं उपकरण, पर विचार करते हुए घरेलू उद्योग की परिवर्तन लागत विदेशी उत्पादकों की परिवर्तन लागत की तुलना में अधिक नहीं होगी। इसके अतिरिक्त यह तर्क दिया गया है कि इस व्यापार में मशीनों के आपूर्तिकर्ता बहुत सीमित हैं और यह कीमत कारकों पर प्रभाव के कारण अंतर बहुत कम हो सकता है कि फिर भी परिवर्तन लागत में इतना अधिक अंतर संभव नहीं है। प्राधिकारी को घरेलू उद्योग के इस दावे में दम प्रतीत होता है कि शुरुआती प्रचालनों के कारण लागत अधिक हो सकती है क्योंकि प्रति सीबीएम आधार पर स्थिर लागत के कुछ तत्व अलग हो सकते हैं परंतु यदि इन लागतों पर विचार क्षमता उपयोग के तर्कसंगत स्तर पर किया जाता है तो कोई खास अंतर प्राप्त नहीं होगा।

130. सार्वजनिक हित के मुद्दे के संबंध में: प्राधिकारी पुनः नोट करते हैं कि पाटन रोधी शुल्क का उद्देश्य सामान्यतः 'पाटन' के अनुचित व्यापार प्रक्रियाओं द्वारा घरेलू उद्योग को होने वाली 'क्षति' का उपशमन करना है ताकि भारतीय बाजार में मुक्त एवं पक्षपात रहित प्रतिस्पर्धा की स्थापना की जा सके जो देश के आम हित में है। पाटन रोधी शुल्क अधिरोपण करने का आशय संबद्ध देशों/भूभागों से आयातों को प्रतिबंधित करना बिल्कुल नहीं है और अतः इससे उपभोक्ता को संबद्ध वस्तु की उपलब्धता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह माना जाता है कि पाटन रोधी शुल्क का अधिरोपण करने से सम्बद्ध वस्तु का प्रयोग करके विनिर्मित उत्पादों के कीमत स्तर को प्रभावित किया जा सकता है और इसके परिणामस्वरूप इन उत्पादों की संगत प्रतिस्पर्धात्मकता पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है। तथापि पाटनरोधी शुल्क खासकर यदि पाटनरोधी शुल्क की वसूली को ऐसी सीमा तक प्रतिबंधित कर दिया जाता है जो घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति कम करने के लिए जरूरी हो तो उससे भारतीय बाजारों में पक्षपात रहित प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी। इसके विपरीत पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने से पाटन प्रक्रिया द्वारा अर्जित अनुचित लाभ दूर होगा, घरेलू उद्योग के पतन को रोकेंगे और संवद्ध वस्तु के ग्राहकों को व्यापक पसंद उपलब्ध कराने में सहायक होगी।

131. इस तर्क के संबंध में की आवेदक घरेलू उद्योग द्वारा भारी मात्रा में आयात किया गया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस तर्क में कोई दम नहीं है कि क्योंकि आवेदक द्वारा प्रभावित आयात *** सीबीएम की सीमा तक बने रहे जिसे महत्वपूर्ण के रूप में नहीं माना जा सकता है, साथ ही इसका बाजार आकार 68,273 सीबीएम है और घरेलू उद्योग ने 50,000 सीबीएम की क्षमता संस्थापित कर ली है।

132. इस तर्क के संबंध में की आवेदक एक सुस्थापित भारतीय उद्योग है और उनकी उत्पादन लाइन का अनुपूरण विभिन्न मोटाई द्वारा किया जा रहा है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यह तथ्य गलत है क्योंकि आवेदक के पास मौजूदा ढांचे से पहले फाइबर बोर्ड का उत्पादन करने और उसकी बिक्री करने के लिए कोई उत्पादन लाइन नहीं थी।

133. आंकड़ा संग्रहण के संबंध में दिये गये तर्क के बारे में प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान मामला 11 नवम्बर, 2011 को शुरू किया गया था; अतः जांच की अवधि 2010-11 मानना बहुत अधिक पुरानी हो जाएगी। इसके अतिरिक्त लम्बी अवधि प्राधिकारी को कथित पाटन और उसके परिणाम स्वरूप होने वाली क्षति का निर्धारण करने के लिए संगत रूप से हाल ही की अवधि के आंकड़े प्राप्त हो जायेंगे।

134. इस तर्क के संबंध में कि एक अन्य उत्पादक (मैसर्स ग्रीन प्लाई) के उत्पादन आंकड़ों को दिया गया है तथा क्षति से संबंधित अन्य सभी आंकड़े गायब हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि मैसर्स ग्रीन प्लाई ने विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन अभी पूरी तरह से शुरू भी नहीं किया था।

135. क्षति से संबंधित तर्क के बारे में प्राधिकारी नोट करते हैं कि केवल यह उम्मीद की गई थी कि आवेदक द्वारा अपने उत्पादन में शुरू में संवृद्धि करने से सकारात्मक विकास होगा। उत्पादन और बिक्री की तुलना माल सूची के साथ करने से यह स्पष्ट होता है कि कंपनी प्रक्षेपित स्तर से बहुत कम स्तर का उत्पादन कर रही थी। इतने न्यून स्तर के उत्पादन के बावजूद इसकी माल सूची में लगातार वृद्धि हो रही थी जिसके कारण इसे न्यून स्तर के बावजूद अपने उत्पादन में कमी/कटौती करनी पड़ी जिससे की माल सूची को कायम/प्रतिबंधित रखा जाये। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि पाटित आयातों की मौजूदगी के कारण उन्हें अपनी माल सूची के स्तर को बनाये रखने के लिए अपने उत्पादन को विनियमित करना पड़ता है।

136. इस तर्क के संबंध में कि इंडोनेशिया से आयात संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान कमोवेश रूप से एक समान स्तर के बने रहे प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इंडोनेशिया से आयातों की समान मात्रा का आशय यह नहीं है कि उनसे घरेलू उद्योग को क्षति कारित नहीं हुई होगी। इंडोनेशिया से आयातों की मात्रा न्यूनतम से अधिक है और पाटन मार्जिन बहुत अधिक है।

137. क्षति से संबंधित अन्य मुद्दे जैसे उत्पादन लागत, आवेदक कंपनी द्वारा क्षमता उपयोग, बाजार हिस्सा, क्षमता तथा मांग, आवेदक की बिक्री कीमत तथा आयात कीमत के बीच संबंध, कीमत अधोदहन या कीमत अधोबिक्रयण, लाभप्रदायकता, उत्पादकता, कच्चे माल की लागत और वेतन में वृद्धि, कारणात्मक संबंधों का अभाव आदि की इस जांच परिणाम की संगत धाराओं में समुचित रूप से जांच की गई है।

138. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाये गये अन्य मुद्दों की जांच इस अंतिम निष्कर्ष में उपयुक्त शीर्षकों के अंतर्गत की गई है।

संचयी आकलन

139. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (iii) में प्रावधान है कि यदि एक देश से अधिक देशों से पाटनरोधी जांच के अध्यक्षीन किसी उत्पाद का आयात एक साथ किया जा रहा है, तो प्राधिकारी इन आयातों के संचयी प्रभावों का आकलन करेंगे यदि यह निर्धारित किया जाता है कि :-

क. प्रत्येक देश से आयातों के संबंध में स्थापित पाटन निर्यात कीमत के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त 2 प्रतिशत से अधिक है और प्रत्येक देश से आयात की मात्रा समान वस्तु के आयातों का तीन प्रतिशत (या अधिक) है या जहां व्यक्तिगत देशों का निर्यात तीन प्रतिशत से कम है वहां ये आयात समान वस्तु के आयातों का सामूहिक रूप से 7 प्रतिशत से अधिक माने जाते हैं; और

ख. आयातों के प्रभाव का संचयी आकलन करना आयातित वस्तु तथा समान घरेलू वस्तु के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थिति के आलोक में उचित है।

140. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि:-

- भारत में संबद्ध वस्तु का पाटन विभिन्न देशों से किया जा रहा है
- प्रत्येक संबद्ध देश से पाटन का मार्जिन निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है;
- प्रत्येक संबद्ध देश से आयातों की मात्रा निर्धारित नगण्य सीमा से अधिक है
- आयातों के प्रभावों का संचयी आकलन करना उचित है क्योंकि संबद्ध देशों से निर्यात सीधे भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत समान वस्तु से प्रतिस्पर्धा करते हैं जो निम्नलिखित साक्ष्यों से स्पष्ट है:-

क. संबद्ध देशों के उत्पादकों द्वारा विनिर्मित उत्पाद और आवेदक द्वारा विनिर्मित उत्पाद के तुलनीय गुणधर्म हैं। दूसरे शब्दों में, विभिन्न संबद्ध देशों द्वारा आपूरित वस्तु और घरेलू उद्योग द्वारा आपूरित वस्तु परस्पर समान वस्तुएं हैं

ख. कुछ ऐसे समान पक्षकार हैं जो विभिन्न स्रोतों से आयातित संबद्ध वस्तु और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु का उपयोग करते हैं। आयातित तथा घरेलू संबद्ध वस्तु दोनों का प्रयोग व्यतिहार्य रूप से किया जा रहा है और घरेलू उत्पाद तथा आयातित उत्पादों के बीच परस्पर प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा है

ग. संबद्ध देशों से निर्यातकों और घरेलू उद्योग ने समान अवधि में समान ग्राहकों को उत्पाद की बिक्री की है। बिक्री सरणियां तुलनीय हैं।

घ. प्रत्येक संबद्ध देश से किये गये आयात की मात्रा महत्वपूर्ण है।

141. उपर्युक्त को देखते हुए प्राधिकारी विचार करते हैं कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के निर्यातों से घरेलू उद्योग को होने वाली संचयी क्षति का आकलन करना उपर्युक्त होगा।

142. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में (क) समान वस्तु के लिए घरेलू बाजार में पाटित आयातों की मात्रा और कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव; और (ख) इन वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव दोनों रूपों में उद्देश्य परक जांच करने का प्रावधान किया गया है। पाटित आयातों के मात्रा प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी को यह जांच करना अपेक्षित होता है कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप से या उत्पादन के संगत रूप से या भारत में खपत के रूप में भारी वृद्धि हुई है। पाटित आयातों के कीमत प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी से यह जांच करने की अपेक्षा की जाती है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा अत्यधिक कीमत अधोरदन किया गया है या इन आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों का भारी मात्रा में निग्रहण करने पर पड़ेगा या ये कीमत बढ़ने से रोकेगी जो अन्यथा भारी मात्रा में बढ़ी होती।

143. घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में पाटन रोधी नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (iv) में निम्नलिखित उल्लेख किया गया है कि; 'संबंधित घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में उन सभी संगत आर्थिक कारकों तथा देशनाकों का मूल्यांकन शामिल होगा जिनका घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है इसमें शामिल है बिक्री में प्राकृतिक एवं संभावित गिरावट, लाभ, आउटपुट, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेश पर अर्जन या क्षमता उपयोग; घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक, पाटन मार्जिन का विस्तार, नकदी प्रवाह पर वास्तविक तथा संभावित नकारात्मक प्रभाव, माल सूची, रोजगार, वेतन, वृद्धि, पूंजी निवेश उगाहने की क्षमता'।

144. आवेदक घरेलू उद्योग ने दावा किया कि भारत में उत्पाद के पाटन से घरेलू उद्योग को क्षति कारित हुई है। इस संबंध में यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने अपना वाणिज्यिक उत्पादन फरवरी, 2010 में शुरू किया था और इस कारण इसका तीन वर्षों से अधिक का प्रचालन इतिहास नहीं है। अतः, संबंधित घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के प्रयोजन के लिए घरेलू उद्योग के निष्पादन का आर्थिक विश्लेषण उस अवधि के लिए किया गया है जिसके लिए याचिकाकर्ता ने उत्पाद का उत्पादन एवं उसकी बिक्री की है। यह विश्लेषण पहले वार्षिक आधार पर किया गया और उसके बाद घरेलू उद्योग के निष्पादन पर तिमाही दर तिमाही आधार पर विचार करते हुए किया गया। तथापि, आयात मात्रा और बाजार हिस्से के प्रयोजन के लिए प्राधिकारी ने जांच की अवधि तथा विगत तीन वर्षों के आंकड़ों पर विचार किया है।

पाटित आयातों का मात्रा प्रभाव तथा घरेलू उद्योग पर प्रभाव

भारत में मांग/खपत

145. देश में उत्पाद की मांग का आकलन घरेलू उत्पादकों द्वारा घरेलू बिक्री तथा सभी स्रोतों से आयातों के जोड़ के रूप में किया गया है।

वार्षिक विश्लेषण

विवरण	मापन की इकाई	2007-08	2008-09	2009-10	अप्रैल10-जून11 (जांच की अवधि)	वार्षिकीकृत (जांच की अवधि)
घरेलू उद्योग की बिक्री	सीबीएम	-	-	334	21,297	17,038
अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री	सीबीएम	-	-	-	4,030	3,224
संबद्ध देशों के आयात	सीबीएम	10,936	32,223	44,009	58,504	46,803
अन्य देशों के आयात	सीबीएम	975	11,704	8,618	1,510	1,208
भारत में मांग	सीबीएम	11,911	43,927	52,961	85,341	68,273

तिमाही विश्लेषण

मांग	मापन की इकाई	फरवरी10-मार्च10	अप्रैल10-जून10	जुलाई10-सितम्बर10	अक्टूबर10-दिसम्बर10	जनवरी11-मार्च11	अप्रैल11-जून11
घरेलू उद्योग की बिक्री	सीबीएम	***	***	***	***	***	***
अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री	सीबीएम	-	-	-	***	***	***
संबद्ध देशों के आयात	सीबीएम	8,259	10,486	8,807	10,284	14,985	13,942
अन्य देशों के आयात	सीबीएम	959	306	236	260	382	326
भारत में मांग	सीबीएम	9,552	13,016	12,870	15,852	21,161	22,443

146. यह नोट किया जाता है कि इस अवधि के दौरान भारत में विचाराधीन उत्पाद की मांग में वृद्धि हुई है।

संबद्ध देशों से आयात की मात्रा

147. संबद्ध देशों तथा अन्य देशों से संबद्ध वस्तु के आयात की मात्रा की जांच घरेलू उद्योग द्वारा आईबीआईएस से प्राप्त लेनदेन वार आयात आकड़ों के आधार पर की गई। यह नोट किया जाता है कि विचाराधीन उत्पाद का कोई समर्पित सीमा शुल्क वर्गीकरण कोड नहीं है और इसलिए संक्षिप्तीकृत सीमा शुल्क आंकड़ों (डीजीसीआईएंडएस द्वारा रिलीज किये गये) पर विश्वास किया गया है। अतः व्यक्तिगत लेनदेनवार आंकड़ों, गौड़ स्रोत (आईबीआईएस)द्वारा यथा उपलब्ध कराए गये, पर विश्वास किया गया है। कार्यवाही के दौरान सौदावार आंकड़े डीजीसीआई एंड एस से भी प्राप्त किये गये थे। चूंकि आईबीआईएस से प्राप्त सौदावार आंकड़े संबद्ध देशों से आयात की अधिक मात्रा प्रदर्शित करते हैं इसलिए आईबीआईएस से रिपोर्ट की गई आयात मात्रा पर क्षति विश्लेषण के लिए विचार किया गया है। संबद्ध वस्तु की आयात मात्रा निम्नलिखित रही है:

वार्षिक विश्लेषण

आयात मात्रा	मापन की इकाई	2007-08	2008-09	2009-10	अप्रैल10-जून11	वार्षिकीकृत (जांच की अवधि)
इंडोनेशिया	सीबीएम	-	39	6,957	10,177	8,142
मलेशिया	सीबीएम	2,943	20,244	22,783	22,052	17,642
श्रीलंका	सीबीएम	7,934	11,171	13,270	20,410	16,328
चीन जन.गन	सीबीएम	59	769	999	5,865	4,692
कुल संबद्ध देश	सीबीएम	10,936	32,223	44,009	58,504	46,803
अन्य देश	सीबीएम	975	11,704	8,618	1,510	1,208
कुल आयात	सीबीएम	11,911	43,927	52,627	60,014	48,011

तिमाही विश्लेषण

आयात मात्रा	मापन की इकाई	फरवरी10-मार्च10	अप्रैल10-जून10	जुलाई10-सितम्बर10	अक्टूबर10-दिसम्बर10	जनवरी11-मार्च11	अप्रैल11-जून11
इंडोनेशिया	सीबीएम	3,553	3,690	1,984	1,130	1,568	1,805
मलेशिया	सीबीएम	2,417	3,873	4,221	3,643	6,131	4,184
श्रीलंका	सीबीएम	2,093	2,663	2,334	4,371	5,332	5,710
चीन जन.गन	सीबीएम	196	259	269	1,140	1,955	2,243
कुल संबद्ध देश	सीबीएम	8,259	10,486	8,807	10,284	14,985	13,942
अन्य देश	सीबीएम	959	306	236	260	382	326
कुल आयात	सीबीएम	9,218	10,792	9,043	10,543	15,368	14,268

148. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि

(क) संबद्ध देशों से आयात में भारी वृद्धि हुई। जांच के अवधि के अंतर्गत तिमाही आधार पर अथवा क्षति अवधि के लिए विचारित आयातों में वृद्धि हुई है।

(ख) इस बात पर विचार करते हुए कि घरेलू उद्योग ने अपना वाणिज्यिक उत्पादन फरवरी, 2010 में प्रारंभ किया था, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन प्रारंभ किये जाने से आयात की मात्रा में गिरावट आनी चाहिए थी। परंतु पिछली तिमाही की तुलना में जुलाई, 2010-सितम्बर, 2010 की तिमाही को छोड़कर अन्य किसी तिमाही में संबद्ध देश से आयात की मात्रा में गिरावट नहीं आई है। इसके अतिरिक्त उत्तरवर्ती तिमाहियों में आयात मात्रा में प्राकृतिक गिरावट दिखाने के बजाय वृद्धि हुई है और अब यह पहले की तुलना में कहीं अधिक है;

(ग) आयातों में वृद्धि काफी अधिक है। जबकि 2007-08 में आयात की मात्रा 11911 सीबीएम थी, अप्रैल-जून, 2011 तिमाही में यह मात्रा 14268 सीबीएम हो गई। समग्र आधार पर आयातों की मात्रा में वृद्धि क्षति अवधि के दौरान 300 प्रतिशत से अधिक हुई है।

मांग में बाजार हिस्सा

149. अधोलिखित तालिका आयातों के बाजार हिस्से में प्रवृत्ति तथा घरेलू उद्योग के हिस्से की प्रवृत्ति का विश्लेषण वार्षिक आधार पर तथा तिमाही आधार पर किया गया है:-

वार्षिक विश्लेषण

विवरण	मापन की इकाई	2007-08	2008-09	2009-10	अप्रैल 10- जून 11
घरेलू उद्योग	%	-	-	0.63	24.96
अन्य भारतीय उत्पादक	%	-	-	-	4.72
कुल संबद्ध देश	%	91.81	73.36	83.10	68.55
अन्य देश	%	8.19	26.64	16.27	1.77

तिमाही विश्लेषण

विवरण	मापन की इकाई	फरवरी 10- मार्च '10	अप्रैल '10- जून '10	जुलाई '10- सितम्बर '10	अक्टू '10- दिस. '10	जन. '11- मार्च '11	अप्रैल '11- जून '11
घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***	***	***
अन्य भारतीय उत्पादक	%	***	***	***	***	***	***
कुल संबद्ध देश	%	86.46	77.99	66.22	64.87	73.81	62.12
अन्य देश	%	10.04	2.28	1.78	1.64	1.88	1.45

150. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने अपना वाणिज्यिक उत्पादन वर्ष 2009-10 में शुरू किया था। इस अवधि के दौरान घरेलू उद्योग ने केवल दो माह तक कार्य किया था। वर्ष 2010-11 याचिकाकर्ता कंपनी के लिए वाणिज्यिक उत्पादन का पहला वर्ष था। संबद्ध देशों के हिस्से का तिमाही वार विश्लेषण दर्शाता है कि अन्य देशों के आयातों के हिस्से में भारी गिरावट आयी परंतु संबद्ध देशों के आयातों की मात्रा में कोई कमी नोट नहीं कि गई इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग का हिस्सा कुल मांग में तिमाही दर तिमाही आधार पर घटता बढ़ता रहा है।

उत्पादन, बिक्री, क्षमता एवं क्षमता उपयोग

151. घरेलू उद्योग का उत्पादन, बिक्री क्षमता और क्षमता उपयोग का विश्लेषण निम्नवत किया गया है;

वार्षिक विश्लेषण

	मापन की इकाई	2009-10	अप्रैल '10- जून '11	वार्षिकीकृत (जांच की अवधि)
कुल उत्पादन	सीबीएम	***	***	***
6 मिमी से कम	सीबीएम	2,262	22,980	18,384
6 मिमी से ज्यादा	सीबीएम	-	***	***
बिक्री मात्रा	सीबीएम	334	21,297	17,038
ग्राही खपत	सीबीएम	***	***	***
क्षमता	सीबीएम	8,333	62,500	50,000
क्षमता उपयोग (@ @)	%	***	***	***

@ @ कुल उत्पादन पर आधारित

तिमाही विश्लेषण

	मापन की इकाई	फरवरी 10- मार्च '10	अप्रैल '10- जून '10	जुलाई '10- सितम्बर '10	अक्टू '10- दिस. '10	जन. '11- मार्च '11	अप्रैल '11- जून '11
कुल उत्पादन	सीबीएम	***	***	***	***	***	***
6 मिमी से कम	सीबीएम	***	***	***	***	***	***
6 मिमी से ज्यादा	सीबीएम	***	***	***	***	***	***
बिक्री मात्रा	सीबीएम	***	***	***	***	***	***
ग्राही खपत	सीबीएम	***	***	***	***	***	***
क्षमता	सीबीएम	***	***	***	***	***	***
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***	***	***

घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

152. पाटित आयातों का कीमतों पर प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी को यह विचार करना अपेक्षित होता है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में उत्पादित समान उत्पाद की कीमत की तुलना में भारी कीमत अधोरदन किया गया है या क्या इन आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों का भारी मात्रा में निग्रहण कर रहा है अथवा उनको बढ़ने से रोक रहा है जो अन्यथा भारी मात्रा में बढ़ी होती। आयात कीमतों के वार्षिक उतार-चढ़ाव का विश्लेषण निम्नलिखित है

इकाई रु./सीबीएम में

सीआईएफ आयत कीमत	मापन की इकाई	2007-08	2008-09	2009-10	अप्रैल '10- जून '11
इंडोनेशिया	रु/सीबीएम	-	12,831	11,104	11,362
मलेशिया	रु/सीबीएम	10,980	11,609	10,726	11,797
श्रीलंका	रु/सीबीएम	12,352	13,236	11,929	12,616
चीन	रु/सीबीएम	7,488	10,234	11,307	11,198
कुल संबद्ध देश	रु/सीबीएम	11,956	12,142	11,162	11,947
अन्य देश	रु/सीबीएम	12,785	12,378	11,434	13,619
कुल आयात	रु/सीबीएम	12,024	12,205	11,206	11,989

153. आयातों कीमतों के उतार चढ़ाव का तिमाही विश्लेषण निम्नलिखित है

सीआईएफ आयत कीमत	मापन की इकाई	फरवरी 10- मार्च '10	अप्रैल '10- जून '10	जुलाई '10- सितम्बर '10	अक्टू '10- दिस. '10	जन. '11- मार्च '11	अप्रैल '11- जून '11
कुल संबद्ध देश	सीबीएम	11,572	11,764	11,847	11,818	11,934	12,256
अन्य देश	सीबीएम	12,288	12,802	14,993	14,497	13,264	13,108
कुल आयात	सीबीएम	11,647	11,794	11,929	11,884	11,967	12,276

154. उपर्युक्त से प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि क्षति अवधि तथा जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देशों से आयात की सीआईएफ कीमत में कोई नोटिस करने योग्य परिवर्तन नहीं आया है। इसके अतिरिक्त, अन्य देशों से आयात की सीआईएफ कीमत संबद्ध देशों से सीआईएफ कीमत की तुलना में अधिक नोट की गई है।

155. जैसा कि उपर नोट किया गया, संबद्ध देशों से आयातों की सीआईएफ कीमत क्षति अवधि तथा जांच अवधि के दौरान में कोई परिवर्तन नहीं आया। प्राधिकारी ने संगत अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं के लिए कच्चे माल की कीमत की प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया। इस संदर्भ में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि लकड़ी, गोंद की लागत तथा अन्य रसायनों की लागत उत्पादन लागत के महत्वपूर्ण तत्व हैं। घरेलू उद्योग तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों का विश्लेषण दर्शाता है कि लकड़ी, गोंद की लागत तथा अन्य तत्वों की लागत कुल उत्पादन लागत का 50 प्रतिशत से अधिक है। घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत की प्रवृत्तियों का विश्लेषण यह दर्शाता है कि परियोजना रिपोर्ट में यथाप्रक्षेपित कीमतों की तुलना में लकड़ी की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है। कच्चे माल अर्थात् संबद्ध देशों से अन्य निर्यातकों के बारे में लकड़ी की कीमतों में उतार चढ़ाव के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि लकड़ी की कीमतों में प्रवृत्ति के संबंध में जानकारी एक सहयोगकर्ता निर्यातक मैसर्स एवर ग्रीन की वेबसाइट पर उपलब्ध है जो निम्नलिखित प्रवृत्ति दर्शाती है।

सूचीबद्ध	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	जांच की अवधि
लकड़ी की कीमत सूचीबद्ध *	136	132	121	148	160
सूचीबद्ध लकड़ी की कीमतें	100	97	89	109	118

* वर्ष 2005 को आधार वर्ष मानते हुए

156. उपर्युक्त से प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि क्षति अवधि तथा जांच की अवधि के दौरान लकड़ी की कीमतों में 18 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। तथापि यह संबद्ध देशों से आयातों की सीआईएफ कीमत में परिवर्तन में प्रदर्शित नहीं होती है। उपर्युक्त के मुताबिक प्रवृत्ति दर्शाती है कि संबद्ध देशों से निर्यातकों ने उत्पादन की लागत में होने वाली वृद्धि का आमेहन कर लिया है कि जैसा कि यह सीआईएफ निर्यात कीमत के परिवर्तनों में प्रदर्शित नहीं होता है।

157. प्राधिकारी पुनः नोट करते हैं कि लकड़ी के अलावा, संबद्ध वस्तु का उत्पादन करने के लिए गोंद एक महत्वपूर्ण तत्व है। गोंद का विनिर्माण विभिन्न रसायनों का संयोजन करके किया जाता है जिसमें सार्वधिक महत्वपूर्ण पैराफीन मोम, यूरिया, मेलामाइन और मेथनोल होता है। इन कच्चे माल की आयात कीमतों में प्रवृत्तियों का विश्लेषण, जैसा कि नीचे संक्षेप में किया गया है, यह दर्शाता है कि इन कच्चे पदार्थों में से कुछ की दरों में भारी वृद्धि हुई है।

	यूनिट	07-08	सूचीबद्ध	2010-11	सूचीबद्ध	% वृद्धि
इनपुट कीमत में उतार- चढ़ाव						
पैराफीन मोम	रु./कि.ग्रा	40.26	100	57.21	142	42
यूरिया / (कारवामी)	रु./कि.ग्रा	12.32	100	13.24	107	7
मेलामाइन	रु./कि.ग्रा	50.56	100	67.18	133	33
मेथनाल	रु./कि.ग्रा	36.12	100	40.61	112	12

158. यह नोट किया जाता है कि गोंद तथा अन्य प्रमुख इनपुटों की इनपुट लागत में भारी वृद्धि हुई है। तथापि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु की सीआईएफ निर्यात कीमत में कोई समनुरूपी वृद्धि नोट नहीं की गई है। उपर्युक्त के आलोक में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इनपुट कीमतों में उतार चढ़ाव का निर्यातकों द्वारा अवशोषण कर लिया गया है। संबद्ध देशों से सहयोग कर्ता निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत किये गये आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर प्राधिकारी नोट करते हैं कि इन निर्यातकों का तृतीय देशों के भारी मात्रा में निर्यात किया जाता है। संबद्ध देशों के सभी सहयोगकर्ता निर्यातकों के मामले में जांच की अवधि से पहले के तीन वर्षों के लिए बिक्री प्राप्ति से यह नोट किया जाता है कि वे भारत को निर्यात कीमत की तुलना में काफी अधिक रहे हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि जांच की अवधि के पहले के तीन वर्षों के लिए भारत को निर्यातित संबद्ध वस्तु की कीमतें पाटित कीमतें थीं।

कीमत अधोरदन और अधोबिक्रयण प्रभाव

159. कीमत अधोरदन का निर्धारण संपूर्ण जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से पाटित आयातों के भारित औसत उतराई मूल्य की तुलना घरेलू उद्योग के भारित औसत निवल बिक्री प्राप्ति से करके किया गया। इस उद्देश्य के लिए संबद्ध देशों से आयात कीमतों के आईबीआईएस आंकड़ों में रिपोर्ट किये गये मूल्य में लागू आधारभूत सीमा शुल्क तथा एक प्रतिशत हैंडलिंग प्रभार जोड़कर आयातों की उतराई मूल्य का परिकलन किया गया है।

160. घरेलू उद्योग के निवल बिक्री प्रापण का निर्धारण करने के उद्देश्य से घरेलू उद्योग द्वारा दिये गये डिस्काउंट, कमीशन आदि और संदत केन्द्रीय उत्पाद कर, यदि कोई हो, को कुल बिक्री प्रापण से कम करके किया गया है।

161. कीमत अधोबिक्रयण का निर्धारण करने के लिए संबद्ध देशों से आयातों की भारित औसत उतराई कीमत की तुलना जांच की अवधि के दौरान निर्धारित घरेलू उद्योग की गैर क्षतिकारी बिक्री कीमत से करके किया गया है।

कीमत अधोरदन

162. घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्रापण का आयातों की उतराई कीमत से तुलनात्मक विश्लेषण दर्शाता है कि आयातों से उद्योग की कीमतों का निम्नलिखित सीमा तक अधोरदन हो रहा है।

कीमत अधोरदन	मापन की इकाई	2009-10	अप्रैल'10-जून'11 (जांच की अवधि)
घरेलू उद्योग का एनएसआर	रु./सीबीएम	***	***
इंडोनेशिया			
उतराई कीमत	रु./सीबीएम	12,370	12,657
अधोरदन	रु./सीबीएम	***	***
अधोरदन	%	***	***
अधोरदन	% रेंज	30-40	20-30
मलेशिया			
उतराई कीमत	रु./सीबीएम	11,948	13,142
अधोरदन	रु./सीबीएम	***	***
अधोरदन	%	***	***
अधोरदन	% रेंज	30-40	20-30
श्रीलंका			
उतराई कीमत	रु./सीबीएम	11,929	12,616
अधोरदन	रु./सीबीएम	***	***
अधोरदन	%	***	***
अधोरदन	% रेंज	35-45	20-30
चीन			
उतराई कीमत	रु./सीबीएम	12,596	12,474
अधोरदन	रु./सीबीएम	***	***
अधोरदन	%	***	***
अधोरदन	% रेंज	30-40	25-35
कुल संबद्ध देश			
उतराई कीमत	रु./सीबीएम	12,024	12,807
अधोरदन	रु./सीबीएम	***	***
अधोरदन	%	***	***
अधोरदन	% रेंज	30-40	20-30

नोट:— वर्ष 2009-10 के लिए पूरे वर्ष के आयातों के लिए उतराई कीमत का परिकलन और घरेलू उद्योग के लिए फरवरी, 10 से मार्च, 10 दो माह का एनएसआर।

163. उपर्युक्त से प्राधिकारी नोट करते हैं कि सभी संबद्ध देशों से उतराई कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत का अधोरदन कर रही है। प्राधिकारी पुनः नोट करते हैं कि वर्ष 2009-10 से जांच की अवधि के दौरान आयातों की उतराई मूल्य में मामूली सी वृद्धि हुई है परंतु घरेलू उद्योग के एनएसआर

में भारी गिरावट के कारण कीमत अधोरदन की प्रमात्रा में कमी आई है। अतः प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग को अपनी बिक्री कीमत में आयातों के उतराई मूल्य के अनुरूप कटौती करने को मजबूर किया गया यद्यपि इससे क्षति होती रही जैसाकि उत्तरवर्ती जांच परिणामों में अभिव्यक्त किया गया है।

तिमाही विश्लेषण

कीमत अधोरदन	मापन की इकाई	फरवरी 10- मार्च 10	अप्रैल'10- जून'10	जुलाई'10- सितम्बर'10	अक्तू.'10- दिस. '10	जन.'11- मार्च'11	अप्रैल'11- जून '11
घरेलू उद्योग का एनएसआर	रु./सीबीएम	***	***	***	***	***	***
इंडोनेशिया							
उतराई कीमत	रु./सीबीएम	12,681	13,062	11,898	11,963	12,387	13,335
अधोरदन	रु./सीबीएम	***	***	***	***	***	***
अधोरदन	%	***	***	***	***	***	***
अधोरदन	% रेंज	30-40	20-30	25-35	25-35	25-35	20-30
मलेशिया							
उतराई कीमत	रु./सीबीएम	11,572	12,341	13,135	12,942	13,225	13,945
अधोरदन	रु./सीबीएम	***	***	***	***	***	***
अधोरदन	%	***	***	***	***	***	***
अधोरदन	% रेंज	35-45	25-35	20-30	20-30	20-30	15-25
श्रीलंका							
उतराई कीमत	रु./सीबीएम	13,171	12,626	12,449	12,464	12,604	12,807
अधोरदन	रु./सीबीएम	***	***	***	***	***	***
अधोरदन	%	***	***	***	***	***	***
अधोरदन	% रेंज	25-35	25-35	20-30	20-30	20-30	25-35
चीन							
उतराई कीमत	रु./सीबीएम	13,954	15,298	17,953	12,317	12,207	11,804
अधोरदन	रु./सीबीएम	***	***	***	***	***	***
अधोरदन	%	***	***	***	***	***	***
अधोरदन	% रेंज	20-30	10-20	नकारात्मक	25-35	25-35	30-40
कुल संबद्ध देश							
उतराई कीमत	रु./सीबीएम	12,511	12,740	12,822	12,562	12,783	13,056
अधोरदन	रु./सीबीएम	***	***	***	***	***	***
अधोरदन	%	***	***	***	***	***	***
अधोरदन	% रेंज	30-40	20-30	20-30	20-30	20-30	20-30

नोट:—केवल फरवरी, 10 मार्च, 10 (2 माह) के लिए विचारित उतराई कीमत परिकलन।

कीमत अधोबिक्रयण

164. घरेलू उद्योग की गैर क्षतिकारी कीमत से बिक्री कीमत की तुलना करने पर यह स्पष्ट होता है कि घरेलू उद्योग को अपने उत्पाद का अधोबिक्रयण करने के लिए मजबूर किया गया।

रु./सीबीएम में

	मापन की इकाई	अप्रैल'10-जून'11 (जांच की अवधि)
गैर क्षतिकारी कीमत	रु./सीबीएम	***
उतराई मूल्य (संबद्ध देश)	रु./सीबीएम	12807
कीमत अधोबिक्रयण	रु./सीबीएम	***
अधोबिक्रयण	%	***
अधोबिक्रयण	% रेंज	50-60

165. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की निबल बिक्री प्रापण घरेलू उद्योग की गैर क्षतिकारी कीमत से कम थी। अतः घरेलू उद्योग संबद्ध वस्तु बिक्री से तर्क संगत लाभ प्राप्त करने में सक्षम नहीं था।

क्षति मार्जिन

166. गैर क्षतिकारी कीमत की तुलना आयातों की उतराई कीमत से करने पर महत्वपूर्ण क्षति मार्जिन प्रदर्शित होता है।

क्षति मार्जिन	मापन की इकाई	एनआईपी	उतराई कीमत	क्षति मार्जिन	क्षति मार्जिन %	क्षति मार्जिन % रेंज
इंडोनेशिया	रु./सीबीएम	***	12,657	***	***	55-65
मलेशिया	रु./सीबीएम	***	13,142	***	***	50-60
श्रीलंका	रु./सीबीएम	***	12,616	***	***	55-65
चीन	रु./सीबीएम	***	12,474	***	***	55-65
कुल संबद्ध देश	रु./सीबीएम	***	12,807	***	***	55-65

167. जांच की अवधि के दौरान सभी संबद्ध देशों से भारी क्षति मार्जिन के परिणाम स्वरूप घरेलू उद्योग को वित्तीय क्षति सहन करनी पड़ी और यह परियोजना रिपोर्ट में दर्शाये गये अनुसार लाभ प्रदायकता के प्रक्षेपित स्तर को प्राप्त करने में सक्षम नहीं हुआ।

लाभ/हानि

168. घरेलू उद्योग द्वारा संबद्ध वस्तु की घरेलू बाजार में बिक्री से अर्जित लाभ निम्नलिखित था:

	मापन की इकाई	2009-10	अप्रैल'10-जून'11 (जांच की अवधि)
बिक्री लागत	रु./सीबीएम	***	***
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति	100	34
बिक्री कीमत	रु./सीबीएम	***	***
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति	100	90
लाभ/ (हानि) प्रति इकाई	रु./सीबीएम	***	***
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति	(100)	(8)
लाभ/ (हानि)	लाख रुपये	***	***
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति	(100)	(519)

169. उपर्युक्त से प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने वर्ष 2009-10 में शुरुआती परिचालनों और क्षमता उपयोग के न्यून स्तर, इसकी वास्तविक लागत, प्रतियूनिट लाभ/हानि बहुत अधिक होने के कारण केवल दो महीने तक प्रचालन कर सका। वर्ष 2009-10 की अवधि केवल शुरुआती

अवधि होने के कारण प्राधिकारी द्वारा कोई प्रवृत्ति विश्लेषण/निष्कर्ष नहीं निकाला जा सका तथापि जांच की उत्तरवर्ती अवधि में घरेलू उद्योग ने एक संपूर्ण वित्त वर्ष के लिए प्रचालन किया था। इस अवधि के दौरान भी घरेलू उद्योग का वित्तीय निष्पादन नकारात्मक ही नोट किया गया था। प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के बिक्री प्रापण में गिरावट आयी और घरेलू उद्योग को वित्तीय क्षति उठानी पड़ी।

निवेश पर अर्जन

170. घरेलू उद्योग द्वारा घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तु की बिक्री से अर्जित निवेश पर आवक निम्नलिखित है:

	मापन की इकाई	2009-10	अप्रैल'10-जून'11 (जांच की अवधि)	वार्षिकीकृत (जांच की अवधि)
ब्याज पूर्व लाभ	लाख रुपये	(***)	(***)	(***)
ब्याज पूर्व लाभ (सूचीबद्ध)	प्रवृत्ति	(100)	(235)	(235)
लगाई गई पूंजी	लाख रुपये	***	***	***
लगाई गई पूंजी (सूचीबद्ध)	प्रवृत्ति	100	90	90
लगाई गई पूंजी पर अर्जन	%	-***%	-***%	-***%
लगाई गई पूंजी पर अर्जन (सूचीबद्ध)	प्रवृत्ति	(100)	(44)	(44)

171. उपर्युक्त से प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा वार्षिकीकृत आधार पर जांच की अवधि के दौरान लगाई गई पूंजी परियोजना रिपोर्ट के अनुसार किये गये प्रक्षेपणों में लगाई गई पूंजी से न्यून थी। अतः प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तु का विनिर्माण करने के लिए संयंत्र को प्रारंभ करने में किसी तरह की लागत अभिभावन को नोट नहीं किया है। तथापि, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग लगाई गई पूंजी पर तर्कसंगत स्तर का अर्जन प्राप्त करने में सक्षम नहीं हुआ क्योंकि इसे संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के कारण जांच की अवधि के दौरान वित्तीय क्षति सहन करनी पड़ी।

नकदी प्रवाह

172. घरेलू उद्योग के नकदी प्रवाह पर पाटन के आयातों के प्रभाव का निर्धारण घरेलू उद्योग द्वारा घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तु की बिक्री से अर्जित नकद लाभ पर विचार किया गया, जो निम्नवत है:-

	मापन की इकाई	2009-10	अप्रैल'10-जून'11 (जांच की अवधि)	वार्षिकीकृत (जांच की अवधि)
लाभ/ (हानि)	लाख रुपये	(100)	(416)	(416)
मूल्यहास	लाख रुपये	100	203	203
नकद लाभ	लाख रुपये	100	(259)	(259)

173. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटित आयातों के कारण कीमत अधोरदन और कीमत अधोबिक्रय होने से कंपनी को जांच की अवधि के दौरान नगद क्षति उठानी पड़ी।

रोजगार एवं वेतन

174. घरेलू उद्योग में रोजगार एवं वेतन की प्रवृत्तियों का वर्णन निम्नलिखित तालिका में किया गया है:

	मापन की इकाई	2009-10	अप्रैल'10-जून'11 (जांच की अवधि)
रोजगार	संख्या	90	113
वेतन	लाख रुपये	100	1399

मालसूची

175. घरेलू उद्योग की माल सूची धारिता की प्रवृत्ति का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है:-

	मापन की इकाई	2009-10	अप्रैल'10-जून'11 (जांच की अवधि)
स्टाक	सीबीएम	***	***
स्टाक सूचीबद्ध	प्रवृत्ति	100	119
उत्पादन	सीबीएम	2,262	22,980
जांच की अवधि के लिए औसत स्टोक	सीबीएम	-	1,318
उत्पादन माह की संख्या के समकक्ष औसत स्टोक	दिन		0.86

176. उपर्युक्त से प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच की अवधि के दौरान, जो घरेलू उद्योग के पूर्ण प्रचालनों का पहला वर्ष था, घरेलू उद्योग 0.86 माह के उत्पादन के बराबर औसत स्टॉक अनुरक्षित किये हुए था। चूंकि घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि वह संबद्ध वस्तु की बिक्री उस सीमा तक करने में सक्षम नहीं हुआ जिस सीमा तक वह उसका उत्पादन करने में सक्षम था, प्राधिकारी ने जांच की अवधि के दौरान घरेलू उपयोग के उत्पादन, बिक्री तथा मालसूची के स्टॉक की प्रवृत्तियों का माह वार विश्लेषण किया है। वह विश्लेषण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:-

महीना	अथ स्टोक	ग्राही के अलावा निवल उत्पादन	क्षमता उपयोग %	बिक्री	इति स्टोक	बिक्री दिनों की संख्या के रूप में इति स्टोक
अप्रैल-10	***	***	***	***	***	***
मई -10	***	***	***	***	***	***
जून-10	***	***	***	***	***	***
जुलाई-10	***	***	***	***	***	***
अगस्त-10	***	***	***	***	***	***
सितम्बर-10	***	***	***	***	***	***
अक्तूबर-10	***	***	***	***	***	***
नवम्बर-10	***	***	***	***	***	***
दिसम्बर-10	***	***	***	***	***	***
जनवरी -11	***	***	***	***	***	***
फरवरी-11	***	***	***	***	***	***
मार्च-11	***	***	***	***	***	***
अप्रैल-11	***	***	***	***	***	***
मई-11	***	***	***	***	***	***
जून-11	***	***	***	***	***	***

177. उपर्युक्त से प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच की अवधि की पहली तिमाही में घरेलू उद्योग ने अपने क्षमता उपयोग में धीरे-धीरे वृद्धि कर ली। तथापि उसी अवधि के दौरान माल सूची में भारी बढ़ोतरी हुई। इसके परिणाम स्वरूप उत्तरवर्ती तिमाहियों में घरेलू उद्योग के उत्पादन और क्षमता उपयोग में अत्यधिक गिरावट नोट की गई। तीसरी और चौथी तिमाही के दौरान उत्पादन, बिक्री तथा अथ भंडार में एक समान प्रवृत्ति नोट की गई। जांच

की अवधि की अंतिम तिमाही में जब घरेलू उद्योग ने अपने प्रचालन के स्तर में वृद्धि तो एक बार फिर मालसूची के स्तर में वृद्धि नोट की गई। अतः प्राधिकारी नोट करते हैं कि माल सूची में भारी वृद्धि के कारण घरेलू उद्योग अपने क्षमता उपयोग के इष्टतम स्तर पर प्रचालन करने में सक्षम नहीं रहा।

उत्पादकता

178. घरेलू उद्योग की उत्पादकता की जांच प्रतिदिन तथा प्रति कर्मचारी के संदर्भ में निम्नवत की गई है

	मापन की इकाई	2009-10	अप्रैल'10- जून'11 (जांच की अवधि)
उत्पादकता प्रतिदिन	सीबीएम/दिन	37.70	67.81
उत्पादकता प्रति कर्मचारी	सीबीएम / संख्या	150.13	211.17

179. यह नोट किया जाता है कि अवधि के दौरान उत्पादकता में सुधार हुआ है।

वृद्धि

180. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने अपना वाणिज्यिक उत्पादन नई उत्पादन सुविधा के साथ प्रारंभ किया था। अतः घरेलू उद्योग की वृद्धि काफी उच्च रहनी चाहिए थी। तथापि घरेलू उद्योग की वृद्धि बहुत कम रही।

क्षति संबंधी अन्य सूचना

181. प्राधिकारी ने जांच की अवधि की सभी तिमाहियों के लिए आंकड़ों का क्षतिविश्लेषण भी किया है और उनका उल्लेख निम्नलिखित है। यह तालिका दर्शाती है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के कारण विपरीत प्रभाव पड़ा है। निम्नलिखित तालिका के आधार पर प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की सभी तिमाहियों में लाभप्रदायकता ऋणात्मक रही है और जांच की अवधि के उत्तरवर्ती छमाही में और भी अधिक वृद्धि हुई। इसी तरह, निवेश पर अर्जन भी ऋणात्मक बना रहा।

क्षति जानकारी

विवरण	यूओएम	अप्रैल'10- जून'10	जुलाई'10- सितम्बर'10	अक्टू'10- दिसम्बर'10	जनवरी'11- मार्च'11	अप्रैल'11- जून'11	अप्रैल'10- जून'11 (पीओआई)
बिक्री लागत	रु/सीबीएम	***	***	***	***	***	***
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति	100.00	100.00	100.00	100.00	99.54	99.87
बिक्री कीमत	रु/सीबीएम	***	***	***	***	***	***
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति	100.00	97.50	97.26	97.67	98.52	98.02
लाभ/ (हानि)	रु/सीबीएम	(***)	(***)	(***)	(***)	(***)	(***)
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति	(100.00)	(114.40)	(115.80)	(113.47)	(105.48)	(110.56)
लाभ/ (हानि)	लाख रु.	(***)	(***)	(***)	(***)	(***)	(***)
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति	(100.00)	(197.07)	(254.39)	(230.19)	(286.30)	(1,067.95)
ब्याज पूर्व लाभ	लाख रु.	(***)	(***)	(***)	(***)	(***)	(***)
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति	(100.00)	(1,412.14)	(2,186.81)	(1,859.75)	(2,618.18)	(8,176.88)
नकद लाभ	लाख रु.	***	***	***	***	***	***
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति	100.00	(86.22)	(196.16)	(149.75)	(257.38)	(589.51)
नियोजित पूंजी	लाख रु.	***	***	***	***	***	***
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति	100.00	97.82	95.64	93.46	91.27	91.27
नियोजित पूंजी पर अर्जन	%	(***)	(***)	(***)	(***)	(***)	(***)
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति						

		(100.00)	(1,443.63)	(2,286.57)	(1,989.97)	(2,868.46)	(1,791.70)
उत्पादकता प्रतिदिन	सीबीएम / दिन	***	***	***	***	***	***
उत्पादकता प्रति कर्मचारी	सीबीएम / सं.	***	***	***	***	***	***

जांच की अवधि के बाद के आंकड़ों का विश्लेषण

182. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के निष्पादन का विश्लेषण जांच की अवधि के बाद की अवधि के लिए तिमाही आधार पर किया है। आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा जांच की अवधि के दौरान की मात्रा के अनुरूप ही जारी रही। दूसरी ओर, घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री मात्रा में जांच की अवधि के पश्चात 6 माह की अवधि में मामूली सा सुधार प्रदर्शित हुआ है। प्राधिकारी पुनः नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से आयातों की उतराई कीमत घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्रापण की तुलना में बहुत कम थी। इसके अतिरिक्त जांच की अवधि के पश्चात के समय में घरेलू उद्योग का एनएसआर भी घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित गैर क्षतिकारी कीमत की तुलना में बहुत कम रहा है जिससे यह संकेत मिलता है कि जांच की अवधि के पश्चात की अवधि में भी घरेलू उद्योग संबद्ध वस्तु से प्रत्याशित बिक्री कीमत प्राप्त करने में सक्षम नहीं रहा था। यह घरेलू उद्योग द्वारा जांच की अवधि के पश्चात की अवधि में उठाये गये वित्तीय घाटे से भी प्रदर्शित होता है।

विवरण	जुलाई '11- सितम्बर'11	अक्टू.'11-दिस. '11
संस्थापित क्षमता सीएमबी	12500	12500
उत्पादन सीएमबी	9611.14	12250.57
क्षमता उपयोग	87.90%	101.58%
बिक्री मात्रा सीएमबी	9110.6	11604.96
आयात मात्रा सीएमबी	11570.69	10485.52
रुपये प्रति सीएमबी बिक्री प्रापण	***	***
लाभ लाख रुपये में	(***)	(***)
लाभ प्रति सीएमबी	(***)	(***)
आयातों का उतराई मूल्य प्रति सीएमबी	13978.6	16778.89
अधोरदन प्रति सीएमबी	***	***
अधोरदन % रेंज	20-30	10-20
क्षति मार्जिन	***	***
क्षति मार्जिन रेंज	40-50	18-28

नवीन निवेश उगाहने की क्षमता

183. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने एक नया संयंत्र स्थापित किया है तथा घरेलू उद्योग द्वारा इसमें निवेश किया गया है। तथापि, घरेलू उद्योग का निष्पादन इतना निराशा जनक रहा की नये निवेश आकृष्ट नहीं हुए।

कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

184. संबद्ध देशों तथा अन्य देशों से आयात कीमत, उत्पाद के लिए लागत ढांचा, घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा, पाटित आयातों के अलावा घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों पर विचार दर्शाता है कि संबद्ध देशों से आयातित माल की उतराई कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से बहुत कम थी जिससे भारतीय बाजार में भारी कीमत अधोरदन हुआ। पुनः यह नोट किया जाता है कि भारतीय उत्पादकों के लिए संबद्ध देशों से आयात कीमतें बेंचमार्क कीमतें हैं। इस उत्पाद का कोई व्यवहार्य स्थानापन्न नहीं है। इस उत्पाद की मांग में भारी वृद्धि हो रही थी और यह कीमते कम होने के लिए एक उत्तरदायी कारक नहीं है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग की कीमतों के लिए एक मात्र उत्तरदायी कारण संबद्ध उत्पाद की आयात कीमतें तथा घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत है। सूचना और आकड़े यह दर्शाते हैं कि यद्यपि उत्पादन लागत अधिक थी परंतु आयात कीमत घरेलू कीमत की तुलना में बहुत कम थी और इसने घरेलू उद्योग को उत्पादन लागत के अनुरूप कीमतें प्रभारित करने से वंचित कर दिया था।

क्षति संबंधी निष्कर्ष

185. विभिन्न क्षति पैरामीटरों पर विचार करते हुए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि नये संयंत्र द्वारा कार्य प्रारंभ किये जाने पर विचार करते हुए घरेलू उद्योग का निष्पादन प्रत्याशित स्तर से काफी कम बना रहा। इस बात पर विचार करते हुए कि घरेलू उद्योग ने नई उत्पादन सुविधाएं स्थापित कर ली है और सहायक कंपनी ने भी विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन शुरू कर दिया है कि फिर भी संबद्ध देशों से आयातों में भारी बढ़ोतरी हुई जबकि आयातों में कमी आनी चाहिए थी। कीमत अधोरदन का स्तर भी बहुत अधिक है। घरेलू उद्योग द्वारा न्यून कीमतें प्रस्तुत किये जाने के बावजूद इसको अपने उत्पाद की बिक्री करने में अक्षमता को देखते हुए इसे इसकी कीमतों में भारी कटौती करनी पड़ी। घरेलू उद्योग को कम कीमत वाले आयातों के पाटन के कारण कीमत निग्रहण के प्रभाव का भी सामना करना पड़ा। घरेलू उद्योग को अपना उत्पाद भारी वित्तीय घाटे पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा जिसके कारण उसे निवेश और नकदी प्रवाह पर ऋणात्मक अर्जन हुआ। देश में इस उत्पाद की भारी मांग के बावजूद घरेलू उद्योग के निष्पादन में विपरीत प्रभाव पड़ा। घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत का समायोजन शुरूआती प्रचालनों से करने के बावजूद घरेलू उद्योग उत्पादन लागत वसूल पाने और तर्क संगत लाभ प्राप्त कर पाने में अक्षम रहा। अतः सम्बद्ध देशों से सम्बद्ध वस्तु के पाटित आयातों की मात्रा का विश्लेषण करने के पश्चात इन आयातों के कारण कीमत प्रभाव तथा पाटनरोधी नियमावली के अनुसार क्षतिपैरामीटरों के रूप में घरेलू उद्योग पर इसके प्रभाव के विश्लेषण से यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग वास्तविक क्षति हुई।

झ. कारणात्मक संबंध

घरेलू उद्योग द्वारा किया गया प्रस्तुतिकरण

186. घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि घरेलू उद्योग की क्षति पाटित आयातों के कारण हुई आयातों और घरेलू उत्पाद की कीमतों के बीच भारी अंतर मौजूद था जिसने घरेलू उद्योग को अपने उत्पाद अपनी उत्पादन क्षमता के अनुरूप बेचने से रोक रखा था। इसके कारण कीमतों में कमी हुई और बिक्री मात्रा में गिरावट आयी तथा निवल बिक्री प्रापण में कमी हुई। एक ओर गैर क्षतिकारक कीमत तथा आयातों की उतराई कीमत के बीच भारी अंतर था और दूसरी ओर घरेलू उद्योग अपने लक्षित स्तर तक उत्पादन बढ़ाने में अक्षम था। घरेलू उद्योग को उत्पादन मानव घंटों में क्षति, बढ़ते उत्पादन के कारण माल सूची में वृद्धि, बढ़ती माल सूची के कारण उत्पादन में गिरावट आयी जिसने सामूहिक रूप से एवं संचयी रूप से यह सिद्ध कर दिया कि घरेलू उद्योग को पाटित आयातों के परिणाम स्वरूप क्षति हो रही है।

अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये प्रस्तुतिकरण

मैसर्स सेगामेट पैनल बोर्ड एसडीएन बीएचडी और मैसर्स मेरबाक एमडीएफ लंका (प्राइवेट) लिमिटेड, श्रीलंका की ओर से किये गये प्रस्तुतिकरण

187. याचिकाकर्ता ने अपना उत्पादन अभी हाल ही में शुरू किया है। इसलिए यह ज्ञात है कि याचिकाकर्ता को विभिन्न कारकों के कारण क्षति होगी जैसे (i) शुरूआती लागत; (ii) अस्थापित बिक्री एवं वितरण सरणियां (iii) संवर्द्धित विपणन व्यय तथा भारी डिस्काउंट। इसके अतिरिक्त हमने आवेदक उद्योग की उच्चतर उत्पादन लागत के लिए मुख्य कारणों की गणना करायी है जिसमें उसकी निहित अक्षमता भी एक कारण है अतः प्राधिकारी से अनुरोध किया जाता है कि वह उपरोक्त तथ्यों को भी ध्यान में रखे जिससे यह स्पष्ट प्रदर्शित होता है कि घरेलू उद्योग पाटित आयातों के कारण कोई क्षति नहीं हुई है और यदि जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को कोई क्षति हुई भी है तो वह उसकी अक्षमता के कारण हुई है। इसके अतिरिक्त यद्यपि जांच अवधि के दौरान उतराई कीमतों में वृद्धि हुई है फिर भी घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में गिरावट आयी है जो यह स्पष्ट करता है कि उनके बीच विपर्यय संबंध है परंतु यह कारणात्मक संबंध नहीं है।

एवरग्रीन फाइबर बोर्ड बेरहाद (ई एफ बी), मलेशिया; एवरग्रीन फाइबर बोर्ड (जेबी) एसडीएन, बीएचडी (ईजेबी) मलेशिया और एवरग्रीन फाइबर बोर्ड (निलाई) एसडीएन.बीएचडी (ईएफएन) मलेशिया की ओर से किए गए प्रस्तुतिकरण

188. याचिकाकर्ता को इसकी क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री, बाजार हिस्सा, वेतन, कर्मचारियों की संख्या, उत्पादकता, मालसूची आदि के रूप में कोई क्षति नहीं हुई है। लाभ प्रदायकता, निवेश पर अर्जन, नकदी प्रवाह और कीमत निग्रहण, यदि कोई, के संबंध में क्षति हुई है तो वह संबद्ध देशों से कथित पाटित आयातों के कारण न होकर इसकी शुरुआती लागत के कारण प्रतियुनिट उच्च लागत की बजट से उच्च लागत, कच्चे माल की उच्च लागत, उच्च उपयोगिता लागत, उच्च निश्चित लागत, उच्च श्रम लागत, उच्च व्याज लागत और उच्च मूल्यहास लागत के कारण हुई है। याचिका में कारणात्मक संबंध विश्लेषण करते समय याचिकाकर्ता ने किसी अन्य भारतीय उत्पादक की बिक्री के बारे में न तो कोई विश्लेषण किया याचिका में उसका विवरण प्रदान कराया। यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता द्वारा सहन की गई क्षति दो घरेलू उत्पादकों के बीच परस्पर प्रतिस्पर्धा के कारण हुई है। इस प्रकार घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति, यदि कोई हो तो, के लिए घरेलू उद्योग तथा कथित पाटित आयातों के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

189. पाटन रोधी नियमावली के अनुरूप प्राधिकारी से, अन्य बातों के साथ-साथ, पाटित आयातों के अलावा उन अन्य कारकों की जांच करना अपेक्षित होता है जो घरेलू उद्योग को क्षति कारित कर रहे हो ताकि इन कारकों द्वारा कारित क्षति के लिए पाटित आयातों को उत्तरदायी न ठहराया जा सके। इस संबंध में जो संगत कारक हो सकते हैं उनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, उन आयातों की कीमत और मात्रा जिनकी बिक्री पाटित कीमतों पर नहीं की गई, मांग में संकुचन या खपत की प्रणाली में परिवर्तन, व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रक्रियाएं और विदेशी एवं घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी विकास और निर्यात निष्पादन तथा घरेलू उद्योग की उत्पादकता शामिल है। यह जांच की गई की क्या पाटन रोधी नियमावली के अंतर्गत सूचीबद्ध यह अन्य पैरामीटर घरेलू उद्योग की क्षति कारित करने में सहयोग दे सकते हैं। यह पाया गया कि:-

क. **तृतीय देशों से आयातों की मात्रा और कीमत:** प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की अवधि के दौरान तृतीय देशों से आयात या तो नगण्य रहे हैं या उनकी मात्रा न्यूनतम रही है। अतः तृतीय देशों से आयातों द्वारा घरेलू उद्योग को क्षति कारित नहीं की गई है।

ख. **मांग में संकुचन और खपत की प्रणाली में परिवर्तन:** यह नोट किया जाता है कि क्षति अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु की मांग में बढ़ोतरी हुई है। खपत प्रणाली में किसी प्रकार के परिवर्तन का भी कोई संकेत नहीं है।

ग. **व्यापार अवरोधक प्रक्रियाएँ तथा विदेशी एवं घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा:** संबद्ध वस्तु के आयातों पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है और देश में उनका मुक्त रूप से आयात किया जाता है घरेलू उद्योग को संबद्ध वस्तु की उतराई कीमत से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। घरेलू उद्योग की कीमत पर संबद्ध वस्तु की उतराई कीमत का भारी प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त, किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने ऐसा कोई प्रस्तुतीकरण नहीं किया है जिससे यह सुझाव मिलता हो कि विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा मौजूद नहीं है अथवा उसके कारण कोई विशेष परिवर्तन आया है।

घ. **प्रौद्योगिकी का विकास:** किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने यह मुद्दा नहीं उठाया है कि प्रौद्योगिकी में विकास के कारण घरेलू उद्योग की क्षति हुई है। प्रौद्योगिकी में किसी खास विकास के बारे में कोई सूचना भी रिकार्ड में नहीं है जो घरेलू उद्योग की क्षति का प्रधान कारण बन सके।

ड. **निर्यात निष्पादन:** प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक घरेलू उद्योग ने किसी संबद्ध वस्तु का कोई निर्यात नहीं किया है।

190. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि सूचीबद्ध ज्ञात अन्य कारकों से घरेलू उद्योग को क्षति होने का कोई संकेत नहीं मिलता है तथापि निम्नलिखित पैरामीटर यह प्रदर्शित करते हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति पाटित आयातों के कारण हुई है।

क. विचाराधीन उत्पाद के आयातों में क्षति अवधि के दौरान भारी वृद्धि हुई है।

ख. स्पष्टतः, घरेलू उद्योग ने भारत में संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों की उपस्थिति के कारण इसकी बिक्री मात्रा को क्षति पहुंची।

ग. संबद्ध देशों से समग्र रूप में आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों का भारी अधोरदन हो रहा है

घ. आयातों के कारण घरेलू कीमतों का भारी अधोबिक्रयण हो रहा है।

ड. घरेलू उद्योग के लाभ तथा लगाई गई पूंजी पर अर्जन में गिरावट स्पष्टतः पाटित आयातों के कारण हुई है।

च. घरेलू उद्योग का निष्पादन कई प्राचलों के कारण नकारात्मक हो गया क्योंकि घरेलू उद्योग कई प्राचलों पर वास्तविक एवं वित्तीय निष्पादन का प्रक्षेपित स्तर प्राप्त करने में अक्षम रहा।

क्षति एवं क्षति मार्जिन का विस्तार

191. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के लिए गैर क्षति कारी कीमत का निर्धारण, यथासंशोधित, पाटन रोधी नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर किया है

सहयोग कर्ता निर्यातक

कंपनी का नाम	गैर क्षति कारी कीमत	उत्तराई कीमत	क्षति मार्जिन	क्षति मार्जिन %	क्षति मार्जिन रेंज %
पीटी सुमाटेरा प्राइमा फाइबर बोर्ड, इंडोनेशिया	***	***	***	***	55 -65
मैसर्स सेगामट पैनल बोर्ड्स एसडीएन बीएचडी, मलेशिया	***	***	***	***	50-60
मैसर्स एवरग्रीन फाइबर बोर्ड बेरहाद (ईएफबी) / मलेशिया	***	***	***	***	50-60
मैसर्स एवरग्रीन फाइबर बोर्ड (जेबी)एसडीएन बेरहाद (ईजेबी) / मलेशिया	***	***	***	***	
मैसर्स मेरबाक एमडीएफ लंका(प्राइवेट) लिमिटेड, श्रीलंका	***	***	***	***	55-65

गैर सहयोगकर्ता निर्यातक

विवरण	यूनिट	चीन जन गण	इंडोनेशिया	मलेशिया	श्रीलंका
गैर क्षतिकारी कीमत	अम.डा. / सीबीएम	***	***	***	***
उत्तराई कीमत	अम.डा. / सीबीएम	***	***	***	***
क्षति मार्जिन	अम.डा. / सीबीएम	***	***	***	***
क्षति मार्जिन (%)	%	***	***	***	***
क्षति मार्जिन (%) रेंज	%	60-70	70-80	60-70	90-100

अम.डा. / सीबीएम में

निष्कर्ष

192. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये प्रस्तुतिकरणों और उनमें उठाये गये मुद्दों की जांच करने तथा रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के पश्चात प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते कि:

क. विचाराधीन उत्पाद का संबद्ध देशों से भारत को निर्यात इससे जुड़े सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर किया गया जिसके परिणाम स्वरूप संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का पाटन हुआ।

ख. घरेलू उद्योग को संबद्ध वस्तु पर वास्तविक क्षति सहन करनी पड़ी।

ग. घरेलू उद्योग की यह वास्तविक क्षति संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के कारण हुई है।

भारतीय उद्योग के हित तथा अन्य मुद्दे

193. प्राधिकारी नोट करते हैं कि सामान्य रूप से पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य 'पाटन' के अनुचित व्यापार व्यवहार द्वारा घरेलू उद्योग को होने वाली 'क्षति' का प्रशमन करना है ताकि भारतीय बाजार में मुक्त एवं पक्षपातरहित प्रतिस्पर्धा की स्थिति पुनः स्थापित हो सके। पाटन रोधी शुल्क का अधिरोपन करने का उद्देश्य संबद्ध देशों से आयातों को किसी भी रूप में प्रतिबंधित करना नहीं है, और, अतः, इससे उपभोक्ताओं को संबद्ध वस्तु की उपलब्धता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

194. यह माना जाता है कि पाटन रोधी शुल्क का अधिरोपण करने से उन उत्पादों की कीमत स्तर पर प्रभाव पड़ सकता है जिनका विनिर्माण संबद्ध वस्तु का प्रयोग करके किया जाता है और इसके परिणाम स्वरूप इन उत्पादों की संगत प्रतिस्पर्धात्मकता पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है कि तथैपि पाटन रोधी उपाय खासकर तब जब पाटन रोधी शुल्क का अधिरोपण घरेलू उद्योग को कारित क्षति का समाधान करने के लिए जरूरी राशि तक प्रतिबंधित कर दिया जाए तो इससे भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा में किसी तरह की कमी नहीं आयेगी। इसके विपरीत, पाटन रोधी शुल्क का अधिरोपण पाटन प्रक्रियाओं द्वारा अर्जित अनुचित लाभ को दूर कर देगा, घरेलू उद्योग को पतन से बचायेगा और उपभोक्ताओं को संबद्ध वस्तु का व्यापक विकल्प की उपलब्धता बनाने रखने में सहायता करेगा।

सिफारिश

195. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह जांच शुरू की गई तथा सभी हितबद्ध पक्षकारों को इसकी सूचना दी गई और निर्यातकों, आयातकों तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के पहलुओं पर सकारात्मक जानकारी प्रदान कराने के लिए उन्हें पर्याप्त अवसर दिया गया। पाटन रोधी नियमावली में दिये गई शर्तों के अनुरूप पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंधों की जांच प्रारंभ करके एवं आयोजित करके तथा इन पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग के लिए सकारात्मक पाटन मार्जिन एवं वास्तविक क्षति की स्थापना करके, प्राधिकारी का विचार है कि पाटन एवं 'क्षति' को दूर करने के लिए निर्णायक शुल्क का अधिरोपण करना अपेक्षित है। अतः प्राधिकारी संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर निर्णायक पाटन रोधी शुल्क निम्नलिखित ढंग और स्वरूप में अधिरोपित करना आवश्यक समझते हैं और उसकी सिफारिश करते हैं।

196. प्राधिकारी द्वारा अपनाये गये न्यूनतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के न्यूनतर के बराबर निर्णायक पाटनरोधी शुल्क अधिरोपण करने की सिफारिश करते हैं जिससे कि घरेलू उद्योग की क्षति को दूर किया जा सके। तदनुसार, संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के सभी आयातों पर, निम्नलिखित तालिका के कॉलम 8 में उल्लिखित राशि के अंतर के बराबर निर्णायक पाटनरोधी शुल्क इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में दी गई तारीख से, अधिरोपित करने की सिफारिश करते हैं।

शुल्क तालिका

क. सं.	शीर्षक / उपशीर्षक*	वस्तु विवरण	उदगम का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	निर्यातक	शुल्क की राशि अम.डा. /सीबीएम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	4411*	'रेजिन या अन्य जैव पदार्थ **	चीन जन गण	चीन जन गण	कोई	कोई	407.14
2	4411*	-- वही--	सम्बद्ध देशों के अलावा कोई अन्य देश	चीन जन गण	कोई	कोई	407.14
3	4411*	-- वही--	चीन जन गण	सम्बद्ध देशों के अलावा कोई अन्य देश	कोई	कोई	407.14
4	4411*	-- वही--	इंडोनेशिया	इंडोनेशिया	पीटी सुमाटेरा प्राइमा फाइबरबोर्ड	पीटी सुमाटेरा प्राइमा फाइबरबोर्ड	338.86

5	4411*	-- वही--	इंडोनेशिया	इंडोनेशिया	क. सं. 4 के अलावा कोई अन्य संयोजन		351.34
6	4411*	-- वही--	सम्बद्ध देशों के अलावा कोई अन्य देश	इंडोनेशिया	कोई	कोई	351.96
7	4411*	-- वही--	इंडोनेशिया	सम्बद्ध देशों के अलावा कोई अन्य देश	कोई	कोई	351.96
8	4411*	-- वही--	मलेशिया	मलेशिया	मैसर्स सेगामट पैनल बोर्ड्स एसडीएन बीएचडी	मैसर्स सेगामट पैनल बोर्ड्स एसडीएन बीएचडी	318.99
9	4411*	-- वही--	मलेशिया	मलेशिया	मैसर्स एवरग्रीन फाइबर बोर्ड बेरहाद (ईएफबी)/मैसर्स एवरग्रीन फायरबोर्ड (जेबी)एसडीएन, बेरहाद (इजेबी)	मैसर्स एवरग्रीन फाइबर बोर्ड बेरहाद (ईएफबी)/मैसर्स एवरग्रीन फायरबोर्ड (जेबी)एसडीएन, बेरहाद (इजेबी)	321.56
10	4411*	-- वही--	मलेशिया	मलेशिया	क. सं. 8 और 9 के अलावा कोई अन्य संयोजन		341.91
11	4411*	-- वही--	सम्बद्ध देशों के अलावा कोई अन्य देश	मलेशिया	कोई	कोई	341.91
12	4411*	-- वही--	मलेशिया	सम्बद्ध देशों के अलावा कोई अन्य देश	कोई	कोई	341.91
13	4411*	-- वही--	श्रीलंका	श्रीलंका	मैसर्स मेरबाक एमडीएफ लंका (प्राइवेट) लिमिटेड	मैसर्स मेरबाक एमडीएफ लंका (प्राइवेट) लिमिटेड	315.00
14	4411*	-- वही--	श्रीलंका	श्रीलंका	क. सं. 13 के अलावा कोई अन्य संयोजन		329.40
15	4411*	-- वही--	श्रीलंका	सम्बद्ध देशों के अलावा कोई अन्य देश	कोई	कोई	329.40
16	4411*	-- वही--	सम्बद्ध देशों के अलावा कोई अन्य देश	श्रीलंका	कोई	कोई	329.40

* विचाराधीन उत्पाद को सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम के अध्याय-44 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तथापि, विचाराधीन उत्पाद का कोई समर्पित सीमा शुल्क वर्गीकरण कोड नहीं है। अतः, सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और यह किसी भी तरह से वर्तमान जांच के दायरे के अंतर्गत बाध्यकारी नहीं है।

** रेजिन या अन्य जैव पदार्थ द्वारा नहीं जुड़े इनसुलेशन बोर्डों, लेमिनेटेड फाइबर बोर्डों, मोल्डेड डोर स्किन्स और बोर्डों को छोड़कर, 2 मि.मी से अधिक और 6 मि.मी से कम की मोटाई वाले बांडेड लकड़ी के अथवा लकड़ी जैसे फाइबर बोर्ड।

(उपर्युक्त सभी इटैलिक्स पाटनरोधी शुल्क से अपर्जित किए जाते हैं।)

197. इस उद्देश्य के लिए आयातों का उतराई मूल्य सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत सीमा शुल्क द्वारा यथानिर्धारित आकलन योग्य मूल्य तथा सीमा शुल्क के समस्त शुल्क होंगे परंतु इसमें सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 3, 3क, 8ख, 9 तथा 9क के अंतर्गत आने वाले शुल्क शामिल नहीं हैं।

198. उपर्युक्त के अध्याधीन प्राधिकारी दिनांक 23 जुलाई, 12 को प्रारंभिक जांच परिणामों की संपुष्टि करते हैं।

199. नियम 23 (1क) उल्लेख करता है कि अधिनियम की धारा 9क के प्रावधानों के अंतर्गत अधिरोपित पाटन रोधी शुल्क, तब तक और उस अनिवार्य सीमा तक प्रभावी रहेगी जब तक उस पाटन को दूर करने के लिए अनिवार्य है जो क्षति कारित कर रही है। सावधानीपूर्वक विचार के पश्चात प्राधिकारी संस्तुति करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क की अवधि अधिरोपण की तारीख से 18 माह होनी चाहिए जिससे घरेलू उद्योग उत्पादन के 4 वर्ष पूरे कर सकें और इस प्रकार घरेलू उद्योग प्रवृत्ति विश्लेषण के पूरे आंकड़े दे सकें। घरेलू उद्योग शुल्क अवधि पूर्ण होने से पहले विचाराधीन उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क की जरूरत को सिद्ध करने की आवश्यक कार्रवाई कर सकता है।

अगली प्रक्रिया

200. अंतिम जांच परिणामों को अधिसूचित कर दिये जाने के पश्चात निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जायेगी।

201. केन्द्रीय सरकार के इन आदेशों के विरुद्ध सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद कर तथा सेवा कर अपीलीय अधिकरण में अपील की जा सकेंगी।

जे.एस.दीपक, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING & ALLIED DUTIES)

NOTIFICATION

Final Findings

Subject: - Anti-dumping investigation concerning imports of 'Resin or other organic substances bonded wood or ligneous fibre boards of thickness below 6mm, except insulation boards, laminated fibre boards and boards which are not bonded either by resin or other organic substances' originating in or exported from China PR, Indonesia, Malaysia and Sri Lanka.

No. 14/29/2010-DGAD: - Having regard to the Customs Tariff Act 1975 as amended from time to time (hereinafter referred as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules thereof, as amended from time to time (hereinafter referred as the AD Rules);

2. The Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority), under the AD Rules, received a written application from M/s. Balaji Action Buildwell, (hereinafter referred to as the Applicant) in accordance with the Act and the AD Rules, alleging dumping of 'Resin or other organic substances bonded wood or ligneous fibre boards of thickness below 6mm, except insulation boards, laminated fibre boards and boards which are not bonded either by resin or other organic substances' (hereinafter also referred to as the "product under consideration", thin fiber board, and "subject goods") originating in or exported from China PR, Indonesia, Malaysia and Sri Lanka (hereinafter also referred to as the subject countries) and requested for initiation of anti-dumping investigation and levy of anti dumping measures.
3. Preliminary scrutiny of the application revealed certain deficiencies, which were subsequently rectified by the Applicant. The application was, therefore, considered as properly documented. The Authority on the basis of sufficient evidence submitted by the

Applicant to justify initiation of the investigation, decided to initiate the investigation concerning imports of the subject goods originating in or exported from the subject countries.

4. The Authority notified the High Commissions / Embassies of the subject countries in India about the receipt of the application containing, *inter alia*, allegations of dumping and consequent injury to the domestic industry before proceeding to initiate the investigation in accordance with Rule 5(5) of the AD Rules.
5. Accordingly, the Authority initiated an investigation into the alleged dumping, and consequent 'injury' to the domestic industry in terms of the Rules 5 of the AD Rules, to determine the existence, degree and effect of alleged dumping and to recommend the amount of anti-dumping measure, which, if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

A. PROCEDURE

6. The procedure described herein below has been followed:
 - i. The Authority issued a public notice dated 11th November 2011 published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating Anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods originating in or exported from the subject countries, in accordance with the Rule 6(1) of the AD Rules to determine the existence, degree and effect of alleged dumping and to recommend the amount of anti-dumping duty, which, if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.
 - ii. The Authority sent a copy of initiation notification dated 11th November 2011, to the High Commissions / Embassies of the subject countries in India, known exporters from the subject countries, known importers/ users and the domestic industry as per the addresses made available by the Applicant and requested them to make their views known in writing within 40 days of the initiation notification.
 - iii. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known exporters and the High Commissions / Embassies of the subject countries in India in accordance with Rule 6(3) *supra*.
 - iv. High Commissions / Embassies of the subject countries in India were informed about the initiation of the investigation in accordance with Rule 6(2) of the AD Rules with a request to advise the exporters/producers from their country to respond to the questionnaire(s) within prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire(s) sent to the exporters/producers was also sent to them along with the names and addresses of the known exporters/ producers.

- v. The Authority sent questionnaire(s) to elicit relevant information to the following known exporters/producers in subject countries in accordance with Rule 6(4) of the AD Rules:

S.N.	Name of Producer/Exporter
1	M/s. Tomrich International Trading Limited, Pudong, Shanghai, China
2	M/s Nanjing ETAI Trading Co Limited, Jinshajing Nanjing, China PR
3	M/s Linyi Hongfu Timber Co Limited, Yitang Town, Linyi Shandong, China PR
4	M/s Shouguang Guihe Economic and Trade Co Limited, Shandong, China PR
5	M/s Linyi Baideli International Trade Co Ltd. Nan Lou Zone, Yitang Town, Lanshan District, Linyi City Shandong China PR
6	M/s Zhanjiang Kingstar Building Material Co Limited, Zhanjiang Guangdong, China PR.
7	M/s Wenzhou Timber Group Co. Ltd., Zhejiang, China PR
8	M/s Daiken Miri Sdn. Bhd., Miri Sarawak, Malaysia
9	M/s Merbok MDF Lanka Pvt Limited, Horana, Sri Lanka
10	M/s Robin Resources (Malaysia) Sdn Bhd, Pahang, Malaysia.
11	M/s. Evergreen Fibre Berhad (JB) SDN. BHD, Johor, Malaysia
12	M/s PT Andalan Karya Bersama, Kakarta Raya, Indonesia
13	M/s La Mobila Pannelli PT, Rukan Enclave Bukit Golf, Pantai Indah Kapuk Indonesia

- vi. In response to the above notification, following interested parties including exporters/producers/ Association etc. have responded:

S.N.	Name of Producer/Exporter
1	M/s. Magna-Foremost SDN, BHD, Malaysia
2	M/s Masonite Components, Ireland
3	M/s Merbok MDF Lanka (Private) Ltd., Sri Lanka.
4	M/s Segamat Panel Boards Sdn, Bhd, Malaysia
5.	M/s P.T. Masari Dwisepakat, Indonesia
6.	M/s P.T. Sumatera Prima Fibre Board, Indonesia
7.	M/s. Evergreen Fibre Board Berhad (EFB), Malaysia
8.	M/s Evergreen Fibre Board (JB) SDN BHD, Malaysia
9.	M/s Evergreen Fibre Board (Nilai), Sdn. Bhd (EFN), Malaysia
10.	M/s Daiken Miri Sdn. Bhd., Miri Sarawak, Malaysia
11.	M/s. P.T. Hijau Lestari Raya Fibre Board, Indonesia
12.	Ministry of International Trade & Industry, Malaysia
13.	Embassy of Republic of Indonesia, New Delhi.
14.	Director General, Kejra Sama Industri International, Jakarta, Indonesia.
15.	M/s. Dongwha Fibre Board SDN. BHD, Malaysia

- vi. Questionnaires were sent to the following known importers/users/Association of subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the AD Rules:

S.N.	Company's Name
------	----------------

1	M/s C.L. Gupta Exports Ltd., Village Jival, J.P. Nagar, UP
2	M/s. Venugopala Slate Industries, Markapur, Andhra Pradesh
3	M/s Moradabad Handicrafts Exporters Association, Moradabad, UP
4	M/s Thamarappally Brothers, M.G. Road, Ernakulam, Cochin
5	M/s Spacewood Furnishers Pvt. Ltd. T-48, MIDC Road, Nagpur-440 016
6	M/s Feroke Boards Ltd, Kaarad, Feroke College, Via- Malappuram, Kerala
7	M/s R.J. Metals, XL/4039 Faba Complex, Jews Street, Ernakulam Cochin, Kerala
8	M/s Kalinga Imports & Exports Pvt. Ltd 18/777 Kallai Road, Calicut, Kerala
9	M/s Victory Plywood Distributors, Stadium Complex, Kannur, Kerala
10	M/s Mathewsons Exports & Imports P.Ltd, Kaloore, Cochin, Kerala
11	M/s Ply Point, Kodampuzha Road, Petta Feroke, Kozhikode Kerala
12	M/s Label Sales Corp., Indradhanush Apartment, Shop No. 7, 8 & 9 T.D. Road, Cochin, Kerala
13	M/s Srivari Traders, Odanthurai Metupalayam, Tamil Nadu
14	M/s Krishna Plywoods, Kamraj road, Karur Tamil Nadu
15	M/s Thamarappally Brothers, Ernakulam, Kochi, Kerala
16	M/s Jacsons Veneers And Panels P. Ltd, Ernakulam, Kochi, Kerala
17	M/s Kutty Flushdoors and Furniture Co. Pvt. Ltd. Koyambedu, Chennai
18	Association of Furniture Manufacturers of India (AFMI), Mumbai

viii. In response to the above notification, following importers/ users, Association have responded:

SN.	Importer's Name
1.	M/s. Venugopala Slate Industries, Markapur, Andhra Pradesh
2.	India Moulded Panel Shutters Manufacturers Association
3.	Moradabad Handicrafts Exporters' Association, Moradabad,
4.	M/s. C.L. Gupta Exports Ltd., Uttar Pradesh (UP), India.
5.	Indian Moulded Panel Shutters Manufacturers Association
6.	Balaji Impex
7.	Koteshwari Slate Works
8.	Saikrupa Slate Works
9.	Vishwamitra Slate Works
10.	All India Fibreboard Manufacturer's Association, Haryana
11.	Sarthak Overseas Delhi

ix. A Market Economy Treatment (MET) questionnaire was forwarded to all the known exporters/producers and Embassy of China PR in New Delhi. For the purpose of initiation, the Normal value in China PR was considered based on the constructed cost of production of the subject goods in China PR, as the applicant pleaded that the information for market economy third country is not available to them. The Authority informed known exporters that it proposes to examine the claim of the applicant in the light of paras 7 and 8 of Annexure I of the AD Rules. The exporters/producers of the subject goods from China PR were therefore requested to furnish necessary information/sufficient evidence as mentioned in sub-paragraph (3) of paragraph 8 of the Annexure of the AD Rules to enable the Authority to consider whether market economy treatment be granted to co-operative exporters/producers from China PR.

x. The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties.

- xi. Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to arrange details of imports of the subject goods for the past three years, including the period of investigation.
- xii. Optimum cost of production and cost to make & sell the subject goods in India based on the information furnished by the Applicant on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) was worked out so as to ascertain if anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.
- xiii. The Designated Authority notified the Preliminary Findings, vide notification No. 14/29/2010-DGAD dated, 23.07.2012 and recommended imposition of provisional anti-dumping duties, concerning imports of subject goods, originating in or exported from the subject countries. The Authority vide Corrigendum Notification No. 14/29/2010-DGAD dated 1st October, 2012 amended the scope of subject goods by excluding moulded door skin. The interim recommendations made by the Designated Authority were accepted by the Central Govt. and interim duties were levied vide notification no. 43/2012-Customs (ADD) dated 21st Sept., 2012. Further, the Central government extended the time to complete the investigation till 10th May 2013.
- xiv. In accordance with Rule 6(6) of the AD Rules, the Authority provided opportunity to all interested parties to present their views orally in a public hearing held on 22nd November, 2012. The parties who presented their views orally in the public hearing were requested to file written submissions of the views expressed orally. The interested parties were also given an opportunity to offer rejoinder to the submissions made by opposing interested parties. The arguments made by interested parties in the written submissions/rejoinders received from the interested parties have been considered, wherever found relevant, in this notification.
- xv. Investigation was carried out for the period starting from 1st April 2010 to 30th June 2011 (POI). The examination of trends, in the context of injury analysis, however, covers the periods April 2007-March 2008, April 2008-March 2009, April 2009- March 2010 and the Period of Investigation (POI) viz. 1st April 2010 to 30th June 2011.
- xvi. Information provided by interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
- xvii. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has recorded these findings on the basis of the 'facts available'.
- xviii. In accordance with Rule 16 of Rules Supra, the essential facts/basis considered for these findings were disclosed to known interested parties vide disclosure statement and comments received thereon, considered relevant by the Authority, have been addressed in this notification.
- xix. The present recommendations are being made within the time period extended by the Central Govt. in view of special circumstances.
- xx. *** in this notification represents information furnished by an interested party on confidential basis, and so considered by the Authority under the AD Rules.

B. Miscellaneous Issues raised by interested parties

Submissions made by other interested parties

7. The submissions made by interested parties, in brief, are as follows:

Submissions made by M/s Venugopala Slate Industries, M/s Segamat Panel Boards Sdn. Bhd. and M/s Merbok MDF Lanka (Private) Ltd, Sri Lanka

- Application filed by the Applicant is grossly erroneous, insufficient to justify initiation and petitioner has resorted to excessive confidentiality.

- Credibility of data cannot be ascertained without the raw data been provided. An entry of HDF has not been included, which was imported at high price. However, entry of lower prize has been included
- The non-confidential version of the petition is wholly deficient and inadequate to enable the other parties to render their comments.
- As per initiation notification, POI is April-2010 to June-2011 but the copy of non confidential version of the application provided by the domestic industry appears to be taking into account April 2010 - March 2011 as the POI.
- There were no oral submission on behalf of Greenply Industries Ltd in the oral hearing. Despite which they have filed written submissions. Claims made by Greenply should be held incorrect if they deny access to their information.
- **It has been submitted that the domestic industry has not made the subject goods of thickness 2.5 mm and less than that during the POI and therefore they should be excluded from the purview of the product under consideration.**

Submissions on behalf of M/s. Magna-Foremost SDN and M/s. Masonite Components, Ireland

- The Authority has initiated this investigation in violation of Article 5.3, despite insufficient evidence to justify doing so. The Authority has in its wisdom, suo moto, changed the period of investigation and injury investigation period from those filed by the Applicant.
- The Authority extended the period of investigation by 3 months originally proposed by the Applicant, i.e., April 2010 – March 2011 (12 months). In addition, the Authority affixed the injury investigation period between 2007 and 2010 despite the fact that no domestic industry had even existed for MDF until at least February 2010. As stated in the Petition, the Applicant did not commence commercial production of MDF until February 2010, while the supporter commenced production much later, in December 2010. The Authority has provided no rationale for amending the said periods. More importantly, however, the changed periods effectively render the evidence provided by the Applicant insufficient to justify initiating this investigation.

Submissions made on behalf of Evergreen Fibreboard Berhad (EFB), Malaysia; Evergreen Fibreboard (IB) Sdn. Bhd. (EIB), Malaysia and Evergreen Fibreboard (Nilai) Sdn. Bhd.(EFN), Malaysia

- the non-confidential version of the petition provided is deficient as it does not contain the information for the whole period of investigation i.e. April 10 to June 11 (15 months). It contains the information only for part of the POI i.e. April 10- March 11 (12 months). Further, the Applicant has not provided the raw import data received by it from IBIS along with the petition nor it indicated that the same has been provided to the Authority.
- That the domestic industry has claimed excessive confidentiality and there is no statement of confidentiality being claimed by the Applicant enclosed with the non- confidential version of the petition.

Submissions made on behalf of M/s PT. Masari Dwisepakat Fiber, Indonesia and M/s PT. Sumatera Prima Fibre board (SPF), Indonesia

- the non-confidential version of the application filed by the Domestic Industry and supplied to them is not in accordance with the new guidelines being followed by the Designated Authority in all the current cases. There is no index to the application for them to appreciate what all documents have been filed in the confidential version, there is no running pagination, there is no reasons in tabular form giving reasons for confidentiality, etc.
- the Applicant industry has not given Application Proforma as are required to constitute a valid and fully documented application. Necessary evidence as prescribed in the Proforma was also not supplied in accordance with the requirement under the garb of excessive confidentiality. The questions in the format application have been changed to suit their own requirements. The certifications given about self imports and relationship are not for the POI by the applicant or by the supporter.
- **Confidentiality:** The non-confidential version of the application filed by the Domestic Industry and

supplied to the exporters not in accordance with the new guidelines being followed by the Designated Authority in all the current cases. The following information has been kept confidential without cogent reasons:

- a. The full functional production flow chart is there on the website of the applicant. Therefore, there is no reason to claim confidentiality on this.
 - b. Methodology adopted for excluding excluded products from the import data for calculation, because on the basis of the widths and thickness all the characteristics of the subject goods are not covered.
 - c. Whether imports made by Balaji are excluded or not from the import data and what is the quantity they have actually imported.
 - d. Non-confidential summary and indexed numbers of the project report on which the applicant relied upon.
 - e. Basis of construction of normal value. It is also not clear whether Applicant has used power rate and other information which is available in the public domain of the subject countries or they have used their own rates. Further, the power information attached in the non-confidential is of no use because it is not for the period of Investigation and there are different rates for different usage.
 - f. The applicant has not provided any source for the information provided in the application in relation to constructed normal value and for calculating export price. Source information given in some places is obsolete and not working. Audited balance sheets are not provided for the injury investigation period.
 - g. Proper certification from the applicant in relation to its relation with export or import Statement of confidentiality is not provided.
- Erroneous Period of Investigation and Injury Period: The period of investigation and injury examination period fixed by the Authority is erroneous and unfair. In the instant case the period of Investigation is April 2010 – June 2011 i.e., of 15 months. The applicant is only new entrant in the market and has only completed 2 months in April 2010. Therefore, the determination of dumping and injury tends to be skewed as the variable costs and fixed costs would be very high for the applicant and no proper or comprehensive analysis can be undertaken. The Authority has not considered the financial year 2010-11, which was the only full financial year that could be analyzed. Although the recently concluded financial year is subsumed in the period of investigation, the data for the same should have been specifically taken as one of the injury period.
 - Adequacy & Accuracy: the investigations have been initiated without adhering to the requirements of Rule 5 of the Anti-dumping Rules, which specifically deals with the initiation of investigation. The mandated parameters were not examined prior to reaching a determination for initiation of the present investigation. In absence of following, the company is unable to offer its comments on adequacy and accuracy of the information in the application:
 - a. The date of application and correspondence exchanged with the applicants prior to initiation.
 - b. Letters addressed to concerned ministry or other producers in India.
 - c. Annual Reports for the past three years for applicant and the supporting producer
 - d. Non-confidential version for calculations done and methodology for Normal Value/Export Price. It may be seen from the non-confidential version of the application that the Applicant Industry has not given any details of the calculation of the constructed normal value and the export price. Further, in terms of the ruling of the Hon'ble Supreme Court, such information has to be provided to the opposing interested parties to enable them to offer their comments.
 - e. It has been claimed by the Applicant Industry that there are no significant difference in manufacturing process adopted by the Applicant Industry compared to the one adopted by the exporters from subject countries. In such a situation confidentiality could not have been claimed by the Applicant on the process of manufacture.
 - There has been substantial delay in making available application that formed the basis of initiation of the present case.
 - The raw import data may be provided as received from IBIS and also list containing excluded entries with explanation for such exclusions.
 - Authority ought to have recommended only reference price duties in this case on the lines of Thick MDF. It is important to note that the production process, raw material, marketing channels, distribution network is

common for thin as well as thick MDF. Under the circumstances, there are no reasons for the Authority to have recommended Reference Price based duty for a part of the same product range and fixed duty for another.

- Basic requirements of Section 9B and Rule 12 for imposition of provisional duties have not been complied with. There is no reasoning, analysis or determination to the effect that provisional duties would be necessary during the investigation.

Submissions made by the domestic industry

8. The submissions made by the domestic industry, in brief, are as follows:

- As regards the contention that NCV petition is wholly deficient and inadequate to enable the other parties to render their comment; referring to the relevant rules & regulations, the Applicant has stated that the petition filed by the domestic industry in fact contains much more than what is the obligation on the domestic industry.
- As regards the contention that POI as per initiation notification is April 2010 to June 2011 but the NCV has data only up till March 2011 and therefore information relied upon by the Authority was incomplete; the Applicant has stated that there is no legal requirement that the DA should have, at the time of initiation, information on record for the period of investigation. The “period in the petition” for which petition has been filed and “period of investigation” chosen by the Designated Authority for elaborate investigations is altogether two different factors/. While the petition must identify a period and must contain all relevant period for the said period; the Designated Authority is at a liberty to consider any other period, including the period suggested by the Applicant for detailed investigation.
- It is really amazing that an interested party is suggesting consideration of 2010-11 as an investigation period in the present case. Firstly, the case was initiated in November 2011 and therefore investigation period of 2010-11 would have implied a stale period for the present purpose. Secondly, period longer than as could have been considered can certainly not prejudice the interests of any party. If the period 2010-11 would have been appropriate for the present purpose, certainly, addition of subsequent quarter is no less inappropriate.
- As regards the contention relating to erroneous period of investigation and injury period fixed is erroneous and unfair: it is submitted that in the previous Para, the interested parties have argued that Applicant is an existing company. In this Para, the interested parties have argued that the Applicant is a new entrant in the market. If Applicant is a new entrant, admittedly, this case falls under material retardation to establishment of an industry, unless opposing parties establish that there was already a production and sale of the product under consideration in the country. It would be relevant to point out in this regard that the previous petition filed in respect of Medium Density Fiber Board included all thicknesses of fiber board. The interested parties, however, strongly argued for exclusion of thin board on the grounds that there was no company in India producing thin board. After due consideration, the Authority came to a conclusion that fiber board below 6 mm was not being produced in the country and accordingly restricted the scope of product under consideration to fiber board of 6 mm and above.
- As regards the contention that mandated parameters were not or examined prior to reaching a determination for initiation of the present investigation; there is no such mandated requirement. Further, since Applicant filed updated petition and since this updated petition formed the basis of initiation of investigations, the correspondence exchange with the Applicant prior to initiation becomes meaningless. As regards, letters addressed to concerned ministry or other producers in India; there is no such mandated requirement under the law. As regards, Annual reports for the past three years for the applicant and supporting producer; there is no mandated requirement for the annual report of the supporting producer. With regard to annual report of Applicant, the issue was earlier raised by the DGAD and addressed by the Applicant. Copies of the letters written by the Applicant are enclosed with these submissions. As regards, NCV version of the calculations done and methodology for normal value/ export

price; the petition is relied upon which contains relevant information.

- As regards production flow chart; Applicant has provided sufficient information on the product process. The same provides sufficient information with regard to flow chart as well. The flow chart enclosed with the petition is the actual production plant flow chart of the Applicant and therefore the same has not been disclosed.
- As regards the contention that there has been substantial delay in making information available to the interested parties; the interested party have been provided sufficient time. It is not the case where interested parties have been given 40 days time from the date of initiation of investigation. The Authority has in fact given 40 days time to the interested parties from the date on which letters were communicated/sent to the interested parties. Thus, interests of opposing parties, in any case, have not got prejudiced.

Examination by the Authority

9. As regards the contention that the non-confidential version of the petition provided was deficient as it did not contain the information for the whole period of investigation i.e. April, 2010 to June 2011 (15 months); the Authority notes that the revised information/data for the POI was duly sought from the Applicant in the instant matter and the same was placed in the public file that was open for inspection by all the interested parties. There is no legal obligation that the POI proposed by the authority for detailed investigations and POI for which petition has been filed before the authority should be the same. The Designated Authority has considered a POI different from the POI proposed in the petitions in a large number of cases.
10. The Authority has taken note of the submissions regarding confidentiality and notes that the information provided by interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has recorded these findings on the basis of the 'facts available'.
11. As regards the contention pertaining to appropriateness period of investigation is concerned; the same has been chosen considering the facts and circumstances of the present case and has been appropriately chosen to cover the latest available data on the subject. Further, it is not correct to state that while the POI as per initiation notification is April 2010 to June 2011 but the NCV has data only up till March 2011 as the information for the POI was duly obtained from the domestic industry and placed in the public file as per the AD Rules. Besides, it is reiterated that the application contained sufficient evidence to justify initiation of an anti-dumping investigation in the present matter. The Authority further notes that that mandated parameters were duly examined and sufficient evidence was available on record to justify initiation of the investigation in the instant matter.
12. As regards the contention regarding delay in making information available to the interested parties; the Authority notes that interested parties have actually been benefitted as 40 days time was duly provided to all known interested parties from the date on which letters were forwarded to the interested parties. Thus, no adverse impact has apparently been caused to their interests.
13. As regards the submission on form of duty, the Authority notes that the form and quantum of duty is dependent inter alia i.e on the magnitude of dumping that is established by the facts of the case. The Rules empower the Authority to recommend the amount of the anti-dumping duty equal to the margin dumping or less, which if levied, would remove the injury to the domestic industry. Further, in the present case, the Authority has examined all the relevant factors having bearing on the subject investigation and considering that the factual matrix of the present investigation, the authority decided form of duty having regard to facts of the case.
14. As regards the contention that basic requirements for imposition of provisional duties have not been complied with, the Authority as mandated under Rule 12 of the Anti dumping Rules and after conducting a preliminary investigation recorded a preliminary finding regarding export price, normal value and margin of dumping and injury to the domestic industry and has thus fulfilled all the requirements for the recommendation of anti dumping duties. Further, the authority stated in the preliminary findings that it was considered necessary & appropriate to recommend imposition of interim measures, pending further investigations. Since then, the Authority has further examined the submissions of various interested parties and has carried out the onsite verification of the information submitted by the various interested parties. The present disclosure statement is being issued which has taken into account the arguments submitted by interested parties after the preliminary findings.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND DOMESTIC LIKE ARTICLE

Submissions made by other interested parties

15. The submissions made by interested parties, in brief, are as follows:

Submissions made by Indian Moulded Panel Shutters Manufacturers Association

16. The submissions made by Indian Moulded Panel Shutters Manufacturers Association, in brief, are as follows:

- It is not clear whether the door skins are under product under consideration as PUC as defined in the initiation notification is too broad and vague. For the purpose of volume and price, the domestic industry in their petition has excluded the imports of HDF and Door Skin from the subject countries but some subsequent submissions shows the issue is open ended for the decision of Authority. Huge variance in import price of Door Skin and that of the PUC itself shows that Door Skin ought to be outside the PUC. Door Skin prices are higher in comparison to MDF or HDF and door skins are a distinct product. The raw material for HDF Door Skins are MDF and HDF board while for MDF and HDF raw materials are wood, resin and others which shows that Door Skins are value added and a separate product. Door Skins cannot be interchangeable with other applications except door. Thus, HDF and MDF are not commercially interchangeable because price of door skin are higher by 200% as compared to MDF. Fibre Board Moulded Door Skin can only be produced from Fibre Board of 3mm thickness with its density above 800 kg/m³. The applicant industry may at best be producing Moulded Door Skin from MDF Board only. Thus, the Moulded Door Skin is a value added product for Applicant in comparison to simple fibre board MDF/HDF. In other words, MDF/HDF is an input material in the process for making door skin for the domestic industry in concern. The average prices for Moulded Door Skins were higher than those for thin MDF (150-200% on average). Further, prices for thin HDF are also significantly higher than thin MDF. Thus, prices between MDF, HDF and Moulded Door Skin are not comparable.
- Applicant deliberately avoided parameter of density and thickness while defining the scope of PUC. It has consequences as the raw material consumption per CBM governs the density of the Board. HDF consumes higher amount of raw materials and is of higher density as compared to MDF. Even catalog itself of applicant domestic industry shows Door Skin is separate from MDF or HDF. The claim that import price of high density board is even lower than the average import price is baseless. Correct evaluations would have made HDF outside the scope of PUC.

Submissions made by M/s Venugopala Slate Industries

17. The submissions made by M/s Venugopala Slate Industries, in brief, are as follows:

- Complete raw import data relied upon by the Applicant needs to be provided to assess whether the methodology adopted by the Applicant to compile the import data for PUC is correct or not as altered import data provided is not sufficient to do the same.
- There were no production of subject product of 2.5 MM and below which majorly used by the Slate industry during the POI. Since there is no commercial production of Thin Fibre Boards of 2.5 MM and below, leave aside any confirmation of quality of any such product produced by the domestic industry, the Slate industry is left with no option but to import the product from subject countries.

Submissions made by Director of Trade, Republic of Indonesia

18. ADD imposed is on wide range of products covered under HS code 4411. Fiberboard under 2.1 mm thickness should be excluded. It must be examined whether the domestic industry possesses the installed machines to commercially manufacture and meet market demand for PUC below 2.1mm.

Submissions on behalf of M/s. Magna-Foremost SDN and M/s. Masonite Components, Ireland

19. The definition provided in the Initiation Notification makes it evident that moulded door facings, also known as door skins, are excluded from the scope of the product under consideration, and this is confirmed by the Applicant's express exclusion of data pertaining to door skins from its product headings and import data. There are differences in production process, differences in applications. Door skins are used exclusively as door

skins – i.e., used in the manufacture of doors to form the outward panels of a door. Because of their chemical properties and dominant surface contours, they cannot be reshaped or resized into other fibre board products and therefore do not compete with or substitute for the vast majority of the Applicant's MDF products.

Submissions made on behalf of M/s Segamat Panel Boards Sdn. Bhd. and M/s Merbok MDF Lanka (Private) Ltd, Sri Lanka

20. The submissions made on behalf of M/s Segamat Panel Boards Sdn. Bhd. and M/s Merbok MDF Lanka (Private) Ltd, Sri Lanka, in brief, are as follows:

- That the domestic industry has stated that it has adopted the transaction-wise import data provided by IBIS because product under consideration does not have a dedicated customs classification code. Such raw import data falling under chapter sub-heading 4411 provided by IBIS should have imports reported in different descriptions and units. However, domestic industry has provided in the application only altered import data with methodology used to compile import data of subject product. Thus, we are not able to understand, whether compilation of import data for subject product by domestic industry is correct or not as complete raw import data has not been provided in the application.

Submissions made on behalf of Evergreen Fibreboard Berhad (EFB), Malaysia; Evergreen Fibreboard (JB) Sdn. Bhd. (EJB), Malaysia and Evergreen Fibreboard (Nilai) Sdn. Bhd.(EFN), Malaysia

21. The following submissions, in brief, have been made on behalf of Evergreen Fibreboard Berhad (EFB); Evergreen Fibreboard (JB) Sdn. Bhd. and Evergreen Fibreboard (Nilai) Sdn. Bhd.:

- The product under consideration in the present investigation has been kept too wide. The domestic industry has included the type of products which are not even manufactured by the Applicant. The same are also not technically and commercially substitutable by the imported products. The domestic industry has included all types of boards below 6mm be it medium density boards or high density boards. The domestic industry is not capable of producing widths below 2.5mm and the same are required to be excluded from the purview of the investigation.

Submissions made on behalf of M/s PT. Masari Dwisepakat Fiber, Indonesia and M/s PT. Sumatera Prima Fibre board (SPF), Indonesia

22. The following submissions, in brief, have been made on behalf of M/s PT. Masari Dwisepakat Fiber, Indonesia and M/s PT. Sumatera Prima Fibre board (SPF), Indonesia:

- Wrongful inclusion of non-product under consideration in the import data: Transaction wise examination reveals that the data included transactions relating to High Density Boards. From the transaction wise description, it is not evident as to how insulated boards and other non-product under consideration were excluded. They are not in a position to understand whether filtration of raw data was undertaken for excluded categories specifically when the narration of each transaction does not give any description of special features like laminated fibre board etc. In any case, the Tariff Heading 4411 not only includes boards that are bound by resins or other organic substances but also includes within its scope board that may not be bound by resin or other organic substances. The Authority may also review the import data and exclude all entries that relate to non-product under consideration. While undertaking such an exercise, the applicants be called upon to disclose the methodology adopted by them when they excluded the products from the raw data and listing of all such exclusions.
- Scope of the Product under Consideration: the present investigations should exclude Thin Fibre board below 3mm thickness from the purview of Product under consideration as the same are neither produced nor sold by the Domestic Industry. Thickness of a Board is a critical parameter for any particular application and different thicknesses cannot be technically or commercially substituted for each other. For instance, if the design requirement is to use 3mm thick Board, it would not be technically possible for any user to substitute the same with any other Board with a different thickness. The end-use of thinner fibre boards is entirely different from thicker sizes. The product scope selected by the applicant is vague and not defined appropriately. The description does not deal with an important factor viz. density. It appears that the approach adopted for not defining the product under consideration through its density is to strategically

include within the produce scope density that is not being produced by the applicants. It appears that the applicant Industry has withheld information relating to captive consumption of the product under consideration. The applicant is mainly into the business of high price subject goods which required plain fiber boards as raw material. In view of the above, the Authority should exclude the followings from the scope of the product under consideration:

- Fiber Boards below the thickness of 2.5 / 3 mm depending upon what the Domestic Industry has produced and “actually” supplied during the POI.
- All Medium Density Boards having emission standard of E2, E3 and any other standard which is not equivalent to E1 emission standard.
 - Fire Retardant Particle Board
 - Veneered MDF and Particle Boards
- In view of aforementioned submissions, the Authority may also review the import data and exclude all entries that relate to non-product under consideration. While undertaking such an exercise, the applicant be called upon to disclose the methodology adopted by them when they excluded the products from the raw data and listing of all such exclusions. We are presently not in a position to understand filtration of raw data was undertaken for excluded categories specifically when the narration of each transaction does not give any description of special features like laminated fibre board etc. In any case, the Tariff Heading 4411 not only includes boards that are bound by resins or other organic substances but also includes within its scope board that may not be bound by resin or other organic substances.
- False declaration about substitutability: Applicant has mentioned in the application that there is no known viable technical and commercial substitute of the subject goods. In this context, the exporters have raised serious objection as there are several viable substitutes available in the market. It is also submitted that the Applicant himself provided the differences between subject goods and other substitutes on its website. Therefore the submission made by the Applicant is incorrect and need to be rejected.

Submissions made on behalf of M/s Balaji Impex, M/s Koteshwari Slate Works and M/s Vishwamitra Slate Works

23. The following submissions, in brief, have been made on behalf of M/s Balaji Impex, M/s Koteshwari Slate Works and M/s Vishwamitra Slate Works:

- Domestic industry produces subject goods with variation thickness as against the uniform thickness wanted for the production of writing slate. Quality of the applicant's product is inferior and has low density and they produce thickness only of 2.5mm to 6.0mm.
- Duty should be exempted for subject goods used for writing slate industry below 2.5 mm and from 2.5mm to 4.00 mm.

Submissions made by domestic industry

24. The following submissions, in brief, have been made on behalf of the domestic industry:

- As regards the contention that the PUC defined is vague and not defined properly and that the description does not deal with density, which is an important factor; it is stated that there is no ambiguity or vagueness in the description. The basis of allegation is not understood as the interested party has not shown how density as a parameter governs/impacts the price. The Applicant has reviewed import listing and finds no consistent pattern with regard to density and price. Price of low density product is sometime higher than higher density product and sometime lower. Unless there is a consistent pattern of product pricing based on a parameter, it must be concluded that the parameter, in fact, has not been followed by the parties concerned. Further, the interested parties have not shown any consistent pattern in this regard.
- As regards the contention that the Applicant only produces thickness ranging from 2.5 to 5mm; it is stated that the present application is in respect of material retardation to establishment of domestic industry. Therefore, the fact of no production during the injury period becomes irrelevant in the present case. The domestic industry is not yet fully established. It is obvious that the domestic industry would not have produced and sold all variants of the product. It may be noted, the domestic industry produced fiber board of 2.1 mm and Lab test reports of 2.1 mm fiber board produced by the domestic industry have been separately filed. The Applicant has produced particle board of E1 standard. If the Applicant can produce particle board of E1 standard, the Applicant can certainly produce product under consideration of E1 standards. The

present petition is in respect of dumping causing material retardation of establishment of domestic industry. As regards Fire retardant particle board; there is no factual basis for the claim. The Applicant has so far produced only selected few categories of product and the petition is in respect of material retardation of establishment of domestic industry. The Applicant, obviously cannot supply all range and types to begin with the production. The moment production is commercialized the Applicant shall offer all those products which are required in the market. However, even the most popular product types produced by the Applicant could not be sold to the extent of production and the Applicant was faced with piling up of inventories. Further, the Applicant was forced to sell the goods produced at significantly adverse price in view of dumping of the product.

- As regards Tariff heading 4411 not only includes boards that are bound by resin but also includes boards that may not be bound by resin; the Applicant is aware and the application is in respect of boards that are bound by resin but also includes boards that may not be bound by resin. The fact that board may be bound by other organic substance does not render the position any different. The Applicant submits that the product under consideration in the present investigations is “resin or other organic substances bonded wood or ligneous fibre boards of thickness below 6mm,” hereinafter, referred to as ‘fibre board’ in the petition. Fibre board is custom wood or craft wood composite engineered product, and is made of heat pressed resin bonded wood fibre. Fibre board can be further mechanically processed, such as laminated, surface coated, carved, molded, etc. Scope of the product under consideration in the present petition includes all products classifiable under customs heading 4411, except (a) fibre boards of thickness 6mm or above, (b) insulation boards, (c) laminated fibre boards and (d) boards which are not bonded either by resin or other organic substances. Besides, Manufacturers may classify the product based on emission standards, as per guidelines set by international organizations, like CARB (California Air Resources Board). Emission standards can be achieved by use of appropriate resin. All producers of fibre board in subject countries and Indian producers are in a position to produce and supply the product under consideration with different emission standards. To make E-1 fibre boards, worldwide the technology used is to add some additives in the Glue of E-2 and lower the Formaldehyde emissions. The Applicant has produced E-1 standard boards.
- Both the domestic producer, i.e., Balaji Action and Greenply were in the process of getting established during the POI therefore, goods not supplied being excluded from the scope of PUC does not arise.
- Domestic Industry is supplying slate manufacturers with the PUC. Letters from slate manufacturers confirming their procurement and satisfaction with the goods have been submitted.
- Lab test report of production of 2.3 mm and 2.0 mm board done by the domestic industry and submitted to the Authority shows that the industry is capable of producing subject goods of width below 2.5mm.
- As regards Density and Thickness; Density and thickness are correlated with each other. Generally density of thin MDF ranges from 750 to 850 kg/cbm. The BIS norms allow density variation of 10%. In reality, if any manufacturer increases the density the cost of raw materials will increase because of more consumption of raw material, power and also the productivity would be down as higher the density higher would be the curing time. It would also be seen that the production declines with lower thickness. However, it is seen that density overlaps between different thicknesses but the variation is not significant. Therefore, there has not been any impact of density and thickness in the product prices. Before the Authority considers any parameter as relevant for price comparison, the interested parties must first establish that the prices varied significantly and consistently with the parameter. If there is no consistent difference in the prices, the parameter in any case is required to be ignored. The interested parties have not kept any consistent difference in the prices on the basis of thickness and density. Such being the case, the Authority may kindly ignore the difference. Mere existence of a factor resulting in difference is insufficient. Such factor must have been recognized in the commerce as a factor that affects the prices. Such factor must have been consistently applied by the producers.
- As regards the contention that there are several viable substitutes available in the market as against what is stated by the applicant; the petition requires information on “viable substitute” for the product. The viable substitute has to be considered on the basis of technical and commercial substitutability of the product. It is a clear position that there is no technical or commercial substitute for the product

under consideration. None of the interested parties have identified any such technical and commercial substitute for the product. Further, if indeed there is any such technical and commercial substitute for the product; the interested parties should not be bothered about the present investigation. They can switch to such viable substitute.

- As regards the contention that T/T data has been adopted by the DI which has imports reported in different descriptions and units and only altered import data along with the methodology adopted has been provided and that complete raw data must be furnished so as to assess the correction of the compilation of import data; there is no such legal requirement for providing raw data. In terms of the prescribed application proforma in its relevant part, the petition should contain (a) volume and value of imports, country wise; and (b) source of information. Evidently, the T/T information itself need not be annexed with the petition. The only obligation on the Applicant is to identify the source and quantified volume and value of imports.
- Like Article: There is no known difference in the product produced by the Applicant company and exported from subject countries. Both the products have comparable characteristics in terms of parameters such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification, etc. Comparison of essential product properties in respect of domestic product and imported product would show that the goods produced by the domestic industry are comparable to the imported goods in terms of essential product properties. The subject goods are produced and sold in a number of variants to meet specific end applications. Different product types are produced using the same or similar raw materials, employing the same or similar production process, technology, employees. Fact of production or non production of a particular product type in the case of the Applicant depends on the market requirements. Further, since the Applicant is in the process of establishing itself in the Indian market, the Applicant is gradually offering different variants.
- If data relating to normal value and export price is business sensitive to exporters, data relating to domestic industry is also equally business sensitive. In fact, the exporters have not even disclosed their gross volume of exports. There can be nothing confidential about gross volume of exports made by the exporters during the relevant period

Examination by the Authority

25. The product under consideration in the present investigation is '*Resin or other organic substances bonded wood or ligneous fibre boards of thickness below 6mm, hereinafter, referred to as 'fibre board', except insulation boards, laminated fibre boards and boards which are not bonded either by resin or other organic substances*'.
26. From the product description, it would be amply clear that it covers wood or ligneous fibre boards of thickness below 6mm that are bound by resin but also includes boards that may not be bound by resin except insulation boards, laminated fibre boards and boards which are not bonded either by resin or other organic substances.
27. Fibre board is a custom wood or craft wood composite engineered product, and is made of heat pressed resin bonded wood fibre. Fibre board can be further mechanically processed, such as laminated, surface coated, carved, moulded, etc. Scope of the product under consideration includes all products classifiable under customs heading 4411, except (a) fibre boards of thickness 6mm or above, (b) insulation boards, (c) laminated fibre boards and (d) boards which are not bonded either by resin or other organic substances.
28. Fibre boards are wood based boards, available in different sizes and thicknesses. However, unlike solid wood made of single piece, they are high-strength engineered product - made from wood or lingo cellulosic material-refined into fibres, and then reconstituted with a resin binder at elevated temperatures, to form boards.
29. Fibre boards, being an engineered product, have certain advantages over solid wood (made out of single solid piece of wood). Fibre board has stronger tolerance to moisture changes, as compared to solid wood, because it is made of wood fibre arranged in overlapping pattern. It has better adaptability to environmental changes, and is very versatile. Fibre board has various applications, like in furniture, handicraft, consumer articles, etc.
30. The product under consideration is classified under Chapter 44 of the Customs Tariff Act. The product under consideration does not have a dedicated customs classification code. Customs classifications are indicative only and in no way binding on the scope of this investigation.
31. It is noted that the interested parties have merely filed their submissions seeking exclusions of different types within the PUC without appropriate reasoning. It is noted that the domestic industry has essentially

claimed injury in the present application.

32. As regards density vis a vis the prices, no consistent pattern has been noted after examining the responses of the interested parties. It is also noted that co-operating exports/producers have not made any distinction in their Appendix 8 data on this account.
33. **It has been submitted by some of the interested parties that the Applicant only produces thickness ranging from 2.5 to 5mm and slate manufacturers cannot use the goods supplied by the Applicant. The matter has been examined and it is noted that the domestic industry has produced subject goods with a thickness up to 2.1mm. After considering the submissions of all interested parties and analyzing their submissions, it is considered appropriate to exclude subject goods of thickness 2mm and below from the purview of the product under consideration as the domestic industry has not manufactured the subject goods with thickness 2mm and below during the POI.**
34. As regards the contention that there are several viable substitutes available in the market, the same has not been substantiated. It is seen that the domestic industry has disputed the claim. The Authority examined the issue further during the course of the investigation, and found that no viable substitute have been established by the interested parties.
35. The Authority concurs with the view that Door Skins are value added and a separate product. Besides, prices of door skin are significantly higher as compared to normal Fibre board. It is further noted that Fibre Board Moulded Door Skin can only be produced from Fibre Board of 3mm thickness with its density above 800 kg/m³. As Moulded Door Skin is a value added product, the same is not within the ambit and scope of the investigation. Thus, the product under consideration is defined as follows:

‘Resin or other organic substances bonded wood or ligneous fibre boards of thickness **more than 2mm and below 6mm,,** except insulation boards, laminated fibre boards, Moulded Door Skins, and boards which are not bonded either by resin or other organic substances.

36. The Authority notes that the imports data used in the present analysis pertains to the PUC. The data has been determined based on the ambit and scope of the PUC as defined in the initiation notification.
37. The Applicant has claimed that there is no known difference in the product produced by the Applicant company and exported from subject countries and that both the products have comparable characteristics in terms of parameters such as physical and chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, distribution & marketing and tariff classification, etc. A comparison of essential properties in respect of the domestic like product and the imported subject goods show that the domestic like product is comparable to the imported subject goods. The subject goods are produced and sold in a number of variants to meet specific end-use applications. Different types of the subject goods are produced using the same or similar raw materials, employing the same or similar production process, technology, employees etc.
38. Thus, the subject goods produced by the Applicant are being treated as like article to the product under consideration imported from the subject countries within the meaning of the AD Rules for the purpose of this investigation.

D. Scope of ‘Domestic Industry’ & ‘Standing’

39. At the time of the initiation of this investigation, Rule 2(b) of the AD Rules defined domestic industry as under:
‘domestic industry’ means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term ‘domestic industry’ may be construed as referring to the rest of the producers only.
40. However, this Rule has been subsequently amended to read as follows:
‘domestic industry’ means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term ‘domestic industry’ may be construed as referring to the rest of the producers.

Submissions made by other interested parties

41. The submissions made by interested parties, in brief, are as follows:

Submissions made by M/s Venugopala Slate Industries

- Applicant did not have the *Locus standi* for being considered as ‘domestic industry’ and the investigation should be terminated immediately as the Applicant has already admitted that it had imported the subject goods during the period of investigation and sold the same in the market at profit.

Submissions made on behalf of M/s Segamat Panel Boards Sdn. Bhd. and M/s Merbok MDF Lanka (Private) Ltd. Sri Lanka

- The Applicant has admitted that it had imported the subject goods during the period of investigation and sold the same in the market at profit. Thus, being an importer of the subject goods, the Applicant falls outside the ambit of ‘Domestic Industry’ as defined in the statute.

Submissions made on behalf of Evergreen Fibre board Berhad (EFB), Malaysia; Evergreen Fibreboard (IB) Sdn. Bhd. (EIB), Malaysia and Evergreen Fibre board (Nilai) Sdn. Bhd.(EFN), Malaysia

- The determination of standing of the Applicant as domestic industry is not in accordance with law as the Applicant has admitted the fact of imports in the period of investigation and hence there is no reason to treat the Applicant as domestic industry in view of the aforesaid. The domestic industry has made contradictory statements regarding imports. It has been submitted that in the initiation notification, it is disclosed that the imports were made in order to bench-mark the product being produced by the company by research and development and not for trading and that the volume of imports is miniscule in comparison with the production of the Applicant. Conversely, in their petition, they have stated that they have sold the imported material in the domestic market and made significant profits.
- Any analysis of imports by the applicant with the total imports or for that matter with sales/capacity is of no consequence as the standing of the petitioner is determined based on its level of production but not based on the volume of total imports/sales/ capacity. No reason given in the preliminary finding for departing from analysis of imports by petitioner in comparison to production.

Submissions on behalf of M/s. Magna-Foremost SDN and M/s. Masonite Components, Ireland

- The Applicant does not have the standing to qualify as the “domestic industry” under Articles 4.1 and 5.4 of the AD Agreement and Rule 2(b) of the Anti-dumping Rules because the Applicant is itself an importer of the subject product.

Submissions made on behalf of M/s PT. Masari Dwisepakat Fiber, Indonesia and M/s PT. Sumatera Prima Fibre board (SPF), Indonesia

- **Self Imports of Subject Goods for Benchmark:** The domestic industry to get over the requirement of Rule 2(b) has mischievously offered defense by stating that the self imports were for benchmark purposes. Such an object can be well achieved by buying imported goods from the local market and not by importing full containers of subject goods. Interestingly, in the petition, it is mentioned by Applicant that they imported the subject goods for research and development but not for trading. On the contrary, in at another page in the petition, they have categorical mentioned that they have sold the imported material at significant profit, that means they have traded the subject goods and earned profit also. Trend analysis for imports faulty due to self imports of applicants prior to POI and during POI. That the website of the Applicant admits that prior to POI they were only resorting to imports. That the case needs to be terminated for another reason as the determinations on standing and pre-conditions of Rule 5 cannot be made under Rule 12 or Rule 17.

Submissions made by domestic industry

- The Applicant Company has not imported the subject goods, barring small volume of imports made after the commencement of commercial production. The product of different thickness from different companies was imported in small quantities for the comparison with the product produced in house. The product comparison is effective only when the whole batch of the product is imported so that the extent of moisture content, glue content and various other product specifications can be compared with the same product range produced by the Applicant. These imports were made in order to benchmark the product being produced by the company by research and development and not for trading. In fact, the volume of imports is miniscule in comparison with the production of the Applicant. Bills of entry in respect of such imports have been provided to the Authority. The Applicant is not related (either directly or indirectly) to any exporter or importer of product under consideration in the subject countries.
- With regard to imports made by the Applicant, the reasons for imports have been given hereinabove. It is not a case where the Applicant has sold the imported material at significant profits. It is clarified that the statement in the application should not be read to mean that the Applicant has sold the product. In fact, the Applicant has not sold the product as such. It has consumed the product in downstream product and sold such downstream product (in downstream products also, the Applicant is suffering financial losses). The Applicant is not resorting to imports in order to benefit from dumping. Thrust of the Applicant has not turned to imports and the thrust continues to be on own production. The Applicant should therefore be

considered as eligible domestic industry within the meaning of the Rules.

- In respect of contention that the Applicant does not have the *locus standi* on account of importing goods during the POI; the argument is without any legal and factual basis. Contrary to the claim made, the definition of domestic industry provides that the Authority shall ordinarily consider “domestic producers as a whole”. Further, in case a domestic producer has imported the product from subject countries, the rules provide that the Authority “may” “construe” such a domestic producer as ineligible domestic industry. It may be noted that firstly, the rule does not say that the Authority shall consider such a company as an ineligible domestic producer. Secondly, because of the usage of the word ‘may’, an interested party must establish before the Authority that such a producer as ineligible domestic producer. This is more so given the ordinary meaning of word domestic industry. In other words, while inclusion should be assumed, the need to exclude must be established.
- In respect of imports made for benchmark purpose and that contradictory statements have been made; it is submitted that the domestic industry has given actual defense for self imports and that the allegation is without basis. Thin Board was not being produced in India before the Applicant started production. Therefore, question of buying the same from local market for benchmarking purposes does not arise. Further, the product imported for benchmark purpose need not be stored indefinitely. Business prudence demands that the same is disposed off once the purpose is achieved. The Applicant has not sold the imported product in the market and has consumed the imported product in downstream product and thereafter sold the product. In fact, it would be seen from the information that the Applicant has suffered losses in downstream products as well.
- Further, the interested parties must establish need for exclusion of a domestic producer from the scope of domestic industry because of imports made by them. The rule is not that if a domestic producer has imported, it may be automatically excluded. The ordinary rule is that the domestic industry means domestic producer as a whole; and in a case, a domestic producer has imported the product, it may be excluded, on being justified.
- A statement showing production by various producers and share of Applicant including that of the supporting company is contained in the application. From the mentioned data, it is evident that there are two companies in India namely Balaji Action Buildwell (the Applicant) and Green Ply Industries, who have recently commenced the production of the product under consideration. Green Ply Industries has commenced the commercial production of product under consideration very recently in December’2010. Green Ply Industries Ltd. has supported the present application. Thus, the Applicant constitutes “a major proportion” in the total Indian Production. Production of the Applicant accounts for more than 50% of the total Indian production (87% approx) and therefore should be considered as majority producer of the product under consideration. The application has been made by or on behalf of the Domestic Industry and therefore satisfies the requirements of standing under Rule 5(1) of the AD Rules.
- As regards the contention on substitutability between fiber board’s, it is submitted that fibre board of different thicknesses are produced on same production lines. The producers can easily switch from one product to another product by mere adjustments in the process control parameters and modification to raw material recipe.

Examination by the Authority

42. The Authority has noted the arguments raised by the interested parties. The Authority notes that the AD Rules confer discretion on the Authority to, *inter alia*, include or exclude a domestic producer that has imported the subject goods from the ambit & scope of the domestic industry on the facts & merits of each case. The amendment dated 1st December 2011 to Rule 2(b) of the AD rules does not alter the situation; but clarifies the same. Rule 2(b) of the AD Rules stipulates that domestic producers which are either related to the exporters or importers or which are themselves importers of the allegedly dumped articles may be excluded when determining the domestic industry in certain situations. The Authority notes that a domestic producer might import the product under consideration for one or more *bona-fide* reasons, including for testing, research & development, seed- marketing purposes (imports of the product to test the quality etc).
43. It is noted that the Applicant Company has imported the subject goods of different thickness in small quantities for the comparison with the product produced in-house to the extent of *** cbm during 2010-11, which accounts for approximately 0.46 % of the total imports. It is noted that these imports were made by the Applicant for bench-marking the product being produced by the company for research and development of its products and not for trading. The volume of imports is miniscule in comparison with the production of the

Applicant. It is also noted that the imports do not form the core activity of the company and it has not abdicated its role of a domestic producer.

44. As per the application, there are two producers of the product in India, namely M/s. Balaji Action Buildwell (the Applicant) and M/s Green Ply Industries Ltd. M/s Green Ply Industries Ltd. has supported the present application. Thus, the applicant along with the supporter account for 100% of the production of the subject goods in India.
45. The Applicant has claimed that the company's thrust continues to be on own production rather than on imports and the Applicant should therefore be considered as eligible domestic industry within the meaning of the AD Rules.
46. In view of the above, it would be inappropriate to exclude such a domestic producer from being treated as domestic industry. The Authority finds merit in the claim of the Applicant that it should not be excluded as a domestic producer of the subject goods in India and be considered as the domestic industry for the purposes of this application.
47. The Applicant accounts for more than 50% of the total Indian production (87 % approx) and therefore is a major producer of the subject goods. Thus, the application has been made by or on behalf of the domestic industry and satisfies the requirements of 'Standing' under Rule 5 of the AD Rules. Further, the Applicant constitutes 'Domestic Industry' in terms of Rule 2(b) of the AD Rules.

Issues raised by the interested parties subsequent to the issue of disclosure statement and examination by the Authority

48. The following interested parties have raised issues subsequent to the issue of disclosure statement
 - a) M/s. Venugopala Slate Industries, Markapur, Andhra Pradesh, (user and importer)
 - b) M/s Segamat Panel Boards Sdn, Bhd, Malaysia.. (exporter)
 - c) M/s P.T. Sumatera Prima Fibre Board, Indonesia. (exporter)
 - d) M/s. Evergreen Fibre Board Berhad (EFB), Malaysia. (exporter)
 - e) M/s Evergreen Fibre Board (JB) SDN BHD, Malaysia. (exporter)
 - f) M/s Merbok MDF Lanka (Private) Ltd., Sri Lanka. (exporter)
 - g) M/s. Balaji Action Buildwell, Delhi (petitioner and domestic industry)
49. It is noted that some of the issues raised by the interested parties are reiteration of their earlier submissions. It is also noted that many issues raised by the interested parties are common and these are not being repeated. The issues raised by the interested parties and examination by the Authority are as follows:

Submissions made by the domestic industry and examination by the Authority
50. The domestic industry has requested the Designated Authority to kindly reconsider the determination of dumping margin in view of the the fact that the exporters are exporting the product under consideration to third countries at higher prices as compared to India. They have submitted that the selling prices of product under consideration by Merbok Srilanka to Pakistan are much higher than India clearly establishing that they are dumping the material in India at much below prices and injuring the Indian domestic industry. Same is the position in respect of other subject countries.
51. On the issue of grant of dumping margin of M/s EFB and EJB, it has been submitted that the raw materials and inputs have been purchased by the company. However, as per information publically available and already submitted on record, it is evident that they have produced some of the important raw materials captive. It has further been submitted that the exporter's related entities are engaged in activities associated with production and/or sale of the subject goods including plantation, power generation, and manufacturing of glue required for manufacturing the subject goods. As majority of the raw material used in MDF manufacturing is wood, power and glue, correct establishment of costs is must before dumping margin can be determined for the exporter based on their response. Thus, mere claims on cost of production are insufficient. It must be shown that such cost of production is reasonably reflect costs associated with production and sale of the product under consideration. With regard to determining the normal value for M/s Segamat Panel Boards Sdn. Bhd, it has been submitted that it is not clear if the interest cost has been adjusted to the actual cost of production. In case the same has not been done, it is evident that records maintained by the company does not reasonable reflect the costs associated with production and sales of the article under consideration. With regard to determining the normal value for M/s PT Sumatera Prima Fibreboard, it has been submitted asto how the Authority has taken into account incomplete information. With regard to Merbok MDF Lanka (Private) Limited, it has been submitted that the export price and domestic sales of the exporter are below costs and the mere fact that the costs are on the basis of records maintained by the company is insufficient. It has further been submitted that the costs must reasonably reflect the cost associated with production and sale of the article under consideration. Further, it has been submitted that the profit for the purpose must be considered @ 10% of cost of production. The matter has

- been examined and it is noted that all their submissions have been examined under the appropriate headings in the subject findings. It is further noted that the Authority has verified the exporter's data and dumping margin has been determined as per the Anti dumping rules.
52. On the issue of injury and causal link, the Domestic industry has reiterated its submissions. It has further been submitted that they have provided injury information for 17 months of commercial production, the period for which the petitioner has produced and sold the product, which has been examined by the Designated Authority. After declaring commercial production, the petitioner has undertaken steady production. It is not a case where the petitioner has undertaken intermittent production. However, even when the petitioner has been able to steadily increase its production, it has been prevented from selling the product at fair price. The petitioner is selling the product at prices materially below the NIP. Imports are significantly undercutting the domestic prices. The domestic industry has even reached break even point, despite which the domestic industry is facing significant financial losses, negative return on investment and negative cash profits. It has further been added that even though the domestic industry has already achieved significant level of production, comparison of its performance with the anticipated/envisaged performance and for the period of its existence shows that the domestic industry has suffered injury to the extent it has produced the goods. With regard to data collection, it has been submitted that WTO itself has recognized those business situations where the period of injury is lower. To quote the Committee "the period of data collection for injury investigations normally should be at least three years, unless a party from whom data is being gathered has existed for a lesser period.....". Further, footnote 15 to the proposed amendment to the WTO ADA, the investigating authority should evaluate, to the extent that data exists, available information with respect to all economic factors and indices. Thus, in a situation where the domestic industry has existed for a shorter period, as the situation is in the present case, the injury analysis needs to be carried out only for such shorter period for which the domestic industry exists. They have further submitted that all mandatory 14 injury parameters have been examined in the present case and since the requirements under injury parameters itself is not exhaustive, performance in the present case must be evaluated in terms of envisaged performance at the time of conceiving the product and the production. The matter has been examined and the issues submitted by the domestic industry has been examined in the appropriate headings in this findings.
 53. The petitioner has submitted that the injury to the Domestic industry is established by the fact that The imports from the subject country have increased substantially, whereas the imports should have declined, given the production offered by the domestic industry. Level of price undercutting is very significant. Despite offering low prices, the domestic industry had to reduce its prices in view of its inability to sell the product. Even when the cost of production of every producer globally increased in view of increase in the input prices, the foreign producers have not increased their prices in proportion to the increase in the costs due to input price increases. In fact, prices remained almost stagnant despite significant increase in the input prices.
 54. The petitioner domestic industry has requested the Authority to disclose the analysis of the third country prices of the exporters and whether the third country prices have also remained at the same levels over the injury period. If not, this clearly shows selective dumping in the Indian market. On the issue of injury, it has been submitted that the domestic industry has been forced to sell the product at significant financial losses, resulting in negative return on investments and cash flow. Further, the performance of the domestic industry was much below the projected levels, despite sufficient demand for the product in the Country. Even after adjusting the cost of production of the domestic industry, it would be seen that the domestic industry was unable to recover its cost of production and earn reasonable profits. It has been submitted that during the Post POI period as well, they continue to suffer injury and they continue to suffer losses during the post POI period as well. It has further been submitted that though their performance has improved in terms of few parameters but overall they continue to suffer injury and run losses on account of dumped imports of subject goods from subject countries. The petitioner therefore has requested the Designated Authority to hold that the petitioner has suffered material injury in the present case. The matter has been examined and the issues submitted by the domestic industry has been examined in the appropriate headings in this findings.
 55. It has been submitted that anti dumping duties should be fixed in US\$ terms and in terms of fixed form of duty. In this regard, it has been stated that since provisional duty levied has been imposed as fixed quantum of anti dumping duty expressed in US\$, there are no justifications to change the form of duty. It has also been submitted that customs port authorities lack a mechanism to ensure correctness of import price reported by an importer and therefore it is neither feasible nor practicable for the port authorities to verify the import price. The matter has been examined and the anti dumping duties have been imposed taking into account the factual matrix of the case, submissions of all interested parties during the proceedings and analysis of these submissions.
 56. On the issue of price undertaking, it has been submitted that the price undertaking should not be accepted in the present case in view of the difficulties in its monitoring. The matter has been examined and it is stated that price undertaking has not been accepted in view of the practical difficulties in monitoring price

undertakings.

Submissions made by producer exporters, importers and users and examination by the Authority

57. It has been submitted by importer and user that all injury factors must be assessed on the basis of quarterly data and not on the basis of annual data or projected performance. This includes items like profitability and any other of the 15 parameters assessed for this purpose. In this regard, it is noted that all the injury factors have been analysed in terms of the quarterly data to the extent that these could be discerned from their records.
58. It has been submitted by importer and user that start up cost in the cost of production charged by domestic industry for the purpose of injury analysis and NIP determination has not been analysed. It has also been stated that all costs should be taken into account to arrive at the per unit cost of production which invariably will be high for new industry. The matter has been examined and it is noted that all adjustments of start up cost in the cost of production charged by domestic industry for the purpose of injury margin and NIP determination has been made. Further NIP determination has been made strictly as per Annexure III of the anti dumping rules as amended which takes care of low level of capacity utilisation of the domestic industry.
59. It has been submitted by importer and user that post POI performance has no relevance in the fresh investigation. It has also been stated that there is no data available for trend analysis causing injury to domestic industries. The matter has been examined and it is stated that anti dumping rules do not forbid Authority to ask for injury data for post POI period. However, for the purpose of determination of dumping margin and injury margin, post POI data has not been taken into account as per the consistent practice of the Authority. More over, the reasons for taking post POI data is that it provides a means of assessing and ensuring that data credibility is maintained keeping in view of the fact that the company was in operation for a shorter period. It is also added that because of the shorter time period of analysis of performance of the domestic industry, quarter wise analysis has been made for determining trends of the domestic industry in terms of various injury parameters.
60. It has been submitted by importer and user that the Applicant only produces thickness ranging from 2.5 to 5mm and slate manufacturers cannot use the goods supplied by the Applicant. It has also been submitted by some of the interested parties that thickness of 2.1mm and less than that should be excluded from the purview of the product under consideration. The matter has been examined and it is noted that the domestic industry has produced subject goods with a thickness up to 2.1mm. After considering the submissions of all interested parties and analyzing their submissions, it is considered appropriate to exclude subject goods of thickness 2mm and below from the purview of the product under consideration as the domestic industry has not manufactured the subject goods with thickness 2mm and below during the POI.
61. With regard to response of M/s Merbok MDF Lanka Pvt Ltd on the issue of adding interest costs to cost of production of the cooperating producer and exporter from Sri Lanka, it has been submitted by the producer exporter M/s Merbok that the exchange control Act of Sri Lanka prescribes that loans shall not exceed LIBOR + 6%. It has also been submitted that para (c) the response indicates that the website of Bank of Ceylon stipulates US\$ loan to exporters between 5-7%. It has also been submitted that consideration of notional interest on owners funds or any other notional interest is not an accepted practice in cost accounting. Further, it has also been contended that DGAD in a previous investigation considered the interest rate at 5.7% on US\$ loan of *** million. In a separate email received, it has been stated that Authority must apply the rate of interest as per the Bank of Sri Lanka or US\$ loan. Further, it has been stated that maximum rate of interest at 5% of COP for constructed normal value should be taken. It has also been submitted that in this case a rate of ***% of COP has been taken. Further, they have drawn the attention of the Authority that the holding company secured a loan in Malaysia for 1.5% but the company was able to secure a loan from commercial bank of Sri Lanka at 4.57%. It has also been added that Bank of Sri Lanka offers US\$ loan to exporters @ 5-7%.
62. It is also noted that the present investigation being specific to the operations of the company in Sri Lanka, what is pertinent is the cost of US\$ financing in Sri Lanka and not any interest rates at which the parent company may be borrowing the capital. Based on the published data made available to the Authority, the prevailing rates of interest on US \$ borrowings have been considered and appropriate adjustments have been made in the interest cost at 7% which covers both the contentions of M/s Merbok that LIBOR+6% is relevant or central bank of Ceylon published US\$ loan of 5-7% may be used.
63. With regard to submissions of M/s Merbok, Lanka regarding the allocation of between PUC and non PUC on the basis of value of respective plant and machinery rather than on the basis of production quantity, it is noted that there were certain errors in the revised data on allocation of plant and machinery between PUC and non PUC furnished by the exporter during onsite verification. The Authority had, therefore, considered the quantity produced as basis for charging depreciation as initially claimed by the exporter. The Authority has since reviewed the revised data furnished by the exporter at the time of onsite verification and reworked the allocation of assets between PUC and non PUC on the basis of value of their

respective plant & machinery in terms of accepted costing principles after the rectifying errors. Accordingly, the ratio of depreciation charged to PUC now works out to ***% as against ***% originally claimed by the exporter.

64. With regard to consideration of post POI data, it has been submitted by cooperating producer and exporter from Indonesia M/s SPF that the designated authority should disclose under which letter the POI data was filed, and at what stage of investigation. The matter has been examined and it is noted that the Authority had called for additional information from the domestic industry subsequent to written submissions and rejoinder submissions of the interested parties. As stated elsewhere in this final findings, the reasons for taking post POI data is that it provides a means of assessing and ensuring that data credibility is maintained keeping in view of the fact that the company was in operation for shorter period. However, it is stated that for the purpose of determination of dumping margin and injury margin, post POI data has not been taken into account as per the consistent practice of the Authority.
65. It has been submitted by one producer exporter M/s Evergreen (EJB and EFB) that PCN identification should have been used for investigation and determination of dumping margin. The same exporter has also talked about low emission boards and standard boards. The said producer exporter has spoken about the glue type determining the low emission board versus the standard board. Further, he has mentioned cost having a limited role in comparison of normal value with export price, and has further stated that exporters are not required to provide cost details PCN wise. The matter has been carefully considered and it is stated that the issue has been well examined in the dumping margin determination of the cooperating producer exporter. As indicated elsewhere by the Authority, it is stated that the said company does not follow product coding system and the type of product is identified on the basis of the description given on the invoice/sales contract etc where no such details were noted. During the examination of response and during the onsite verification of data, it was noted that there are no major differences in the goods sold or produced in the domestic market or exported to India in physical/ technical / chemical characteristics. The Authority further noted that based on the criteria, as claimed by the exporter, no trends are emerging either in the cost of production or the sales price of the subject goods (including low emission boards). The reasons for the variations in the costs, selling prices and profitability for each type or PCN could not be explained by the company with the evidence. Further, it may recalled that no other interested parties comprising other producer exporters from subject countries including the domestic industry has commented upon or given information about the desirability of determining dumping margin based on PCN. With regard to the argument that cost has a limited role in the computation of normal value with export price, it is stated that the same is required for determination of normal value as ordinary course of trade test is carried out by comparing sales price with the cost of production. With regard to one duty for both the group companies i.e EFB and EJB, it is stated that the Authority has determined one duty as per the consistent practice of the Authority as both the companies are related companies.
66. It has been submitted by M/s Evergreen (EJB and EFB) that the consumer of the subject goods are small in number and duty on reference price basis would be appropriate to address the interest of these consumers. The matter has been examined and keeping into account the facts of the matter and taking into account the submissions of all interested parties, the Authority considers it appropriate to recommend anti dumping duty on a reference price basis.
67. It has been submitted by M/s Evergreen (EJB and EFB) that the Authority should do an objective examination and the Designated authority must investigate this case with an unbiased manner without favouring the interest of any interested party or group. It has further been submitted that on all the 15 parameters, there is no injury. The matter has been examined and it is stated that based on the examination of information submitted by the domestic industry, the domestic industry has suffered price under cutting as well as price under selling on account of dumped imports of subject countries into India. Further, an examination of the impact on the price effect on the domestic industry on account of dumped imports of subject countries reveal that the domestic industry has suffered losses during all the quarters of the POI. In addition, the domestic industry has suffered negative return on investment and cash flow during the injury period.
68. It has been submitted by M/s Evergreen (EJB and EFB) that there is an inverse relationship between import price and domestic price and that that injury is self inflicted and self contributory and not because of alleged dumping procedure. In this regard, it is noted that based on the verification of data for all the cooperating producers and exporters, the quantum of dumping has been found to be significant. Further, the price undercutting as well as underselling is significant resulting in financial losses suffered by the domestic industry.
69. On the issue of causal link, the matter has been examined and though the import price has marginally increased during the POI from previous year, it has to be seen in the light of the fact that there was significant increase in the raw material prices for the subject goods during the same time and export price of subject goods from subject countries do not take into account the increase in the raw material prices which appears to have been absorbed by the exporters. With regard to the fact that domestic industry prices indicate a decline during the same time indicate that the domestic industry was finding it difficult to

sell the subject goods at the same or higher price and thus to increase its sales and market share, it had reduced its selling prices. With regard to improvement in the some of injury parameters, it is stated that the fact that the domestic industry performance of the domestic industry has improved in one or more parameters does not imply that the domestic industry has not suffered injury. The facts that the domestic industry has suffered continued financial losses, adverse return on investment and cash flow, price undercutting, price depression, and also the fact that the domestic industry is faced with significant price underselling shows that the injury to the domestic industry. In addition, it is stated that the authority is required to come to a conclusion on the basis of overall assessment of the performance of the domestic industry whether the domestic industry has suffered injury and not on the basis of few parameters.

E. NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN

Submissions made by other interested parties

70. The submissions made by interested parties, in brief, are as follows:

Submissions made on behalf of Sri Lanka High Commission

- Method of calculation of cost of production is inconsistent the with previous cases of MDF. To make a fair justification on the case, a consistency in calculation method needs to be maintained.

Submissions made on behalf of Evergreen Fibreboard Berhad (EFB), Malaysia; Evergreen Fibreboard (JB) Sdn. Bhd. (EJB), Malaysia and Evergreen Fibreboard (Nilai) Sdn. Bhd.(EFN), Malaysia

- The normal value has been incorrectly determined on the basis of high consumption norms of the domestic industry for raw material and utility whereas the consumption norm for raw material and utility are much lower for the exporters.
- Single dumping margin for two separate legal separate distinct entities cannot be determined. Authority is required to determine separate dumping margin for each known exporter.
- Normal value for EJB has been constructed. However, normal value should be determined on the information provided by the exporter when such information is available. Exporter has provided all the information.

Submissions made on behalf of M/s PT. Masari Dwisepakat Fiber, Indonesia & M/s PT. Sumatera Prima Fibre board (SPF), Indonesia

- Selection of Surrogate Country: The Authority failed to follow proper procedure as prescribed under paragraph 7 of Annexure I to select appropriate market economy third country. Under the procedure, the domestic industry was required to provide sufficient evidence and names of producers for the Authority to propose such selection in the initiation notification. Neither did the domestic industry provide any material or evidence nor did the Authority make any efforts to select an appropriate market economy third country out of the three countries proposed. No efforts whatsoever had been made by the Authority to seek appropriate information. Further, the Authority failed to appreciate that in spite of the legal obligation under paragraph 7, it failed to put the parties to the investigation at notice without unreasonable delay about selection of the third country market economy or surrogate country. The applicant has not even specified as to which country was proposed to be taken as a surrogate country, despite having full knowledge of several similar economies involved in the production of the subject goods and also of their participation in the current investigation.
- Adjustments in the Export Price: In the initiation notification, the Authority has only considered ocean freight, marine insurance, documentation charges, cleaning charges and manifestation charges for calculating ex factory price for exports, but in the petition the Applicant has considered commission also. In this regard, the Authority should provide the final export price used for initiation purpose. Further, the commission charged by the Applicant is very high. In most of the cases commission is considered as 1% of FOB price.

Submissions made on behalf of the domestic industry

- As regards the contention that Authority failed to follow proper procedure under para 7 of Annex. 1 to select

appropriate market economy third country etc; it is stated that the stage of application of Para 7 by the Authority has not even arrived as yet. The Applicant submits that normal value for China PR could not be determined on the basis of price or constructed value in a market economy third country for the reason that the relevant information is not available to the Applicant. It is noted that such normal value must be “comparable price in the ordinary course of trade for the like article when meant for consumption in such market economy third country”. In order to arrive at normal value on this basis, the Authority shall require complete & exhaustive verifiable information on all domestic sales made by a cooperating producer in such third country, along with its cost of production and all other associated information and evidences (including all information in the ordinary course of trade). Principles of fair comparison as laid down under Article 2.4 of the Agreement are also relevant in this respect. The Applicant has not been able to procure such information from a producer in market economy third country.

- The Applicant submits that India is an appropriate surrogate country for China PR. Not only the consideration of India as a surrogate country would result in access to accurate and adequate information, there is no factual basis to consider that India would not be a proper surrogate country. India has been considered as an appropriate surrogate by other Investigating Authorities too. The normal value in China can be determined on any of the above-mentioned basis. The normal value in China can thus be determined on the basis of (a) price in India, and (b) cost of production in India, duly adjusted, including selling, general and administrative expenses and profit. The normal value has been determined accordingly on the basis of cost of production in India, duly adjusted, in view of the fact that the selling price is a loss making price.
- Further, the Applicant refers to Para 8 of Annexure-I to the rules which provides that the Authority shall examine whether the product or the producers in China are operating in market economy environment. The Authority is required to provide sufficient opportunity to the parties concerned in this regard. It is only thereafter that the Authority can consider application of Para 7 and a question of surrogate country shall arise. Information from such surrogate country at this stage shall imply a presumption on the part of the Authority that the Chinese exporters, in any case, would not claim market economy status either for the product or in respect of the companies.
- As regards the contention that in the initiation notification adjustment to export price included does not include commission, whereas the Applicant has claimed adjustment on account commission in the application; the DA need not accept all the claims made by the Applicant; nor rejection of the claim with regard to commission would make dumping margins significantly different. The application should contain sufficient prima facie evidence of dumping.
- As per information known to the Applicant, a number of producers are engaged in production of the product under consideration in the subject countries. Before accepting any response, the Applicant requests the Authority to kindly cross check the claims made by these interested parties with the Indian Customs data. Static import price despite rising raw materials is a clear evidence of dumping. It would be seen that there is a significant increase in the input costs. If the import prices are adjusted for the increase in the input prices, it would be seen that the import prices in fact have significantly declined [i.e. cost adjusted import prices show huge decline over the period. It is thus evident that dumping has intensified over the period.
- M/s Evergreen Fibreboard Berhad (EFB) has a subsidiary, namely M/s Evergreen Fibreboard (JB) Sdn. Berhad (EJB) who have filed questionnaire response. However, another group company M/s Evergreen Fibreboard (Nilai) Sdn. Bhd, which is producing and selling the subject goods in the domestic market has not filed questionnaire response therefore response from evergreen should be rejected.
- The Authority cannot determine normal value on the basis of domestic prices unless the exporter has established that the same is “in the ordinary course of trade”. No such information/evidence has been advanced by the exporter and therefore the questionnaire response must be rejected.

Examination by the Authority

71. The Authority notes that the Applicant domestic industry is required to provide information that is reasonably available to it and sufficient information was made available to justify initiation of the investigation in the instant matter.
72. As regards the issue that normal value has been incorrectly determined on the basis of high consumption norms of the domestic industry for raw material and utility whereas the consumption norm for raw material and utility are much lower for the exporters, the same is incorrect. As recorded in the initiation notification, the

Applicant had estimated the Normal values in the subject countries by considering the constructed normal value approach. For the purpose, it had estimated cost of production of the foreign producers by adopting such information as is reasonably and publically available. The Authority had prima-facie considered the normal value of the subject goods in the subject countries on the basis of constructed values for the purpose of the initiation of this investigation. The Authority, however, notes that it expected concerned exporters/producers from the subject countries to co-operate in the investigative process by filing their exporter's questionnaire response for facilitating appropriate determination of the dumping margins so that the Normal values could be determined based on their respective questionnaire responses. It is noted that a few exporters /producers from the subject countries (except from China PR) have filed their exporter questionnaire's response. An examination of the exporters' questionnaire response along with additional information /data sought by the Authority, shows that the dumping margins are significantly positive.

73. As regards the contention that Authority failed to follow proper procedure under para 7 of Annex. 1 to select appropriate market economy third country etc; the Authority notes that the issue has been raised by an Indonesian exporter, who should not be concerned with this issue as para 7 is not applicable to them at all. No Chinese exporter/producer has sought to question the same. Notwithstanding the same, the Authority notes that the Applicant had submitted that Normal value for China PR could not be determined by them on the basis of price or constructed value in a market economy third country as relevant information was not accessible to them. It needs to be noted that appropriate market economy third country must be comparable keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question. The Authority notes that it did not have any reliable information that was made available to it at the time of initialing this investigation. Besides, the Applicant had submitted that India is an appropriate surrogate country for China PR as not only India has been considered as a surrogate country to China PR in the past by WTO Members but it would also result in access to accurate and adequate information. The normal value had thus been determined on the basis of cost of production in India, duly adjusted. While doing so, the Authority had moderated the claims of the Applicant and it was thus determined that there was sufficient evidence on record in this respect to justify initiation of the investigation.
74. As regards adjustments in the Export Price at the time of initiation notification; it is clarified that the Authority had considered ocean freight, marine insurance, documentation charges, cleaning charges and manifestation charges and had disregarded the claim with respect to commission for the purposes of estimating ex factory price of the subject goods from the subject countries. Thus, rather than considering commission @ 1% of FOB price as suggested by the interested party, the Authority had not made any adjustment in the export price for the same.
75. The Authority sent questionnaire to the known exporters/producers from the subject countries, advising them to provide information in the form and manner prescribed. Response to the questionnaires were received from the following:

S.N.	Name of Producer/Exporter
1	M/s. Magna-Foremost SDN, BHD, Malaysia
2	M/s Masonite Components, Ireland
3	M/s Merbok MDF Lanka (Private) Ltd., Sri Lanka.
4	M/s Segamat Panel Boards Sdn, Bhd, Malaysia
5.	M/s P.T. Masari Dwisepakat, Indonesia
6.	M/s P.T. Sumatera Prima Fibre Board, Indonesia
7.	M/s. Evergreen Fibre Board Berhad (EFB), Malaysia
8.	M/s Evergreen Fibre Board (JB) SDN BHD, Malaysia
9.	M/s Evergreen Fibre Board (Nilai), Sdn. Bhd (EFN), Malaysia
10.	M/s Daiken Miri Sdn. Bhd., Miri Sarawak, Malaysia

76. M/s Daiken Miri Sdn. Bhd., Miri Sarawak, Malaysia has stated that they have not exported the subject goods during the POI.

Examination of Market Economy claims in respect of China PR by the Authority

77. The Authority notes that in the past three years China PR has been treated as a non-market economy country in anti-dumping investigations by India and other WTO Members. China PR has been treated as a non-market economy country subject to rebuttal of the presumption by the exporting country or individual exporters in terms of the AD Rules.
78. As per Paragraph 8 of Annexure I of the AD Rules, the presumption of a non-market economy can be rebutted, if the exporter/producer(s) from China PR provide information and sufficient evidence on the basis of

the criteria specified in sub paragraph (3) of Paragraph 8 and establish the facts to the contrary. The co-operating exporters/producers of the subject from People's Republic of China are required to furnish necessary information/sufficient evidence as mentioned in sub-paragraph (3) of paragraph 8 of Annexure I of the AD Rules in response to the Market Economy Treatment questionnaire to enable the Authority to consider the following criteria as to whether: -

- the decisions of concerned firms in China PR regarding prices, costs and inputs, including raw materials, cost of technology and labour, output, sales and investment are made in response to market signals reflecting supply and demand and without significant State interference in this regard, and whether costs of major inputs substantially reflect market values;
 - the production costs and financial situation of such firms are subject to significant distortions carried over from the former non-market economy system, in particular in relation to depreciation of assets, other write-offs, barter trade and payment via compensation of debts;
 - such firms are subject to bankruptcy and property laws which guarantee legal certainty and stability for the operation of the firms and
 - the exchange rate conversions are carried out at the market rate.
79. The Authority indicated, in the initiation notification that the applicant has claimed that China PR should be treated as Non Market Economy and therefore Normal value in case of China PR should be determined in accordance with Para 7 and 8 of Annexure I of the AD Rules. The applicant has submitted that they have not been able to access information from a market economy third country for the purposes of determination of Normal value in respect of China PR and has pleaded that India can be considered as an appropriate market economy third country for determination of normal value in China PR. The Authority informed known exporters/producers from China PR that it proposes to examine the claim of the Applicant in the light of para 7 and 8 of Annexure I of the AD Rules. The exporters/producers of the subject goods from China PR were therefore requested to furnish, *inter alia*, necessary information/sufficient evidence as mentioned in sub-paragraph (3) of paragraph 8 of the Annexure I of the AD Rules to enable the Authority to consider whether market economy treatment be granted to cooperative exporters/producers from China PR.
80. The Authority notes that consequent upon the initiation notice issued by the Authority; none of the Chinese producer/exporter has submitted its questionnaires' response including the market economy questionnaire response and thus has not sought to rebut the non-market economy presumption.

Determination of Normal value in respect of Exporters / Producers from China

81. Para 7 of Annexure I of the AD Rules provides that

In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India or where it is not possible, or on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner, keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question, and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of selection. Accounts shall be taken within time limits, where appropriate, of the investigation made in any similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without any unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments.

82. The Authority notes that sufficient information and evidence is not available on record in respect of the price or constructed value of a market economy third country that has the comparable level of development *vis a vis* China PR, particularly considering the subject goods. Thus, in view of the above facts, the Authority determines the Normal value in respect of exporters/producers from China PR on available reasonable basis, in terms of second proviso of para 7 of Annexure I to the AD Rules. Accordingly, the ex-works Normal Value of the product under consideration have been determined based on constructed costs of production, duly adjusted. The Normal Values have been constructed as per the methodology described below:

Methodology adopted for constructing Normal Value in case of China PR

83. Accordingly, the Authority has constructed Normal value for producers in China PR on the basis of:
- the price of inputs as procured by the domestic industry,
 - efficient consumption norms of raw materials of domestic industry as considered in the NIP.
 - the utilities cost and conversion costs of the domestic industry as considered in NIP.
 - After arriving total cost of production for CNV as above, 5% profit has been allowed.
84. The normal value so determined is mentioned in the table showing dumping margin.

Normal value in respect of Indonesia, Malaysia and Sri Lanka – responding exporters

85. Response to the questionnaire were filed by the following companies from Malaysia.

SN	Name of Producer/Exporter
1	M/s. Magna-Foremost SDN, BHD, Malaysia
2	M/s Masonite Components, Ireland
3	M/s Merbok MDF Lanka (Private) Ltd., Sri Lanka.
4	M/s Segamat Panel Boards Sdn, Bhd, Malaysia
5.	M/s P.T. Masari Dwisepakat, Indonesia
6.	M/s P.T. Sumatera Prima Fibre Board, Indonesia
7.	M/s. Evergreen Fibre Board Berhad (EFB), Malaysia
8.	M/s Evergreen Fibre Board (JB) SDN BHD, Malaysia
9.	M/s Evergreen Fibre Board (Nilai), Sdn. Bhd (EFN), Malaysia
10.	M/s Daiken Miri Sdn. Bhd., Miri Sarawak, Malaysia

86. M/s. Magna-Foremost SDN and M/s. Masonite Components, Ireland has stated that they have not exported the subject goods to India and that they have only exported door-skins. Since it has already been clarified that door-skins are not part of the PUC, no further examination of their data has been undertaken for determining individual dumping margin in their case. Following the preliminary findings, M/s P.T. Masari Dwisepakat, Indonesia did not consent to the verification of the information filed by them after the initiation and their information remained unverified.

87. **Following verification of the cooperating producer and exporters, a verification report was issued to all concerned producers and exporters for their comments. Their comments with regard to determination of dumping margin were taken into account by the Authority in the disclosure statement. Following the issuance of disclosure statement, the details of the normal value and export price determination was given to all the concerned producers and exporters. In addition, the details of the workings of the dumping margin determination including the workings in excel sheet were given to all concerned exporters for their comments. The workings were also explained to those exporters who wished to be explained. The comments from these concerned exporters to the disclosure statement have been taken into account in the dumping margin determination which is explained below.**

General methodology followed for the responding exporters for determination of Normal Values

88. The Authority has determined individual dumping margin in respect of co-operative exporters / producers who have provided the requisite information. The general methodology adopted for determination of Normal value is as follows:
89. It was first seen, whether the domestic sales of the subject goods by the responding exporters/producers in their domestic markets were representative and viable for permitting determination of Normal values on the basis of their domestic selling prices and whether the ordinary course of trade test was satisfied as per the data provided by the respondents and sought by the Authority. Wherever the respondents have provided transaction-wise details of the sales of the like article in their home markets, the information so provided has been relied upon to determine the Normal value for the subject goods after carrying out the ordinary course of trade test and sufficiency test subject to further investigation and verification.
90. For carrying out the OCT test, the costs of production have been examined with reference to the exporter's/producer's questionnaire responses filed by them and in terms of the additional information sought by the Authority. This information was further verified during the onsite verification of cooperating producers and exporters from subject countries. Wherever discrepancies in the information/data filed have been noted, the Authority has therefore constructed the cost to make and sell the goods based on best information available on record.
91. Wherever, there were no domestic sales or no sufficient domestic sales, the Normal value has been determined by the Authority on the basis of 'facts available' in terms of Rule 6(8) of the AD Rules.
92. In their responses, it is noted that the respondent producers and exporters provided transaction-wise details of sales made of the subject goods in their home markets as well as exports to India. Further, all domestic sales transactions were examined with reference to the costs of production of the subject goods/ constructed costs, to determine whether the domestic sales were in the ordinary course of trade. It was also seen whether the loss-making transactions account for over 20% of the sales or not. Wherever the profitable domestic sales transactions were found to be accounting for more than 80% of total sales, the weighted average price of all the domestic sales have been taken into consideration. However, wherever the profitable sales volume was found to be less than 80%, the weighted average price of the profitable domestic sales has been taken into consideration.

Determination of Normal value in respect of Co-operative Exporters / Producers from Indonesia, Malaysia and Sri Lanka

M/s Evergreen Fibreboard Berhad (EFB)

M/s Evergreen Fibreboard (JB) Sdn. Berhad (EJB)

93. It is noted that the company is having shareholding in different companies in Malaysia engaged in the down-stream and also up-stream products. In their response and during verification, it was stated that the company purchased the raw materials i.e. wood log and glue from related companies namely *** and *** respectively. It was further claimed by the producer and exporter on the basis of PCN devised by them that the goods having the same PCN sold in the domestic market and the export markets are identical. However, from the perusal of the response of the company it is noted that the company does not follow product coding system and the type of product is identified on the basis of the description given on the invoice/sales contract etc where no such details were noted. During the examination of response and during the onsite verification of data, it was noted that there are no major differences in the goods sold or produced in the domestic market or exported to India in physical/ technical / chemical characteristics. The Authority further noted that based on the criteria, as claimed by the exporter, no trends have been noted either in the cost of production or the sales price of the subject goods. The reasons for the variations in the costs, selling prices and profitability for each type or PCN could not be explained by the company with the evidence.
94. The questionnaire' response submitted by the company was perused. It was found that the respondent has provided selling price and other details of the subject goods in relevant Appendixes of their response. It is noted that M/s Evergreen Fibreboard Berhad (EFB) has a subsidiary, namely M/s Evergreen Fibreboard (JB) Sdn. Berhad (EJB), which has also filed its questionnaire response. Besides, it is also noted that there is another group company M/s Evergreen Fibreboard (Nilai) Sdn. Bhd, which is producing and selling the subject goods in the domestic market but no response had initially been filed on behalf of this company. In response to query from the Authority, it was clarified that the response has not been filed as the company has not exported the subject goods to India. The company subsequently submitted their response.
95. It is noted from the published data available on the web-site of the company that the company has a number of related entities engaged in activities associated with production of the subject goods including plantation, power generation, manufacturing of glue required for manufacturing the subject goods.
96. It was noted that the Company had made domestic sales of *** m3 of the subject goods in the period of investigation. As per Appendix-1, the company had claimed adjustments on account of credit cost, bank charges, inland freight etc which was allowed after verification of information. After verification of the information, it is noted that the company has earned profits on domestic sales. In the circumstances, the Authority has determined the Normal value based on domestic sales, which is mentioned in the table showing the dumping margin.

M/s Evergreen Fibreboard (JB) Sdn. Berhad (EJB)

97. It is noted that the company is having shareholding in different companies in Malaysia engaged in the down-stream and also up-stream products. During verification, it was stated that the company purchased the raw materials i.e. wood log and glue from related companies namely *** and *** respectively. It was claimed by the producer and exporter on the basis of PCN devised by them that the goods having the same PCN sold in the domestic market and the export markets are identical. However, from the perusal of the response of the company it is noted that the company does not follow product coding system and the type of product is identified on the basis of the description given on the invoice/sales contract etc where no such details were noted. During the examination of response and during the onsite verification of data, it was noted that there are no major no major differences in the goods sold or produced in the domestic market or exported to India in physical/ technical / chemical characteristics. The Authority further noted that based on the criteria, as claimed by the exporter, no trends are emerging either in the cost of production or the sales price of the subject goods. The reasons for the variations in the costs, selling prices and profitability for each type or PCN could not be explained by the company with the evidence.
98. The questionnaire' response submitted by the company was perused. It was found that the respondent has provided selling price and other details of the subject goods in relevant Appendixes of their response. It is noted that M/s Evergreen Fibreboard Berhad (EFB) has a subsidiary, namely M/s Evergreen Fibreboard (JB) Sdn. Berhad (EJB), which has also filed its questionnaire response. Besides, it is also noted that there is another group company M/s Evergreen Fibreboard (Nilai) Sdn. Bhd, which is producing and selling the subject goods in the domestic market but no response has been filed on behalf of this company. In response to query from the Authority, it was clarified that the response has not been filed as the company has not exported the subject goods to India.
99. It is noted from the published data available on the web-site of the company that the company has a number of related entities engaged in activities associated with production of the subject goods including plantation, power generation, manufacturing of glue required for manufacturing the subject goods.
100. It was noted that the Company has made domestic sales of *** m3 of the subject goods in the period of investigation. As per Appendix-1, the company has claimed adjustments on account of credit cost, bank charges, inland freight etc which was granted after verification of the same. In the circumstances, the Authority has determined the Normal value based on domestic sales, which is mentioned in the table showing the dumping margin.

101. In view of the fact that once company is the subsidiary of the other; the Authority has decided to determine a single dumping margin for both the respondents, that is, M/s Evergreen Fibreboard Berhad and M/s Evergreen Fibreboard (JB) Sdn. Berhad.

M/s Segamat Panel Boards Sdn. Bhd.

102. It is noted from response of the exporter that M/s SPB commenced its production in Malaysia in August 2002 with shareholder's funds of ***. It was further noted from their response that the company is a ***% subsidiary of Singapore based trading company M/s-***. It was further informed that they have a particle board plant along with the MDF plant. It was submitted by the company that the particle board plant is yet to be commissioned. The Company has sold *** CBM of the subject goods in the domestic market. From the perusal of the response of the company it is noted that SPB only produces thin MDF ranging from 2.2 MM thickness to 6.00 MM.
103. The questionnaire' response submitted by the company was perused. It was noted that the Company had sold *** CBM of the subject goods in the domestic market. It was explained that sales of above subject goods in domestic market was carried out either on Ex-factory basis or on delivered basis. In case of delivered basis company had paid inland freight. It was found that the respondent has provided selling price and other details of the subject goods in relevant Appendixes of their response. The examination of the questionnaire response filed by the company along with the additional information/data sought by the Authority indicates that the company has incurred financial losses on the overall sales of the subject goods after excluding the realizations from the non-cost items. In response to the query from the Authority, the company clarified that its domestic operations for the subject goods are making profits whereas the losses are only in third country exports (other than India) because of higher incidence of . It is recalled that a verification report was issued to the company following verification of the information submitted by them. During verification, the Authority noted that the company has received interest free loans from some of the related parties. In their comments to the verification report, the company stated that notional interest which is not charged in their books of accounts should not be considered in the cost of production. The response of the company was further examined by the Authority and it was noted that their profitable domestic sales are less than 80% by the way of volume. The adjustments claimed by the company have been accepted after due verification and after adjustments for the interest on the borrowings from the related entities. Thus, the normal value has been based on the domestic sales of the company i.e after taking into account the profitable domestic sales of the company as worked out and mentioned in the table showing dumping margin.

PT SUMATERA PRIMA FIBREBOARD

104. It is noted from the response that M/s PT Sumatera Prima Fibre board (SPF) is a private limited company incorporated under the company laws of Indonesia. The Company is located at Jl Jend. Sudirman Kav., Jakarta, Indonesia. It was noted that the Company has made domestic sales of *** m3 of the subject goods in the period of investigation. As per Appendix-1, the company has claimed adjustments on account of credit cost, bank charges, inland freight etc which was allowed after verification of the information. From the perusal of the response of the company it is seen that the company has claimed that the goods sold in the home market are identical to the exported goods for the same specifications. Therefore, the comparison of prices in the two markets ought to be made for each product code. It was also submitted by the company that the exporter SPF are in a position to manufacture the boards below the thickness of 1.5mm. However, in reply to a query by the investigation team about the sales made by them of the said thickness, they replied that they had not sold anything of less than 2.3 mm thickness during the POI to India as well as in their domestic market and as on date, they have yet to make any sales to India of lesser thickness product.
105. The questionnaire' response submitted by the company was perused. It was found that the respondent has provided selling price and other details of the subject goods in relevant Appendixes of their response. It is seen that the domestic sales transactions are overwhelmingly loss-making and hence, the Normal value has been constructed based on their Appendix 8B data, subject to verification. Accordingly, the normal value for the exporter has been determined which is mentioned in the table showing dumping.

M/s Merbok MDF Lanka (Private) Limited

106. It is noted that M/s Merbok commenced its investment in Sri Lanka in 2000 with shareholder's funds of USD ***. In ***, the Merbok Group installed and commissioned its first MDF (Line- 1) production line in Horana Sri Lanka. In late *** Merbok commissioned its second production line (Line-2) for the production of "thin" MDF as well as a short cycle laminating line. It was also noted that the initial production equipment together with land and buildings were purchased on behalf of *** ("Company") by the holding company and 100% shareholder, *** (Malaysia). As per Appendix-1, the company had claimed adjustments on account of Credit Expenses which was allowed after taking into account the interest rate prevailing during the POI. It is further noted that the domestic sales are on ex-factory basis and the Company has sold *** CBM of the subject goods in the domestic market. From the perusal of the response of the company it is seen that the company has claimed that there is no difference between the goods sold in the home country compared with the goods exported to India except thickness and brand and that there are no differences in the goods sold or produced in the domestic market or sold

- to countries other than India in physical/ technical/ chemical characteristics from those exported to India except thickness and brand.
107. The verification report was issued to the company following verification of the information submitted by them. In the verification report, it was stated that the company failed to substantiate its claims with regards to the basis for claiming adjustments on the rates of interest for credit cost. It was further noted that M/s Merbok Sri Lanka had received interest free loan from its holding company. As per notes to the accounts, no interest has been charged on these loans. It is recalled that during verification, the company had claimed that an amount of US\$ *** Million which was a loan from holding company carrying interest *** % . However for working capital purpose , this was converted into interest free loan in ***. In respect of this loan no interest has been paid to the holding company from *** onwards . In support of the above claim the Company produced Board Resolution passed by both the companies. It was also stated by M/s Merbook that companies in Sri Lanka are allowed to obtain loans from foreign countries, parent company etc as per the Exchange Control Act and the interest rate applicable on such borrowings are fixed at LIBOR plus margins. It was also submitted by the exporter that to ensure consistency, interest rate applicable in Malaysia should be considered in the present case as well as was done in a previous investigation by DGAD.
 108. In response to the verification report issued by the Authority, the exporter has reiterated their submissions made with regard to interest rates which is mentioned earlier in the above paragraphs. They have also stated that the interpretation of prevailing rates of interest in Sri Lanka needs to be seen in the light of exchange control Act of Sri Lanka. The exporter has also commented upon treatment of depreciation, raw material and utility in response to the verification report.
 109. The issues raised by the exporter was examined and it is noted that the interest rate as claimed in the said order are subject to a number of stipulations and is specific to the industries as listed in the Annexure to the order. Further no borrowings under the said order have been availed by the company as such. It is also noted that the present investigation being specific to the operations of the company in Sri Lanka, what would be relevant is the cost of financing in Sri Lanka and not any interest rates at which the parent company may be borrowing the capital. The company admitted during the verification that the prevailing rates of interest (PLR) for borrowing and the average cost of borrowing as reflected from the published sources were significantly higher in Sri Lanka during the POI.
 110. The questionnaire' response submitted by the company was then perused. It was found that the respondent has provided selling price and other details of the subject goods in relevant Appendixes of their response. As stated earlier, the examination of the response filed by the company shows that the company has received significant financial support from its holding company as interest-free loan. In the Appendixes 7 & 8 of the questionnaire's response filed by the company, no expenses on account of finance costs have been reflected. It was noted that after considering the interests costs on the loan so obtained, the company has incurred losses for its domestic operations. Hence, the Authority has constructed the Normal value based on their cost of production after appropriate adjustments for interest costs, depreciation, raw material costs and utility which is mentioned in the table showing the dumping margin.

Determination of Normal value in respect of Non-Co-operative Exporters / Producers

111. The normal value in respect of Non-Co-operative Exporters / Producers has been determined on the basis of 'facts available'.

F. EXPORT PRICE

Export price for the responding exporters

M/s Evergreen Fibreboard Berhad (EFB)

112. The Authority has examined the export prices in respect of above responding exporter on the basis of questionnaire responses filed by the respondent. The export prices have been allowed after examination and onsite verification of the information submitted by them. It was noted that the respondent had furnished information in Appendix 2 relating to exports to India including the adjustments. The adjustments on account of Overseas Freight, Inland Transportation, Packing, Local Insurance, Customs handling, Clearance charges and Bank Charges have been accepted after onsite verification. The ex factory export price thus worked out is mentioned in the table showing the dumping margin.

M/s Evergreen Fibreboard (JB) Sdn. Berhad (EJB)

113. The Authority has examined the export prices in respect of above responding exporter on the basis of questionnaire responses filed by the respondent. The export prices have been allowed after examination and onsite verification of the information submitted by them. It was noted that the respondent had furnished information in Appendix 2 relating to exports to India including the adjustments. The adjustments on account of Overseas Freight, Inland Transportation, Packing, Local Insurance, Customs handling, Clearance charges and Bank Charges have been accepted after onsite verification. The ex factory export price thus worked out is mentioned in the table showing the dumping margin.

M/s Segamat Panel Boards Sdn. Bhd.

114. The Authority has examined the export prices in respect of above responding exporter on the basis of

questionnaire responses filed by the respondent. The export prices have been allowed after examination and onsite verification of the information submitted by them. It was noted that the respondent had furnished information in Appendix 2 relating to exports to India including the adjustments. The adjustments on account of Overseas Freight, Inland Transportation, Packing, Local Insurance, Customs handling, Clearance charges and Bank Charges have been accepted after onsite verification. The ex factory export price thus worked out is mentioned in the table showing the dumping margin.

PT. Sumatera Prima Fibreboard

115. The Authority has examined the export prices in respect of above responding exporter on the basis of questionnaire responses filed by the respondent. The export prices have been allowed after examination and onsite verification of the information submitted by them. It was noted that the respondent had furnished information in Appendix 2 relating to exports to India including the adjustments. The adjustments on account of Overseas Freight, Inland Transportation, Packing, Local Insurance, Customs handling, Clearance charges and Bank Charges have been accepted after onsite verification. The ex factory export price thus worked out is mentioned in the table showing the dumping margin.

PT. Masari Dwisepakat Fiber

116. It is noted that the responding producer and exporter did not consent to verification of information which was submitted earlier by them. In view of this, their export price could not be verified. Therefore, their export price has been taken on the basis of facts available.

M/s Merbok MDF Lanka (Private) Limited

117. The Authority has examined the export prices in respect of above responding exporter on the basis of questionnaire responses filed by the respondent. The export prices have been allowed after examination and onsite verification of the information submitted by them. It was noted that the respondent had furnished information in Appendix 2 relating to exports to India including the adjustments. The adjustments on account of Overseas Freight, Inland Transportation, Packing, Local Insurance, Customs handling, Clearance charges and Bank Charges have been accepted after onsite verification with the exception of credit costs which have been modified as per the prevailing interest rate. The ex factory export price thus worked out is mentioned in the table showing the dumping margin.

Determination of Export Price in respect of Non-Co-operative Exporters/Producers

118. Since no other response has been received from any other producer/exporter of the subject goods; the Authority has determined the Export price as per 'facts available' in terms of Rule 6(8) of the AD Rules. The data has been collated as per the information provided by the applicant and the information provided by the co-operative exporters.

G. DUMPING MARGIN

119. Considering the Normal values and Export prices as determined above, the dumping margins have been determined as follows:

S.No.	Country- Producer/Exporter	Normal Value	Net Export Price	Dumping Margin	Dumping Margin %	Dumping margin range %
	China PR					
1.	All producers and exporters	***	***	***	***	80-90
	Indonesia					
2.	Pt Sumatera Prima Fibreboard	***	***	***	***	25 - 35
4.	All other producers and exporters	***	***	***	***	60-65
	Malaysia					
5.	M/s Segamat Panel Boards Sdn. Bhd.	***	***	***	***	15-20

6.	M/s Evergreen Fibreboard Berhad (EFB) /	***	***	***	***	15-20
	M/s Evergreen Fibreboard (JB) Sdn. Berhad (EJB)	***	***			
7.	All other producers and exporters	***	***	***	***	35-40
Sri Lanka						
8.	M/s Merbok MDF Lanka (Private) Limited	***	***	***	***	15-25
9.	All other producers and exporters	***	***	***	***	50-60

120. Following the issuance of preliminary findings and issuance of verification reports, the following producers and exporters have offered price undertaking to the Authority and have requested the Authority to kindly provide them the format of the price undertaking at the earliest.

- I. Pt Sumatera Prima Fibreboard, Indonesia.
- II. M/s Evergreen Fibreboard Berhad (EFB) / M/s Evergreen Fibreboard (JB) Sdn. Berhad (EJB), Malaysia
- III. M/s Merbok MDF Lanka (Private) Limited, Sri Lanka.

121. The offer of the price undertaking by these producers and exporters has been examined and it is proposed not to accept the price undertaking offered by the producers and exporters as it is felt that acceptance of such undertaking is not practical.

H. INJURY AND CAUSAL LINK

Submissions made by other interested parties

122. The submissions made by interested parties, in brief, are as follows:

Submissions made by M/s Venugopala Slate Industries and Sarthak Overseas

- There is no merit in the Applicant's claim that their selling price is lower than the prices projected in the project report. Such projection lacks reasonableness and relevancy as international prices have all along been significantly lower than Indian prices during injury period. Any error in their judgment ought not to be corrected through anti-dumping mechanism. It is incorrect to compare the actual selling price *vis-à-vis* selling price assumed in the project report disregarding the prevailing international price.
- Applicant has misinterpreted provisions of material retardation as Rule 11 (1) provides for mutually exclusive provisions; hence the claim lacks any factual and legal basis. Applicant cannot claim nascent stage after almost 17 months of commercial production and they should not be allowed to misuse anti dumping mechanism to care for their higher cost of production caused by their inherent inefficiency in terms of higher raw material rate, higher fixed cost etc. No Material Injury has been caused to the Domestic Industry as per the data contained in the petition. Arguments on levels of imports are exaggerated; whereas factually imports from subject countries have slightly increased by approx 1% which is negligible and it should be seen along with an admittedly miniscule production and increase in demand. Market share of alleged dumped imports has declined despite the growth in demand. Various other injury parameters showed superb growth and any sign of injury can be seen. The cost of production of the applicant is abnormally high as compared to other East Asian countries as compared to the co-operating exporters. Fixed conversion cost of domestic industry appears to be very high; hence, higher amount of fixed cost should be removed from the injury examination to ensure fair analysis.
- Raw material cost of PUC is influenced by two variables i.e. raw material rate and actual consumption of raw material per unit of output. Raw material rates and consumption norms appear close to double of international rates. Such inefficiencies and losses due to other reasons should be examined and cannot be attributed to injury caused by dumping. Any losses to the Applicant, if any, can be attributable only to higher cost of production. Any imposition of anti dumping duty would be against public interest in the present case as any duty would lead to passing on burden of higher cost due to inefficiencies on importers which in turn seriously affect the interest of user industry.
- Landed price from subject countries have increased whereas selling price of applicant are showing declining trend in the same period. This reflects an inverse relationship and shows no correlation between landed prices *vis-à-vis* domestic selling prices.

- The Applicant has commenced their production recently. Hence, any injury on account of factors such as Start up cost, Un-established sales and distribution channels, increased marketing expenses coupled with higher discounts, higher cost of production etc cannot be attributed to alleged dumping. It has also been submitted that as 2.3 mm is not being produced by the domestic industry so anti dumping duty can not be imposed.

Further, submissions have also been made with regard to inability of domestic industry to produce rubber MDF and specific sizes of subject goods and also with regard to the fact that they have just started production 2-3 years back and this is less time to judge the financial position of the company.

Submissions made on behalf of M/s Segamat Panel Boards Sdn. Bhd and M/s Merbok MDF Lanka (Private) Ltd, Sri Lanka, Consulate General of Democratic Socialist republic of Sri Lanka.

- If any, injury to the domestic industry was on account of wood price and consumption norms during the injury period.
- Reasonableness of the projections made in the Project Report: In support of their claim for injury the Applicant has claimed that the price at which the company is forced to sell the product in the market is below than the prices projected in the project report. In this regard, it is submitted that the least selling price of Applicant was approx Rs. 16,935 per CBM during 2009-10 and declined to Rs 15,164 per CBM in POI. We have estimated such selling price from the trending of price undercutting. Pertinently, prices of subject goods in international market have all along been significantly lower than these Indian prices during injury period. While it is for the financial institution for make realistic profitability projections while appraising project for financing having regard to current prevailing prices in the international market, any error in their judgment ought not be corrected through anti-dumping mechanism which is meant to counter act the effect of unfair trade practices. Under anti dumping laws, there are set practices for price comparison under free trade regime. It is incorrect to compare the actual selling price vis-à-vis selling price assumed in the project report disregarding the prevailing international price.
- Literal meaning of the term “materially retards the establishment of any industry in India” reflects a situation when dumping prohibits the commencement of any industry in India though the plant is ready to declare its commercial production. The term commencement cannot and should not be misinterpreted to denote growth and expansion by the domestic industry which the applicant have tried to do. The use of words ‘import of such article into India causes or threatens material injury to any established industry in India or material retards the establishment of any industry in India’ in Rule 11 (1) makes it amply clear that Material injury, threat of material injury and material retardation are mutually exclusive. However, initiation notification states that domestic industry has suffered apparently material retardation and also material injury. Hence, test of material retardation relied by the Applicant is inapplicable to the Applicant as plant is already in operation.
- The Applicant has commenced the commercial production w.e.f. 2nd February 2010. It is strange that even after 17 months of commercial production, applicant industry claims to be in its nascent stage. In addition, it is submitted that the claim of the applicant industry for material retardation when they have actually realized selling price above international prices is unfounded and untenable. Further, if the cost of production of the domestic industry is higher due to their inefficiencies, higher raw material rate and higher fixed cost etc then how such industry can claim material retardation as nascent industry and attribute the same to dumping.
- The Authority has stated in the initiation notification that the imports from the subject countries have substantially increased, which should have declined, given that the domestic industry has set up new production facilities and supporting company has also commenced the production of the product under consideration. However, imports from subject countries was 44,009 MT in 2009-10 which slightly increased to 44,562 CBM in the proposed POI and the rate of such increase was approx 1% only which is very negligible.
- There is no material injury to the Domestic Industry. The data contained in the petition does not show existence injury to the domestic industry on account of alleged dumped imports. In fact, Proforma IVA shows that the production, capacity utilization, market share and sales of the domestic industry have all improved during the POI vis-à-vis the previous year. It is a peculiar situation when operating injury parameters have shown improvement, its market share has improved, and realizing selling prices above the prevailing international prices yet domestic industry is claiming injury. That capacity utilization of Applicant which was only 27% during 2009-10 improved to 32% during POI, thus showing no injury.
- That the domestic industry is not at all competitive when its cost of production is higher by 100% over the international levels. We have tried, (based on our estimation) to compare the actual cost of production and selling price of our exporter vis-à-vis domestic industry. This indicates that the cost of production of the Applicant was abnormally higher as compare to exporters and reasons of higher cost of Applicant have been analyzed as under:
 - a. Higher Fixed Conversion Cost of Applicant: that fixed conversion cost of the Applicant was Rs. 6,372

per CBM whereas it should be Rs. 2,246 per CBM at normal utilization (90%). Thus, fixed conversion cost of domestic industry was high by Rs. 4,126 per CBM during POI due to lower capacity utilization. Further, actual fixed costs of the applicant industry are more than double of the exporters. Therefore, higher amount of fixed cost should be removed from the injury examination to ensure fair analysis as the injury suffered by the Applicant due to this cannot be attributable to alleged dumped imports from the subject countries.

- b. **Raw Material Rate and Consumption Norms of Applicant:** It is submitted that raw material cost of PUC is influenced by two variables i.e. raw material rate and actual consumption of raw material per unit of output. A comparison of raw material rates of applicant industry with the corresponding rates of exporters, it may be seen that raw material rates of domestic industry are close to double of cooperating exporter. This difference in rates, explains partially the reason for difference in cost of production of applicant domestic industry vis-à-vis exporters. This is further compounded when we compare the actual consumption of raw material per unit of output of exporter with applicant industry which is higher by about 28%. This is nothing but inefficiency of operation by applicant industry. The possibility of padding up of costs by showing higher consumption material cannot be ruled out which may be critically looked into by the Authority. There are differences in raw material cost and such difference in raw material cost cannot and should not be attributed to alleged dumping.
- c. Thus, the cost of the Applicant is over by almost Rs. 9,142 per CBM only on account of inefficiencies in terms of low capacity utilization and higher consumption of raw material. Hence any losses caused on account of such other reasons cannot be attributable to dumping.
- That the Applicant has suffered losses when the least net selling price of Applicant was Rs. 15,164 per CBM and such price was higher than international prices which were 12,000 per CBM. We have estimated such selling price from the trending of price undercutting. Therefore, reason of losses to the Applicant was higher cost due to inefficiencies. The landed price from subject countries have increased from Rs. 12,024 MT in previous year to Rs. 12,730 MT in the period of investigation whereas selling price of applicant are showing declining trend in the same period. This reflects an inverse relationship and shows no correlation between landed prices vis-à-vis domestic selling prices.
- That the Applicant has commenced their production recently. Therefore, it is quite known that the Applicant would suffer injury on account of various factors such as (i) Start up cost; (ii) Un-established sales and distribution channels; (iii) increased marketing expenses coupled with higher discounts. There is no causal link.
- The consulate general of Sri Lanka has brought to notice certain inconsistencies in the treatment of loan component in the determination of cost of production and have asked for withdrawal of anti dumping duties on subject goods from Sri Lanka.

Submissions made by Director of Trade, Republic of Indonesia

- Injury from material retardation of the establishment of the domestic industry and material injury to the domestic industry are distinct and footnote 9 of the AD Agreement.
- With regard to material retardation, production, capacity utilization and sales of the domestic industry are reasonable considering that they represent a relatively new entrant on the market; and with regard to material injury, the Indian market cannot be expected to absorb start up costs of a new entrant and as such it is normal that there is a period in which selling price would not necessarily cover costs.
- Domestic industry is located in north India whereas most Indonesian exports are concentrated in Southern markets. Markets concerned are distinct.
- Cost of internal freight from the North to South effectively renders the domestic industry uncompetitive.

Submissions made on behalf of Evergreen Fibreboard Berhad (EFB), Malaysia; Evergreen Fibreboard (JB) Sdn. Bhd. (EJB), Malaysia and Evergreen Fibreboard (Nilai) Sdn. Bhd.(EFN), Malaysia

- The rule lays down that there are three types of injury that may be caused to the domestic industry i.e. material injury to an established industry, threat of material injury to an established industry or threat of material retardation of establishment of an industry. The word 'or' used in the above Rule makes it clear that there cannot be a finding of all three types of injury or any two types of the injury existing at the same time. Therefore, injury in the form of material retardation and material injury cannot co-exist. It is also important to mention that the Applicant nowhere in the petition has mentioned that it is a case of material injury. It has merely stated for material retardation and there is no material retardation of the establishment of the domestic industry.
- The import analysis is wholly incorrect. It is amply clear that total imports have conversely declined substantially in 2010-11. Further, a negligible increase of about 1% in the imports from the subject countries over the same period cannot be regarded by any stretch of imagination as substantial increase. That the import data has been incorrectly sorted by the domestic industry.
- The initiation notification, with regard to injury it has been mentioned that the domestic industry has suffered material retardation of its establishment. The domestic industry has been successfully producing the subject

goods for 17 months including the period of investigation and also continues to manufacture the subject goods beyond the period of investigation.

- Analysis of imports should be done from 2009-10 onwards when the domestic industry started production which shows increase in imports are negligible.
- Employment figures have not been analysed. All injury parameters shows improvement.
- There is no material injury to the domestic industry as may be seen from the following:
 - i. *Capacity*: The installed capacity of the Applicant has increased significantly from 8333 to 50000 m3 in 2010-11 as compared to previous year.
 - ii. *Production*: The production of the Applicant has substantially increased from 2262 m3 in 2009-10 to 15860 m3 in 2010-11.
 - iii. *Capacity Utilization*: The capacity utilization of the Applicant has increased from 27% in 2009-10 to 32% in 2010-11.
 - iv. *Sales*: The sales of the Applicant have also substantially increased from 334 m3 to 15347 m3 in a single year which is more than 4600%.
 - v. *Inventories*: The domestic industry in 2010-11 produced 15860 m3 and sold 15347 m3 and the balance of 423 m3 is stock for this year. That the stock of mere 2.67% of production in 2010-11 or less than 10 days of inventory cannot be regarded as piling up of inventories.
 - vi. *Market Share*: The market share of the Applicant has increased from 0.63% in 2009-10 to 25.23% in 2010-11.
 - vii. *Profitability, Return on capital employed, Cash profits and price undercutting*: The injury with respect to them, if any is not because of the alleged dumped imports from subject countries but because of its high cost due to high per unit cost on account of start-up cost, high raw material cost, high utility cost, high fixed cost, high labour cost, high interest cost and high depreciation cost.
 - viii. *Wages*: It is submitted that the wages paid to the employees have substantially increased in 2010-11 over the previous year.
 - ix. *Number of Employees*: there is no decline in the number of persons employed by the Applicant.
 - x. *Productivity*: The productivity of the Applicant has increased.
- There is no causal link between the injury, if any to the domestic industry and alleged dumped imports. It is submitted that injury, if any has been suffered by the Applicant on account of inter-se competition between the two domestic producers and self imports made by them.

Submissions made on behalf of M/s PT. Masari Dwisepakat Fiber, Indonesia and M/s PT. Sumatera Prima Fibre board (SPF), Indonesia

- The applicant Industry has withheld information relating to captive consumption of the product under consideration. It is mainly into the business of high price subject goods which required plain fiber boards as raw material.
- After 15 months of commercial production, no industry can claim to be in its nascent stage and claim material retardation.
- The applicants have not substantiated how the present case falls within the scope of material retardation. There is no basis to claim also that the industry is still in its nascent stage. The applicant is an already established industry in India. The present case is a case in which the applicant's production line is being supplemented with another line with a different thickness. As an established industry player in this market, the applicants have been benefited by their current setup as they already possess some of the common equipment, employees, expertise, existing distribution network and systems, existing customer bases, and/or other components, raw material suppliers needed to produce and distribute the fiber board below 6 mm and are able to leverage these factors for purposes of their additional production line operations. In view of the above, and specific language of the initiation notification, we are of the considered opinion that present case is not a case seeking protection for retardation of establishment of an industry in India due to dumped imports and injury as a result thereof. It is settled jurisprudence that a case of material retardation can be made only and only when production has not begun or the industry has not yet achieved its commercial volumes.
- The initiation notification is like a show cause notice and has not put any party to notice that the claim of applicants for material retardation has been accepted by the Authority. In the absence of an initiation for material retardation, we are presently not offering any further comments on material retardation.
- The period of investigation and injury examination period fixed by the Authority is erroneous and unfair. In the instant case the period of Investigation is April 2010 – June 2011 i.e., of 15 months. The applicant is only new entrant in the market and has only completed 2 months in April 2010. Therefore, the determination of dumping and injury tends to be skewed as the variable costs and fixed costs would be very high for the applicant and no proper or comprehensive analysis can be undertaken.
- As per the application there is only one more producer (Green Ply) of the subject goods in India and such new

producer also started producing the subject goods from December 2010. The applicant has only provided the production figures in the non-confidential version of the application and all the other injury related information is missing. The Designated Authority may also ascertain such factual claims made by the applicants from other authentic sources.

- Injury parameters: In this connection the following may be noted:
 - a. Figures of depreciation, interest, and wages are negative.
 - b. Productivity per employee and per day has also increased.
 - c. In Proforma IV-A, interest shown shows sudden increase from base year. This sudden increase may be one of the reasons why the Applicants are not doing well.
 - d. Applicant has not shown captive consumption in Proforma IV A.
 - e. Average inventory has decreased in comparison to base year, when they have started their production.
 - f. When we compare inventory by diving by per day sale it is seen that the inventory comes down significantly.
 - g. Information relating to GFA, NFA, Working Capital and Price underselling not provided.
 - h. As per the revised Proforma IV-A Applicant has performed well as compared to base year 2009-10.
 - i. Applicant is mainly selling value added products which is costly as compared to plain MDF. They are making door skin, MDF coated boards, melamine boards out of this line and exterior grade MDF. Therefore, we would request the Authority to kindly consider the issue to captive consumption while computing the cost and NIP of the Applicant and also kindly provide the non-confidential version of calculation sheet for our effective comments.
- The imports from Indonesia remained more or less same throughout the injury investigation period. As shown in the table that the value increased 21.70% during 2010-11 whereas the volume increased by 20%. In the Annualized figures the value of Indonesian imports increased by around 20%, whereas volume increased only by 12% as compared to 2009-10.
- All injury parameters shows improvement in the performance of the domestic industry despite being a new player in the market.
- Analysis of major raw material from 2007-08 would be wrong and misleading because the applicant was not producing the subject goods during that period. Therefore, we request the Authority to kindly analysis the raw material prices from Feb 2010.

Submissions on behalf of M/s. Magna-Foremost SDN and M/s. Masonite Components, Ireland

- The claims of material retardation and material injury are mutually exclusive: where a domestic industry is in fact already established, it cannot claim material retardation. The fact that the Applicant accounts for approximately 87% of total Indian production of the subject product strongly evidences that, in this case, the domestic industry is already established. The Applicant – which admits to having commenced production in February 2010, 21 months before this investigation was initiated – can hardly be considered to be not yet established, making any claim of material retardation improper in this case.

Submissions made by the domestic industry

123. The submissions made by the domestic industry, in brief, are as follows:

- In respect of contention that DI is forced to sell the product in the market below than the prices projected in the project report; it is submitted that mere fact that the export price was comparable to some other “international” price does not mean anything. In fact, there is nothing like “international price”. Even two transaction prices need not be the same. Prices to two customers can differ. Under this economic reality, the exporter is projecting one of the “international price”. The selling price of the domestic industry, in fact, is required to be compared with the target price in order to determine price underselling. It is universally accepted principle to determine price underselling by considering target prices and actual selling price.
- As regards the contention that even with 17 months of commercial production, domestic industry claims to be in the nascent stage and that the claim of material retardation in the case when selling price has been realized above the international prices is unfound and untenable; it is submitted that the Authority is required to assess injury to the domestic industry by comparing domestic industry performance during investigation period with preceding years. By practice, the Authority is considering preceding three years and compares the performance in period of investigation with preceding three years. Thus, typically, the Authority considers period of investigation and preceding three years for injury assessment. In the present case, however, the Applicant does not have actual operational history for period of investigation and preceding three years. This, itself, establishes that the case of the Applicant is that of nascent industry. Notwithstanding the Applicant has established injury on both ways –
 - By considering its actual performance for the period of its existence;

- By comparing its performance with the projected/target performance Both clearly establish that the domestic industry has suffered injury.
- In respect of the contention that rate of increase in imports from a year prior to the POI was only 1%, whereas rate of increase in demand was 16%, whereas the level of production by the DI was miniscule; it is submitted that the very fact that the production by the domestic industry was miniscule despite significant capacities and demand in the market itself establishes that the domestic industry is not able to produce to the extent of its capacities, establishes injury suffered by the domestic industry. In the facts and circumstances of an industry like present, where commercial production commenced in February, 2010 and where demand for the product is significantly high and domestic industry has significant capacities, inability of the domestic industry to reach the target levels of capacity utilization itself establishes that the domestic industry is being prevented from commercializing production to the targeted extent. Establishment of an industry must be seen with reference to the way it was projected to establish. The domestic industry projected that its capacity utilization shall be 60 %, 80% and 90% in first, second and third year of its operation respectively. Thus, it is clear that the domestic industry would be in establishment unless it reaches 90 % of its capacity utilization. As opposed to this target levels, the capacity utilization of the domestic industry have been woefully low. The Authority should consider the capacity utilization of the exporter and compare the same with the capacity utilization of the domestic industry.
- In respect of the contention that Proforma IV-A shows that the production, capacity utilization, market share and sales of the DI have increased in the POI as compared to the previous year; it is submitted that the argument lacks appreciation of the way a domestic industry commencing production from a new production facility shall perform. Having commenced commercial production in February, 2010, it is obvious that the domestic industry will make efforts to increase its production and sale over the period. It is obvious that the domestic industry would not achieve 100% capacity utilization on day one. The capacity utilization would gradually improve. Thus, increase in production and sale over the injury period is clearly reflective of the efforts of the domestic industry to get established in the market. However, the capacity utilization of the domestic industry was substantially below the levels it had projected. If dumping is not the cause of injury to the industry to the domestic industry, than why domestic industry is faced with such adverse capacity utilization as compared to the levels projected. If the argument of the interested parties is that Applicant is not able to run the plant at this level, it is submitted that Applicant has in fact run the plant at high levels. However, such levels could not be maintained for long period, as the same resulted in huge piling up of inventories and Applicant thereafter had to curtail the production. It would also be seen from the injury information that the Applicant had to reduce its selling price immediately after commencement of sales in the market on finding that it was unable to dispose off the product in the market. Further, after reducing the prices, the Applicant had to increase discounts etc. in order to push the sales. The selling price of the domestic industry declined immediately after start up of production and sale. Further, the net sales realization of the domestic industry declined over the period. This decline in net sales realization and reduction in selling price was despite lower prices offered by the domestic industry. Further, appreciating that the Applicant had somewhat higher fixed cost due to initial start up operation, the Applicant has determined its cost structures by adopting higher level of optimum capacity utilization, whereby the Applicant would have posted profits in its first quarter of operations, but suffered financial losses towards the end of the investigation period. In other words, if starts up cost are excluded, the Applicant had started operation with profitable prices; but went into losses because of dumping of the product in the country. From a comparison of net sales realization of the domestic industry and sales volumes, it would be seen that as the domestic industry reduced its realization, its sales volume improved. In other words, the domestic industry had to compromise on selling price in order to get some volumes. From a comparison of selling prices of the domestic industry and weighted average landed price of imports from subject countries, it would be seen that –
 - When the domestic industry offered its product in the market, the price difference between the domestic product and imported product was quite significant.
 - The domestic industry reduced the prices in order to somewhat bridge the gap between domestic and imported product. However, in view of very significant price difference between the domestic product and imported product, the volume of imports remained significant and did not decline.
 - The import volumes should have declined substantially after commencement of production by the domestic industry. Given that the domestic industry product was an “*import substitutive product*”, it was a legitimate expectation of the domestic industry that imports of such a product would substantially fall as the domestic production ramps up production and takes over the demand in the market.
- In respect of the contention relating to the cost of production in India; it is submitted the Applicant has set up the latest plant in this industry and is having machines comparable to the machines available with the foreign producers. Given comparable technology and plant & equipment, it is impossible that the conversion cost of the domestic industry would be substantially different (and higher) as compared with the conversion costs of the foreign producers. Any such claim implies that the foreign producers have manipulated their data and have suppressed true conversion cost. There are limited machine suppliers in this trade, while minor variation might come from country to country in view of difference in price factors, significant difference in conversion costs are impossible. It only implies that facts are being suppressed from or misrepresented to the Authority. The

machine deployed by the Applicant at the least can be considered more efficient than the other producers in the subject countries. There is no basis for the presumption that the fixed costs of the domestic industry are higher than the exporters. While some elements of fixed cost on per CBM basis may be higher due to start up operations, if the costs are considered at reasonable level of capacity utilization, no significant difference shall be found. Applicant submits that the foreign producers are producing and selling a number of products. It is quite likely that they have resorted to apportionment of expenses in such a manner that the costs are understated for the product under consideration and expenses are diverted to other product. It is pointed out in this regard that there is no mandatory requirement under accounting principles to maintain separate information for different products. It is, therefore, very easy for the foreign producers to manipulate their cost data and report lower cost of production. Thus, it is not a question of inefficiencies but a question of manipulated/fabricated data being provided by the exporters to the Authority.

- In respect of the contention relating to Selling prices of domestic industry vis a vis landed price of the imports ; it is submitted that the domestic industry started its journey by pricing its product which were just above the optimum cost of production where it would have fetched some nominal profit, albeit below reasonable levels. Despite so realistic and reasonable price offered by the domestic industry, so significant was the price difference between domestic industry price and import price that the domestic industry had to immediately take a corrective action and reduce the price, despite which the sales volumes were not moving to the levels the domestic industry has production capacities. Therefore, the domestic industry was further forced to offer increasing discounts in order to somehow attract customers to buy domestic product. However, since the price difference still remains significant, the domestic industry could not eventually achieve optimum levels of production.
- In respect of causal link; it is submitted that the injury to the domestic industry is on account of dumped imports as significant price difference between imported and domestic product has prevented the domestic industry from selling its product to the extent of production capacities, which led to reduction in price and low level of sales volumes, reduction in net sales realization, significant difference between non injurious price and landed price of imports on one hand and inability of the domestic industry to increase its production to the extent of target levels on the other hand, significant loss of production man hours, increase in inventories with rising production, decline in production due to rising inventories, collectively and cumulatively establishes that the domestic industry is suffering injury as a result of dumped imports.
- In respect of the contention that the Applicant has withheld information relating to captive consumption of the PUC; it is submitted that sufficient information is already on record. Should the Authority require any further information, the Applicant will provide the same.
- In respect of the contention that substantial imports are reported by the Applicant and other supporting producer in India and entire analysis has been undertaken without taking into account such vital facts; it is submitted that there is no substance in the argument as the imports by the Applicant are not substantial. The imports by the Applicant were *** cbm in a market size of 68,273 cbm and against a capacity of 50,000 cbm.
- In respect of the contention relating to “materially retardation of the establishment of any industry in India; it is submitted that the understanding with WTO members with regard to material retardation makes the meaning of material retardation very clear. Even in a situation where the product is already being produced, the Authority may record a finding of material retardation. Further, material retardation does not mean that company should not have commenced commercial production. Contrary to the arguments of the interested party, in fact, the jurisprudence emerging on the subject is very clear, i.e., the Authority must examine injury information of the domestic industry to the extent it exists. Proposition advanced by the interested party, in fact, implies that only a company not commencing commercial production can bring application. This would in fact imply that an anti-dumping duty may be imposed even when a company may not have commenced commercial production. Notwithstanding above, the information filed by the Applicant domestic industry in any case clearly establishes that its performance was adverse and deteriorated over the period. The Applicant relies upon the application and the past determinations by the Authority. It has set up manufacturing facilities for production of the product under consideration in the country. There is no other producer of the product in the country who was producing the product under consideration in the country before the Applicant commenced commercial production. The previous investigation by the Authority included all kinds of medium density fiberboard at the stage of initiation. The interested parties heavily argued for exclusion of thin boards on the grounds that the same was not being produced in India. The Authority having satisfied itself that there was no production of thin board in India restricted the scope of the product under consideration to 6mm and above. Further, the Applicant has provided information with regard to its injury to the extent it has produced and sold over the injury period. The Authority may examine the performance of the domestic industry to the extent of its existence.
- The contention that the Applicant is already an established industry in India and that their production line is only being supplemented with another line with a different thickness is without basis as the Applicant did not have any production line for production and sale of fiberboard before the present set up. There was no “current setup” of the company. The Applicant intended to setup three production lines – (i) Thin Fiber Board line, (ii) Thick Fiber Board Line (the same is still being setup) and; (iii) Particle Board Line. Further the Applicant has set up facilities for other downstream products such as Floor Tiles, Door Skin, Laminated Flooring, Direct Printed Board,

Insulation & Hard Board, Flush Doors, Ply Boards, Veneer Coated Board, Furniture & Fixture Comp., Composite Board, Decorative Laminated Board, Block Board, UV Coated Board, and Laminated Particle & MDF Boards. Assuming that the company was already an “existing” company and efforts were being made to supplement the existing setup with addition of a production line of a product not hitherto produced in the Country, the same would still fall in the category of material retardation to the establishment of the domestic industry, so long as the product under consideration was not being produced earlier and fresh production facilities have been setup for production of product under consideration.

- In respect of contention relating to data collection; it is really amazing that an interested party is suggesting consideration of 2010-11 as an investigation period in the present case. Firstly, the case was initiated in November 2011 and therefore investigation period of 2010-11 would have implied a stale period for the present purpose. Secondly, period longer than as could have been considered can certainly not prejudice the interests of any party. If the period 2010-11 would have been appropriate for the present purpose, certainly, addition of subsequent quarter is no less inappropriate.
- With regard to the argument that variable cost and fixed cost would be high for the Applicant, the Applicant has provided information with regard to cost of production assessed by them at the time of setting up of the plant. These costs are not at low level of production. These costs are at much higher level of capacity utilization. In any case, the mere fact that the cost of production of the Applicant may be higher is insufficient to deprive the Applicant relief under the law.
- As regards the contention that only production figures of the other Indian producer (green ply) has been given, all the other injury related figures are missing; the Applicant has contended that there is no legal requirement to provide injury information in respect of “other domestic producers”. Applicant has provided injury information in respect of “domestic industry”. Applicant has claimed that it constitutes “domestic industry” and has accordingly provided information in respect of its own operations. Applicant has not claimed that Applicant and Greenply constitute domestic industry. The rules require determination of injury in respect of domestic industry and therefore information concerning Greenply with regard to injury to the domestic industry becomes wholly irrelevant. It is, however, pointed out that Greenply has not even fully commenced production of the product under consideration in view of dumping of the product.
- As regards the contention relating to injury; there is no such negative figure.

Improvement in productivity does not imply that the domestic industry has not suffered injury. The present petition is in respect of material retardation. As the Applicant is augmenting its production after commencing the same, it is obvious that all business expenses would show an initial growth expected from any company commencing commercial production. As regards captive consumption, relevant information is available to the Authority. A comparison of inventory with production and sale clearly shows that-

- i. The company was producing much below the projected levels.
 - ii. Inventories were rising despite such low level of production.
 - iii. The company had to reduce/curtail production despite low levels, in order to contain/restrict inventories.
 - iv. Rise in inventories along with production, fall in inventories along with restriction on production clearly establishes that the domestic industry has been regulating its production in order to contain inventory levels. Applicant submits that the man hour worked and available itself will clearly establish that the domestic industry has been forced to substantially keep the plant idle because of dumping of the product in the country.
- As regards Information regarding GFA, NFA and price underselling not provided; the relevant information is available with the authority. Under the rules, the authority is required to determine injury considering return on investment and not considering GFA and NFA. Further, price underselling is required to determine by the authority and is not required to be determined by the Applicant. The prescribed format nowhere requires this information to be provided by the Applicant.
 - As regards the contention that imports from Indonesia remained more or less same through the injury period; Low volume of imports from an individual country does not imply that the same has not caused injury. It is nobody’s argument that volume of imports from Indonesia were below *de-minimis* or the dumping margin in respect of Indonesia is *de-minimis* or conditions of competition between Indonesia and other subject countries were materially different so as not to cumulate the injury to the domestic industry. Whereas injury to the domestic industry is required to be cumulatively assessed, the fact that the volume of imports from particular company has remained relatively flat becomes irrelevant.
 - Annexure-I to the Rules provides, *inter-alia*, that due allowance shall be made in each case, on its merits, for differences which affect price comparability, including differences in conditions and terms of sale, taxation, levels of trade, quantities, physical characteristics, and any other differences which are demonstrated to affect price comparability. It would be seen that mere existence of a factor resulting in difference is insufficient. Such factor must have been recognized in the commerce as a factor that affects the prices. Such factor must have been consistently applied by the producers. For example, if the foreign producers have sold boards of different thickness at prices which did not consider thickness as a parameter, it may not be

necessary to determine separate normal value, export price and dumping margin for boards having different thickness. The Authority may therefore first examine the questionnaire responses and the import data and ascertain whether at all the foreign producers have consistently followed some parameters for fixing the prices.

- The Designated Authority recommended interim duties only after coming to a conclusion that imposition of such duty is necessary
- The domestic industry is unable to even produce to the extent of its capacity and capability due to indiscriminate dumping of the product
- If factor other than dumped imports are causing injury to the domestic industry, the interested party must identify such factors and thereafter demonstrate effect of the same on the domestic industry. Moreover, during period of investigation, production of the petitioner constituted 84% of Indian production. It is, thus, evident that internal competition could not have caused the claimed injury

Examination by the Authority

124. The Authority has taken note of various submissions of the interested parties on injury to the domestic industry and has analyzed injury to the domestic industry considering the facts available on record and applicable law as follows. The submissions made by the interested parties have been considered to the extent found pertinent and have been examined as follows and in the relevant sections of these findings:
125. As regards the contention that the export price was comparable to the international price does not mean that the subject goods have not been dumped. In fact, a perusal of the exporters' questionnaires response shows that the subject goods have been dumped into India.
126. As regards the contention that even after 17 months of commercial production, the domestic industry claims to be in the nascent stage, the Authority notes that the domestic industry commended its production of the subject goods in February 2010 only. The Authority notes that the domestic industry has been adversely impacted **on account of dumped imports of subject goods from subject countries**
127. As regards the contention that the rate of increase in the imports was only 1%, whereas the rate of increase in demand was 16%; the Authority notes that the same needs to be examined in the backdrop that there was no domestic producer of the subject goods in India till very recently and hence the entire demand was being met by the imports. The very existence of domestic producers in the market is likely to impact the market share as now the users would have the option to procure the subject goods through the indigenous sources as well.
128. As regards the contention that Proforma IV-A shows that the production, capacity utilization, market share and sales of the domestic industry have increased in the POI as compared to the previous year; the Authority notes that the performance of the domestic industry is expected to improve considering that it has recently commenced production of the subject goods. Any producer is expected to take steps to improve its performance as regards its production and sales over the period. As a result thereof, the capacity utilization gradually improves. Thus, the increase in production and sales over the injury period is clearly reflective of the efforts made by the domestic industry to establish itself in the market. However, its capacity utilization has been significantly below the projected levels.
129. As regards the contention pertaining to cost of production in India; it is noted that the Applicant has set up its plant recently and has claimed to have installed machines comparable to the machines available with the foreign producers. It has been contended by them that considering comparable technology, plant and equipment, the conversion costs of the domestic industry would not be significantly higher as compared to the conversion costs of foreign producers. It has been further contended that there are limited machine suppliers in this trade and that while minor variation might be there due to difference in price factors but significant difference in conversion costs is not possible. The Authority finds merit in the domestic industry's claim that there could be higher costs due to start up operations because of some elements of fixed cost on per CBM basis but if these costs are considered at reasonable level of capacity utilization, no significant difference would be found.
130. As regards the issue of Public Interest: The Authority further notes that the purpose of the anti-dumping duties, in general, is to eliminate 'injury' caused to the domestic industry by the unfair trade practices of 'dumping' so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the Country. Imposition of the anti-dumping measures would not restrict imports from the subject countries/territory in any way, and, therefore, would not affect the availability of the subject goods to the consumers. It is recognized that the imposition of anti-dumping duties might affect the price levels of the products manufactured using the subject goods and consequently might have some influence on relative competitiveness of these products. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the anti-dumping measures, particularly if the levy of the anti-dumping duty is restricted to an amount necessary to redress the injury caused to the domestic industry. On the contrary, imposition of the anti-dumping measures would remove the unfair advantages gained by the dumping practices, would prevent the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods.
131. As regards the contention that substantial imports have been made by the Applicant domestic industry; the Authority notes the contention is devoid of any merit as the imports effected by the Applicant were to the extent

- of *** cbm, which cannot be considered as significant *vis a vis* the market size of 68,273 cbm and the domestic industry's installed capacity of 50,000 cbm.
132. As regards the contention that the Applicant is already an established industry in India and that their production line is only being supplemented with another line with a different thickness; the Authority notes that the same is factually incorrect as the Applicant did not have any production line for production and sale of fiberboard before the present set up.
 133. As regards the contention relating to data collection; the Authority notes that the present case was initiated on 11th November 2011; thus, period of investigation as 2010-11 period would have been relatively old. Besides, a longer period would enable the Authority to take on board relatively recent data for determination of alleged dumping and consequent injury.
 134. As regards the contention that only production figures of the other Indian producer (M/s Green ply) has been given and all the other injury related figures are missing; the Authority notes that M/s Greenply had not even fully commenced production of the product under consideration.
 135. As regards the contention relating to injury; the Authority notes that it is only expected that the Applicant having augmented its production would initially show a positive growth. A comparison of inventory with production and sales clearly shows that the company was producing much below the projected levels. Its inventories were rising despite such low level of production; whereby it had to reduce/curtail production despite low levels, in order to contain/restrict inventories. The domestic industry has claimed that it has been regulating its production in order to contain inventory levels because of the presence of dumped imports.
 136. As regards the contention that imports from Indonesia remained more or less the same through the injury period; the Authority notes that similar volume of imports from Indonesia would not mean that these would not caused injury to the domestic industry. The volume of imports from Indonesia is above *de-minimis* and the dumping margins are significant.
 137. Other injury related issues such as pertaining to cost of production, capacity utilisation by the applicant company, market share, capacity *vis a vis* demand, relationship between the sales price of the applicant and the import prices, price undercutting or price underselling, profitability, productivity, increase in cost of raw materials and wages, absence of causal link etc have been examined appropriately in the relevant sections of these findings.
 138. Other issues raised by the interested parties have been examined under the appropriate headings in this **in this final findings.**

Cumulative assessment

139. Annexure II para (iii) of the AD Rules provides that in case imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to anti-dumping investigations, the Authority will cumulatively assess the effect of such imports, in case it determines that: -
 - a. the margin of dumping established in relation to the imports from each country is more than two percent expressed as percentage of export price and the volume of the imports from each country is three percent (or more) of the import of like article or where the export of individual countries is less than three percent, the imports collectively accounts for more than seven percent of the import of like article and
 - b. Cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic articles.
140. The Authority notes that:—
 - The subject goods are being dumped into India from a number of countries.
 - The margins of dumping from each of the subject countries are more than the *de- minimis* limits prescribed;
 - The volume of imports from each of the subject countries is more than the negligible limits prescribed;
 - Cumulative assessment of the effects of imports is appropriate as the exports from the subject countries directly compete with the like articles offered by the domestic industry in the Indian market, which is evident from the following:—
 - a. The products manufactured by the producers from the subject countries and the products manufactured by the Applicant have comparable properties. In other words, goods supplied by various subject countries and by the domestic industry are *inter-se* like articles.
 - b. There are common parties who are resorting to use of the imported subject goods from various sources and the goods produced by the domestic industry. Both, the imported and the domestic subject goods, are being used interchangeably and there is direct competition between the domestic product & imported products and *inter-se* amongst imported products.
 - c. The exporters from the subject countries and domestic industry have sold the product in the same periods to the same set of customers. The sales channels are comparable.

d. The volume of imports from each of the subject countries is significant.

141. In view of the above, the Authority considers that it would be appropriate to assess injury to the domestic industry cumulatively from exports of the subject goods from the subject countries
142. Annexure-II of the AD Rules provides for an objective examination of both, (a) the volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices, in the domestic market, for the like articles; and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such articles. With regard to the volume effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute term or relative to production or consumption in India. With regard to the price effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress the prices to a significant degree, or prevent price increases, which would have otherwise occurred to a significant degree.
143. As regards the impact of the dumped imports on the domestic industry para (iv) of Annexure- II of the AD Rules states as follows: "The examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry concerned, shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the Industry, including natural and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of margin of dumping actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments."
144. The Applicant domestic industry has claimed that dumping of the product in India has caused injury to the domestic industry. In this regard, it is noted that it has commenced commercial production in February 2010 and thus does not have operational history for more than three years. Therefore, the economic analysis of the performance of the domestic industry for the purpose of examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry concerned has been carried out for the period during which the petitioner has produced and sold the product. The analysis has been done first on an annual basis and thereafter by considering performance of domestic industry on a quarter by quarter basis. However, for the purpose of import volumes and market share, the Authority has considered the investigation period and the preceding three years.

Volume Effect of Dumped Imports and Impact on Domestic Industry

Demand/consumption in India

145. Demand of the product in the Country has been assessed as the sum of domestic sales of the domestic producers and imports from all sources.

Annual Analysis

Particulars	Unit of Measurement	2007-08	2008-09	2009-10	April'10-June'11 (POI)	Annualized (POI)
Sales of Domestic Industry	CBM	-	-	334	21,297	17,038
Sales of Other Indian Producer	CBM	-	-	-	4,030	3,224
Subject Countries imports	CBM	10,936	32,223	44,009	58,504	46,803
Other Countries imports	CBM	975	11,704	8,618	1,510	1,208
Demand in India	CBM	11,911	43,927	52,961	85,341	68,273

Quarterly Analysis

Demand	UOM	Feb'10-March'10	April'10-June'10	July'10-Sep'10	Oct'10-Dec'10	Jan'11-March'11	April'11-June'11
Sales of Domestic Industry	CBM	***	***	***	***	***	***
Sales of Other Indian Producer	CBM	-	-	-	***	***	***

Subject imports	Countries	CBM	8,259	10,486	8,807	10,284	14,985	13,942
Other imports	Countries	CBM	959	306	236	260	382	326
Demand in India		CBM	9,552	13,016	12,870	15,852	21,161	22,443

146. It is noted that the demand for the product under consideration in India has increased significantly over the period.

Import Volume from Subject Countries

147. The volume of imports of the subject goods from the subject countries and other countries have been examined based on the transaction-wise imports data as obtained by the domestic industry from IBIS. It is noted that the product under consideration does not have a dedicated Customs classification code and therefore summarized Customs data (as released by DGCI&S) has not been relied upon. Thus, individual transaction wise data, as made available by the secondary source (IBIS), has been relied upon. **During proceedings, the transaction wise data from DGCIS was also received. Since the transaction wise data from IBIS shows higher volume of imports of subject countries, therefore, the imports volume reported by the IBIS has been considered for injury analysis.** Volume of imports of the subject goods have been as follows:

Annual Analysis

Imports Volume	UOM	2007-08	2008-09	2009-10	April'10-June'11	Annualized (POI)
Indonesia	CBM	-	39	6,957	10,177	8,142
Malaysia	CBM	2,943	20,244	22,783	22,052	17,642
Sri Lanka	CBM	7,934	11,171	13,270	20,410	16,328
China PR	CBM	59	769	999	5,865	4,692
Total Subject Countries	CBM	10,936	32,223	44,009	58,504	46,803
Other Country	CBM	975	11,704	8,618	1,510	1,208
Total Imports	CBM	11,911	43,927	52,627	60,014	48,011

Quarterly Analysis

Import Volume	UOM	Feb'10-March'10	April'10-June'10	July'10-Sep'10	Oct'10-Dec'10	Jan'11-March'11	April'11-June'11
Indonesia	CBM	3,553	3,690	1,984	1,130	1,568	1,805
Malaysia	CBM	2,417	3,873	4,221	3,643	6,131	4,184
Sri-Lanka	CBM	2,093	2,663	2,334	4,371	5,332	5,710
China	CBM	196	259	269	1,140	1,955	2,243
Total Subject Countries	CBM	8,259	10,486	8,807	10,284	14,985	13,942
Other Country	CBM	959	306	236	260	382	326
Total Imports	CBM	9,218	10,792	9,043	10,543	15,368	14,268

148. The Authority notes that

- Imports from the subject countries have increased significantly. Imports have increased, when considered over the injury period or on quarterly basis within the investigation period;
- Given that the domestic industry has commenced commercial production in February 2010, the import volumes should have declined with the commencement of the production by the domestic industry. But no decline in the volume of imports from the subject countries was noted except in the quarter July 2010 – September 2010 over the previous quarter. Further, in the subsequent quarter the volume increased, instead of showing a natural decline and are now much higher than before;
- The increase in the imports is quite significant. Whereas the volume of imports in 2007-08 was 11,911 cbm, the volume of imports in April-June, 2011 quarter itself was 14,268 cbm. On an overall basis, the

increase in volume of imports was more than 300% over the injury period;

Market share in demand

149. The table given below analyses the trends in the market share of imports *vis-à-vis* the share of the domestic industry on an annual basis and quarterly basis:

Annual Analysis

Particulars	UOM	2007-08	2008-09	2009-10	April'10-June'11
Domestic Industry	%	-	-	0.63	24.96
Other Indian Producer	%	-	-	-	4.72
Total Subject Countries	%	91.81	73.36	83.10	68.55
Other Countries	%	8.19	26.64	16.27	1.77

Quarterly Analysis

Particulars	UOM	Feb'10-March'10	April'10-June'10	July'10-Sep'10	Oct'10-Dec'10	Jan'11-March'11	April'11-June'11
Domestic Industry	%	***	***	***	***	***	***
Other Indian Producer	%	***	***	***	***	***	***
Total Subject Countries	%	86.46	77.99	66.22	64.87	73.81	62.12
Other Countries	%	10.04	2.28	1.78	1.64	1.88	1.45

150. The Authority notes that the domestic industry has commenced the commercial production of the subject goods in the year 2009-10. During this period the domestic industry functioned for only 2 months. The year 2010-11 was the first year of commercial production of the petitioner company. The quarter wise analysis of the share of the subject countries indicates that while the share of imports of the other countries has declined significantly, no decline in the volume of imports for the subject countries has been noted. Further, the share of domestic industry in the total demand has fluctuated on a quarter to quarter basis.

Production, sales, capacity and capacity utilization

151. The production, sales, capacity and capacity utilization of the domestic industry has been analyzed as follows:

Annual Analysis

	UOM	2009-10	April'10-June'11	Annualized (POI)
Total Production	CBM	***	***	***
Below 6mm	CBM	2,262	22,980	18,384
Above 6mm	CBM	-	***	***
Sales volume	CBM	334	21,297	17,038
Captive consumption	CBM	***	***	***
Capacity	CBM	8,333	62,500	50,000
Capacity utilization (@ @)	%	***	***	***

@ @ Based on total production

Quarterly Analysis

	UOM	Feb'10-March'10	April'10-June'10	July'10-Sep'10	Oct'10-Dec'10	Jan'11-March'11	April'11-June'11
Total Production	CBM	***	***	***	***	***	***
Below 6mm	CBM	***	***	***	***	***	***

Above 6mm	CBM	***	***	***	***	***	***
Sales volume	CBM	***	***	***	***	***	***
Captive consumption	CBM	***	***	***	***	***	***
Capacity	CBM	***	***	***	***	***	***
Capacity utilization	%	***	***	***	***	***	***

Price effect of the dumped imports on the domestic industry

152. With regard to the effect of the dumped imports on prices, the Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. Annual movement of the import prices has been analyzed as follows:

Unit in Rs/cbm					
CIF Import Price	UOM	2007-08	2008-09	2009-10	April'10-June'11
Indonesia	Rs/CBM	-	12,831	11,104	11,362
Malaysia	Rs/CBM	10,980	11,609	10,726	11,797
Sri Lanka	Rs/CBM	12,352	13,236	11,929	12,616
China	Rs/CBM	7,488	10,234	11,307	11,198
Total Subject Countries	Rs/CBM	11,956	12,142	11,162	11,947
Other Countries	Rs/CBM	12,785	12,378	11,434	13,619
Total Imports	Rs/CBM	12,024	12,205	11,206	11,989

153. Quarter wise movement of the import prices has been analyzed as follows:

CIF Import Price	UOM	Feb'10-March'10	April'10-June'10	July'10-Sep'10	Oct'10-Dec'10	Jan'11-March'11	April'11-June'11
Total Subject Countries	CBM	11,572	11,764	11,847	11,818	11,934	12,256
Other Countries	CBM	12,288	12,802	14,993	14,497	13,264	13,108
Total Imports	CBM	11,647	11,794	11,929	11,884	11,967	12,276

154. The Authority notes from the above that there is no noticeable change in the CIF price of imports from the subject countries during the injury period and the period of investigation. Further, the CIF price of imports from the other countries was noted to be higher than the CIF price from the subject countries.
155. As noted above, no changes in the CIF prices of imports from the subject countries have been noted during the injury period and the POI. The Authority has undertaken an analysis of the trends in the prices of raw material for the subject goods during the relevant period. In this context, the Authority notes that the wood, glue cost and other chemicals are important elements in the cost of production. The analysis of the data submitted by the domestic industry and the other interested parties, shows that the element of wood, glue cost and other elements in the total cost of production is more than 50%. An analysis of the trends in the cost of production of the domestic industry indicates that there has been a significant increase in the prices of wood over the prices as projected in the project report. With regards to the movements in the prices of raw materials i.e. wood in respect of other exporters from the subject countries, the Authority notes that the information with regards to trends in the prices of wood, as available at the website of one of the co-operating exporters M/s Evergreen indicates the following trends:

Indexed	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	POI
Wood price indexed *	136	132	121	148	160
Indexed wood prices	100	97	89	109	118

*with year 2005 as base year

156. The Authority notes from the above that there has been an increase in the price of wood during the injury period and the POI by as much as 18%. However, this is not reflected in the changes in the CIF price of imports from the subject countries. The trends, as above, reflects that the exporters from the subject countries have absorbed the increase in the cost of production, as the same is not reflected in the changes in the CIF export prices.
157. The Authority further notes that apart from wood, glue is an important element in the production of the subject goods. Glue is manufactured by using a combination of different chemicals, most important of them being Paraffin Wax, Urea, Melamine and Methanol. An analysis of trends in the import prices of these raw materials, as summarized below also indicates that there has been a substantial increase in the rates of some of these raw materials.

	Unit	07-08	Indexed	2010-11	Indexed	% increase
Input price movement						
Paraffin Wax	Rs.Kg	40.26	100	57.21	142	42
Urea / (Carbamie)	Rs.Kg	12.32	100	13.24	107	7
Melamine	Rs.Kg	50.56	100	67.18	133	33
Methanol	Rs.Kg	36.12	100	40.61	112	12

158. It is noted that there has been a significant increase in the input costs for glue and other major inputs. However, no commensurate increase in trend have been noted in the CIF export price of the subject goods from the subject countries. In view of the same, the Authority notes that escalation in the cost of inputs has been absorbed by the exporters. Based on the analysis of data furnished by the cooperating exporters from the subject countries, the authority notes that these exporters have significant volume of exports to third countries. The sales realization in case of all the cooperating exporters from the subject countries for three years prior to the period of investigation was noted to be significantly higher than the export price to India. This indicates that the prices at which the subject goods have been exported to India for three years prior to the POI were dumped prices.

Price undercutting and underselling effects

159. Price undercutting has been determined by comparing the weighted average landed value of dumped imports from the subject countries over the entire period of investigation with the weighted average net sales realization of the domestic industry. For this purpose landed value of imports has been calculated by adding 1% handling charge and applicable basic customs duty to the value reported in the IBIS data of import prices from the subject countries.
160. In order to determine the net sales realization of the domestic industry, discounts, commissions, etc. offered by the domestic industry and the central excise duty paid, if any, have been deducted from the total sales realization.
161. For the purpose of price underselling determination the weighted average landed price of imports from the subject countries has been compared with the Non-injurious selling price of the domestic industry determined for the POI.

Price Undercutting

162. The comparative analysis of the Net Sales Realization of the domestic industry with the landed value of imports indicates that the imports are undercutting the domestic industry's prices to the extent mentioned below:

Price undercutting	UOM	2009-10	April'10-June'11 (POI)
NSR of Domestic Industry	Rs/CBM	***	***
Indonesia			
Landed Price	Rs/CBM	12,370	12,657
Undercutting	Rs/CBM	***	***
Undercutting	%	***	***
Undercutting	% Range	30-40	20-30
Malaysia			
Landed Price	Rs/CBM	11,948	13,142
Undercutting	Rs/CBM	***	***
Undercutting	%	***	***

Undercutting	% Range	30-40	20-30
Sri Lanka			
Landed Price	Rs/CBM	11,929	12,616
Undercutting	Rs/CBM	***	***
Undercutting	%	***	***
Undercutting	% Range	35-45	20-30
China			
Landed Price	Rs/CBM	12,596	12,474
Undercutting	Rs/CBM	***	***
Undercutting	%	***	***
Undercutting	% Range	30-40	25-35
Total Subject Countries			
Landed Price	Rs/CBM	12,024	12,807
Undercutting	Rs/CBM	***	***
Undercutting	%	***	***
Undercutting	% Range	30-40	20-30

Note: Landed Price calculation for 2009-10 full year imports and NSR for DI only two months Feb '10 to March'10.

163. The Authority notes from the above that the landed prices from all the subject countries were undercutting the sales price of the domestic industry. The Authority further notes that while there was a marginal increase in the landed value of imports during the POI over the year 2009-10, the quantum of undercutting declined on account of significant decline in the NSR of the domestic industry. The Authority, therefore, notes that the domestic industry was forced to reduce its selling prices in line with the landed value of imports, although it continued to incur losses, as elaborated subsequently in these findings.

Quarterly Analysis

Price undercutting	UOM	Feb'10- March'10	April'10- June'10	July'10- Sep'10	Oct'10- Dec'10	Jan'11- March'11	April'11- June'11
NSR of Domestic Industry	Rs/CBM	***	***	***	***	***	***
Indonesia							
Landed Price	Rs/CBM	12,681	13,062	11,898	11,963	12,387	13,335
Undercutting	Rs/CBM	***	***	***	***	***	***
Undercutting	%	***	***	***	***	***	***
Undercutting	% Range	30-40	20-30	25-35	25-35	25-35	20-30
Malaysia							
Landed Price	Rs/CBM	11,572	12,341	13,135	12,942	13,225	13,945
Undercutting	Rs/CBM	***	***	***	***	***	***
Undercutting	%	***	***	***	***	***	***
Undercutting	% Range	35-45	25-35	20-30	20-30	20-30	15-25
Sri Lanka							
Landed Price	Rs/CBM	13,171	12,626	12,449	12,464	12,604	12,807
Undercutting	Rs/CBM	***	***	***	***	***	***
Undercutting	%	***	***	***	***	***	***
Undercutting	% Range	25-35	25-35	20-30	20-30	20-30	25-35
China							
Landed Price	Rs/CBM	13,954	15,298	17,953	12,317	12,207	11,804
Undercutting	Rs/CBM	***	***	***	***	***	***
Undercutting	%	***	***	***	***	***	***
Undercutting	% Range	20-30	10-20	Negative	25-35	25-35	30-40

Total Subject Countries							
Landed Price	Rs/CBM	12,511	12,740	12,822	12,562	12,783	13,056
Undercutting	Rs/CBM	***	***	***	***	***	***
Undercutting	%	***	***	***	***	***	***
Undercutting	% Range	30-40	20-30	20-30	20-30	20-30	20-30

Note: Landed Price calculation only considered Feb '10 & March'10 (2 Months)

Price Underselling

164. Comparison of non injurious price with the selling price of the domestic industry shows that the domestic industry was forced to undersell the product:

In Rs/CBM

	UOM	April'10-June'11 (POI)
Non injurious price	Rs/CBM	***
Landed value (subject countries)	Rs/CBM	12807
Price underselling	Rs/CBM	***
Underselling	%	***
Underselling	% Range	50-60

165. The Authority notes that the Net Sales Realization of the domestic industry during the POI was below the non-injurious price of the domestic industry. Therefore, the domestic industry was not able to recover reasonable profit on its sales of the subject goods.

Injury margin

166. Comparison of non injurious price with landed price of imports shows significant injury margin.

Injury Margin	UOM	NIP	Landed Price	Injury Margin	Injury Margin %	Injury Margin % Range
Indonesia	Rs/CBM	***	12,657	***	***	55-65
Malaysia	Rs/CBM	***	13,142	***	***	50-60
Sri Lanka	Rs/CBM	***	12,616	***	***	55-65
China	Rs/CBM	***	12,474	***	***	55-65
Total Subject Countries	Rs/CBM	***	12,807	***	***	55-65

167. As a result of significant injury margins from all the subject countries during the POI, the domestic industry has suffered financial losses and has not able to achieve the projected level of profitability as per the project report.

Profits/Loss

168. Profits earned by the domestic industry from the sales of the subject goods in the domestic market were as follows:

	UOM	2009-10	April'10-June'11 (POI)
Cost of sales	Rs/CBM	***	***
Indexed	Trend	100	34

Selling Price	Rs/CBM	***	***
Indexed	Trend	100	90
Profit/ (Loss) per unit	Rs/CBM	***	***
Indexed	Trend	(100)	(8)
Profit/ (Loss)	Rs Lacs	***	***
Indexed	Trend	(100)	(519)

169. The Authority notes from the above that in the year 2009-10 since the domestic industry operated for only 2 months, due to start-up operations and low level of capacity utilization, its actual cost, profits / losses per unit were very high. In view of the period 2009-10 being only a start-up period, no trend analysis / conclusions could be drawn by the Authority. However, subsequently in the period of investigation, the domestic industry has operated for the complete financial year. During this period also the financial performance of the domestic industry was noted to be negative. The Authority notes that the sales realization of the domestic industry declined during the period and the domestic industry suffered financial losses.

Return on investment

170. Return on investment earned by the domestic industry from the sale of the subject goods in the domestic market were as follows:

	UOM	2009-10	April'10- June'11 (POI)	Annualised (POI)
Profit before interest	Rs Lacs	(***)	(***)	(***)
Profit before interest (Indexed)	Trend	(100)	(235)	(235)
Capital employed	Rs Lacs	***	***	***
Capital employed (Indexed)	Trend	100	90	90
Return on capital employed	%	~***%	~***%	~***%
Return on capital employed (Indexed)	Trend	(100)	(44)	(44)

171. —The Authority notes from the above that the capital employed by the domestic industry during the POI on an annualized basis was lower than the projections of the capital employed as per project report and therefore, no cost overruns have been noted by the Authority in the commissioning of the plant for manufacture of subject goods. **The Authority, however, notes that the domestic industry was not able to achieve the reasonable returns on capital employed as it suffered financial losses during the POI on account of dumped imports of the subject goods.**

Cash flow

172. Impact of dumping on the cash flow of the domestic industry was determined by considering cash profits earned by the domestic industry from the sales of the subject goods in the domestic market were as follows:

	UOM	2009-10	April'10- June'11 (POI)	Annualized (POI)
Profit/ (Loss)	Rs.Lacs	(100)	(416)	(416)
Depreciation	Rs.Lacs	100	203	203
Cash Profit	Rs.Lacs	100	(259)	(259)

173. The Authority notes that due to price undercutting and price underselling on account of dumped imports, the company has suffered cash losses during the POI.

Employment and wages

174. The trends in the employment and wages in the domestic industry are tabulated below:

	UOM	2009-10	April'10-June'11 (POI)
Employment	Nos.	90	113
Wages	Rs.Lacs	100	1399

Inventories

175. The trends in inventory holding of the domestic industry has been summarized below:

	UOM	2009-10	April'10-June'11 (POI)
Stocks	CBM	***	***
Stock Indexed	Trend	100	119
Production	CBM	2,262	22,980
Average Stock for POI	CBM	-	1,318
Average Stock equivalent no of months production	Days		0.86

176. The Authority notes from the above that during the POI, which was the first year of full operations of the domestic industry, the domestic industry was maintaining on an average stocks equivalent to 0.86 months production. Since, the domestic industry has claimed that it has not been able to sell the subject goods to the extent it was able to produce, the Authority has undertaken a month-wise analysis of the trends in the production, sales and stocks of the inventories of the domestic industry during the POI. The analysis of the same is given in the table below:

Monthly	Opening Stock	Net Production excluding captive	Capacity Utilisation %	Sales	Closing Stock	Closing stock as no of Days sales
Apr-10	***	***	***	***	***	***
May-10	***	***	***	***	***	***
Jun-10	***	***	***	***	***	***
Jul-10	***	***	***	***	***	***
Aug-10	***	***	***	***	***	***
Sep-10	***	***	***	***	***	***
Oct-10	***	***	***	***	***	***
Nov-10	***	***	***	***	***	***
Dec-10	***	***	***	***	***	***
Jan-11	***	***	***	***	***	***
Feb-11	***	***	***	***	***	***
Mar-11	***	***	***	***	***	***
Apr-11	***	***	***	***	***	***
May-11	***	***	***	***	***	***
Jun-11	***	***	***	***	***	***

177. The Authority notes from the above that in the first quarter of the POI the domestic industry gradually

increased its capacity utilization. However, during the same period there was a significant buildup of the inventories. As a consequence, in the subsequent quarter the production and the capacity utilization of the domestic industry were noted to be significantly lower. During the third and fourth quarter, generally the production, sales and the closing stocks noted uniform trends. In the last quarter of the POI, when the domestic industry increased its level of operations, once again significant levels of inventories were noted. The Authority, therefore, notes that due to significant buildup of inventories, the domestic industry was not able to operate at the optimum level of capacity utilization.

Productivity

178. The productivity of the domestic industry has been examined with reference to production per day and per employee as follows:

	UOM	2009-10	April'10-June'11 (POI)
Productivity per day	CBM/day	37.70	67.81
Productivity per Employee	CBM/Nos	150.13	211.17

179. It is noted that productivity has improved over the period.

Growth

180. It may be noted that domestic industry commenced commercial production at a new production facility. Therefore, growth of the domestic industry should have been quite high. However, the domestic industry is faced with poor growth.

Other Injury Information

181. The Authority has also analysed injury data for all quarters of the POI and these are mentioned below. The table shows the adverse impact due to dumped imports of subject goods from subject countries. Bases on the table below, the Authority notes that the profitability of the domestic industry for all the quarters was negative and it has significantly deteriorated in the later half of the POI. Similarly, the returns on investments continue to be negative.

Injury information

Particular	UOM	April'10-June'10	July'10-Sep'10	Oct'10-Dec'10	Jan'11-March'11	April'11-June'11	April'10-June'11 (POI)
Cost of Sales	Rs/CBM	***	***	***	***	***	***
Indexed	Trend	100.00	100.00	100.00	100.00	99.54	99.87
Selling Price	Rs/CBM	***	***	***	***	***	***
Indexed	Trend	100.00	97.50	97.26	97.67	98.52	98.02
Profit/ (Loss)	Rs/CBM	(***)	(***)	(***)	(***)	(***)	(***)
Indexed	Trend	(100.00)	(114.40)	(115.80)	(113.47)	(105.48)	(110.56)
Profit/ (Loss)	Rs Lacs	(***)	(***)	(***)	(***)	(***)	(***)
Indexed	Trend	(100.00)	(197.07)	(254.39)	(230.19)	(286.30)	(1,067.95)
Profit before interest	Rs Lacs	(***)	(***)	(***)	(***)	(***)	(***)
Indexed	Trend	(100.00)	(1,412.14)	(2,186.81)	(1,859.75)	(2,618.18)	(8,176.88)
Cash Profit	Rs Lacs	***	***	***	***	***	***
Indexed	Trend	100.00	(86.22)	(196.16)	(149.75)	(257.38)	(589.51)
Capital Employed	Rs Lacs	***	***	***	***	***	***
Indexed	Trend	100.00	97.82	95.64	93.46	91.27	91.27
Return on capital Employed	%	(***)	(***)	(***)	(***)	(***)	(***)
Indexed	Trend	(100.00)	(1,443.63)	(2,286.57)	(1,989.97)	(2,868.46)	(1,791.70)
Productivity per day	CBM/Day	***	***	***	***	***	***
Productivity per Employee	CBM/Nos	***	***	***	***	***	***

Analysis of Post POI data

182. The Authority has also undertaken analysis of the performance of the domestic industry in the post period of investigation on a quarterly basis. Based on the analysis of the data, the authority notes that the volume of imports from the subject countries continued to be in line with the volume during the POI. On the other hand, the production and sales volume of the domestic industry have shown marginal improvement in the six months period post POI. The authority further notes that while the landed value of imports from the subject countries was significantly below the net sales realization of the domestic industry. Further, the NSR of the domestic industry in the post POI also continued to be significantly below the NIP determined for the domestic industry indicating that even in the post POI period, the domestic industry was not able to realize the expected selling price from the subject goods. This is further reflected from the financial losses suffered by the domestic industry in the post POI period.

Particular	July'11-Sep'11	Oct'11-Dec'11
Installed Capacity CMB	12500	12500
Production CMB	9611.14	12250.57
Capacity Utilisation	87.90%	101.58%
Sales Volumes CMB	9110.6	11604.96
Import Volumes CMB	11570.69	10485.52
Sales Realisation Rs per CMB	***	***
Profits In Rs lacs	(***)	(***)
Profits per CMB	(***)	(***)
Landed Value Of Imports per CMB	13978.6	16778.89
Undercutting per CMB	***	***
Undercutting % range	20-30	10-20
Injury Margin	***	***
Injury margin range	40-50	18-28

Ability to raise fresh Investment

183. It may be noted that the domestic industry has set up a new plant and the investments made by the domestic industry. However, should the performance of the domestic industry remain so dismal, fresh investments are likely to suffer.

Factors affecting prices

184. Consideration of factors such as the import prices from the subject countries and other countries, cost structures for the product, competition in the domestic market, factors other than the dumped imports that might be affecting the prices of the domestic industry in the domestic market shows that the landed value of imported material from subject countries are significantly below the selling price of the domestic industry, causing severe price undercutting in the Indian market. It is further noted that the benchmark for the Indian producers prices are the import prices from subject countries. There is no viable substitute for this product. Demand for the product was showing significant jump and could not have been a factor responsible for low prices. It is thus evident that the only factors responsible for the domestic industry prices are the subject import prices of the product and the cost of production of the domestic industry. As the information and data shows, while the cost of production was higher, the import prices have been much lower than the domestic prices and have prevented the domestic industry from charging prices in line with the costs.

Conclusion on injury

185. **Considering the various injury parameters, it may be concluded that the performance of the domestic industry has remained low considering the commencement of the new plant. The imports from the subject country have increased, whereas the imports should have declined, given that the domestic industry has set up new production facilities and supporting company has also commenced the production of the product under consideration. Level of price undercutting is significant. Despite offering low prices, the domestic industry had to immediately reduce its prices in view of its inability to sell the product. The domestic industry is facing price depression effects due the significantly low priced dumped imports. The domestic industry has been forced to sell the product at financial losses, resulting in negative return on investments and cash flow. The performance of the domestic industry was adverse despite sufficient demand for the product in the Country. Even after adjusting the cost of production of the domestic industry for the start up operations, the domestic industry was unable to recover its cost of production and earn reasonable profits. Thus, after analysis of the volume of dumped imports of subject goods from subject countries, the price effect on account of such imports and its impact on the domestic industry in terms of injury parameters as per anti dumping rules, it is noted that the domestic industry suffered material injury.**

I. Causal Link

Submissions made by the Domestic Industry

186. The Domestic Industry has submitted that injury to the domestic industry is on account of dumped imports as significant price difference exists between imported and domestic product, which has prevented the domestic industry from selling its product to the extent of its production capacities. This led to reduction in price and low level of sales volumes, reduction in net sales realization. There is significant difference between non injurious price and landed price of imports on one hand and inability of the domestic industry to increase its production to the extent of target levels on the other hand. The domestic industry has suffered from significant loss of production man hours, increase in inventories with rising production, decline in production due to rising inventories, which collectively and cumulatively established that the domestic industry is suffering injury as a result of dumped imports.

Submissions made by other interested parties

Submissions made on behalf of M/s Segamat Panel Boards Sdn. Bhd and M/s Merbok MDF Lanka (Private) Ltd. Sri Lanka

187. The petitioner has commenced their production recently. Therefore, it is quite known that the petitioner would suffer injury on account of various factors such as (i) Start up cost; (ii) Un- established sales and distribution channels; (iii) increased marketing expenses coupled with higher discounts. Further, we have already quantified as above the main reasons for higher cost of production of applicant industry caused by inherent inefficiencies. Therefore, the Authority is requested to kindly take into account the above facts which would clearly demonstrate that no injury has been caused to the domestic industry on account of the alleged dumped imports and if there is any injury to the domestic industry during POI which was on account of their inefficiencies. Further, while landed prices have gone up during POI, the selling prices of domestic industry have declined clearly showing inverse relationship not to speak of causal link.

Submissions made on behalf of Evergreen Fibreboard Berhad (EEB), Malaysia; Evergreen Fibreboard (IB) Sdn. Bhd. (EIB), Malaysia and Evergreen Fibreboard (Nilai) Sdn. Bhd.(EFN), Malaysia

188. There is no injury to the petitioner in terms of its capacity, production, capacity utilization, sales, market share, wages, number of employees, productivity, inventories etc. The injury with respect to profitability, return on investment, cash flow and price suppression, if any is not because of the alleged dumped imports from subject countries but because of its high cost due to high per unit cost on account of start-up cost, high raw material cost, high utility cost, high fixed cost, high labour cost, high interest cost and high depreciation cost. While making a causal link analysis in the petition, the petitioner has not made any analysis with respect to sales of the other Indian producer nor provided any details in the petition. It is submitted that injury, if any has been suffered by the petitioner on account of inter-se competition between the two domestic producers. Thus there is no causal

link between the injury, if any to the domestic industry and alleged dumped imports.

Examination by the Authority

189. As per the AD Rules, the Authority, *inter alia*, is required to examine any known factors other than the dumped imports which at the same time are injuring the domestic industry, so that the injury caused by these other factors may not be attributed to the dumped imports. Factors which may be relevant in this respect include, *inter alia*, the volume and prices of imports not sold at dumped prices, contraction in demand or changes in the patterns of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers, developments in technology and the export performance and the productivity of the domestic industry. It was examined whether these other parameters listed under the AD Rules could have contributed to injury to the domestic industry. It was found that:-
- a. **Volume and Price of imports from third countries:** The Authority notes that imports from third countries are either negligible or their volume is *de-minimis* during the POI. Thus, imports from third countries could not have caused injury to the domestic industry.
 - b. **Contraction in Demand and Changes in pattern of consumption:** It is noted that the demand of the subject goods has increased over the injury period. There is also no indication of any change in the consumption pattern.
 - c. **Trade Restrictive Practices of and Competition between the Foreign and Domestic producers:** The import of the subject goods is not restricted in any manner and the same are freely importable in the country. The domestic industry competes with the landed prices of the subject goods. The price of the domestic industry is influenced significantly by the landed price of the subject goods. Moreover, no evidence has been submitted by any interested party to suggest that the conditions of competition between the foreign and the domestic producers do not exist or have undergone any change.
 - d. **Development of Technology:** None of the interested party has raised any issue with regard to developments in technology as being the cause of injury to the domestic industry. No information, in respect of any significant development in technology is on record that could be the principal cause of injury to the domestic industry.
 - e. **Export Performance:** The Authority notes that the Applicant domestic industry has not exported the subject goods.
190. The Authority notes that while listed known other factors do not show injury to the domestic industry, the following parameters show that injury to the domestic industry has been caused by dumped imports.
- a) Imports of the product under consideration have increased significantly during the injury period.
 - b) Apparently, the domestic industry has lost its sales volumes due to the presence of the dumped subject goods in India.
 - c) The imports, from the subject countries as a whole, are significantly undercutting the prices of the domestic industry.
 - d) The imports are significantly underselling the domestic prices.
 - e) The deterioration in the domestic industry's profits and return on capital employed are apparently as a result of the dumped imports.
 - f) The domestic industry's performance has become negative in respect of a number of parameters as the Domestic industry has not been able to attain the projected levels of Physical and Financial performance on a number of parameters.

Magnitude of injury and injury margin

191. The Authority has determined non-injurious price for the domestic industry on the basis of principles laid down in the AD Rules, as amended.

Co-operating Exporter

Name of the company	NIP	Landed Price	Injury Margin	Injury Margin %	Injury margin range %
Pt Sumatera Prima Fibreboard, Indonesia	***	***	***	***	55 -65
M/s Segamat Panel Boards Sdn. Bhd. Malaysia	***	***	***	***	50-60
M/s Evergreen Fibreboard Berhad (EFB)/, Malaysia	***	***	***	***	50-60

M/s Evergreen Fibreboard (JB) Sdn. Berhad (EJB), Malaysia	***	***			
M/s Merbok MDF Lanka (Private) Limited, Srilanka	***	***	***	***	55-65

Non-Co-operating Exporter

Particulars	Unit	China PR	Indonesia	Malaysia	Sri Lanka
NIP	US\$/cbm	***	***	***	***
Landed Price	US\$/cbm	***	***	***	***
Injury Margin	US\$/cbm	***	***	***	***
Injury Margin(%)	%	***	***	***	***
Injury Margin(%) range	%	<u>60-70</u>	<u>70-80</u>	<u>60-70</u>	<u>90-100</u>

In US\$/cbm

Conclusions:

192. After examining the submissions made by the interested parties and issues raised therein; and considering the facts available on record, the Authority concludes that:
- The product under consideration has been exported to India from the subject countries below the associated normal values, thus resulting in dumping of the subject goods from the subject countries.
 - The domestic industry has suffered material injury in respect of the subject goods.
 - The material injury to the domestic industry has been caused by the dumped imports of the subject goods from the subject countries.

Indian industry's interest & other issues

193. The Authority notes that the purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate 'injury' caused to the domestic industry by the unfair trade practices of 'dumping' so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the Country. Imposition of anti-dumping measures would not restrict imports from the subject countries in any way, and, therefore, would not affect the availability of the subject goods to the consumers.
194. It is recognized that the imposition of anti-dumping duties might affect the price levels of the products manufactured using the subject goods and consequently might have some influence on relative competitiveness of these products. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the anti-dumping measures, particularly if the levy of the anti-dumping duty is restricted to an amount necessary to redress the injury caused to the domestic industry. On the contrary, imposition of the anti-dumping measures would remove the unfair advantages gained by the dumping practices, would prevent the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods.

Recommendations

195. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the exporters, importers and other interested parties to provide positive information on the aspects of dumping, injury and causal link. Having initiated and conducted investigation into dumping, injury and the causal link thereof in terms of the AD Rules and having established positive dumping margins as well as material injury to the domestic industry caused by such dumped imports, the Authority is of the view that imposition of definitive duty is required to offset dumping and 'injury'. Therefore, the Authority considers it necessary and recommends imposition of definitive anti-dumping duty on imports of the subject goods originating in or exported from the subject countries in the form and manner described hereunder.

196. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends imposition of definitive anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, the definitive anti-dumping duty equal to the difference between amount indicated in Col 8 of the table below and the landed value is recommended to be imposed on all imports of subject goods originating in or exported from the subject countries

Duty table

Sl. No	Heading/ Sub-heading*	Description of goods	Country of Origin	Country of Exports	Producer	Exporter	Amount in US \$ /cbm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	4411*	'Resin or other organic substances **	China PR	China PR	Any	Any	407.14
2	4411*	--do--	Any country other than the subject countries	China PR	Any	Any	407.14
3	4411*	--do--	China PR	Any country other than the subject countries	Any	Any	407.14
4	4411*	--do--	Indonesia	Indonesia	Pt Sumatera Prima Fibreboard	Pt Sumatera Prima Fibreboard	338.86
5	4411*	--do--	Indonesia	Indonesia	Any other than combination at Sr. Nos. 4		351.34
6	4411*	--do--	Any country other than the subject countries	Indonesia	Any	Any	351.96
7	4411*	--do--	Indonesia	Any country other than the subject countries	Any	Any	351.96
8	4411*	--do--	Malaysia	Malaysia	M/s Segamat Panel Boards Sdn. Bhd.	M/s Segamat Panel Boards Sdn. Bhd.	318.99
9	4411*	--do--	Malaysia	Malaysia	M/s Evergreen Fibreboard Berhad (EFB) / M/s Evergreen Fibreboard (JB) Sdn. Berhad (EJB)	M/s Evergreen Fibreboard Berhad (EFB) / M/s Evergreen Fibreboard (JB) Sdn. Berhad (EJB)	321.56
10	4411*	--do--	Malaysia	Malaysia	Any other than combination at Sr. Nos. 8 & 9		341.91

11	4411*	--do--	Any country other than the subject countries	Malaysia	Any	Any	341.91
12	4411*	--do--	Malaysia	Any country other than the subject countries	Any	Any	341.91
13	4411*	--do--	Sri Lanka	Sri Lanka	M/s Merbok MDF Lanka (Private) Limited	M/s Merbok MDF Lanka (Private) Limited	315.00
14	4411*	--do--	Sri Lanka	Sri Lanka	Any other than combination at Sr. No. 13		329.40
15	4411*	--do--	Sri Lanka	Any country other than the subject countries	Any	Any	329.40
16	4411*	--do--	Any country other than the subject countries	Sri Lanka	Any	Any	329.40

* The product under consideration is classified under Chapter 44 of the Customs Tariff Act. However, the product under consideration does not have a dedicated customs classification code. Thus, Customs classifications are indicative only and in no way binding on the scope of this investigation.

****bonded wood or ligneous fibre boards of thickness more than 2mm and below 6mm, except *insulation boards, laminated fibre boards, Moulded Door Skins, and boards which are not bonded either by resin or other organic substances.***

(all italics mentioned above are excluded from anti dumping duty)

197. Landed value of imports for the purpose shall be the assessable value as determined by the Customs under the Customs Act, 1962 and all duties of customs except duties under sections 3, 3A, 8B, 9 and 9A of the Customs Tariff Act, 1975.

198. Subject to the above, the Authority confirms the preliminary findings dated 23rd July 2012.

199. Rule 23(IA) states that any anti-dumping duty imposed under the provision of section 9A of the Act, shall remain in force, so long as and to the extent necessary, to counteract dumping, which is causing injury. After careful consideration, the Authority recommends that duration of anti dumping duty should be only 18 months from the date of its imposition which allows the domestic industry to complete 4 years of production and therefore enable the domestic industry to provide full data for trend analysis. The domestic industry can take necessary action to prove the need for anti dumping duty on product under consideration prior to completion of the duty period.

Further Procedure

200. The following procedure would be followed subsequent to notifying the final findings: -

201. An appeal against the order of the central government shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act.

J S DEEPAK, Designated Authority